राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या: 08

सोमवार,

15 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा संभाग में नहरों का जीर्णोद्धार

127. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में नहरों के जीर्णोद्धार के लिए क्या सरकार द्वारा 1274 करोड़ रुपये की कोई योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कब?

(2) वर्तमान में उक्त योजना की क्या स्थिति है तथा उक्त योजना में कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना कार्य अब तक शेष है?

(3) क्या सरकार को उक्त योजना में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या व उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त योजना के तहत नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य समय पर पूर्ण करवाने हेतु क्या-क्या प्रयास कर रही है? व अब तक किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 1274.00 करोड़ के जीर्णोद्धार कार्य चम्बल परियोजना की दायीं एवं बायीं नहरों पर करवाये जाने की घोषणा की गयी थी। बजट घोषणा के क्रियान्वयन अन्तर्गत राशि रु. 707.46 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये हैं।

(2) वर्तमान में उक्त योजना के तहत तीन चरणों में कार्य करवाये जा

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

रहे हैं। जिन पर माह जून 2019 तक राशि रु. 707.46 करोड़ के कार्यादेश के विरुद्ध राशि रु. 219.88 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 31 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 69 प्रतिशत कार्य अभी शेष है।

(3) जी हां। चम्बल नहरों के प्रथम चरण के जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच बाबत मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता जल संसाधन, राजस्थान जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। संवेदक को डिफैक्टिव कार्य तोड़कर पुनः किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, संवेदक द्वारा एक पैकेज से सम्बन्धित डिफैक्टिव कार्य को दुरुस्त किया। शेष तीन पैकेज में कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों अनुसार न होने एवं धीमी प्रगति के कारण अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही करते हुए संवेदक के जोखिम एवं लागत पर गुणवत्ताहीन कार्य के पुनर्निर्माण को सम्मिलित करते हुए दूसरे संवेदक को कार्य आबंटित कर दिये गये हैं। इस क्रम में एक कनिष्ठ अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता को सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र कार्मिक विभाग को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया।

(4) उक्त योजना के तहत नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य समय पर पूर्ण करवाने के लिए धीमी गति से कार्य कर रहे संवेदकों को नोटिस दिये जा रहे हैं तथा संवेदकों के विरुद्ध अनुबंध की धारा 2 के तहत शास्ति आरोपित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र 31 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है और वह भी छह वर्ष में, यह बड़ा गम्भीर विषय है। हालांकि विभाग ने कार्यवाही की है परन्तु किसानों के पास टेल तक पानी इन तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। वस्तु स्थिति यह है कि सम्पूर्ण सीएडी की भूमि पर कई स्थानों पर अतिक्रमण कर लिये गये हैं। ड्रेन सिस्टम बिलकुल ब्लाक है जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुसता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, मैं सीधे-सीधे कह रहा हूं कि वाटर लोस है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इस वाटर लोस को रोका जाए। तकनीकी कारणों को सही करके, किसानों को टेल तक पानी पहुंचाया जाए। पानी के नहीं पहुंचने पर सारी फसल नष्ट हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ रहे हैं या सोल्यूशन दे रहे हैं?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इन तकनीकी कारणों को सही करने का सरकार क्या प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से वाटर लोस हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रेनेज साफ नहीं हो पा रहा?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह नहीं कहूंगा कि पिछले सालों के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पिछले पांच सालों में जो कुछ भी हुआ वह विभाग द्वारा ही हुआ। प्रगति नहीं हुई, इसका जिम्मेदार भी विभाग है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। अभी आपने यह बात की कि इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो बजट 2012-13 में अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी 1274 की, वह इसी मकसद से की गयी कि जो वाटर लोस हो रहे हैं इन वाटर लोस में कच्ची खालों का पक्का निर्माण कैसे किया जाए, वाटर लोस कैसे बचाया जाए। पांच साल में इसकी प्रोग्रेस नहीं हुई इसके कई कारण हैं। क्या कारण हैं वह आप भी अच्छी तरह से जानते है, आप भी उसी क्षेत्र से हैं। काम करने की अवधि है वह तीन माह भी नहीं है उससे कम की अवधि के अंदर ही अपन काम कर सकते हैं। सोइल का नेचर भी आप अच्छी तरह से जानते हो। पांच साल के अंदर बजरी की स्थिति रही या दूसरी स्थितियां रहीं इन विभिन्न कारणों से जो प्रोग्रेस आनी चाहिए थी वह प्रोग्रेस नहीं आई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठे-बैठे नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज बैठें, अंकित नहीं होगा। आप बैठें प्लीज। आप सीनियर मैम्बर हैं, प्लीज। बैठे-बैठे नहीं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अधिकारी और ठेकेदार स्तर पर जो

(श्री हरीश चौधरी)

भी कमियां रही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भविष्य में हम लोग यह कार्य प्राथमिकता से करवाएंगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे संवेदकों को सस्पैंड करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। बात हो गयी। प्रश्न नहीं पूछ रहे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा द्वितीय प्रश्न यह है कि चम्बल सिंचाई प्रोजेक्ट से राजस्थान को मांग के अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सहमति नहीं हो पाने के कारण....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे। माननीय कटारिया जी। आप एक मिनट विराजो। कटारिया जी, पूछिए। आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जो पैसा स्वीकृत हुआ वह 2012-13 के बजट में हुआ। आपने कहा कि 707 करोड़ रुपये का वर्क आर्डर दिया है। वर्क आर्डर कब दिया था और कितने समय में यह काम पूरा होना था? इसको पूरा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, जिस अवधि में इसको पूरा होना था, क्या समय-समय पर उन्होंने ठेकेदार को अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी की है? उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रयत्न किया?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि जो अवधि तय की गयी उस अवधि के अंदर कार्य नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अवधि कितनी है, कांट्रैक्ट कब दिया?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अगर आप इजाजत दें तो सबके लिए अलग-अलग कार्य दिये गये उसके बारे में बता दूं। अलग-अलग कम्पनी थी। कार्य करने की वास्तविक अवधि प्रति वर्ष, मैसर्स साई कृपा कंस्ट्रक्शन बड़ौदा द्वारा 2015 के उपरान्त प्रथम चरण में पांच कार्यों में से तीन कार्य अधूरे

(श्री हरीश चौधरी)

छोड़ दिये गये। द्वितीय चरण में दो कार्य आरम्भ ही नहीं किये गये। जिन्हें अनुबंध की धारा 2 एवं 3 की कार्यवाही के उपरांत माह दिसम्बर, 2017 से अप्रैल, 2018 के मध्य पूर्ण संवेदक की जोखिम एवं लागत पर संवेदक को आबंटित किये गये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, खाली यह प्रश्न है कि जो काम दिये हैं उनको कितनी अवधि में पूरा करना था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वर्क आर्डर कब दिया?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 36 माह की अवधि दी गयी थी। एक वर्क आर्डर 21.09.2013 को दिया गया था। सभी वर्क आर्डर 21.09.2013 को दिये गये और 36 माह की अवधि दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष: इनका प्रश्न था कि 36 माह की अवधि में जिस कांट्रैक्टर ने काम नहीं किया उनको नोटिस दिये या नहीं दिये।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सभी को नोटिस दिये गये। उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी। कार्यवाही क्या की गयी, जैसे साई कृपा के खिलाफ कार्यवाही करके 16 करोड़ की पैनल्टी लगायी गयी। उस 16 करोड़ में से 5.4 करोड़ की तो रिकवरी भी हो गयी। कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे भी लिया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। माननीय सदस्य, संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल सिंचाई प्रोजेक्ट से राजस्थान को मांग के अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा। राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, बोलने तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सहमति नहीं बनने के कारण चम्बल बेसिन के मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट भी अटक गया है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): राजस्थान सरकार मध्यप्रदेश के बीच....

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न, कालीचरण सराफ। आप बैठें, प्लीज बैठें। (व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात। प्लीज बैठिए। अलग तरह से लेकर आइये, प्लीज बैठिए। अगला प्रश्न, कालीचरण सराफ।

आर.टी.डी.सी. होटल्स को निजी कम्पनियों को देने की योजना

128. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के अधीन आने वाले गढ़, किले, आर.टी.डी.सी. की होटल्स और जी.ए.डी. के डाक बंगलों के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों व किन शर्तों पर विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के अधीन आने वाले किन-किन गढ़, क़िले, आर.टी.डी.सी. की होटल्स और जी.ए.डी. के डाक बंगलों को पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने का निर्णय कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) जी नहीं।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अनुसार विभाग के अधीन गढ़ एवं किलों का संचालन एवं रख-रखाव निजी कम्पनियों द्वारा कराये जाने का विचार नहीं है।

जी.ए.डी. के अनुसार डाक बंगलों का संचालन जी.ए.डी. द्वारा नहीं किया जाता है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने का सैद्धांतिक अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा, दिनांक...(व्यवधान) ध्यान से सुनें। 17.06.2015 के द्वारा किया गया। तदनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निगम के अध्यधीन इकाइयों को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान पर्यटन विभाग/राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा भूमि, सम्पत्तियों का व्ययन नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(पर्यटन मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, बिलकुल गलत और सदन को गुमराह करने वाला जवाब है।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि 29 अप्रैल, 2019 को मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सी.पी.पी. प्रोजेक्ट की समीक्षा की गयी थी और पुराने प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया था? क्या यह भी सही है कि इस मीटिंग के बाद मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों को निर्देश जारी किये थे कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले गढ़, किले, आर.टी.डी.सी. के होटल्स और जी.ए.डी. के डाक बंगलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कम्पनियों को दी जाए और इसके लिए सम्बन्धित विभागों को सचिवों को निर्देश जारी किये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कि इसके लिए प्राइवेटों निवेशकों की तलाश शुरू करें और आप यह कह रहे हो कि ...(व्यवधान) हमारा कोई विचार ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्रश्न, प्रश्न ...(व्यवधान) जवाब आने दें।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बड़ी एम्फैटिक्ली कहा था कि यह निर्णय लिया गया था, 17.06.2015 में, जब सरकार आपकी थी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, हां तो?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): नहीं, एक मिनट, आप मुझे सुन लें।

दूसरी बात यह है कि जब यह मीटिंग सी.एस. ने की तो आचार संहिता लगी हुई थी और जो मीटिंगें अफसर करें, निर्णय सरकार करती है। मीटिंगें करने से निर्णय नहीं हो जाता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब नहीं कर रहे हैं न आप?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये क्या तरीका है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आप फैसला नहीं करके, निजी कम्पनियों को नहीं देंगे? यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): देखिये, मैं तो एक और चीज पूछ रहा हूं। अभी मैंने आपको जवाब दिया, जो सरकार को जवाब देना है। मीटिंगें अभी किस स्तर पर हुईं, मंत्रिमण्डल के स्तर पर नहीं हुईं, न केबिनेट में हुई। दूसरी चीज यह है, अगर आप बुरा न मानें, तो मैं आपके इस सवाल के पूछने का मकसद जानना चाहता हूं। अपन, आप अलग बात कर लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्रश्नकाल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। अगला प्रश्न। छगन सिंह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बात तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री छगनसिंह (आहोर): प्रश्न संख्या 129

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, छगनसिंहजी। (व्यवधान) आप प्लीज, छगनसिंहजी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागरा (जालौर) का क्रमोन्नयन

129. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, बैठें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आहोर के अंतर्गत ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पहले वाला कवेश्चन ...(व्यवधान) स्थगित हो गया होगा।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, बैठें। (व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) अगला प्रश्न। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, राठौड़ साहब। बैठिये, प्लीज। आप बैठें। (व्यवधान) आप मुझे धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान) बैठिये, प्लीज। बैठिये, प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। प्लीज बैठें। आप पहले सुन लीजिये। आपने सुना नहीं क्या? उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई है, सरकारी अधिकारी लेवल पर। मंत्रिमण्डल लेवल पर कुछ नहीं हुआ। जवाब क्या देना इसमें। अगला प्रश्न। (व्यवधान) बात हो गयी। (व्यवधान) बैठिये प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, कटारियाजी, नहीं, मैंने अगला प्रश्न पूछ लिया है। कटारियाजी, मैंने अगला प्रश्न पूछ लिया। कटारियाजी मैंने अगला प्रश्न पूछ लिया, नहीं। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) अगला प्रश्न पुकार लिया मैंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माफ करें मुझे। प्लीज, मुझे क्षमा करें। अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप क्षमा करें। अगला प्रश्न पूछ लिया। नहीं बिलकुल नहीं। अब बिलकुल नहीं। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अगला प्रश्न।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आहोर के अंतर्गत पंचायत समिति आहोर का पूर्ण एवं पंचायत समिति जालौर का आंशिक क्षेत्र आता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पंचायत समिति जालौर (विधान सभा क्षेत्र आहोर का आंशिक क्षेत्र) में बागरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। (व्यवधान) पंचायत समिति जालौर का जो क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र आहोर के अंतर्गत आता है, की वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 90,921 है तथा जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सियाणा संचालित है। अत: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछना है? प्रश्न पूछना है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा। अगला प्रश्न श्री अमृतलाल मीणा। प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

उदयपुर जिले के छात्रावासों में बायोमैट्रिक मशीनों द्वारा उपस्थिति

130. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर) (श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) के स्थान पर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के छात्रावासों में बायोमैट्रिक मशीनों द्वारा उपस्थिति होती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर बायोमैट्रिक मशीनें सही हैं व कहां-कहां पर खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खराब मशीनों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सामाजिक न्याय मंत्रीजी। मंत्रीजी, जवाब दीजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बैठें। (व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं की बायोमैट्रिक द्वारा हाजिरी होती है। बायोमैट्रिक मशीन जहां पर सही है तथा जहां मशीन खराब है, का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। (व्यवधान)

(2) जी हां। विभाग द्वारा बायोमैट्रिक मशीन अगर खराब हो जाती है, तो उन्हें निर्धारित सम्बन्धित फर्म द्वारा शीघ्रातिशीघ्र ठीक करवाये जाने हेतु भिजवाई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। अमृतलाल मीणा। (व्यवधान) अगला प्रश्न, श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

बानसूर में प्रदूषण मुक्त उद्योगों की स्थापना

131. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अलवर जिले के नीमराणा, बहरोड़, खुशकखेड़ा एवं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हैं एवं इन्हीं से लगता हुआ बानसूर क्षेत्र है, क्या सरकार बानसूर में प्रदूषण मुक्त कोई बड़ा, मध्यम एवं लघु उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(2) क्या सरकार उक्त जिले में स्थापित कम्पनियों/उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) राज्य सरकार स्वयं बानसूर में प्रदूषण मुक्त कोई बड़ा, मध्यम एवं लघु उद्योग स्थापित करने का विचार नहीं रखती है बल्कि राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य (जिसमें बानसूर क्षेत्र स्वत: ही शामिल है) में उद्योग स्थापना हेतु प्रयत्नशील रहती है तथा निजी उदयमियों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। (व्यवधान)

(2) जी नहीं। नई इकाइयों द्वारा राजस्थान (जिसमें अलवर जिला स्वत: ही शामिल है) के मूल निवासियों को रोजगार देने पर वित्तीय प्रोत्साहन के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 में आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधन किए गए हैं, की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इस संशोधन के अनुसार नई इकाइयों को रोजगार सृजन अनुदान हेतु देय राशि की गणना में केवल उन्हीं कार्मिकों को ही सम्मिलित किया जाएगा जो राजस्थान के मूल निवासी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन, शोरगुल व नारे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि यह बानसूर क्षेत्र नहीं, बल्कि यह स्वत: ही सभी जगहों पर स्थापित किये जाएंगे। लेकिन निजी उद्योग लगाने के लिए अभी वर्तमान में सरकार की तरफ से कौन-कौनसी योजनाएं अब युवाओं के लिए बनाई गयी हैं? और कोई युवा अगर निजी उद्योग लगाएगा तो उसको सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी दी जाएगी? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी। मैंने इनको परिशिष्ट दे दिया, जिसमें सब्सिडी का प्रावधान है। राजस्थान के मूल निवासियों को, जो राजस्थान के हैं, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., बोनाफाइड जो राजस्थान के हैं, उनको 45,000 रुपये प्रति इकाई, प्रति कैंडिडेट, प्रति वर्ष, और बाहर के, उनको 30,000, जो दूसरी कैटेगिरी है शिड्यूल्ड एरिया में,

(श्री परसादी लाल)

उनको एस.सी., एस.टी. और महिलाओं को 40,000, और बाकी को 35,000 जो राजस्थान के बाहर के हैं। इसी तरह हमने प्रोविजन किया है कि राजस्थान के मूल निवासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन मिलें, इसलिये हमने सब्सिडी का प्रावधान ज्यादा किया है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सैकिण्ड जो पैरा है, उसमें दिया गया है कि मूल निवासियों को वहां पर जगह दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी युवा कम्पनियों में जाता है तो उन्हें इंटरव्यू ले करके यह कह दिया जाता है कि आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय युवाओं को वहां पर जगह नहीं दी जा रही है। इसके लिए क्या आप कम्पनियों को चैक करवाएंगे कि कितने प्रतिशत हमारे राजस्थान के या वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा सवाल पूछा, प्राइवेट कम्पनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। निजी उद्योग जो लगाएंगे, हम उनको सब्सिडी देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। उन्हीं के लिए आदेश जारी किया गया है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती इन्द्रा।

बौंली के संस्कृत महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

132. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के राजकीय संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय, बौंली को आचार्य में क्रमोन्नत करने हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा ज्ञापन दिये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त राजकीय संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय को जनहित में आचार्य महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां।

राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बौंली को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किये गये, किन्तु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(2) वर्तमान में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति में वर्णित प्रावधान को पूरा करने, क्षेत्र की मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही सम्भव है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, शास्त्री से आचार्य करने के लिए केवल दो प्रोफेसर की जरूरत है इसके अलावा ज्यादा विशेष वित्तीय प्रबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दो प्रोफेसर लगाकर आचार्य क्रमोन्नत किया जाए ताकि लोगों को आसानी से शिक्षा मिल सके। हर वर्ष 300 से ज्यादा बालिकाएं जयपुर आती हैं और कई सारी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वित्तीय प्रबंधों का बहाना बनाकर काम को नहीं टालें क्योंकि मेरे जितने भी सवाल लगे हैं उनमें केवल एक ही जवाब मिला है कि वित्तीय प्रबंधन नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि दो प्रोफेसर की व्यवस्था कर दी जाए ताकि क्षेत्र में लोगों को, मेरे युवाओं को, जो बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं उनको आसानी से पढ़ाई मिल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि थर्ड ईयर बौंली में छात्र संख्या 93 है और टोटल प्रति वर्ष का जो खर्चा विभाग ने निकाला है वह करीब-करीब 36 लाख रुपये का खर्चा आता है। लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए सरकार निश्चित रूप से जैसे ही इस तरह की प्राब्लम साल्व, संसाधन उपलब्ध होंगे, आपके विचार को स्वीकार किया जाएगा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई खर्चा आता है या कोई बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, हाल की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने विधायक कोटे से उपलब्ध करवा दूंगी लेकिन मुझे दो प्रोफेसर चाहिए और क्रमोन्नत चाहिए। धन्यवाद।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मैं यह बताना चाहूंगा कि केवल बिल्डिंग के खर्चे की बात नहीं है जो रेकरिंग एक्स्पैंसेज आते हैं, उन खर्चों की बात है, जो कि एम.एल.ए. फंड से अलाउ नहीं होते हैं तो यह 36-37 लाख की बात है, लेकिन फिर भी अभी इस पर विचार करेंगे। जिस तरह की भी, राज्य स्तर पर नीति का निर्माण करके फिर बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): थैंक यू, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाएं। माननीय कटारियाजी। अपने स्थान पर जाएं। अपने स्थान पर जाएं।

अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

प्रश्न संख्या 133

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

प्रश्न संख्या 134

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

प्रश्न संख्या 135

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनिया।

प्रश्न संख्या 136

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

प्रश्न संख्या 137

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

आप बैठें, मैं बोल रहा हूं। आप एक मिनट विराजें। एक मिनट आप विराजें। आप बैठें। आप विराजें। मैं यहां पर नहीं बोलूंगा। यहां पर नहीं, आप हल्ला कर रहे हैं। आप अपनी जगह पर जाइए, यहां पर मैं नहीं बोलूंगा।

अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा।

धौलपुर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

138. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला धौलपुर में किस-किस चिकित्सालय में चिकित्सकों के कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विभिन्न रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में कुछ अधिकारी-कर्मचारी अपने पदस्थापित स्थान के बजाय प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थान पर पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जिला धौलपुर मे चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला धौलपुर में पदोन्नति/विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी/पीजी पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया तथा चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरने का प्रयास किया जाएगा।

(3) जी नहीं।

जिला धौलपुर में कोई भी चिकित्सक/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य व्यवस्था हेतु प्रशासनिक कारणों से अन्यत्र पदस्थापित किया हुआ है। विवरण परिशिष्टब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप पहले अपनी जगह पर बैठें, अपनी जगह पर जाएं। अपनी जगह पर जाएं। मैं उसके बाद बोलूंगा, पहले आप अपनी जगह पर जाएं, यहां पर अलाउ नहीं करूंगा। आप अपनी जगह पर जाएं। यहां पर नहीं, अपनी जगह पर जाकर बोलें। मैं कटारियाजी की बात सुनूंगा, आप अपनी जगह पर जाएं। जगह पर जाएं। जगह पर जाएं। आप अपनी जगह पर जाएं। सुनना चाहते हैं तो आप अपनी जगह पर जाएं। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सी.एच.सीज. आती हैं, मनिया और राजाखेड़ा में, इनमें डाक्टर्स की 2012 से लेकर 2017 तक काफी वेकेंसीज हैं। यहां के लोगों को चिकित्सक नहीं होने की वजह से धौलपुर भागना पड़ता है। तो मेरी इतनी-सी विनती मंत्री महोदय से है कि जल्दी से जल्दी सी.एच.सीज. मनिया और राजाखेड़ा के खाली पद भर दिए जाएं जिससे कि धौलपुर नहीं जाना पड़े और कुछ डाक्टर्स मनिया सी.एच.सीज. से सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में पदस्थापित हैं, उन लोगों को वापस मनिया भेज दिया जाए, जिससे कि वहां पर सुचारु रूप से काम कर चल सके।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी जगह पर बैठें। आप अपनी जगह पर बैठें, मैं बात सुनूंगा। आप अपनी बात जगह पर जाकर बोलें। आप जगह पर जाकर अपनी बात कहें। आपकी बात सुनूंगा, जगह पर जाएं। जगह पर जाकर बात कहें। मैं यहां पर नहीं सुनूंगा। नहीं सुनना चाहें तो बात अलग है। आप अपना प्रश्न पूछिए। रघुजी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी रिक्त पद हैं वे अतिशीघ्र भरे जाएंगे, कोई चिकित्सक के पद या पैरामेडिकल स्टाफ के पद वहां पर खाली नहीं रहेंगे।

अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

प्रश्न संख्या 139

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

प्रश्न संख्या 140

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री मोहन राम चौधरी।

प्रश्न संख्या 141

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री राकेश पारीक।

राजकीय महाविद्यालय, मसूदा (अजमेर) के विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन

142. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय मसूदा (अजमेर) में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र मसूदा से 31 कि.मी. दूर श्री प्रज्ञा महाविद्यालय विजयनगर है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्यार्थियों की अत्यधिक दूरी को मद्देनजर रखते हुए राजकीय महाविद्यालय मसूदा (अजमेर) में परीक्षा केन्द्र रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मसूदा की पंचायत समिति मुख्यालय भिनाय में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ.11/परीक्षा/केन्द्र/पीजी/एमडीएसयू/2015/76917 दिनांक 09.10.2014 के बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र घोषित करने के लिए महाविद्यालय को मान्यता के बाद 3 वर्ष पूर्ण करना आवश्यक है। राजकीय महाविद्यालय, मसूदा की स्थापना 2018-19 में हुई है। अतः यह महाविद्यालय अन्य मानदण्ड पूर्ण करने पर 2021-22 में परीक्षा केन्द्र के लिए पात्र होगा। इस कारण महाविद्यालय के विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र श्री प्रज्ञा महाविद्यालय, विजयनगर दिया गया है।

(2) परीक्षा केन्द्र की पात्रता के सभी मानदण्ड हासिल करने पर परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन कर दिया जाएगा।

(3) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर मसूदा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय भिनाय में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखण्ड कार्यालय पर बजट में भी घोषणा हुई है। मेरे मसूदा के चारों तरफ गरीब छात्र रहते हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसी

(श्री राकेश पारीक)

सत्र में मेरे यहां पर भिनाय उपखण्ड में एक महाविद्यालय खोला जाए, यह मेरी मांग है, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मंत्रीजी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय पर, भिनाय में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के लिए माननीय सदस्य द्वारा जो बात कही गयी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा आगामी समय में विधान सभा स्तर पर और उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है और नवीन महाविद्यालय खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर पूरा विचार करके आगामी समय में निर्णय लिया जाएगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 143

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 144

अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 145

अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री गोविंद राम।

खाजूवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

146. श्री गोविंद राम (खाजूवाला): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कितने पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता है? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.सी. खोलने का

(श्री गोविन्द राम)

विचार रखती है? खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ में पी.एच.सी. व सी.एच.सी. में कितने-कितने डाक्टर, कम्पाउण्डर, ए.एन.एम., जी.एन.एम. व लैब टैक्नीशियन के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बहुत से गांवों में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं। क्या सरकार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर खाजूवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला, छतरगढ़ एवं पूगल में चिकित्सकों, नर्स श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	**रिक्त पदों की संख्या**		
	सीएचसी, खाजूवाला	**सीएचसी, छतरगढ**	**सीएचसी, पूगल**
कनिष्ठ विशेषज्ञ	-	1	1
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
चिकित्सा अधिकारी	1	1	1
नर्स श्रेणी-प्रथम	2	1	1
नर्स श्रेणी-द्वितीय	6	5	3
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	2
लैब टैक्नीशियन	-	1	-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया से यथासंभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

अराजपत्रित संवर्ग में पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

विभाग में नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता/आवश्यकता के साथ भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री गोविंद रामजी।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारी सी.एच.सी. है, उसमें जो स्पेशलिस्ट के पद हैं, गायनोकोलोजिस्ट, आर्थोपेडिक्स, सर्जन, ये पद काफी वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें गायनोकोलोजिस्ट की अति-आवश्यकता है और यह नर्स के पद खाली पड़े हैं, टैक्नीशियन के पद खाली पड़े हैं, इन्हें भरवाएं। हालांकि इनके आने के बाद दो कनिष्ठ डाक्टर लगे हैं, फिर भी स्पेशलिस्ट एक भी नहीं है। गायनोकोलोजिस्ट नहीं है, इसलिए कब तक यह पद भरने की मंशा रखते हैं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो चिकित्सकों के रिक्त पद हैं, वह उपलब्धता के आधार पर हम शीघ्र उनको

(श्री रघु शर्मा)

भरने की कोशिश करेंगे और जो पैरा-मेडिकल के हैं व नान-गजेटेड जो पोस्ट हैं, उनको भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है और जल्दी ही उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जब वह पद भरे जाएंगे तो इनके यहां भी खाली पड़े पदों को हम भर देंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। माननीय सदस्य, बैठें। अभी मैं बात नहीं सुन रहा।

अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

प्रश्न संख्या 147

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माननीय सदस्य, आप सुनना चाहें तो बैठें। आप सुनना चाहें तो बैठें, नहीं तो बात ठीक है।

प्रश्न संख्या 148

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 149

अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 150

अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 151

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

हाउस 12.00 बजे तक एडजोर्न किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.34 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

विश्वेन्द्र सिंह, श्री, पर्यटन मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात सुनना चाहें तो हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि माननीय मंत्री महोदय का क्या इन्टेन्शन था कि आप किस मंशा से पूछ रहे हो, इसका मतलब हम इस हाउस में कोई लेन-देन करके प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछने के पीछे हमारा कोई इन्टेन्शन खराब है? इतना बड़ा आरोप, जिस आरोप से सारे राजस्थान ने जिसने भी यह सुना होगा, ये सारे विधायक प्रश्नों में कोई न कोई रूचि होती है, उसी प्रश्न को पूछते हैं, तो हमारी छवि खराब करने का काम आप कर रहे हैं न?

अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से आपसे यह चाहता हूं, आप इस बात को ठीक समझते हो कि उन्होंने जिस भाव से पूछा, किस भाव से पूछा कि हम क्या इन्टेन्शन से प्रश्न पूछते हैं और अगर इसमें हमारा इन्टेन्शन खराब है तो स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई एक आदमी गलत करता है, लोक सभा में आठ एम.पी. सस्पैंड हुए हैं क्वेश्चनों के बारे में। जब उनके इन्टेन्शन की जांच हुई और पता लगा कि उन्होंने गलत काम किया, तो वे बी.जे.पी. के हो, चाहे कांग्रेस के हो, जिसने भी प्रश्न गलत तरीके से पूछा। लेकिन आपने तो सारे के सारे लोगों पर एक ऐसा आरोप लगा दिया कि हम प्रश्न किसी न किसी इन्टेन्शन से पूछते हैं। तो, अध्यक्ष जी, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं जब तक हमारा इन्टेन्शन स्पष्ट नहीं होगा, हम यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय नेता ने बोला, अब मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय विपक्ष के नेता, आपने जो बात कही है उसकी गम्भीरता को सभी समझते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी की मंशा यह नहीं है। मंत्री मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था मैंने प्रश्न यह पूछा था कि क्या आप इस तरह का बेचने का फैसला करना चाहते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मंत्रिमण्डल स्तर पर

(श्री अध्यक्ष)

कोई चर्चा नहीं हुई, यह कोई सी.एस. लेवल पर मीटिंग हुई है, आचार संहिता के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि उनका इन्टेंट भी कोई मोटिव लगाने का नहीं है। इसलिए आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है, मेरे से चैम्बर में मिले थे और उन्होंने यह बात कही थी। (व्यवधान) ना, ना। नहीं, आप अपनी बात कहें, या तो आप बात कहें या मुझे कहने दें। या मैं बैठ जाता हूं, आप अपनी बात कहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो बात आप कह रहे हो, मंत्री महोदय अपने श्रीमुख से बता दें कि उनका पूछने का इन्टेन्शन क्या था?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): मैं जवाब दूं इसका?

श्री अध्यक्ष: आप उचित समझते हैं क्या?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): मैं दे दूं। आप हमारे बुजुर्ग हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसे नहीं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और सभी, यहां जितने भी सम्माननीय विधायकगण विराजमान हैं जमीन पर। मेरा इन्टेन्शन बिलकुल क्लीयर था, आपका इन्टेन्शन क्लीयर नहीं था। आपने यह आरोप पहले मेरे ऊपर लगाया कि मैंने सदन को गुमराह किया है, पहले उसका जवाब दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

माननीय कटारिया साहब, मैंने उनकी पूरी बात को सुना है, समझा है और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, उनका इन्टेंट नहीं है और किसी भी मंत्री का इन्टेंट यह नहीं होता है कि कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछे तो उसके लिए मोटिव लगाएं। मैं समझता हूं कि उनका इन्टेंट यह नहीं था। माननीय कालीचरण सराफ साहब ने जो प्रश्न पूछा उसकी आप लैंग्वेज पढ़ लें, मेरे चैम्बर में आ जाएं, आप देख लें, पढ़ लें, आपको लगता है कि उन्होंने इस पृष्ठभूमि में, तो मैं आपसे चर्चा करूंगा।

मैं मंत्री जी से मिला हूं, मेरे से बात हुई है और मैं फिर आपको

(श्री अध्यक्ष)

आश्वस्त करना चाहता हूं, न मंत्री जी का यह इन्टेंट था, न सरकार का कोई मंत्री इस तरह का इन्टेंट रखने का इरादा रखता है। प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रश्न पूछा जाना चाहिए और प्रश्न पूछने में किसी का इन्टेंट नहीं है। यह उनकी इच्छा नहीं थी और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसी स्पिरिट में लेकर आप सभी माननीय सदस्यों को कहें, अपने स्थान पर रहें।

एक बात समझें। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। एक बार आप इस प्रश्न के संदर्भ में जो पूरी चीजें रिकार्ड हैं, उनको देख लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगा। हम एक लिबर्टी नहीं ले सकते हैं। हम मंत्री पर तो आरोप लगाएं कि वह गुमराह कर रहा है, मंत्री कहे तो समझ में नहीं आए, दो तरह का नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चैम्बर में आ जाएं आप प्रोसीडिंग देख लें और प्रोसीडिंग देखने के बाद आपको लगे कि नहीं, उनका इन्टेंट इस तरह का था तब तो मैं समझता हूं ...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण)

ऐसे अलाउ नहीं है, इस तरह से अलाउ नहीं है। इस तरह से अलाउ नहीं हैं। करिये फिर आप, बैठे-बैठे बोलते रहिये। आप बैठे-बैठे बोलते रहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप जो बात कह रहे हो उससे तो हम लोग भी और राजस्थान के लोग भी इस बात में हैं, लेकिन मंत्री इस बात को क्यों नहीं कह सकते कि उनका इस सवाल पूछने के पीछे कि, आपका इन्टेन्शन क्या है, आपने किस भाव से इन शब्दों का प्रयोग किया, वह स्पष्ट कर दें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम बस इतनी बात चाह रहे हैं, आपने किस इन्टेन्शन से कहा कि आप किस इन्टेन्शन से पूछ रहे हो? हमारा इन्टेन्शन अगर आपको पता हो तो बता दो। अगर हमारा कोई इन्टेन्शन खराब हो तो बता दो, हमारा इन्टेन्शन खराब नहीं है तो आपका क्या अभिप्राय: था, वह स्पष्ट कर दो।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा, फिर अपील करना चाहता हूं यह कन्फ्यूजन है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण)

नहीं है, तो आप बैठो, फिर आप बैठे रहें। मैं बैठे-बैठे नहीं सुनना चाहता, मेरी आदत नहीं है, आप बैठे-बैठे बोलते रहिये, धन्यवाद। नहीं सुनना

(श्री अध्यक्ष)

चाहते तो धन्यवाद। (व्यवधान) कटारिया जी, यह बैठे-बैठे बोलना चाहते हैं। यह भी आप कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन मैं मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा कि उन्होंने इन्टेन्शन शब्द का प्रयोग क्यों किया?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों किया हमारे लिए इन्टेन्शन शब्द का प्रयोग?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप मेरी तरफ देखें, मैं खुद चेयर पर खड़ा हूं। मैं खुद चेयर पर खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं मान्यवर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपको हमारे खिलाफ कार्यवाही करनी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं, आप सीनियर लीडर हैं। आप सीनियर लीडर हैं, कम से कम बैठो तो सही, मैं खड़ा हुआ हूं। इसको तो मानेंगे आप।

कटारिया जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका पूरा सम्मान है लेकिन माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोलें, यह भी ठीक नहीं है। यह परम्परा भी ठीक नहीं है। आपने जो कहा है मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं और मैं मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, मंत्री जी, आपका इन्टेंट नहीं है तो खड़े होकर कह दो, मेरा इन्टेंट नहीं है, बात खतम होती है। आप खड़े होकर कह दो, मेरा इन्टेंट नहीं है, बात खतम होती है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण)

प्लीज, बैठिये, मैं अलाउ नहीं करूंगा। किरण जी, आप सीनियर लीडर हैं, बैठे-बैठे गलत परम्परा डाल रहे हैं। मंत्री जी की बात सुन रहा हूं, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। (व्यवधान) वैल में बैठे हो तो अधिकार है आपको वैल में बैठने के बाद नियम तोड़ने का?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष से और प्रतिपक्ष से, सभी सदस्यों और सदस्याओं से कि इसमें मेरा कोई गलत इन्टेन्शन नहीं था। लेकिन एक बात भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा ...(व्यवधान) नहीं,

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

एक मिनट, आप मेरी पूरी बात सुन लें। आप लोगों ने भी मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि मैंने सदन को गुमराह किया, इसका मुझे दु:ख है। इतना जरूर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद आपसे निवेदन है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, कटारिया जी, आप सदस्यों से कहें अपने स्थान पर बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बात तो स्पष्ट हुई न, क्या है। अब क्लीयर हो गया न, और क्या! अब आ जाओ।

श्री अध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहौर में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से लगातार पर्यावरण प्रदूषण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अनिता भदेल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से अलवर जिले के राठ क्षेत्र में पशुधन एवं वाहन चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से सरदारशहर, चूरू में एक दलित युवक की पुलिस अभिरक्षा में निर्ममतापूर्वक हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से चूरू जिले में पुलिस अभिरक्षा में मौतें एवं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा किसानों के बचत खाते में जमा न कर ऋण खाते में जमा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में डी.टी.ओ. कार्यालय न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले को अत्यधिक फार्म पौण्ड स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से शहरी क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 15 हजार लीटर पानी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का वाटर चार्ज लेने सम्बन्धी घोषणा की विभाग द्वारा पालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से निजी बसों का टैक्स बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा, श्री जोराराम कुमावत, श्री रामलाल शर्मा, श्री कालीचरण सराफ एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गिरधारी लाल, सदस्य की ओर से बाड़मेर ग्रिल पावर प्लांट को बंद किए जाने से हो रही परेशानियों के संबंध में।

(2) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय मुण्डावर स्थित राजकीय महाविद्यालय के नवीन भवन हेतु भूमि आबंटित किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से तिजारा व भिवाड़ी में बंद पड़े सीवरेज कार्यों से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजकीय विद्यालयों में नि:शुल्क साइकिलों से वंचित छात्राओं को साइकिल दिलवाए जाने के संबंध में।

(5) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विजयनगर में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई किए जाने के संबंध में।

(6) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से न्यू मेडिकल कालेज, कोटा में 150 करोड़ की लागत से तैयार सुपर स्पेशयलिटी विंग में स्टाफ की कमी से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से प्रदेश के कतिपय जिलों में निवास करने वाले सिंधी मुसलमानों को ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र बनवाने में हो रही परेशानी के संबंध में।

(9) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर में दिन-दहाड़े नई नवेली दुल्हन का अपहरण कये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से पुष्कर तीर्थ विकास मंडल, 1972 का पुनर्गठन कर पुष्कर को टैम्पल टाउन घोषित किये जाने के संबंध में।

(11) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग के पिपलिया चौराहे से रूणजी के बीच कोटा स्टोन की खानों से हो रहे अवैध खनन के संबंध में।

(12) श्री छगन सिंह, सदस्य की ओर से आहौर स्थित सामुदायिक अस्पताल में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से मरीजों को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 15 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
1.	श्री अविनाश	जैतारण राजकीय महाविद्यालय में रोडवेज बसों को ठहराव के संबंध में
2.	श्री राजकुमार रोत	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे राज्य में मनाए जाने के संबंध में।
3.	श्री रामलाल मीणा	विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाए जाने एवं आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में
4.	श्री अमृत लाल मीणा	सड़क स्टेट हाई वे-32, उदयपुर से सलूम्बर, बांसवाड़ा, भोपाल तक जाने वाली सड़क स्वीकृत किये जाने हेतु वन विभाग से 10 किलोमीटर की एनओसी दिलाए जाने के संबंध में

माननीय सदस्य, आज सुबह मुझे नेता, प्रतिपक्ष, उप नेता, प्रतिपक्ष और कतिपय सदस्य मिले, जिन्होंने ध्यानाकर्षित किया कि आज की घटना जो पुलिस की है जयपुर में और जो चूरू की घटना है, सरकार से स्टेटमेंट देने का उन्होंने निर्णय लिया है। समय मैं आपको सूचित कर दूंगा। जब स्टेटमेंट हो जाएगा, तब इस पर चर्चा कर लेंगे।

माननीय सदस्य, श्री संयम लोढ़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सिरोही में प्रधान मंत्री फसल बीमा राशि का किसानों के ऋण खाते में समायोजन

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल, तत्कालीन

(श्री संयम लोढा)

सरकार ने किसानों के कर्जे माफ करने का निर्णय किया। उसके लिए 2017 की एक तारीख सरकार ने तय की कि इस तिथि तक के जितने भी किसानों के कर्जे हैं, वह माफ कर दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में 2017 की खरीफ की फसल में खराबा हुआ। 508 में से 408 गांव में फसल, जो सरकार के निर्धारित मापदंड हैं, उसके तहत पूरी तरह से खराब हो गयी। 50 फीसदी से 75 फीसदी और 75 फीसदी से 100 फीसदी, दोनों के क्राइटेरिया में करीब साढ़े 3 लाख किसानों की फसल का खराबा हुआ। प्रधान मंत्री फसल बीमा में जिन-जिन किसानों की फसल का बीमा हो रखा था, उसके तहत सिरोही जिले को 50 करोड़ 88 लाख 76 हजार 677 रुपये प्राप्त हुए। लेकिन राजस्थान सरकार के सिरोही केन्द्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन एम.डी. ने एक आदेश निकाल दिया कि प्रधान मंत्री फसल बीमा का जो पैसा सिरोही जिले के किसानों के लिए प्राप्त हुआ है, उसे किसानों के ऋण खातों में जमा कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने तिथि तय की 30 सितम्बर, 2017 की, उस अवधि पर जो कर्जा है किसानों का, वह माफ होगा। 2018 में जो पैसा प्राप्त हुआ बैंक को प्रधान मंत्री फसल बीमा में, वह पैसा तत्कालीन एम.डी. ने आर्डर करके किसानों के ऋण खाते में जमा करा दिया। ऋण खाते में जमा करा दिया तो किसानों के ऋण की राशि घट गयी। पूरे राजस्थान के किसानों का जो कर्जा माफ हुआ 2017 की अवधि का, सिरोही जिले के किसानों को उस पैसे का लाभ नहीं मिला और उनकी ऋण राशि 51 करोड़ रुपये घट गयी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो राज्य सरकार की मंशा के विपरीत, किसानों के हित के खिलाफ, किसानों का गला घोटने का तत्कालीन एम.डी. ने जो काम किया, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा, सिरोही जिले के किसानों का ऋण का पैसा सेविंग अकाउंट में डालने की बजाय लोन अकाउंट में डालने से जो पैसा कम माफ हुआ और उनको नकदी में भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ, वह पैसा आप किस तरीके से किसानों को लौटाएंगे? यह दो बातें मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बोलना है मंत्री जी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो सरकार के ध्यान में लाया गया है इस प्रकार का मामला, तो निसंदेह इसकी पूर्ण जांच कराकर, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे तथ्य तो रख दिये। अब जांच क्या करवा लेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जोराराम कुमावत। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: जोराराम कुमावत। नहीं, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। यह परिपाटी नहीं है। आप बैठें। स्थगन प्रस्ताव में मैं अलाउ नहीं करुंगा। अब मैं अलाउ नहीं करुंगा। श्री जोराराम कुमावत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आपकी बात सरकार के नोटिस में आ गयी है। बैठें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अंकित नहीं होगा। जोराराम कुमावत। बोलिए, जोराराम जी कुमावत। बोलना है आपको?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: संयम जी, प्लीज। I will not allow. प्लीज, आप बैठें। अंकित नहीं होगा। श्री जोराराम कुमावत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। जोराराम जी कुमावत। don't disturb. सीनियर लीडर हैं आप, प्लीज। आप बैठें। माननीय सदस्य, आप गलत परम्परा नहीं डालें। आप सीनियर सदस्य होते हुए गलत परम्परा डालेंगे, स्थगन प्रस्ताव में नहीं मिलता प्रश्न का उत्तर। माननीय सदस्य, जोराराम जी कुमावत।

सुमेरपुर में डी टी ओ कार्यालय की स्थापना

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि सुमेरपुर पश्चिमी राजस्थान का, पाली, जालौर, सिरोही का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। वह सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है। यहां पर ट्रांसपोर्ट यूनियन, कार, ट्रैक्टर के शो-रूम, सभी दुपहिया वाहनों के शो-रूम और एजेंसी भी हैं। पाली जिले में पाली शहर के बाद सबसे ज्यादा वाहन सुमेरपुर में खरीदे-बेचे जाते हैं। यहां राजकीय महाविद्यालय सहित 10 कालेज, कोचिंग सेंटर, कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र व 30 से ज्यादा सरकारी व निजी विद्यालय, इंस्टीट्यूट्स, छात्रावास व 25 से ज्यादा अस्पताल और सबसे बड़ा भगवान महावीर हास्पिटल भी है।

वर्तमान में सुमेरपुर में व्यावसायिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में वाहनों का ज्यादा चलन हो गया है। परिवहन के साधनों की संख्या ज्यादा रहने से वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए डीटीओ आफिस नहीं होने से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि सुमेरपुर में डीटीओ आफिस खुलता है तो पाली से भी ज्यादा राजस्व सुमरेपुर में परिवहन विभाग को होगा।

नगरपालिका सुमेरपुर डीटीओ आफिस हेतु नि:शुल्क जमीन आबंटन के लिए तैयार है। नगरपालिका सुमेरपुर ने भूमि आबंटन का प्रस्ताव बनाकर नगर नियोजक को पत्र क्रमांक 577 दिनांक 18.04.2016 के माध्यम से पूर्व में ही भेज दिया है। वर्तमान में भी नगरपालिका बड़ी बिल्डिंग डीटीओ आफिस संचालन के लिए देने को तैयार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार डीटीओ आफिस खोलने की मंशा रखती है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर में डीटीओ कार्यालय खोलने की मांग माननीय सदस्य ने की है। सुमेरपुर में और पूरे राजस्थान में जितनी भी हमारी तहसीलें हैं, जहां-जहां से भी डीटीओ कार्यालय खोलने की डिमांड आ रही है, अभी तक राज्य सरकारें पिछली रही हों, वर्तमान रही हो, कोई पॉलिसी बनी हुई नहीं है, अब हम पॉलिसी भी बनाने जा रहे हैं।

इस वक्त सुमेरपुर में 43806 वाहन पंजीकृत हैं। राज्य सरकार की

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पॉलिसी में अभी तक यह तय किया गया है कि डीटीओ कार्यालय वहां खोले जाएंगे, जहां 1 लाख वाहन हैं। लेकिन लाइसेंस को लेकर और अन्य कामों को लेकर, सब जगह राजस्थान में जो परेशानियां आ रही हैं, उसको देखते हुए हमने सब जगह एक अभियान चला रखा है। उसकी एक नई पालिसी बनाने जा रहे हैं। उसी पॉलिसी के तहत अभी भीनमाल में शनिवार को ही मैं डीटीओ कार्यालय का उद्घाटन करके आया हूं। वहां पर लाइसेंस का काम चालू किया है।

सुमेरपुर की भी हम पूरी जांच करवा रहे हैं। माननीय सदस्य की भी भावनाएं हम समझ रहे हैं। पूरे राजस्थान में जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे दे सकें, और लोगों को लाइसेंस बनवाने में, टैक्स जमा करवाने में, वाहनों का पंजीकरण कराने में ज्यादा सुविधा मिल सके, इसके लिए हम जल्दी ही पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। पालिसी भी ऐसी बना रहे हैं जिससे लाइसेंस प्रक्रिया सरल हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कार्यालय हम खोल सकें, ऐसी हम नीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी वह नीति बन जाएगी, माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए, इनके यहां भी जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर में किसानों को फार्म पोण्ड की स्वीकृति

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में आज से 30 साल पहले सिंचाई की व्यवस्था थी कि कुएं के माध्यम से किसान अपनी खेती का काम किया करते थे। 30 सालों में पानी की जैसे-जैसे कमी आई वैसे-वैसे ट्यूबवैलों का सहारा लेने लग गये। उसी के दौरान पहले धोरों के माध्यम से सिंचाई होती थी, फिर पानी थोड़ा कम हुआ तो हौद के माध्यम से सिंचाई होने लगी, फिर पानी कम हुआ तो किसान फव्वारे पर आ गये, फिर पानी कम हुआ, किसान ड्रिप इर्रिगेशन पर आ गये लेकिन बहुत कम एरिया ऐसा बचा है जहां पानी है। बरसात का पानी ही एकमात्र विकल्प किसानों के पास है कि उसके माध्यम से वह खेती करें। आज जयपुर जिले के अंदर अधिकांश किसान बरसात के पानी को इकट्ठा करके फिर खेती करने की पद्धति पर चल रहे हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के अंदर आज जो किसान पोण्ड के आधार पर आवेदन करते हैं उनमें बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें पोण्ड के आवेदन किए हुए एक-एक, दो-दो, तीन-तीन साल हो गये हैं लेकिन अभी तक भी उनके आवेदन स्वीकार नहीं किये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि जयपुर जिले में जितने भी पोण्ड के फार्म पैंडिंग पड़ें हैं उनको आप अधिक से अधिक स्वीकृत कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक और निवेदन है कि गंगानगर और बीकानेर में डिग्गी के माध्यम से जो अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है वह बहुत अधिक होती है, पोण्ड की राशि जो स्वीकृत की जाती है वह बहुत कम है। इसके अंदर कच्ची मिट्टी का काम होता है उसमें एक रुपये का अनुदान भी सरकार के द्वारा किसान को नहीं दिया जाता, सिर्फ पक्का निर्माण जो पोण्ड में किया जाता है उसी का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। माननीय मंत्रीजी, आप भी किसान के बेटे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए किसानों के जितने भी आवेदन हैं उन आवेदनों का तत्काल निस्तारण करवाएंगे। जो भी किसान इस पद्धति पर आना चाहते हैं उनके अधिक से अधिक पोण्ड स्वीकृत करने का आप काम करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): जयपुर जिले में दिनांक 9.7.2019 तक 1254 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, उसमें से 776 कृषकों को आवेदन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी तथा 451 फार्म पोण्ड हैं वह किसानों द्वारा, खुद ने तैयार किये हैं। जैसे ही आनलाइन डिमांड आती है उसके आधार पर सर्वे करके सभी को करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी यदि आपके कोई ध्यान में हो तो आप पधारें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय मंत्रीजी, सारे के सारे ही आवेदन अटक रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न न करें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): इनकी जानकारी लेकर मैं आपका बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

शहरी क्षेत्र में मुख्य मंत्री की घोषणा के विपरीत वाटर चार्ज की वसूली

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, 8 मार्च, 2019 को लोक सभा चुनाव से पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि शहरी क्षेत्रों में 15 हजार लीटर पानी का उपयोग यदि कोई करेगा तो उसको सीवरेज और शहरी विकास शुल्क की छूट दी जाएगी और वाटर चार्ज भी उसके लिए नहीं लगेगा। केवल 55 रुपये मीटर चार्ज और 27 रुपये 50 पैसे फिक्स चार्ज लगेगा। यानी हर महीने कुल 39 रुपये 50 पैसे का बिल आएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन लोक सभा चुनाव होते ही 18 जून, 2019 को जलदाय विभाग ने सर्कुलर जारी किया कि यह छूट केवल चालू मीटर कनेक्शनों पर ही मिलेगी। यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि मीटर बदलने की जिम्मेदारी तो जलदाय विभाग की ही है। विभाग ने मीटर तो बदले नहीं और मुख्य मंत्रीजी के आदेश को ही बदल दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में 4 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं और उसमें से लगभग 2 लाख 61 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं के मीटर बंद हैं। इनको यह छूट नहीं मिलेगी। जलदाय विभाग अभी तक भी बंद मीटर वालों को मनमाने बिल भेज रहा है, यदि किसी का पिछले साल प्रति माह का 25 रुपये बिल था, तो उसको 200 रुपये प्रति माह का बिल भेजा जा रहा है। पिछली बार चूंकि बीसलपुर में पानी नहीं आया 30 परसेंट की आपने कटौती की तो 30 परसेंट पानी कम आ रहा है, तो भी आपको बिल 200 रुपये का ही भेज रहे हैं। इंजीनियर्स को पूछते हैं कि मीटर कब चेंज करेंगे तो वह कहते हैं कि नये मीटर आएंगे तब चेंज करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह पूछना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा की क्या मंशा थी? मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा किस मंशा से की थी और उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8.3.2019 में शहरी क्षेत्रों के 15 एमएम के घरेलू कनेक्शनों के चालू मीटर वाले उपभोक्ताओं का जल उपभोग 15 हजार लीटर प्रति माह तक होने पर जल शुल्क नहीं लिए जाने का

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सीवरेज शुल्क भी नहीं लिए जाने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार ही 15 हजार लीटर तक मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से जल शुल्क एवं सीवरेज शुल्क नहीं लिया जा रहा है। 15 हजार लीटर तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से स्थायी शुल्क 27 रुपये 50 पैसे प्रति माह एवं मीटर सर्विस शुल्क 22 रुपये प्रति माह ही लिया जा रहा है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केवल चालू मीटर वाले उपभोक्ताओं को ही यह लाभ देय है। मीटर यदि बंद होगा तो कैसे पता चलेगा कि उसने 15 हजार तक ही उपयोग किया है। बंद, खराब मीटर वाले जल सम्बन्ध की जल उपभोग की न्यूनतम राशि रुपये 57 प्रति माह या औसत उपभोग के आधार पर बिल जारी किया जाता है। औसत उपभोग की गणना हेतु मीटर खराब/बंद होने से पहले माह का उपभोग अथवा विगत तीन माह का औसत उपभोग अथवा गत वर्ष उसी माह का उपभोग में से जो भी अधिकतम उपभोग होता है, इसके आधार पर बिल जारी किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि यदि उपभोक्ता का उपयोगिता अनुसार औसत मासिक उपभोग 15 हजार लीटर तक का रहता है तो उसे न्यूनतम राशि का बिल ही जारी किया जाता है।

अमृत योजना में 70 हजार मीटर बदलने का प्रावधान किया गया। अमृत योजना का कार्यादेश 18.2.2018 को जारी किया गया, अब तक 35 हजार मीटर बदले जा चुके हैं और शेष बदलने का कार्य नवम्बर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

श्री अध्यक्ष: नवम्बर, 2019 तक सबके मीटर लग जाएंगे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 70 हजार?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 70 हजार में से 35 हजार लगा दिए, बाकी 35 हजार का लक्ष्य नवम्बर, 2019 तक है। आगे जैसे-जैसे मीटर उपलब्ध होंगे, वैसे-वैसे बदले जाएंगे। (व्यवधान) यह मैंने स्पष्ट कर दिया। माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे बिल दिए जा रहे हैं, उसी माह का पुराना बिल है उसी आधार पर बिल दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जिनके मीटर लगा हुआ है उनके तो 15 हजार रुपये का लाभ मिल रहा है। जिनके मीटर नहीं लगा हुआ है उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या उन्होंने बताई है 2 लाख और समथिंग।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 2 लाख 61 हजार।

श्री अध्यक्ष: तो 2 लाख और जो भी, कंजूमर हैं, जिनके मीटर नहीं हैं उनको 15 हजार लीटर की छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। यह मीटर लगाने की प्रक्रिया कब कमप्लीट हो जाएगी ताकि उनको लाभ मिल सके, यह मोटा प्रश्न है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि जिनके मीटर खराब हैं, उनको बिल पुराने महीने के बिल का जल उपभोग किया हुआ है उसी के अनुसार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही, वैसे ही बिल दे दिया। हम लोग जैसे मान लीजिए पुराने जून के महीने में उसका बिल 150 रुपये का है तो उसको बिल 150 रुपये का ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। उसका हमारे पास रिकार्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी मीटर उपलब्ध होने पर आगे भी और लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसका दूसरा तरीका निकाल सकते हैं कि 15 हजार लीटर तक जितना पैसा आ रहा था, उस पैसे को आधार मान कर माफ कर दें मीटर नहीं है तो। दूसरा तरीका यही हो सकता है न उसमें। अगर किसी का 15 हजार लीटर तक का कंजम्प्शन है उस आदमी का बिल एवरेज कितना है उसका पता लगा लें, उतना जो बाकी कंजूमर हैं उन सबको लाभ मिल जाए, इसके बारे में विभाग सोचे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी नहीं। प्लीज गलत परम्परा नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

निजी बसों के टैक्स में बढ़ोतरी

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय का ध्यान

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि निजी बसों पर सरकार द्वारा जो हमारा 2019-20 का बजट है उसमें जो टैक्स बढ़ाया है उस पर मैं यहां चर्चा करना चाहूंगी।

(12:29 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

हम गांव, गरीब की बात करते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि निजी बसों में भी अगर हम आज की तारीख में देखें तो कोई कार वाला व्यक्ति उसमें बैठकर सफर नहीं करता।

या तो किसान का बेटा बैठेगा या गांव का गरीब बैठेगा। आज हमने जो कर बढ़ाकर उनके ऊपर बोझ डालने का काम किया है, हमें इसमें बहुत परिवर्तन करना चाहिए और यह कहीं न कहीं गलत काम हमसे हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी तरह का कोई कर नहीं बढ़ाया है। सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बात कह रहे थे, लेकिन आप देखिए कितना कर हमने निजी बसों का बढ़ा दिया, हमने दोगुने से लेकर सात गुना तक बढ़ाया है।

इसका सीधा-सीधा असर जनता पर पड़ेगा। इसका जीता-जागता उदाहरण आप और हम सब देख रहे हैं। आप देखिए, जो पूर्व में निजी बसें चलती थीं, उसमें जो टैक्स प्रति माह लगता था, वह 2266 रुपये हुआ करता था। हमने उसे बढ़ाकर पचास सीटर बस का 16 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। मैं कहूंगी कि जो निजी बस संचालनकर्ता हैं, यह उनके साथ एकदम अन्याय है। इसमें जो कुछ हमने किया है, वह बहुत गलत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जो हमारी स्टेट कैरिज बसें थीं, उसमें जो टैक्स लिया जाता था, उसके लिए हमने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रखी थी। उसको कम से कम 30 किलोमीटर टैक्स 16 हजार रुपये प्रति माह करके बहुत बड़ा गलत काम हमसे हुआ है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। मैं कोटा संभाग से आती हूं और पूरे कोटा संभाग में एक भी ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा, जो 300 किलोमीटर की दूरी का हो। ऐसा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोई निजी मार्ग है ही नहीं। इसमें अगर हम परिवर्तन करेंगे तो जनता को भी लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं ये जो बस मालिक हैं, उन्हें भी रिलीफ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि स्लीपर कोच की हमारी बसें थीं, जो कि 34 हजार रुपये प्रति माह देकर संचालित होती थीं, वर्तमान में हमने उनका टैक्स दोगुना कर दिया, 68 हजार रुपये प्रति माह कर दिया। इसका सिंगल स्लीपर से दो सीट का जो टैक्स लिया जाता था, मैं कहूंगी यह एकदम अन्याय है। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है और हम दो व्यक्तियों का टैक्स ले रहे हैं, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण स्थिति हो चुकी है। इसमें हमें कहीं न कहीं सुधार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री को बताना चाहूंगी कि परिवहन की जो हमारी बसें हैं, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हम लोगों ने इनकी तादाद बढ़ाने का काम किया था और जनहित जन सेवा से अनुज्ञा पत्र भी जारी किये थे, जिनका कि लगभग 50 सीटर बस का टैक्स 40 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है, जबकि आरएसआरटीसी रोडवेज से 26 हजार रुपये प्रति माह लेती है। इनमें भी किसी भी स्लैब में बनाकर आरएसआरटीसी से कम लेना जनहित में होगा। सीधा-सीधा गरीब को इसका लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कहीं न कहीं हम इसमें रिलीफ देने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय सम्माननीय सीएम साहब से बातचीत करें। जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, पहले राजस्थान में दो प्रकार के टैक्स थे, पथ कर एवं विशेष पथ कर। इन दोनों करों को मिलाकर मोटर वाहन कर के रूप में लागू किया गया। आपने जो सदन का ध्यान दिलाया, उसमें मैं इस बात में आपसे सहमत हूं। मुझसे काफी बस वाले आज सुबह मिले थे, इन बसों में आपने जो डिमांड्स उठायीं, उनमें आप यह कहना चाहती हैं कि जो छोटी दूरी की बसें चलती हैं ग्रामीण रूटों पर, उनके प्रोब्लम क्रिएट हुई है।

आज सैकड़ों की तादाद में बस वाले मेरे घर पर आए थे, मेरी उनसे बात हुई। आज जितने भी राजस्थान की बस यूनियन के लोग हैं, उन्हें मैंने

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

साढ़े पांच बजे सचिवालय में आमंत्रित किया है। उनकी बात वहां आज सुनेंगे और कहीं भी यदि यह लगता है कि आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप लिखकर दे दीजिएगा। हम उस पर बातचीत कर लेंगे और लोगों को सुविधा पहुंचाना हमारा मकसद है। ज्यादा टैक्स इसमें नहीं लगाये गये हैं, लेकिन यह जो टैक्स का नाम बदला गया है, उसमें पहले पालिसी अलग थी और अब पालिसी अलग है। उप-नगरीय बसें जो चल रही हैं ग्रामीण रूटों पर, उसमें यह डिमांड आ रही है कि 300 किलोमीटर तक जो आपने टैक्स लगाया है और 300 किलोमीटर से ज्यादा लगाया है, ए सी बसें जो 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर चलती हैं तो वे बसें कैसे चल पाएंगी ? क्योंकि वे इतना बड़ा टैक्स देकर नहीं चल पाएंगी, उनके किराये बढ़ जाएंगे।

सभापति जी, किराये बढ़ने से बस वालों की हालत खराब हुई, इस पर तो हम बातचीत कर लेंगे और डिस्कस करके रास्ता निकालेंगे जो भी रास्ता हो सकता है। मुख्य मंत्री जी से भी बात कर लेंगे। सभापति जी, ज्यादा प्रोब्लम यह आ रही है कि केन्द्र सरकार ने अभी डीजल और पैट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इतना जबर्दस्त महंगा कर दिया कि उससे पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में हालत खराब है। राजस्थान से जितनी भी सर्विस बाहर जा रही है, सुबह बस वाले कह रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने क्या किया था, 4 परसेंट तो वैट बढ़ाया इन्होंने। मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं? मंत्री जी क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, सुबह जब पूरे राजस्थान के बस वाले मेरे पास आये तो मैंने बड़े सम्मान के साथ उनसे बात की। मैंने पूछा कि आपको क्या-क्या प्रोब्लम्स हैं? राठौड़ साहब तो बस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, आप बताएं, आप इतना जल्दी भूल गये हैं। मिनी बस वाले आज भी चिल्ला-चिल्लाकर कहते हैं, कहां हैं राठौड़ साहब, कहां हैं राठौड़ साहब? राठौड़ साहब ने तो धोती क्या पहनी, पूछते ही नहीं हैं मिनी बस वालों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यहां हैं राठौड़ साहब, यहां हैं राठौड़ साहब।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): क्या करते हैं आप, मिलते ही नहीं आप। गलत बात। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि राठौड़ साहब हमारे सीनियर लीडर हैं और मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि मिनी बस वाले आज सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि हमें राठौड़ साहब से मिलना है तो मैंने कहा कि ये मेरे सीनियर रहे हैं, मैं भी बस यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं, वे भी बस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे मिलो और कई तो इनके साथ के हैं, जो शाम को इनके साथ पार्टियां करते थे, इनके लिए खाना लेकर जाते थे, वे मेरे पास आये थे आज।

मैं सच कह रहा हूं, असत्य नहीं बोल रहा। आपको मिला दूंगा, आप शक्ल देखते ही पहचान जाएंगे। बलजीत यादव भी अध्यक्ष रहे हैं, बलजीत जी हमारे छोटे भाई हैं, वे भी अध्यक्ष रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, अपना दर्द बताकर मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। उन्होंने मुझे यह कहा है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, जितने सीनियर आप बैठे हैं, हमारी सबकी विनती है कि पैट्रोल-डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, आप दिल्ली चलें, प्रधान मंत्रीजी से रिक्वैस्ट करें और पैट्रोल-डीजल की रेट कम कराने के लिए राजस्थान की जनता का दर्द बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पहले तो आप मुख्य मंत्री जी के पास चलें। डीजल पर 4 परसेंट वैट बढ़ाया उन्होंने। भूतो न भविष्यते। क्या बात करते हैं आप?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह दर्द बताना जरूरी है। यदि यह दर्द नहीं बताएंगे, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हालात बहुत खराब हैं, हर आदमी यह चाहता है कि पैट्रोल-डीजल की रेट्स कम होनी चाहिए। पैट्रोल-डीजल की रेट्स कम कराने में आदरणीय कटारिया साहब हमारे सीनियर हैं और राठौड़ साहब को पैरवी करते हुए दिल्ली जाकर मोदी जी से मिलना चाहिए, जिससे पैट्रोल-डीजल सस्ता हो। आदरणीय चन्द्रकान्ता मेघवाल जी ने जो बात उठायी है, उस बात का सम्मान हो और लोगों का दर्द वहां तक पहुंचे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए आप। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति जी, मैं पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन पर बोलना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। श्री गिरधारीलाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: आप इतने वरिष्ठ लोग भी इस तरह से करेंगे? विराजिए आप। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति जी, मैं पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन पर बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप 295 पर बोल रहे हैं, इसके अलावा और किसी बात पर नहीं बोल रहे हैं आप। 295 स्टार्ट हो गया है, अब 295 पर बोलना है तो आप बोलिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बाड़मेर के बन्द ग्रिल पावर प्लांट को चालू करवाना

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आपने पुकारा नहीं, सर। सभापति महोदय, आपने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी सरकार ने बड़ी ही आशा के साथ 2007 में ग्रिल पावर प्लांट की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत से ही कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक होने की ओर ध्यान नहीं देने से तथा ध्यान में आने के बाद सरकार ने इस ग्रिल पावर प्लांट को ठीक करवाने के बजाय अपनी आदत के अनुसार इसे कौड़ियों के भाव बेचने

(श्री गिरधारीलाल)

का इरादा किया, जिससे सैकड़ों कर्मचारियों के रोजगार खतम होने के साथ ही प्रदेश की जनता को बिजली उत्पादन की कमी के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी और सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि प्रदेश की जनता के हित में बाड़मेर ग्रिल पावर प्लांट को तुरन्त ठीक करवाकर चालू किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मुण्डावर राजकीय महाविद्यालय को सरकारी भूमि आबंटन के सम्बन्ध में निवेदन है कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय मुण्डावर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय खोला गया था। यहां पर तत्काल यह महाविद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एक पुराने भवन में खोल दिया गया। ग्रामीण परिवेश होने से बच्चों एवं अभिभावकों में अति उत्साह था किन्तु आज दिन तक इस महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने भूमि आबंटित नहीं की है। इससे क्षेत्र के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पुराने भवन में कोई सुविधा नहीं है। आज तक इसमें रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। मुण्डावर क्षेत्र में अधिकांश लोगों का मुख्य कारोबार कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है व इस महाविद्यालय में गरीब माता-पिता के बच्चे पढ़ने जाते हैं जो कि बिना भवन व बिना कर्मचारियों के ही संचालित है। क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन गरीब, पिछड़े छात्र-छात्राओं को बेहतर रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए इस महाविद्यालय को स्वयं की भूमि आबंटित करें।

अत: माननीय सभापित महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि मुण्डावर राजकीय महाविद्यालय के सरकारी भवन का निर्माण करवाकर मुझे व जनता को अनुग्रहीत करें।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

तिजारा शहर में अपूर्ण सीवरेज कार्य

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग द्वारा एन.सी.आर.पी.बी. योजना के अन्तर्गत तिजारा शहर में सीवरेज लाइन का कार्य शुरू किया गया था जो कि मैसर्स बीम कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण किया जाना था। खुदाई में 34 किलोमीटर की सड़क तोड़ दी गयी लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उक्त कंस्ट्रक्शन कम्पनी को कार्य पूर्ण करने हेतु दिये गये एक्सटेंशन के बाद भी कार्य अपूर्ण है और इसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा कम्पनी को बीच-बीच में टर्मिनेशन लैटर भी दिया जा चुका है। ऐसी ही स्थिति भिवाड़ी में भी है जहां डब्ल्यू.पी.आई.एल. कम्पनी द्वारा एन.सी.आर.पी.बी. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य अप्रैल, 2018 तक पूर्ण किया जाना था जहां लगभग 116 किलोमीटर की सड़कें खुदाई गयी थीं लेकिन सीवरेज लाइन का कार्य बन्द पड़ा है व कार्य अपूर्ण है।

अत: सरकार से निवेदन है कि तिजारा व भिवाड़ी के क्षेत्रवासियों की असुविधा व परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए दोनों जगह पर बन्द पड़े कार्यों को तुरन्त शुरू करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

राज्यावास के विद्यालय में नि:शुल्क साइकिल वितरण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में वितरित नि:शुल्क साइकिल न पाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राज्यावास में कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा, जिसका नाम दीपू लौहार है, जो कि कक्षा 9वीं में सत्र 2017-18 में भी अध्ययनरत थी तथा उसने 9वीं व 10वीं दोनों कक्षाएं इसी विद्यालय से उत्तीर्ण की थीं। जब उक्त विद्यालय में साइकिलें वितरित की जा रही थीं उस दिन किसी कारणवश वह छात्रा विद्यालय में अनुपस्थित थी। जब छात्रा अगले दिन विद्यालय में गई तब उसे साइकिल वितरित नहीं की गयी। उसके द्वारा प्रयास करने पर भी उसे साइकिल नहीं दी गयी।

अत: मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करती हूं कि उक्त छात्राओं जैसी अनेक छात्राएं, जो नि:शुल्क साइकिल लेने से वंचित रह गयी हैं

(श्रीमती अनिता भदेल)

उन्हें यथाशीघ्र साइकिल वितरित की जाए। इसी आशा व विश्वास के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर क्षेत्र में वर्ष 2019 में रबी की फसल के समय ओलावृष्टि हुई थी जिसमें चना, सरसों, गेहूं आदि की फसलं लगभग 80 प्रतिशत नष्ट हो गयी थी पर अभी तक पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिला है इसलिए मैं आपके माध्यम से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग करता हूं।

श्रीमान् जी, विजयनगर क्षेत्र के कई गांव जैसे कि ग्राम पंचायत भातीवाला, कमरानिया, 41जीबी, 6 बीएलएम, 10एएस एवं इसके साथ स्थित आस-पास की ग्राम पंचायतों के गांवों का लगभग 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव 38पीएस, 40 पीएस, 41 पीएस, 42 पीएस, 43 पीएस सहित कुल 19 चकों में भी ओलावृष्टि हुई थी जहां पर भी बहुत नुकसान हुआ। इन सभी क्षेत्र के किसान फसल के अभाव में कर्ज से दब गये हैं और यही कारण है कि मेरे क्षेत्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण नुकसान की भरपाई न हो पाना भी है।

अत: मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर स्थित जिन-जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवायी जाए ताकि अन्नदाता किसान की स्थिति सुधर सके।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी सामान्य चिकित्सालय में व्याप्त समस्याएं

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय में आमजन को हो रही असुविधा व प्रशासन की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय संचालित है

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

जहां सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले के ही नहीं, अपितु अन्य जिलों से भी मरीजों का इलाज हेतु आवागमन होता है। वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में हालत काफी खराब है जिससे आमजन को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है।

उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में पर्याप्त स्टाफ नहीं है जिनमें मुख्य रूप से विभिन्न रोग विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ, न्यूरो फिजिशियन की समस्या काफी विकट है। चित्तौड़गढ़ का श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ एवं आसपास के क्षेत्र का एकमात्र बड़ा चिकित्सालय है लेकिन फिर भी यहां पर कैथ लैब का न होना एक गम्भीर विषय है। प्रतिदिन यहां पर जितनी संख्या में आउटडोर मरीजों का आवागमन होता है तथा उनमें से गम्भीर रोगियों को भर्ती किया जाता है, उस संख्या में रोगी शैयाओं की संख्या 400 है, जो काफी कम है, जिसे बढ़ाने की मांग भी बार-बार आमजन व जन-प्रतिनिधियों द्वारा होती रही है। साथ ही वर्तमान में चिकित्सालय में आने-जाने वाले आगन्तुकों से अब वाहन पार्किंग शुल्क भी लिया जाने लगा है जबकि चिकित्सालय में वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त जगह है। ऐसा करने से आगन्तुक अपने वाहनों को पार्किंग से अलग अन्यत्र या चिकित्सालय के बाहर मुख्य सड़क पर खड़ा करते हैं जबकि पूर्व में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी सामान्य चिकित्सालय की उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराने का श्रम कर अनुग्रहीत करें।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार एवं सुधार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत न्यू मेडिकल कालेज, कोटा में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित कर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया।

(श्री संदीप शर्मा)

अब गम्भीर बीमारी के लिए मरीज को कोटा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इलाज भी भामाशाह में नि:शुल्क होगा या बहुत ही कम कीमत पर होगा। इस विंग में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की गयी हैं। एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज मिलने लगा है। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा यहां स्टाफ नहीं लगाए जाने से 150 करोड़ की ये बिल्डिंग पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रही है और मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सुपर स्पेशिलिटी विंग में 9 सुपर स्पेशलिटी ब्लाक बनाए गये हैं। जिसमें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कॉर्डियोलॉजी, कॉर्डियोथोरेसिक सर्जरी, पीडियाट्रिक, प्लास्टिक सर्जरी शामिल है।

इस प्रोजेक्ट पर 120 करोड़ केन्द्र व 30 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने खर्च किये हैं। सुपर स्पेशलिटी 260 बैड की है। इसमें 60 बैड आइसीयू व 180 बैड जनरल है। 20 बैड विशेष मरीजों के लिए होंगे। यहां 250 बड़े वाहनों की पार्किंग है।

सभी अत्याधुनिक मशीनों को स्थापित कर दिया गया है। इस सुपर स्पेशलिटी विंग के संचालन हेतु न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय के स्टाफ को ही लगाया गया है। जिसके कारण दोनों चिकित्सालयों में कार्य प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसमें नये चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मी नहीं लगाये गये हैं। जिसके कारण इसका संचालन पूर्ण रुप से नहीं हो रहा है। मेडिकल कालेज चिकित्सालय में द्वितीय तल का कार्य भी रुका हुआ है। वर्तमान में चिकित्सालय का मुख्य मार्ग भी संकरा है। जिसके कारण मरीजों को आवगमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को प्रारम्भ करने में आ रही स्टाफ संबंधित परेशानी का समाधान व सुधार किया जाए, ताकि दूर-दराज से आने वाले रोगियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

सिंधी मुसलमानों के ओबीसी प्रमाण पत्र

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करने बाबत मैं लोक हित के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं राजस्थान में सिंधी मुसलमान जिला बाड़मेर,

(श्री अमीन खां)

जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली एवं नागौर में बसते हैं। इसके अलावा सिंधी मुसलमान राजस्थान में कहीं नहीं रहते हैं।

ये सिंधी मुसलमान मूलत: भेड़, बकरी, ऊंट, इत्यादि जानवरों के पेशेवर पशुपालक हैं, जो सदियों से यहीं रहते हैं। आज के वक्त में यह वर्ग शिक्षा, व्यापार, नौकरी इत्यादि धंधे में शून्य पर हैं। ऐसी हालात में राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर 10 वर्ष पहले राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात् ओबीसी में सिंधी कौम को शामिल कर दिया था। लेकिन आज भी सिंधी मुसलमान के युवाओं को ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने पर दिक्कत आ रही है। क्योंकि, जो भी व्यक्ति ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने अधिकारी के पास जाता है तो अधिकारी सर्वप्रथम यह कहता है हम जानते हैं कि आप मुसलमान हैं। लेकिन आप सिंधी मुसलमान हो अथवा पठान हो, मेव हो उसका हमें ऑन रिकार्ड क्या पता है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि निम्न उप जातियां सिंधी मुसलमानों की हैं, जो इस प्रकार हैं- महर, भैया, कलर, कोहरी, मंगलिया, शमा, समेजा, नोहड़ी, रएमा, साउद, रामदिया, गज्जू, हालीपोतरा, जुनेजा, हिलोलजा, भंम्भरा, आलीसर, साहता, सोलंकी, परिहार, राजड़, लंगा, जोईया, सेठार, पन्नू, हिंगोरा, कुम्हार, हज्जाम। ये 32 जातियां हैं, तत्काल मारवाड़ सरकार के गजट नोटिफिकेशन में ये उप जातियां सिंधी के नाम से छपी हुई हैं और इसी आधार पर सिंधी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया है।

अत: इन उप जातियों के संबंध में सरकार एक आदेश जारी कराए ताकि सिंधी मुसलमानों ओबीसी सर्टिफिकेट में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

कोटा शहर में दुल्हन का अपहरण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख। कोटा शहर में दिन दहाड़े एक नव नवेली दुल्हन का, उसके भाई व सहेली का अपहरण कर लिया गया। उस दुल्हन की शादी 21 जून को ही हुई थी। 3 दिन बाद ही दुल्हन पगफेरे हेतु पीहर लौट आई परन्तु शादी का

(श्री मदन दिलावर)

पंजीयन व अन्य कार्यवाही हेतु दूल्हे ने उसे बुला लिया। कानूनी कार्यवाही कर दुल्हन लौट रही थी तभी दुल्हन की सहेली व दुल्हन के भाई का दुल्हन सहित मोनू पठान नाम के हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। बाद में दुल्हन के भाई व सहेली को कुन्हाड़ी पैट्रोल पम्प के आस-पास उतार गये।

दुल्हन के पिता नवल किशोर द्वारा 25 जून, 2019 को कोटा शहर के किशोरपुरा थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस आरोपी को पकड़ने व दुल्हन को तलाशने के बजाय उन्हें टरकाने लगी। नवल किशोर मेघवाल ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई।

इसके बाद मोनू पठान की मां और उसके परिजन नवल किशोर मेघवाल के घर जाकर मुकदमा वापस लेने हेतु धमकाने लगे तथा परिवार को इसके परिणाम भुगतने की धमकी दी। एक तरफ तो नव विवाहिता बेटी के अपहरण का सदमा और दूसरी ओर पुलिस की कोई मदद नहीं मिलने से नवल किशोर सदमे में था। दूसरी तरफ बेटी का अपहरण करने वाले हिस्ट्रीशीटर के परिवार की धमकी ने नवल किशोर मेघवाल की हिम्मत पूरी तरह से तोड़ डाली, मदद का कोई रास्ता नहीं निकलता देख परेशान नवल किशोर को ऐसा धक्का लगा कि उसके हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गयी। यानी मोनू पठान व पुलिस की शिथिलता ने उसे मार दिया।

नवल किशोर मेघवाल के 5 बेटियां व एक बेटा है 12 वर्ष का है। जो कि वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है। कमाने वाला घर में मात्र नवल किशोर ही था। जो काफी गरीब था। किराये का ऑटो चलाकर परिवार पालता था। उसने अभी पाई-पाई जुटाकर किश्तों पर एक नया ऑटो लिया था। अब संकट यह है कि परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा।

सरकार द्वारा मात्र कुछ राशि देकर इतिश्री कर ली गयी। मृतक के परिवार का मजाक उड़ाया है। क्या दुल्हन के साथ मोनू पठान द्वारा दुष्कर्म नहीं किया गया, ऐसे बलात्कार के मामले में सरकार द्वारा पर्याप्त राशि देने का प्रावधान है तथा गैर-अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारने का कारण बनता है तो लगभग 8 लाख रुपये व परिवार के लोगों को घर जाकर धमकाने पर भी राशि देने का प्रावधान है। अत: सरकार अनूसचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लगभग 15 लाख

(श्री मदन दिलावर)

रुपये इस परिवार को दे ताकि परिवार का पालन-पोषण हो सके। इसी के साथ प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लिखा हुआ पढें आप। इसके अलावा कोई अंकित नहीं होगा। श्री सुरेश सिंह रावत। श्री कालूराम।

डग स्थित कोटा स्टोन की खानों से अवैध खनन

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, आपने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 295 के तहत बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिपलिया चौराहे से रूणजी के बीच कोटा स्टोन की खानों में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। जिससे मैंने सभी उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया, मगर किसी माइंस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। एन एच 19 पर माइनिंग वालों ने रोड के सहारे अवैध खनन कर रखा है व रोड के सहारे रोड से करीब तीन से चार मीटर दूर पक्की दीवार बनाकर अपनी माइंस को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी की जगह में बड़ा नाला निकाला गया है। जिससे पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। किसी अधिकारी द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 295 के तहत इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी। इसकी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक 10 जून, 2019 को एक एससी का व्यक्ति अपने खेत पर जेसीबी मशीन से अपने खेत पर खाई खुदाई का कार्य करवा रहा था, तहसीलदार गंगधार ने जब्त कर माइंस विभाग के अधिकारी को बुलाकर बदले की भावना से कार्यवाही कर अवैध खनन बताकर मशीन जब्त कर ली गयी। जबकि ग्राम बिलावली तहसील गंगधार में कोई माइंस की खान नहीं है, तो किसान किस चीज का खनन कर रहा था। वह पशुओं से अपने खेत में फसल बचाने के लिए खेत के चारों तरफ मेड़बंदी का कार्य करवा रहा था, जो अवैध खनन नहीं है। तहसीलदार ने अवैध खनन बताया, चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण बताकर मशीन जब्त कर ली गयी। अगर चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण था, तो 91 की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। इस प्रकार से किसी व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

(श्री कालूराम)

अत: उक्त समस्या के समाधान के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

आहोर सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि आहोर स्थित सामुदायिक अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 11 पद स्वीकृत हैं जिसमें से हाल में सिर्फ 4 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, उनमें से भी एक डाक्टर जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एक डाक्टर के पास ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी का पद है तथा एक डाक्टर दंत चिकित्सक है, जो आपातकाल स्थिति को सम्भाल नहीं पाते हैं। ले-देकर एक डाक्टर बचता है। यहां रोज की पांच सौ ओ.पी.डी. है। यहां आस-पास के लगभग 60-70 गांवों के लोग इलाज के लिए आते हैं। चिकित्सकों की कमी के कारण उनको मजबूरन निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई बार पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए गुजरात जाना पड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से निजी अस्पतालों का खर्च अधिक होने से इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। आमजन के पास इतना रुपया नहीं होता कि वे निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकें। जिससे वे ब्याज से पैसा लाकर निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं तथा भारी ब्याज भरने में ही उनकी जिन्दगी निकल जाती है। न ही वे ठीक हो पाते हैं और न ही वे उधार लिया हुआ पैसा चुका पाते हैं।

यह चिकित्सालय आहोर उपखण्ड का एकमात्र चिकित्सालय है। आहोर क्षेत्र में आये दिन दुर्घटना होती रहती हैं, तत्काल प्राथमिक इलाज नहीं होने से कई मौतें होती हैं।

अस्पताल में चिकित्सकों की कमी की वजह से क्षेत्र में आमजन परेशान रहते हैं। इसी परेशानी से पीड़ित आमजन, क्षेत्र में ज्ञापन व धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चिकित्सकों की कमी के कारण आमजन को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या के सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: जो प्रस्ताव है उसको देखकर बोलें।

श्री छगनसिंह (आहोर): आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से। श्री अविनाश।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैतारण राजकीय महाविद्यालय के लिए रोडवेज बसों का ठहराव

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे पर्ची के माध्यम से आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय, जैतारण है। पूर्ववर्ती भाजपा की वसुन्धरा जी की सरकार द्वारा 26 जून, 2007 को शुरू इस स्थानीय राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय के चार कक्षा कक्षों से तीन सौ विद्यार्थियों के साथ शुरू हुए इस महाविद्यालय में 13 सितम्बर, 2009 को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा साठ लाख रुपये की लागत से एक नया भवन बनकर तैयार हुआ। आगे चलकर 2017 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे पीजी कालेज के रूप में क्रमोन्नत किया गया और तीन सौ छात्रों के साथ में शुरू हुआ महाविद्यालय अब आज की तारीख में लगभग सात सौ छात्र-छात्राओं के साथ में सुचारु रूप से कार्यरत है। इन सात सौ छात्र-छात्राओं में साढ़े तीन सौ,चार सौ के करीब छात्राएं अध्ययनरत हैं।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्तमान में यह जैतारण और निमाज दोनों के मध्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-112 पर स्थित है। जैतारण और निमाज के बीच में स्थित इस महाविद्यालय में जाने के लिए छात्र-छात्राओं को आवागमन में स्थानीय रोडवेज बसों के ठहराव के लिए पूर्व में भी मेरे और मेरे छात्र संगठन एबीवीपी के द्वारा लगातार इस बात के प्रयास किये गये कि कैसे भी करके इस विद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं को आवागमन में सुविधा हो। उसके लिए रोडवेज बसों के अस्थायी बस स्टाप की हमने बहुत बार मांग की थी। अभी कुछ दिनों पहले माननीय परिवहन मंत्री जी से भी उनके आफिस जाकर उनको एक लैटर दिया। मैंने कहा कि 2007 के बाद से लगभग 12 साल हो गये इस कालेज को बने हुए और उस कालेज के बनने के 12 साल बाद भी एक बार भी यहां स्थानीय रोडवेज बसों का ठहराव नहीं हुआ।

(श्री अविनाश)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जैतारण विधान सभा क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतें हैं और लगभग साठ किलोमीटर का एरिया है। जैतारण मुख्यालय से साठ किलोमीटर मगरा क्षेत्र पड़ता है। साठ किलोमीटर कुड़की मीराबाई की जन्मस्थली पड़ती है। वहां से लोग आते हैं और नियरेस्ट पचास किलोमीटर के आस-पास में कोई महाविद्यालय नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर अपना ध्यान करें और जैतारण राजकीय महाविद्यालय जो इस समय नेशनल हाई वे-112 पर स्थित है वहां पर पाली आगार की बसें आती हैं, जोधपुर आगार की आती हैं, ब्यावर आगार की आती हैं, उनको पाबंद करें कि बस स्टैण्ड पर अस्थायी रूप से जो पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा वहां घोषित हो रखा है वहां एक टीनशैड का छोटा-सा बना हुआ भी है स्टोपेज के लिए। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए उसको मंजूर करें और इस महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 14 पद स्वीकृत हैं उनमें से दस पर कार्यरत हैं, चार पद रिक्त हैं। उसके साथ में, यह मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि महाविद्यालय के बनने के बाद में दो करोड़ रुपये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रमसा के तहत तीन कक्षा कक्ष, दो लैबोरेट्री, कांफ्रेंस हाल का निर्माण कराया गया और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज एक और बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के द्वारा माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा राजस्थान में कुल पांच इण्डोर स्टेडियम का...

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): एक सेकंड दीजिये, साहब। पांच इण्डोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया पूरे राजस्थान में।

श्री सभापति: आप विषयान्तर हो रहे हैं। आपका सीधा-सा रोडवेज बस ठहराव मामला है, वहां तक सीमित करें आप।

श्री अविनाश (जैतारण): सर, एक मिनट। पांच में से एक इण्डोर स्टेडियम जैतारण में लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपये का दिया गया है बाहर से वाले खिलाड़ी भी यहां आते हैं उनको भी परेशानी होती है। मेरा सब्मिशन इतना है श्रीमान्, कि आने वाले समय में बहुत जल्द परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि जैतारण कालेज में छात्र-छात्राओं की परेशानी को दूर करने के लिए जो अस्थायी बस स्टोपेज है उसको चालू करने के लिए पाली आगार, जोधपुर आगार, ब्यावर आगार को पाबंद करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) को पूरे राज्य में आयोजन

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज मेरा विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। 1994 से आज पच्चीस वर्ष हो चुके हैं, लेकिन न इस देश की सरकार और न इस राज्य की सरकार इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाने को लेकर चिंतित है। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि विश्व आदिवासी दिवस जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने का निर्णय लिया तो इसके पीछे कई कारण थे। क्योंकि पूरे विश्व में कई देशों में आदिवासियों की जो स्थितियां हैं, आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, आदिवासियों को कंपनी के नाम से, डैम के नाम से जो विस्थापित किया जा रहा है और इस प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रकृति को बचाना है और पर्यावरण को शुद्ध करना है तो आदिवासियों को बचाना है और आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण करना है, लेकिन आज हमारे राज्य की बात करें तो पच्चीस वर्ष होने को आये लेकिन कहीं भी विस्तृत रूप से बड़ा आयोजन या विश्व आदिवासी दिवस के लिए कोई भी सरकार रही हो, आज तक चिंतित नहीं रही है। इसी वजह से आज आदिवासी बहुल क्षेत्र में भुखमरी हो रही है, छुआछूत हो रहा है। आदिवासियों को जो वन विभाग के क्षेत्र में रह रहे हैं उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों के बच्चे गिरवी रखे जा रहे हैं।

सभापति महोदय, यह बहुत चिन्ता का विषय है क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारें हर प्रकार का आंकड़ा रखती हैं, हर चीज की निगरानी रखती हैं। आज मैंने भी अनुभव किया कि वन विभाग के द्वारा जंगलों में कौन सा जानवर, सियार कहां है, शेर कहां है, सूअर कहां है, उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन राजस्थान का जो शिड्यूल्ड एरिया है वहां पर कई बच्चे बाहर राज्य में गिरवी रखे जा रहे हैं। कई महिलाओं और बालिकाओं का आज तक अता-पता नहीं है। सरकार इस विषय पर, क्योंकि अगर विश्व आदिवासी दिवस विस्तृत रूप से मनाया गया होता तो आज कहीं न कहीं सरकार भी और उस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके साथ भी जो घटनाएं हो रही हैं वे कहीं न कहीं रुकतीं। आज उस एरिया में डैम के नाम, खनन के नाम से भी विस्थापित

(श्री राजकुमार रोत)

किये जा रहे हैं। अब चार वर्षों से सामाजिक संगठनों द्वारा इस राज्य में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और पिछली बार जो सरकार थी, चार वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए तो उस सरकार ने रोकने का काम किया है। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मना रहे संगठनों को उनको नक्सलवाद भी बोल दिया गया और ज्यादा दबाव पड़ने पर पिछली सरकार ने जो विश्व आदिवासी दिवस था उसको कल्याण दिवस मनाने के रूप में काम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों के जो अधिकार हैं, आदिवासियों की जो ऐतिहासिक परम्परा है, जो उनकी संस्कृति है, उसको बचाना है तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि राज्य में अवकाश घोषित किया जाए क्योंकि छत्तीसगढ़, एमपी, तैलंगाना राज्यों में भी अवकाश घोषित है। हम भी चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार इस राज्य में अवकाश घोषित करे और बड़े आयोजन कराये जाएं। विश्व आदिवासी दिवस को इस राज्य सरकार के माध्यम से मनाया जाए और पूरे देश में इसका अच्छा संदेश दे। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज विश्व आदिवासी दिवस और आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(13.10 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व आदिवासी दिवस के बारे में अभी राजकुमार जी भी बता रहे थे। मूल निवासियों के मानवाधिकारों को लागू करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए 1982 में यूएनए में एक कार्य दल आयोग का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त, 1982 को हुई थी। इसलिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी। इसको देखते हुए यू एन ए ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व में विभिन्न देशों में मूल निवासी जहां अपनी उपेक्षा,

(श्री रामलाल मीणा)

बेरोजगार और बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। 1993 में भी कार्य दल ने 11वें अधिवेशन में मूल निवासी को मान्यता मिलने पर 1994 को मूल निवासी वर्ष 9 अगस्त, 2009 को मूल निवासी दिवस यानी विश्व आदिवासी दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रपति महोदय की अधिसूचना के अनुसार भारत देश में भारतीय संविधान में दो प्रकार के कानून लागू हैं। उसमें 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची का भी प्रावधान किया गया है। उसमें विशेष प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया गया है। आपको पता ही होगा कि देश में जब आजादी की लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं, उस समय महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हल्दीघाटी के युद्ध में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का ही करिश्मा था जिससे पुंजा भील के नेतृत्व को काम में लिया गया। इस युद्ध के बाद में कई वर्षों तक मुगलों के आक्रमण को विफल करने में भीलों की शक्ति का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उनके वंश में जन्मे भील राणा पुंजा को युगों-युगों तक याद रखने के संदर्भ में ही मेवाड़ के राजचिन्ह में भील का प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और तीन, चार दिन पहले छत्तीसगढ़ में यह घोषणा की गयी है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन सरकारी छुट्टी घोषित की जाए और राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यालयों में, स्कूलों में सब में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। जिससे सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र में एक अच्छा मैसेज जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से आदिवासी हर क्षेत्र में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और लगभग तीन, चार वर्षों से राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें यह देखा गया है कि विशेषकर युवा जागृति की ओर आ रहे हैं। इस जागृति की वजह यह सारे कार्यक्रम हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा और था कि आज आदिवासी समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित है। छोटी-छोटी जमीनें हैं, सिंचाई की सुविधा नहीं है। नरेगा में काम मिलता नहीं है, मिला है तो अभी तक पेमेंट हुआ नहीं। केन्द्र सरकार पांच साल में नरेगा को मरणासन्न पर ले आयी है। आज साल भर से नरेगा में भुगतान नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि उदयपुर संभाग जो टीएसपी क्षेत्र है, वहां कुछ समय पहले वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विषयान्तर नहीं, हो गयी बात।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा का भी अभाव है। उच्च शिक्षा में सरकार की तरफ से कोई प्रावधान कर दिये जाते हैं तो यह समस्या नहीं रहेगी। आज उस क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग उठ रही है। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी 12 में से 5.5 की आरक्षण की मांग अलग से उठ रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग और डाक्टरेट में 5.5 परसेंट अलग से आरक्षण तो हमें प्राप्त हो गया इंजीनियरिंग और डाक्टरेट में अलग से डोनेशन सीटों का भी प्रावधान कर दिया, जनजाति मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि डोनेशन वाली सीटों में आदिवासी जो 19-20 हजार रुपये सालाना कमाते हैं, वह 5-7 लाख रुपये डोनेशन के नहीं भर पाते हैं, इसलिए वह डोनेशन की फीस जनजाति विभाग भरे ताकि गरीब आदिवासियों के बच्चों का भी डाक्टर बनने का सपना पूरा हो सके।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन केवल इतना-सा करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डाक्टर और इंजीनियर में 12 में से 5 परसेंट अलग से आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में की गयी है, उसी प्रकार से राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में भी अलग से 12 में से 5.5 परसेंट की आरक्षण की व्यवस्था होती है तो गरीब क्षेत्र के जो युवा हैं वह आज बड़ी तैयारी करके बैठते हैं लेकिन उनका चयन अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात में आरक्षण और 12 में 5.5 परसेंट राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में हो जाए जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

राज्य उच्च मार्ग 32 के सलूम्बर अंश की वन विभाग से स्वीकृति

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का जो मौका दिया, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उदयपुर से एक सड़क सलूम्बर, बांसवाड़ा और भोपाल, दो राज्यों को जोड़ती है। उसकी स्वीकृति 2017-18 में सलूम्बर तक मेगा हाई वे की मिली लेकिन 19 किलोमीटर सड़क हल्लुघाटी केवड़ा से माही डैम के बीच में वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से रुकी हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रोड है। सलूम्बर हाड़ा रानी की भूमि को जोड़ने वाला रोड है। जयसमंद की मीठे पानी की झील को जोड़ने वाली सड़क है। बांसवाड़ा, भोपाल, इंदौर और रतलाम से जोड़ने वाली सड़क है। 50 किलोमीटर की सड़क पूर्ण हो चुकी है, 19 किलोमीटर की सड़क माही बांध से लेकर केवड़ा तक की सड़क रुकी हुई है। वहां चौड़ाईकरण ज्यादा है लेकिन वन विभाग सड़क पर कार्य नहीं होने दे रहा है। यह सड़क सराड़ा रेंज में आती है। जयसमंद वन्य अभयारण्य रेंज भी है लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। सलूम्बर, सराड़ा और जयसमंद के लोग जो उदयपुर ट्यूरिज्म की दृष्टि से जाते हैं, वहां एक दिन भी एक्सीडेंट हुए बिना नहीं निकलता। पूरी सड़क सर्पकार आकार की है। पल पल पर खतरे की घंटी है। मेरा यह सरकार से निवेदन है कि इस रोड को फोरेस्ट विभाग से एनओसी दिलाकर जो 19 किलोमीटर की शेष बची हुई सड़क है उसको सुचारु रूप से शुरू कराया जाए ताकि आये दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोका जाए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद माननीय गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री अमीनुद्दीन कागजी

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किशनपोल में मकान मालिकों द्वारा मकान को पारियों में किराये पर देने एवं सबलैटिंग की प्रवृत्ति

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में रिहायशी मकान मालिकों द्वारा मकान को

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

पारियों में किराये पर दिये जाने एवं अवैध रूप से सबलैटिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठें। मंत्री जी, 131 पर आपको बोलना है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी गम्भीरता है।

श्री अध्यक्ष: आपके उस प्रश्न में गम्भीर हो गये थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय कागजी साहब ने जिस बात पर ध्यान आकर्षित किया है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इनके किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में मकान मालिकों के साथ वहां पर रह रहे किरायेदारों का संबंधित थानों द्वारा सत्यापन किया जाकर उनका रिकार्ड थाने में संधारित किया जा रहा है। समय-समय पर किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले किरायेदारों की संबंधित थाने द्वारा तसदीक की जाती है। किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में किरायेदारों की संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रण रखे जाने के संबंध में थानों द्वारा सादे वस्त्रों में पुलिस ज़ाब्ता नियोजित किया जाता है। मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की सूचना पुलिस को उपलब्ध नहीं कराये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं जयपुर पुलिस के द्वारा जैसा कि आपने बताया कि रिकार्ड रखा जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के जितने भी थाने हैं, उसमें जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, जिन कालोनियों का, जिन इलाकों का, उसमें कितने लोगों के रिकार्ड आज तक सरकार के पास उपस्थित हैं या रिकार्ड में हैं, राजस्थान के बाहर के जो निवासी हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बीट प्रणाली प्रचलित है। हर बीट अधिकारी को एक एरिया दिया जाता है, जिससे वह पूरी की पूरी सूचना,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कितने मकान हैं, वहां कौन मालिक है, उसके बारे में डिटेल। कौन किरायेदार है, उसके बारे में डिटेल। इस तरह की सारी सूचना करना आवश्यक है। वह चाहे मुंसिफ हो, चाहे वायरलैस में काम करता हो, चाहे महिला हो, हर को बीट प्रणाली के तहत काम दिया जाता है। मेरा निवेदन है जैसा कि आपने पूछा है आपके किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में कुल मिलाकर आठ थाने हैं। इसमें चांदपोल का थाना भी आ गया, शास्त्रीनगर, माणकचौक, सुभाष चौक, रामगंज मण्डी वगैरह भी आ गये। इसमें कुल मिलाकर डोर टू डोर जो सर्वे होता है, उसमें मकानों का जो सर्वे किया गया, उसमें 4212 मकानों का सर्वे बीट प्रणाली के द्वारा किया गया है। इन मकानों के अलावा, मकान मालिक के द्वारा जो किरायेदारों का सत्यापन करवाया गया, वह 289 आदमियों का सर्वे करवाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बीट अधिकारी के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति कब आया और आया तो कहां से आया, उससे एक पर्चा भी भरवाया जाता है वह किस थाने से आया है। मान लीजिए वह बिहार के किसी थाने से आया है, तो उसकी सूचना वह अपने पास रखता है और यहां से अगर कहीं चला गया तो कहां चला गया, उसकी सूचना भी वह अपने पास रखता है। इसमें पुलिस एक्ट की धारा-45 के अनुसार अच्छी तरह से वाच की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि प्रत्येक स्वामी से किरायेदार या घरेलू सहायक का ब्यौरा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रारूप में दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): अध्यक्ष जी, जैसा कि अनुमान है मेरे विधान सभा क्षेत्र में तकरीबन 37 हजार मकान हैं और मंत्री महोदय ने बताया कि इनके पास करीब 4 हजार मकानों का रिकार्ड संधारित है। मैं समझता हूं कि अभी इसमें रिकार्ड एवं जांच की और आवश्यकता है। मेरा इसमें यह कंसर्न है कि जिस तरीके से जयपुर में पिछले दिनों जो माहौल खराब हुआ, उसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक लार्ज लेवल पर एक मुहिम चलाकर, जयपुर में इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): हाउस टू हाउस सर्वे करवाया जाता है और वक्त-वक्त पर किरायेदार उस मकान को छोड़कर किसी दूसरे मकान पर भी चला जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जिस मकान में मकान मालिक रहता हो, वहां पर किरायेदार रहे ही रहे। आपने 37 हजार मकान बता दिये तो 37 हजार के 37 हजार मकानों पर किरायेदार थोड़े ही रहते हैं। मैक्जिमम, जहां-जहां सम्भव हो सका, हाउस टू हाउस सर्वे में जहां पर भी सम्भव हो सका, उसकी सूचना बीट अधिकारी के द्वारा ली जाती है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त। श्री जोराराम।

सुमेरपुर में स्टेडियम का निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-131 के अंतर्गत सुमेरपुर शहर में आउटडोर व इन्डोर स्टेडियम की स्वीकृति के संबंध में युवा एवं खेल राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्तमान में आउटडोर-इन्डोर स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम - 2015 के अंतर्गत पंचायत समिति मुख्यालय पर एथलेटिक्स, बास्केटवाल, बालीवाल, खो-खो, कबड्डी के मैदान सहित स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण हेतु स्वीकृति देखी जाएगी।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर उपखण्ड मुख्यालय है और उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी कालेज सहित दस कालेज हैं। और आस-पास चार सौ से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं। वहां इतने अध्ययनरत छात्र-छात्राएं हैं, उनको खेल की पूरी सुविधा नहीं मिलती है। सुमेरपुर हैडक्वार्टर पर स्टेडियम होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा उन्हें मिलेगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां स्टेडियम बनाने की व्यवस्था की जाए तो खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं आगे आएंगी और खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष

(श्री अशोक)

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): बजट कब तक उपलब्ध होगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। इसमें इतनी ही चर्चा होती है। श्री अंजना उदयलाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

(1) राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

(2) राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(3) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड का अंकक्षेण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18.

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे।

शासकीय वक्तव्य

सरदारशहर में पुलिस हिरासत में मृत्यु

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये तीन वाक़ये निश्चित तौर पर गम्भीर हुए हैं और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं आपके सम्मुख यह स्टेटमेंट दे रहा हूं। 7 जुलाई, 2019 को पुलिस थाना सरदारशहर में चोरी के एक मामले में थाने में पूछताछ हेतु सौनपालसर गांव के एक 28 वर्षीय युवक नेमीचंद नायक की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय के इस विषय पर निर्देशों की पालना में उक्त मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर द्वारा 176 सीआरपीसी संहिता के तहत की जा रही है। पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना के समय उपस्थित थाना अधिकारी सहित आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है तथा 19 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

सरदारशहर थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित बलात्कार

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण का जो पहला पार्ट है, वह मैंने बताया है। सैकण्ड पार्ट में, दिनांक 13 जुलाई, 2019 को मृतक के पति, नेमीचंद और उसके साथ उसके परिवारजन भी साथ थे, मतलब औरत के पति, बलात्कार का आरोप जिस औरत ने लगाया है, उसके पति के साथ अन्य लोग भी डीजीपी से मिले। डीजीपी से मिलकर के उन्होंने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके बयान करवा देते हैं। इसके पश्चात राज्य अपराध शाखा से एक महिला अधिकारी भेजकर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी पीड़िता से लेकर तुरन्त अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये।

सीआईडी (अपराध शाखा) की महिला पुलिस निरीक्षक ने एसएमएस अस्पताल में 13 जुलाई की शाम को पर्चा बयान लिया और पर्चा बयान में मृतक नेमीचंद की भाभी ने यह आरोप लगाया कि पुलिस नेमीचंद को ले जाने के बाद, उसको भी उसी दिन, उसी दिन मतलब 3 जुलाई को, 3 जुलाई को थाना सरदारशहर पर ले गये और रात को मार-पीट कर चोरी के गहने बरामद करने के लिए दबाव डाला। उसी रात थानाधिकारी व अन्य पांच-छह पुलिस वालों ने मेरे साथ बलात्कार किया। यह बयान उसने दिये। अगले दिन दो-तीन तक वह मेरे साथ मार-पीट करते रहे और दुर्व्यवहार करते रहे। इसके बाद 7 जुलाई को मेरे देवर की पिटाई से थाने में मौत हो गयी। जैसा कि उसने बयान

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

में लिखा है। उसके दाह संस्कार के समय 7 जुलाई की शाम को मुझे गांव छोड़ दिया गया। दाह संस्कार के बाद मेरे पति सीताराम ने सात तारीख को सरदारशहर अस्पताल में मुझे भर्ती करा दिया। जहां से मुझे चूरू रैफर कर दिया गया। लेकिन पुलिस वालों ने मुझे चूरू नहीं जाने दिया। उसके बाद मेरे पति मुझे 11 जुलाई को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए सरदारशहर से जयपुर आ गये और जयपुर आकर वह अस्पताल में भर्ती हो गयी। भर्ती होने के बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को महिला के पति और उसके साथ अन्य लोग डीजीपी साहब के पास गये। उनसे कहा कि साहब यह इस तरह की घटना हुई है तो डीजीपी साहब ने उसके बयान पर्चा करने के लिए अधिकारी को नियुक्त कर दिया। उसने बयान लिया। बयान लेने के बाद उक्त पर्चा बयान पर एफआईआर नंबर 378/19 दिनांक 14/7, बताया 13 तारीख को उसने, पर्चा बयान जो उस औरत ने दिया वह 13 तारीख को दिया है और पुलिस की आप एफिशिएंसी देखिए कि फौरन 14 तारीख को यह केस रजिस्टर कर दिया गया। 14/7/19 को धारा 143, 323, 343, 376(डी) और 376(2क) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत सरदारशहर में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसका अनुसंधान जारी है।

दूसरी बात, इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला अधिकारी को सारा का सारा अनुसंधान सुपुर्द किया गया। महिला का मेडिकल करवाया जाकर अनुसंधान की अग्रिम कार्यवाही भी की जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि जब यह वाकया हुआ कि 7 तारीख को नेमीचंद की मौत हो गयी। नेमीचंद की मौत होती है दिन में 12 बजे करीब। उसके 15 मिनट के अंदर, वहां के वर्तमान माननीय विधायक भंवरलाल जी को इत्तला होती है। भंवरलाल जी अपने घर की गाड़ी भेजकर उसके परिजनों को वहां पर बुलाते हैं और बुलाकर उनसे सारी बातचीत करते हैं। उन्होंने चार मांगें वहां पर रखी। चार मांगों में सबसे पहली मांग तो यह थी कि हमारी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरी, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तीसरी यह थी कि पुलिस थाना पूरा का पूरा सस्पैंड होना चाहिए और चौथी बात यह थी कि मेडिकल बोर्ड से हमारा मुआयना होना चाहिए। चारों बातें मान ली गयीं। 12 बजे मौत हुई है और 2 बजे तक यह सारा मामला निपटकर उनके परिजनों को, नेमीचंद के परिजनों को शव सौंप दिया गया और 5 बजे करीब उसका दाह संस्कार हो गया। अब सवाल यह उठता है कि इसमें न्यायिक जाचं हो रही है। न्यायिक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जांच के दौरान जो पुलिस मैक्सिमम धाराएं उसके बयान के मार्फत लगा सकती थी, वह लगा दी गयी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता स्वयं होम मिनिस्टर रहे हैं। वह बता दें कि कौनसी धारा छूट गयी? पुलिस के द्वारा कहां लापरवाही हो गयी? पुलिस के द्वारा एफीशिएंसी दिखाई गयी या नहीं दिखाई गयी? हाथों-हाथ फटाफट बयान हुए या नहीं हुए? जैसे उसने बयान दिए, उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ? किसी भी तरीके की नैग्लीजेंस पुलिस के द्वारा नहीं की गयी। लेकिन उसके बावजूद भी डीजीपी ने यह आर्डर किया और यहां से अफसर भेजा। अफसर भेजकर यह मालूम करवाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुपरवाइजरी नैग्लीजेंस हो गयी हो। सुपरवाइजरी नैग्लीजेंस के चक्कर में वहां के वृत्त अधिकारी और वहां के पुलिस अधीक्षक, दोनों को एपीओ कर दिया गया। पहला मामला तो यह है, इस पर हो जाए या दूसरा भी लूं।

श्री अध्यक्ष: पहले एक हो जाने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, पुलिस की एफीशिएंसी पर मैं कोई टीका-टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पूरा राजस्थान जानता है इन दिनों पुलिस की एफीसिएंसी। मेरा पहला सवाल तो यह है कि सीआरपीसी 176 के अंदर जो न्यायिक जांच की बात आप कर रहे हैं, उसके टर्म्स और रेफरेंस क्या हैं? अध्यक्ष महोदय, यह इतनी सामान्य बात नहीं है। ये घटनाएं दो हैं। एक घटना नेमीचंद की मौत की है और दूसरी घटना नेमीचंद की भाभी के साथ +++ के साथ जो बलात्कार हुआ है, +++ के साथ हुआ है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसी महिला का नाम नहीं ले सकते हैं। आपने किसी महिला का नाम कैसे लिया? क्षमा याचना करिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कानून के खिलाफ है यह।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। रामलाल जी, आप बैठिए। इसको डिलीट किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, 3 जुलाई को नेमीचंद को सरदारशहर की पुलिस पकड़कर लाती है। 3 जुलाई को उसका मेडिकल मुआयना होता हैं। मेडिकल मुआयने की कापी मेरे पास है, उसमें तीन चोट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आती है। 7 तारीख को जब उसका पोस्टमार्टम आता है, उसमें 21 चोट आती हैं। इससे साफ है कि नेमीचंद की मौत पुलिस कस्टडी में हुई।

दूसरी बात, मैं निवेदन करूं, जब 4 जुलाई को नेमीचंद की भाभी को पुलिस कस्टडी में लेती है और उसके बाद 7 जुलाई को नेमीचंद की मौत के बाद दाह संस्कार में जब उसको लेकर जाती है और यह बेहोश होकर गिर जाती है तो पुलिस उसको आनन-फानन के अंदर सरदारशहर लेकर जाती है। सरदारशहर से पुलिस रैफर होती है चूरू के लिए और पुलिस के अधिकारी एक निजी वाहन के अंदर उसको वहां से चौमूं के अंदर बराला हास्पिटल में लेकर आते हैं। 8 तारीख को, 9 तारीख को उसको बराला हास्पिटल में, निजी हास्पिटल में रखा जाता है। निजी गाड़ी में एक एएसआई लेकर जाता है। 10 तारीख को इसी महिला को रतनगढ़ लेकर आते हैं। रतनगढ़ में बीडीओ के सामने यह कहलवाते हैं, रतनगढ़ में एफिडेविट यह लेते हैं कि मेरा जो देवर था वह आदतन चोरी करता था। मेरे देवर को पुलिस वाले पहले 3 तारीख को पकड़कर ले गये। 6 तारीख को छोड़ दिया और 6 तारीख को उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि वह महिला मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखती है। पत्र मेरे पास है। पत्र में वह साफ लिखती है कि मेरे साथ इन-इन लोगों ने दुष्कर्म किया, नामजद करती है। मैं मंत्री महोदय, जानना चाहूंगा कि यह जो मामला है इसमें महिला के 164 के बयान आप कब करवाएंगे? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब यह तय हो गया कि पुलिस कस्टडी के अंदर नेमीचंद के 31 चोट लगी हैं, जिसके कारण उसकी मौत हुई है तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जो पुलिसकर्मी जिनको आपने सिर्फ एपीओ किया है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अध्यक्ष महोदय, घटना यही नहीं है। इस घटना के अंदर जिस प्रकार उसका दाह संस्कार किया गया। पूरी पुलिस मिली हुई। पहले उसको 3 तारीख को पकड़ कर लाते हैं। उसके बाद 3 से 6 तारीख को जब उसको कठोर यातनाएं देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है।

तो मृत्यु होने के बाद पुलिस के लोग वापस उसको उस निशानदेही पर 6 तारीख को लेकर जाते हैं। वहां उसके घर में गड्ढा खोदते हैं, नहीं मिलते हैं तो वापस आते हैं। उस समय चश्मदीद लोग यह कहते हैं, पुलिस के लोग कहते हैं, नेमीचंद राम-राम कर ले, इस गांव में तेरा आखिरी है, तेरा काम तमाम होना है। उसके बाद वापस वहां से चलते हैं, अरसीसर गांव आता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, अरसीसर गांव में शराब के ठेके से दो बोतल लेते हैं, वापस आकर रात को 10 बजे उसके साथ मारपीट करते हैं, इधर मारपीट हो रही है और वह दूसरी जगह उसकी भाभी के साथ बलात्कार हो रहा है। मंत्री महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं 1.10 बजे नेमीचंद की मौत हो जाती है और उसके बाद डाक्टर राजेश गुप्ता को बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है कि इसको हार्ट अटैक दिखा दे। मरे हुए नेमीचंद को हास्पिटल में लेकर जाते हैं, मरे हुए नेमीचंद का ईसीजी होता है और ईसीजी के रिकार्ड पर ऐसा ही आ जाता है। उसके बाद यह प्लान करते हैं, उसके बाद मैं नहीं कहता कि क्या घटना हुई, उसके बाद उसको हार्ट अटैक दिखाकर, जबदस्ती उसका दाह संस्कार कराया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, पूरे मामले में 302, 376 में गिरफ्तारी नहीं होगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, आपने थानागाजी के मामले में नौकरी देने की बात कह दी। आप कह रहे हो कि भंवरलाल जी, यह हमारे बहुत आदरणीय हैं, इन्होंने करवाया ठीक है, आप नौकरी देने की बात कब करोगे। जब एक बलात्कार के मामले में नौकरी देने की बात कर रहे हो ...(व्यवधान) तो इसको कब दोगे।

श्री अध्यक्ष: भंवरलाल जी बैठो। प्लीज बैठो। आप भी बोलना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि आज के युग में इतने वर्षों बाद, आप यह फोटो देख लो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू चल जाते हैं, प्लास से खींचकर नाखून निकाले जाते हैं और फिर पुलिस की एफीशिएंसी की बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: भंवरलाल जी, आपको बोलना है?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट भी पूरा सुना, इनके पास अधिकारियों की दी हुई रिपोर्ट है। माननीय राजेन्द्र जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं। कुछ बातें जो आपने कही हैं जैसे अड़सीसर ठेके की, अड़सीसर इस रास्ता में आता ही नहीं है। नेमीचंद की पिटाई, वह कोई बड़ा चोर नहीं था, छोटी-मोटी चोरियां गांव में करता था, धीरासर गांव में चोरी करने के बाद, धीरासर के लोगों ने उसे पकड़कर पीटा। आप तीन चोट बता रहे है, पुलिस ने मुआयना कराया तो उसमें 52 चोटे आई हैं,आप पता कर लीजिए। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। न पुलिस का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पक्ष ले रहा हूं, न किसी को फंसाने की बात कर रहा हूं और न ही किसी को बचाने की बात कर रहा हूं। मैं 06 तारीख को सरदारशहर था, 07 को संडे था, 6 तारीख को एक बजे मेरे पास टेलीफोन आया कि नेमीचंद की हास्पिटल में मृत्यु हो गयी, पुलिस कस्टडी में। मेरे को पुलिस ने भी इत्तिला दी। मेरे कार्यकर्ताओं ने भी इत्तिला दी। मैंने तुरन्त गाड़ी भेजकर गांव के मुखियाओं को इकट्ठा किया। नायक समाज के लोगों को इकट्ठा किया, पूछा कि क्या हुआ। भाभी के साथ बलात्कार का मामला है, और बातों से तो जैसे चोटें आई हैं मैं सहमत हूं, लेकिन राठौड़ साहब बलात्कार की बात है वह सरासर गलत है। इस ढंग से बलात्कार नहीं हो सकता। 03 तारीख रात का बलात्कार और 07 तारीख को लिखकर देती है कि हमारी चार मांग हैं, उनकी चारों बातें मान ली गयीं। डैड बाडी मैंने रवाना कराई है दो बजे। मेरे कार्यकर्ता गये हैं। उन्होंने वहां जाकर दाह संस्कार कराया है। नाखून वाली बात है, उस महिला को बुला लें, आज भी उसके नाखूनों की बनावट वही है। नाखून और बलात्कार वाली बात झूठी है, और सारी बातों से मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पुलिस कस्टडी डैथ के लिए मजिस्ट्रेट जांच होती है, पुलिस और विभाग ने उसके बारे में जांच दे दी। क्या हुई, कैसे हुई, उसमें कौन दोषी है, नहीं है उसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन अगर उन्हीं दिनों उसके साथ बलात्कार होने की बात उसने पहले ही दिन कही तो फिर हमको एफआईआर 14 तारीख को दर्ज करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। वह गलत थी, कोई बात गलत साबित हो जाती, लेकिन जिस दिन उसने बलात्कार की बात कही या शिकायत की, पुलिस को उसी दिन दर्ज करना चाहिए था, एक। दूसरा यह कि उसको हास्पिटल ले जाने की दृष्टि से जो डिले हुआ, जिस ढंग से एक हास्पिटल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसका मतलब कोई न कोई सीरियस होगी तभी तो हास्पिटल की आवश्यकता महसूस हुई। उसके पति ने अगर लाकर बाद में एस एम एस में भर्ती करवाया, जिन डाक्टर्स ने उसे देखा होगा, भर्ती किया होगा, जिसने बयान लेने की बात की होगी, उसकी सीरियसनैस का कारण क्या था जिसके कारण वह सीरियस थी, जिसके कारण आपको इतना डिले करना पडा। उसके बाद की कार्यवाही आपने की, उससे रिकार्ड लिया, जिनको सस्पैंड करना था, किया, लेकिन जिस समय 3 या 4 तारीख को बलात्कार हुआ, जैसा भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसने कहा, हुआ या नहीं हुआ वह तो जांच का विषय होगा लेकिन उसको दर्ज करने में 10 दिन डिले का क्या कारण है? उसको एक हास्पिटल से दूसरे हास्पिटल, आपके पास जब सरकारी हास्पिटल उपलब्ध है तो फिर प्राइवेट हास्पिटल का सहारा लेने के पीछे पुलिस की मंशा क्या थी? क्यों पुलिस ने केस को दबाने के लिए इधर से उधर घुमाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी राठौड़ साहब ने कहा नेमीचंद की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। हुई मानते हैं। दूसरी बात आपने कही कि 176 सीआरपीसी, तो 176 सीआरपीसी में टर्म्स एंड रैफरेंस डिफाइंड है। वह Determination cause of death**,** जब एक बार न्यायिक जांच चालू हो जाती है तो पुलिस समानान्तर जांच नहीं कर सकती। समानांतर जांच नहीं होती। इसके रिजल्ट आते हैं उसके बाद धाराएं लगती हैं, सब कुछ लगती हैं लेकिन पुलिस की एफीशिएंसी है कि उन्होंने औरत के बयान पर ही जो धाराएं सम्भव थी, जो लग सकती थीं, सारी की सारी लगाईं। जैसा कटारिया साहब ने फर्माया। नेमीचंद की चोटों के बारे में भी आपने कहा, तो सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी बात बता दी कि छोटा-मोटा चोर था, वह पिटता रहता था, उसे लोग पीटते रहते थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठें। गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ऐसे लोगों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। आप सीनियर आदमी हैं, मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात यह है, प्रतिपक्ष के नेता ने फर्माया कि आपने 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज क्यों की, जबकि वाकया 3 तारीख का था। 3 तारीख से 13 तारीख तक आप मुझे कृपया यह बता दें कि उसने कहीं रिपोर्ट दी क्या? जब वह रिपोर्ट नहीं देगी, उसके परिवार वाले नहीं देंगे, जनता का कोई आदमी आकर रिपोर्ट नहीं देगा कि साहब, इसके साथ बलात्कार हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी? पहली बार उसके पति और परिवारजन 13 तारीख को डीजीपी से

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मिले। डीजीपी ने फौरन आदेश देकर उसके बयान करवाकर 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी के बयानों पर सीआरपीसी की जितनी भी धाराएं लग सकती थीं, वह लगाईं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। किसी भी कम्पलेनेंट को डीजीपी तक आने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उसके पहले वाले स्टेजेज थे, उन स्टेजेज में उसने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। केवल और केवल उसको डीजीपी पर ही क्यों विश्वास रहा। नीचे असफल हुआ होगा तब कोई आदमी यहां तक आता है, उसके पहले नहीं आ सकता। तो नीचे वालों ने पूर्णत: सहयोग नहीं किया इसलिए उसको यहां आना पड़ा। इसका मतलब इसमें संदेह तो निश्चित है कि घटना के बारे में, जो भी वहां अधिकारी होगा, एक दूसरे ने लीपापोती करके, किसी भी तरह से दबाव में लेकर शांत करने का प्रयास किया। लेकिन उसने अपने दु:खों को जहां अंतिम सीढ़ी है, वहां पर आकर बताया इसका मतलब बीच के स्टेजेज ने सहयोग नहीं किया इसके कारण से यहां आना पड़ा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। (व्यवधान) अलाऊ नहीं करूंगा, आप बैठें प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है। मैं अला नहीं करूंगा। (व्यवधान) कटारिया जी, कटारिया जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। चर्चा समाप्त हुई, अगला स्टेटमेंट।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बलात्कारी सरेआम घूम रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। प्लीज बैठिए, चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। यह कोई तरीका है क्या चर्चा का, प्लीज आप बैठिए। रोज का तरीका बना रखा है। आपके सीनियर लीडर बोल गये, जवाब आ गया ... (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई। अगला स्टेटमेंट दीजिए। अगला स्टेटमेंट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस पर नहीं बोलना, साहब?

श्री अध्यक्ष: दूसरा स्टेटमेंट दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा आपका आदेश। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जवाब दें, सुनना आपका अधिकार है, प्लीज। (व्यवधान) कैसे खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं गलत परम्परा अलाउ नहीं करूंगा, कोई रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, अगला स्टेटमेंट दीजिये आप। अगला स्टेटमेंट दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

भीम थाना, राजसमन्द के हैड कांस्टेबल की हत्या

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिला राजसमन्द के भीम थाना के हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी पर हमला कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 13.07.2019 को बाद दोपहर हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी नम्बर 567, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द,...(व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

प्रकरण संख्या 392/19, धारा 448, 323 आई.पी.सी., प्रकरण संख्या 372/19, धारा 379 आई.पी.सी. में निरीक्षण घटना स्थल पर आवश्यक अनुसंधान हेतु पदमेला बरार की तरफ गये थे। चल दिये।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये, मंत्रीजी। आप बोलिये प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मैं बोलूंगा। बोलूंगा, लेकिन ये ऐसे थोड़े होता है।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, ऐसे क्या, यह कोई तरीका है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बोलिये। आपको स्टेटमेंट देना है, छोड़िये फिर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दिनांक 13.07.19 को समय 05 बजकर 57 मिनट पर जरिये टेलीफोन किसी ने सूचना दी कि हैड कांस्टेबल, अब्दुल गनी के साथ मारपीट की सूचना मिली है। थानाधिकारी मौके पर पहुंचकर अब्दुल गनी को घायल अवस्था में भीम अस्पताल पहुंचाया गया और उनके बयान लिए गये।

बयान के अनुसार मुकदमे से सम्बन्धित एक पक्ष के 7-8 लड़कों ने हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी पर जानलेवा हमला किया तथा उसके सरकारी कागजात व अन्य सामग्री को भी छीन लिया। जिस पर प्रकरण संख्या 394/19, धारा 302, 333, 353, 147, 148, 149, 396 आई.पी.सी. दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी, भीम के द्वारा प्रारम्भ किया गया। दौरान-ए-इलाज हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी की भीम अस्पताल में मृत्यु हो गयी। बाद आवश्यक कार्यवाही सम्मान गार्ड के साथ हैड कांस्टेबल का शव वारिसान को सौंपा गया, जिसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा में हो चुका है।

घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर; जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द; अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द एवं वृत्त अधिकारी, भीम एवं कुम्भलगढ़ एवं थानाधिकारी ने मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। वृत्ताधिकारी, भीम एवं कुम्भलगढ़ के नेतृत्व में थानाधिकारी, भीम, देवगढ़, दिवेर की अलग-अलग टीमों का गठन कर घटना करने वाले अभियुक्तों की पहचान कर नामजद छह में से चार अभियुक्त, नम्बर एक, नागेश्वर; नम्बर दो, श्रीमती नैना देवी; नम्बर तीन, लक्ष्मण सिंह; नम्बर चार, मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है और शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बहुत दुःखद है कि एक पुलिस कांस्टेबल अगर तामील कराकर आये, लोग उसको रास्ते में मार दें। इससे बड़ा गम्भीर मामला कुछ नहीं है। लेकिन इस विषय को थोड़ा-सा समझना चाहता हूं, जो मुकदमा है, जिसके लिए वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चालान, तफतीश के लिए वहां सूचना देने गये, वह मुकदमा किन धाराओं में था। अगर सामान्य धाराओं में कोई मुकदमा हो और उसके परिवार के लोग उसको मार दें, यह हमारी समझ से बाहर है।

अगर वास्तव में कोई सामान्य, 323 का केस है या सामान्य केस है तो वैसे भी तामील कराने जाते हैं और अकेला ही गया। ऐसा भी नहीं है कि वह और किसी को साथ लेकर गया या वहां कोई दुर्घटना हो गयी, या कोई आपस में बोलाचाली हो गयी या कोई छीना झपटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं था।

यह कितनी दूर वहां से आ गया और उसके बाद इसको सड़क पर घेर करके मारा है, इस विषय को समझने की आवश्यकता होगी। केवल इतना मान लेना, ठीक है, मेरी रात को भी एस.पी. से बात हुई, दूसरे दिन भी हुई। उन्होंने अपना काम किया। उनकी फोर्स गयी। जिनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई करना था, किया। उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं यहां नहीं समझ पा रहा हूं कि एक सामान्य केस में कोई भी परिवार या कोई भी परिवार के लोग किसी कांस्टेबल को मार दें, यह समझ के बाहर है। इस घटना का कोई न कोई और उद्देश्य होना चाहिए। जब तक पुलिस उस उद्देश्य तक नहीं जाएगी तब तक इसकी हकीकत बाहर नहीं आएगी। सामान्य घटना पर कोई भी, किसी को मारे, यह बात समझ में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुलिस के द्वारा अनुसंधान जारी है, और अनुसंधान से ही सब कुछ पता लग पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 323 तो खैर बहुत छोटा केस है, लेकिन वह भी नहीं होता तो भी आपस में बोलचाल पर ही हत्या हो जाती है। तो इस बात को नकार देना कि उसके खिलाफ हल्की धाराएं लगाई गयी थीं। हल्की धाराएं नहीं थीं, 379 भी था। 379, चोरी का मुकदमा, वगैरह-वगैरह ऐसे दो प्रकरण थे। एक नहीं, उसके खिलाफ दो प्रकरण थे। हो सकता है, उसमें कुछ होट-टोक्स हो गयी हों और होट-टोक्स में कुछ न कुछ हो गया हो। यह सब अनुसंधान की बातें हैं। अनुसंधान के बाद पता लग जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है। काफी दूरी पर आकर, मेन रोड पर, अब कैसे तो उनके पास सूचना थी और कैसे उन बच्चों ने उनको घेरकर, पीट करके मारा। कहीं न कहीं, कोई न कोई उस घटना के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साथ-साथ, जिस जगह यह मारपीट हुई, वहां कोई न कोई विषय या कोई न कोई बात होनी चाहिए। चाहे वह बच्चे सैंस में हों, न हों, कुछ बात हुई हो, कुछ नहीं, पर उस घटना से कोई मार दे, क्योंकि बहुत सिम्पल केस है, जिस केस की इन्होंने जाकर तामील कराई, वह केस ऐसा नहीं है कि कोई परिवार इस सीमा तक चला जाये। इसको देखने की आवश्यकता होगी। उसके कारण से इतनी बड़ी घटना हो जाए और एक कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया जाए, यह सामान्य बात नहीं है। इस डिपार्टमेंट के सम्मान की रक्षा के लिए भी और कांस्टेबल के सम्मान की रक्षा के लिए भी इसके ठेठ नीचे तक जाना चाहिए, जिससे वास्तव में हकीकत का पता लग सके कि किस कारण से हुई।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अगला स्टेटमेंट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें कोई फैक्ट्स आपके पास हों ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला स्टेटमेंट, अनुंसधान में इस चीज को ध्यान रखें आप, प्लीज। अगला स्टेटमेंट।

जयपुर शहर में अपहरण घटना में सफलता

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 14.07.2019 की रात्रि को दो बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार हथियारबंद बदमाशों ने अजमेर रोड पर एक वर्ना गाड़ी, वर्ना ...(व्यवधान) गाड़ी का नाम है वर्ना। वर्ना का मतलब आप उलटा मत समझ जाना, कई बार।

वर्ना गाड़ी में सवार चार व्यक्तियों के साथ मारपीट कर उनमें से तीन व्यक्तियों को मौके पर छोड़कर एक व्यक्ति को मय गाड़ी अपहरण करके ले गये। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि स्कोर्पियो गाड़ी थी बदमाशों के पास और चार व्यक्ति एक वर्ना गाड़ी में सवार थे। जब वह वर्ना गाड़ी आगे जा रही थी तो स्कोर्पिओ ने उसको ओवरटेक करके उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी और उस गाड़ी को रोक लिया। रोक करके, उनमें से एक आदमी के साथ वर्ना गाड़ी को ले करके ये बदमाश रवाना हो गये, तीन छूट गये, और तीन को भी नीचे सड़क पर उतार गये। एक को ले करके चले गये। थोड़ी दूर ले जाकर के उसको भी छोड़ दिया और वर्ना गाड़ी को ले करके रवाना हो गये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस बात की सूचना, जो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति था, सबसे पहले उसने सौ नम्बर पर टेलीफोन करके दी। उसके बाद फिर इन लोगों ने दी।

इसमें सबसे बढ़िया बात यह हुई कि उस वर्ना गाड़ी में एक मोबाइल पड़ा हुआ था। वह मोबाइल उसमें रह गया। मोबाइल से पुलिस को पकड़ने में बहुत आसानी रह गयी कि इसकी लोकेशन कहां है और उसकी लोकेशन का एग्जेक्ट पता लग गया। पुलिस तुरन्त पहुंच गयी। उसके तीन-चार किलोमीटर में आप यह देखिये कि 100 या 120 की स्पीड से चला करके पुलिस वहां पर इतनी जल्दी पहुंची कि ज्योंहि वह स्कोर्पिओ गाड़ी, नई कालोनी है न बहुत बड़ी, उस टाउनशिप में वह पहुंची तो पहुंचने के दो मिनट बाद में ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी ने चौकीदार से पूछा कि कोई गाड़ी इधर आई क्या। कहा, हां, साहब, स्कोर्पिओ गाड़ी है, वह आई है और वह खड़ी हुई है। वहां पर आगे जा करके देखा। वहां पर कुल मिला करके एक व्यक्ति, एक लड़का मिल गया। उस लड़के को पकड़ा। उसके पास में पिस्तौल वगैरह-वगैरह, और भी हथियार थे। उसको पकड़ करके पुलिस वालों ने तलाश जारी की।

(14.00 बजे)

इस सूचना पर पुलिस ने तुरन्त नाकाबंदी कर दी। थानाधिकारी भांकरोटा एवं रात्रि गश्त में लगे अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर बदमाशान की तलाश आरम्भ हो गयी। घटना स्थल में तीन-चार किलोमीटर दूर अपहृत व्यक्ति पुलिस को मिला। अपहृत व्यक्ति वहां पर ही मिल गया और जिसके साथ, उसी ने बताया कि साहब, उसमें एक मोबाइल भी पड़ा हुआ है, जिसको साथ लेकर पुलिस ने बदमाशों की तलाश जारी की। इस घटना की सूचना पर पुलिस आयुक्त (पश्चिम)-विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-बजरंग सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त तथा छह-सात थानाधिकारी मय ज़ाब्ते के क्षेत्र में पहुंचकर अपराधियों की तलाश जारी की। जिस टाउनशिप में...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): शंकरा रेजिडेंसी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): शंकरा रेजिडेंसी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): शंकरा, हां, इन्हीं का है वह। मिले हुए हैं सब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप सीरियसनैस से बात करिए, गंभीरता से बात करिए। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इस प्रकार से मजाक में उड़ा रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या सारे आप ही की तरह हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो आपकी पापुलेरिटी बता रहा हूं कि वह आप ही का आदमी है। यह तो पापूलर हो आप।

यह सब पहुंच गये। छह-सात थानाधिकारी मय जाब्ता क्षेत्र में पहुंचकर अपराधियों की तलाश जारी कर दी। साइबर-सैल की मदद से अपराधियों की लोकेशन के बारे में ठोस सुराग मिलने पर पुलिस अविलम्ब ओमैक्स सिटी, ओमैक्स सिटी है वह। शंकरा रेजिडेंसी, जिसके लिए आप कह रहे हैं न, उसको ओमैक्स सिटी बोलते हैं। ओमैक्स सिटी में स्थित शंकरा रेजिडेंसी पर पहुंची। वहां पर बदमाशों की सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी मौजूद मिली जिसमें मौजूद बदमाशान पुलिस को देखकर रात्रि के अंधेरे में इधर-उधर भागने लगे, जिस पर पीछा कर पुलिस ने एक बदमाश को हथियार समेत पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गये इस व्यक्ति ने शंकरा रेजिडेंसी में स्थित अपने ठिकाने के बारे में सूचना दी, पर पुलिस ने उस फ्लैट पर तो छापा मारा ही मारा लेकिन उसके साथ-साथ तीन व्यक्ति जो और बंधक बने हुए थे, उनकी भी तलाश जारी की।

आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि पुलिस की एफीशिएंसी क्या होती है? 400 पुलिस वालों ने पूरी रात 600 फ्लैटों की तलाशी ली, 600 फ्लैटों की। 400 पुलिस वालों ने और सातों के सातों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन सातों मुलजिमों के पास 3 अपहृत व्यक्ति थे। एक कर्नाटक का था, एक आंध्र का था और एक पता नहीं कहां-कहां का था, जिनकी पुलिस को कोई सूचना ही नहीं थी। यहां की पुलिस को कोई सूचना नहीं थी कि इस प्रकार से हमारा आदमी भी कोई अपहृत हुआ है। मैं आपको

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यह बताना चाहता हूं कि 12 घंटे तक इस सर्च आपरेशन में ERT and QRT सहित 400 पुलिस-कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान पूरी सतर्कता रखते हुए लगभग 600 फ्लैटों की सघन तलाशी ली गयी। लगभग 12 घंटे चले सर्च एवं कॉम्बिंग ऑपरेशन के पश्चात् पुलिस को छह शेष बदमाशों सहित सात बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।

इनके कब्जे से दो हथियार, कारतूस, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बी.एम.डब्ल्यू. और लूटी हुई Verna गाड़ी भी बरामद की गयी। गिरफ्तार किये हुए बदमाश महेन्द्रगढ़ हरियाणा के कुख्यात अपराधी हैं, जिनके द्वारा पूर्व में हरियाणा व राजस्थान में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है। बंधक बनाए गये व्यक्तियों से पूछताछ पर पता चला कि इन व्यक्तियों को बंधक बनाकर उनके मालिक, बैंगलोर निवासी रफीक को बिटकाइन का झांसा देकर उससे लगभग 8 करोड़ रुपये ऐंठने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण संख्या 357/2019, धारा-365, 364 (क), 368, 120(बी) भारतीय दंड संहिता, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना-बगरू और दूसरा प्रकरण 423/2019, धारा-395, 398, 365, 143, 323, 341 भारतीय दंड संहिता तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भांकरोटा में दर्ज किया गया। दोनों प्रकरणों का अनुसंधान जारी है।

मैं प्रतिपक्ष के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका तो इस पुलिस से बहुत पाला पड़ा है। आपने बहुत अच्छी तरीके से पुलिस के कार्यों को भी देखा है और पुलिस के कार्यों में जहां-जहां भी लापरवाही होती थी, आपने सुधारने का प्रयत्न भी किया है। क्या आप इस पूरी घटना में पुलिस की कार्यवाही को एप्रीशिएट नहीं करेंगे? यह कंजूसी मत करिए। मेहरबानी करके आप यह कहिए कि इस एफीशिएंसी के लिए पुलिस अधिकारियों को इनाम दिया जाना चाहिए। उनकी गंभीरता को सराहना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर से बोले हैं। इस शहर को अभियुक्तों का अड्डा बनाने में पुलिस की नाकामी नहीं है? यह जो अड्डा बना है, यह हरियाणा के बदमाश लोग हैं। यहां पर लंबे समय से रहकर इस प्रकार के लोगों को बंधक बनाकर वसूली कर रहे हैं। यह तो उनका दुर्भाग्य था कि रात को उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक करके उनके साथ मारपीट की और उसमें से भी एक आदमी को पकड़ लिया जिसके कारण से पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन उसके पहले यह राजस्थान की राजधानी है, थोड़ा संतोष से बोलिए। जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा। इस पुलिस की एफीशिएंसी यह बताती है कि यहां पर आकर किराये का मकान लेकर अड्डा बनाकर हिन्दुस्तान के लोगों को बुलाकर यह जो घटनाक्रम खुला है न, यह आप और मेरे मुंह पर कालिख पोतता है कि आखिर यहां इस प्रकार का अड्डा चलता हुआ था, पुलिस क्या कर रही थी? पहले तो जिस मकान को उसने किराये पर लिया, क्या किराये पर लेने से पहले, लेने वालों के बारे में, उनके बायोडेटा मंगवाने का नियम है या नहीं है? कैसे तो इसने इस फ्लैट को किराये पर लिया और कैसे यह रहा? कैसे उस फ्लैट में, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थीं, लोगों को टोर्चर करने के लिए, आपको लगा कि 19 वर्ष का जो महाराष्ट्र का बच्चा था मोहम्मद, यह उनके पास गिरफ्तार था, उनके पास था। इसी तरह से पी.मंगल पठान उसके पास गिरफ्तार था। बीकानेर का निवासी मोहम्मद शहजाद उसमें से गिरफ्तार था और उनसे यह चौथ-वसूली का काम हो रहा था।

यही नहीं, ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं होगा, मैं आज आपको चुनौती देता हूं कि राजस्थान की राजधानी में अपराधों का ग्राफ चार महीने में 36 परसेंट बढ़ा है, आपको विचार करना चाहिए। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आए दिन आप और मैं भी इसको देख रहा हूं कि हमारे यहां की गैंग, आप यह दूसरे प्रदेश के बच्चों को लाकर, बिहार से बच्चों को लाकर यहां पर जितनी शादियां होती हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चों को लाकर उन्होंने, उनके घर वालों को कुछ पैसे देकर लाते हैं और उन बच्चों का उपयोग कर रहे हैं, इन शादियों में से लोगों के जेवर उठाने का काम और फिर यह हमारे लिए उपलब्धि है? इसको हम उपलब्धि मानेंगे?

इसी तरह से आपने देखा होगा कि यू.पी. से विकलांग बच्चों को लेकर आ रहे हैं और विकलांग बच्चों को लाकर उन विकलांगों को उनका मेक-अप करने के बाद भिखमंगेपने का काम यहां पर करवा रहे हैं तो आखिर उन बच्चों के आधार पर क्या आपने उस गैंग तक पहुंचने काम पहले किया?

यह तो उनका दुर्भाग्य था कि वह घटना रात की हो गयी, उन्होंने थाने पर 100 नम्बर पर सूचना दे दी और आपकी इस पुलिस ने पहुंचकर उसके बाद का काम किया, उसके लिए पुलिस की बहुत-बहुत तारीफ। लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके पहले हमारी राजधानी में, हमारे सबके नाक के नीचे जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं न, 47 परसेंट, अफसोस होगा राजस्थान को कि महिला अपराध केवल चार महीने में राजस्थान में 47 परसेंट बढ़ा है, अख़बार का कोई पन्ना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पाइंट पर, इश्यू पर बोलिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम अच्छा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे नीचे जिस प्रकार से अभियुक्त यहां पर पनप रहे हैं, शरण लिए हुए हैं, यह जिम्मेदारी पुलिस की है या नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। आप प्लीज बैठें। गलत परम्परा नहीं डालें। लीडर के बाद बोल रहे हैं, क्या अजीब हैं आप?

No please, I'll not allow. प्लीज बैठें। लीडर आफ अपोजिशन के बाद, मतलब ही क्या? Why should we have a senior leader? जो पार्टी का लीडर है, उसका सम्मान तो करना चाहिए आपको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने दो बार यह कहा कि जोर से बोलने से काम नहीं चलता। आदमी जोर से कब बोलता है? जब उसके तर्कों में दम होता है और अच्छी बातें सुनने के लिए विपक्ष तैयार नहीं होता, तब आदमी जोर से बोलता है। मेरा निवेदन यह है कि आप भी पांच साल तक लगातार होम मिनिस्टर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार की घटनाएं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें ..(व्यवधान) माननीय राजेन्द्र जी, चर्चा बंद, चर्चा समाप्त कर दूंगा। यह तरीका नहीं है। संयम जी, बैठें। संयम जी, प्लीज। (व्यवधान) संयम लोढ़ा जी, यह तरीका नहीं। (व्यवधान) आप प्लीज। राजेन्द्र जी, कहां देख रहे हैं आप? माननीय राजेन्द्र जी, आप कहां देख रहे हैं? मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा, यह तरीका नहीं है। आप अध्यक्ष को भी नहीं देख रहे

(श्री अध्यक्ष)

हैं, आप खड़े होकर बोले जा रहे हैं। काहे के सीनियर लीडर हैं आप? नो प्लीज। आप चर्चा को नहीं चलाना चाहते, चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वैशाली नगर की वह घटना भी आपको याद होगी, जब उस औरत के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गयी थी, आपके टाइम पर। पचासों घटनाएं इस प्रकार की हुईं, जिसमें आपके वक्त में वह अंजाम तक नहीं पहुंचीं। उनका अनुसंधान तक पूरा नहीं हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस आधार पर इनको प्रश्रय मिलना चाहिए क्या?

श्री अध्यक्ष: एक बार आप सुन तो लें। आप सुनें प्लीज। कटारिया जी, मंत्री बोल रहे हैं तो आप सुनेंगे तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने पाप किया तो हम उस पाप के आधार से आपको पाप का लाइसैंस दे देंगे क्या? हद ही करते हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, माननीय कटारियाजी, यह परम्परा नहीं डालें। मंत्री की बात तो सुनेंगे आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सबसे बड़ा अपराध है कत्ल करना। 302 की धारा है जिसमें फांसी की सज़ा भी होती है। फांसी की सज़ा का प्रोविजन भी है। क्या उसके बाद भी कत्ल होने बंद हो गये। इतना बड़ा शहर है 45 लाख की पापुलेशन का, जिसमें कहां, कौन आकर, कब रह जाता है, यह बड़ा मुश्किल होता है, यह आप भी समझते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य..(व्यवधान) माननीय सदस्य, नीचे बैठें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आपने पूछा कि वह कब आ गये, कैसे आ गये? अब यही पता लग जाता तो बात ही दूसरी हो जाती। आपको तो इस बात को एप्रीशिएट करना चाहिए। मैं आपको क्या निवेदन करूं, आप इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं और उसके बावजूद भी इधर-उधर के तर्क दे रहे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं। मेहरबानी करके इस बात को एप्रीशिएट करिए कि कितनी तेजी से, रात को 2 बजे, वक्त देखिए, रात के 2 बजे, यह एफीशिएंसी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उनको तनख्वाह मिलती है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तनख्वाह तो आपको भी मिलती है, हमें भी मिलती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अपना जवाब दें प्लीज। (व्यवधान)चर्चा समाप्त हुई।

आय-व्ययक पर चर्चा, श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

आय व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, 10 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने इसको जनता का बजट बताया और उन सभी बिन्दुओं पर आम आदमी से प्रदेश की सात करोड़ जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनका प्रयास रहा और सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस एक मिनट।

सूचना

पीलाधर, उदयपुर में हुई हत्या से जनाक्रोश

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को थोड़ा-सा एक आवश्यक सूचना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी पीलाधर, उदयपुर में पुलिस गोली चलाने की स्थिति आ गयी। बहुत अधिक भीड़ है। मैं सोचता हूं उस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, उसमें दो लोगों को पकड़कर लाये थे, उनका विश्वास यह था कि ये दो लोग तो उसको ले जाने वाले जरूर थे, लेकिन मुख्य मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहा, जिसकी पुलिस को जानकारी हो जाए। यह आंदोलन वहां पिछले पांच दिनों से चल रहा है और अभी वहां गोली चल रही है, लगभग छह-सात हजार लोगों की भीड़ सड़क पर खड़ी है और बहुत बड़ी जन-हानि हो जाएगी, इसको आप तुरन्त देखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप इस घटना पर ध्यान रखें, घटना का पता लगाएं। भरत सिंहजी।

आय व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): बजट पेश करते समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने जल और जल से जुड़े मुद्दों के ऊपर ध्यान दिलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए महात्मा गांधी के 150 वर्ष, उनके जन्म दिन का उल्लेख किया और यह घोषणा की कि महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष की जयंती के अवसर पर हम एक साल तक इसको मनाएंगे इस प्रदेश में। चुनाव की व्यस्तता की वजह से इस कार्यक्रम को उस रूप से हम नहीं कर सके इस प्रदेश में, जिस रूप से होना चाहिए था। मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा कि आज जो हालात पूरे मुल्क में हैं, उन परिस्थितियों में महात्मा गांधीजी का उल्लेख उन्होंने बजट के शुरू में किया और बजट में समाप्ति के समय भी उन्होंने महात्मा गांधीजी के सात पाप का उल्लेख किया। मैं सात पाप का तो उल्लेख नहीं करूंगा, पर एक पाप के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसको महात्मा गांधीजी ने अपनी बात में रखा है- 'सिद्धान्तविहीन राजनीति' और वह सिद्धान्तविहीन राजनीति, सिद्धान्त बचे ही कहां हैं राजनीति में? आज स्थिति यह हो गयी कि जो इसकी उलटी दिशा में जाए, संभावना यह है कि उसके शीर्ष पद पर पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ गयी और इसलिए महात्मा गांधीजी को याद करना, उनके बारे में उल्लेख करना निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी की सोच में इस बात की पीड़ा होगी, इसलिए उन्होंने सात पाप का जिक्र किया है।

जल का जब उल्लेख है, अभी वर्षा ऋतु का समय है और राजस्थान में जो स्थिति बन रही है, बरसात दिखाई नहीं देती। जिन्होंने फसल बोई है, वह सूखने के कगार पर है और बहुत जगह बुआई हुई नहीं है। अर्थव्यवस्था का आधार जब प्रदेश में कृषि को बताया है और है, हमारी इस प्रदेश की पूरी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कहा है, ease of doing farming.

मैं इस सदन में इस समय जो युवाओं की भावना है, वह यह है, is it worth doing farming. आज किसान का बेटा खेती से दूर जा रहा है और नौकरी ढूंढ रहा है, जो है नहीं। खेती की बात करते हुए उन्होंने पैरा नंबर-19

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

में यूरिया का उल्लेख किया कि हम यहां पर प्रदेश में दो लाख मीट्रिक टन का स्टाक तैयार करेंगे ताकि खाद की दिक्कत नहीं आए।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यहां पर बोलते समय केवल जो घोषणाएं हैं, उनके कसीदे नहीं गिनाऊंगा, मैं सुझाव रखूंगा कि किस प्रकार से हमारी जो समस्याएं हैं, उनको हम पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में हमारे कोटा शहर में एशिया का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट, और अगर कोटा में खाद के लिए लाइनें लगें तो सवाल उठता है कि खाद जा कहां रहा है?

(14.15 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप सहकारी में खाद की व्यवस्था, जो हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, जो मोटे रूप से हर ग्रामीण क्षेत्र में खाद की व्यवस्था करती हैं, उनको क्यों पाबंद कर रखा है कि वह इफको, कृभको से ही खाद खरीदें? उनको सीधा खाद, जो हमारे यहां खाद प्रोड्यूज हो रहा है, उनसे खाद का आबंटन करें। कांडला के पोर्ट से यूरिया आए और यहां किसानों को दिया जाए। हमारे राजस्थान में जो खाद पैदा हो रहा है, जो कोटा में खाद बन रहा है, जो कमी आ नहीं सकती, मगर इसका अलाटमेंट भारत सरकार के माध्यम से होता है। हमारा सहकारी विभाग और हमारे मुख्य मंत्रीजी इस बात पर विचार करें कि यह यूरिया जब किसानों को उसकी आवश्यकता होती है, वह कम मिलता है तो उसका निस्तारण इस रूप से हो सकता है कि यूरिया का आबंटन हमारे प्रदेश में प्रोड्यूज यूरिया से किया जाए।

बिन्दु संख्या-32 पर पी.डब्ल्यू.डी. का जिक्र किया है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. की जितनी सड़कें दी हैं, उसका उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी करीब दो साल इस प्रदेश के पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में लगभग दो लाख किलोमीटर डामर सड़क है और अच्छी सड़क क्या होती है, अच्छी सड़क यह होती है जिस पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरे और घास का एक तिनका नहीं उग सके। जिसको हम अच्छी सड़क कहते हैं, पर्यावरण के लिए वह सबसे सत्यानाश करती है। क्योंकि जितनी सड़क बनेगी, पर्यावरण बिल्कुल खराब होगा। मगर सड़क के लिए आवश्यक है कि उस पर खड्डे नहीं पड़ें।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मैं दूसरी बात पर ध्यान दिला रहा हूं कि जब सड़क बनती है, जब दो लेन से चार लेन होती है और जब चार लेन से छह लेन होती है तो जितने भी पेड़, जो हमारे पहले वाले लोगबाग ने प्रदेश में पेड़ लगाये थे, वे पेड़ हमें कटते हुए तो दिखते हैं मगर लगाने की बात है, बीच में कनेर लगा दिये, बोगनबेलिया लगा दिये। पेड़ कट गये और टोल वसूल करते रहे, पेड़ खड़े होंगे नहीं तो पानी आएगा कहां से? जल है कहां, वृक्ष है नहीं। सैस की बात की, वह जो सैस ले रहे हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट लेती है, चाहे भारत सरकार लेती है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सड़कों के सहारे पेड़ खड़े हों। कोई पूछ सकता है कि आप भी रहे, आपने क्या किया? मैंने प्रयास किये, बहुत कम समय था, मैं उसमें सफल नहीं हो सका मगर अभी जो भी इस मंत्रालय को देखते हैं और आने वाली जो भी सरकारें आएं इस दिशा में काम करेंगी, आप जो सैस लगाते हैं सड़कों पर, पैट्रोल पर, डीजल पर उसका एक हिस्सा पेड़ लगाने पर जाना चाहिए।

जल संसाधन विभाग के बारे में बिंदु संख्या 54 और 68 पर कहा है। ग्रेट ईस्टर्न कैनाल, जैसे राजस्थान कैनाल बनी पश्चिम राजस्थान को पानी देने के लिए। पिछली सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की कल्पना की और कालीसिंध नदी के ऊपर पहला बैराज बनाने का काम भी शुरू किया। 37 हजार करोड़ की यह योजना है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 37 हजार करोड़ की योजना की हम कल्पना कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। पहला बांध बन कहां रहा है, कालीसिंध नदी पर। बांध बनेगा, यह एक सपना है, आगे जाकर साकार होगा। मगर, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करता हूं कि एक बांध इस कालीसिंध नदी के ऊपर कांग्रेस सरकार में 2009 में स्वीकृत हुआ था, 2014 में बांध बनकर तैयार हो गया प्रथम चरण, कालीसिंध नदी पर ही बना है। यह बांध भी कालीसिंध नदी पर ही बनना है जिस स्थान पर भंवरासा बांध बना, उसका द्वितीय चरण जिसमें एक हजार करोड़ रुपये लगने हैं, उसके लिए पैसे नहीं। 2004 से 2019 के बजट में हम बात कर रहे हैं, एक-एक बूंद पानी को रोकने की बात करते हैं, राजस्थान को एक परसेंट वर्षा जल मिलता है, उसकी बात करते हैं। मगर भंवरासा बांध जो एक हजार करोड़ के अन्दर, उससे कम, 700-800 करोड़ रुपये के अन्दर पूरा पानी रोका जा सकता है, पानी रुकता है तो पानी काम आएगा और पानी नहीं होगा, अगर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

वर्षा नहीं हुई तो फिर पानी की याद आएगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि जो भंवरासा बांध है पहले उस पर पानी रोका जाए और जो 37 हजार करोड़ की योजना है यह सफल हो, आगे बढ़े, उसके लिए भारत सरकार हमको पैसा दे।

इंडस्ट्री लगाने के लिए रीको को जमीन देने की बात की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इंडस्ट्री के लिए जमीन जरूर मिलनी चाहिए। मगर माननीय सभापति जी, पहले जो जमीन दी गयी, मान लीजिए मेरे को भरत सिंह को, इंडस्ट्री के लिए रीको की मैंने जमीन ले ली, मैं कोटा की बात कर रहा हूं, और उस जमीन का किया क्या? बिना अनुमति, बिना इजाजत बड़े-बड़े छात्रावास खड़े कर दिये। सरकार आई और गयी, कोई पूछने वाला नहीं। क्या गारंटी है कि जो दूसरी जमीन देंगे उसका सही उपयोग होगा? मैं चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए।

दस हजार लोगों की सड़क एक्सीडेंट्स में मौत होने का उल्लेख किया है। जिस प्रदेश में प्रति वर्ष दस हजार मौतें एक्सीडेंट से हो रही हैं और एक्सीडेंट होता है तो दस हजार परिवार प्रभावित होते हैं। क्यों नहीं हम जो टोल पर सैस लिया जाता है उसमें से एक हिस्सा, जिस टोल रोड पर एक्सीडेंट होता है चाहे स्टेट हाई वे की हो, चाहे राजस्थान की हो, उससे जो राशि इकट्ठी होगी उससे उसको भुगतान किया जाए। उससे नहीं किया जाता है तो प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वह हर साल ही तो टैक्स बढ़ाता है, उस बढ़े हुए टैक्स से उन परिवारों को जिनमें एक्सीडेंट में मौत होती है, हम कुछ पैसा उसके लिए रखें और उनको दें। एक्सीडेंट जब होता है अगर मुखिया मर गया तो उस परिवार का क्या होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है, उस प्रकार की व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से यह बजट और सार्थक हो जाएगा अगर हम उन लोगों के लिए प्रोविजन करें।

चिकित्सा का उल्लेख करते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देहात के उन सब सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलवाऊंगा कि डाक्टर सब बनना चाहते हैं और डाक्टर बनकर शहर में ही काम करना चाहते हैं। आज शहरों में शफाखानों में जो भीड़ हो रही है उसका एक बड़ा कारण यह है। आपके देहात में जो व्यवस्था है वह इसलिए चरमरा रही है कि

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

अगर कर्मचारी की पोस्टिंग भी देहात में है तो वह किसी प्रभावशाली लोगों से मिल जाता है, तनख्वाह वहां से उठाता है और सेवा शहर में देता है। इस व्यवस्था पर जो भी सरकार में हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि इम्बैलेंस नहीं हो। आज यह समस्या है कि गांव के लोगबाग शहरों में आ रहे हैं, हास्पिटल के साथ-साथ अन्य व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

मैं सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनकी विशेषता यह है कि वे सत्ता में रहकर अपने विपक्ष के साथियों का पूरा ध्यान रखते हैं और जो आज एम.एल.ए. नहीं भी हैं और रहे हैं उनको भी इज्जत प्रदान करते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि जो छीपाबड़ौद में महाविद्यालय खोला गया प्रेमसिंह सिंघवी जी, जो पूर्व विधायक थे उनके नाम पर महाविद्यालय रखा। यह बहुत बड़ी बात है सत्ता में होते हुए। इसी प्रकार श्री गुरुशरण जी छाबड़ा के नाम, जो सूरतगढ़ का कालेज है, उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा और इस बात की घोषणा की। मैं उनको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

एक विषय कौशल विकास का उल्लेख किया गया है। आज केन्द्र सरकार कौशल विकास के चौथे साल की सालगिरह मना रही है। एक नया मंत्रालय खोला गया है, कौशल विकास, भारत सरकार एक करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कर रही है, हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। माननीय सभापति जी, कौशल विकास है कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? मगर अभी जो पुलिस की डिबेट रही थी उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कौशल विकास का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है, किसी की जेब काट लेना और किसी के गले में से चेन निकाल लेना, यह भी एक कौशल विकास का हिस्सा हो गया। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं सरकार कभी यह भी आंकड़ा इकट्ठा करवाये कि इस गलत काम में, गलत अपराध में कितने लोगबाग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? यह चिन्तन का विषय है। आज समाज में बढ़ती जनसंख्या के बैकग्राउंड में जब रोजगार नहीं मिलेगा और जो लोगबाग इस रास्ते पर उतर गये हैं, चीफ जस्टिस आफ इंडिया, गोगोई साहब ने जो बात कही है वह बात बिलकुल उनके ऊपर खरी उतरती है। उन्होंने कहा है कि आज कानून का भय बचा ही नहीं है। आप और हम जैसे, जिनका पाला नहीं पड़ा है, भला आदमी, वह जेल जाने से घबराता है। मगर जो जेल में जा रहा है, जेल सुधार

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

की बात की जा रही है, वह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां अपराधी जाते हैं और आपस में विचार-विमर्श करके, और गुण सीखकर आते हैं। इसको उस दृष्टि से भी आपको देखना पड़ेगा।

आज डाक्टर्स का कैम्प होता है जगह-जगह, इंजीनियर्स होते हैं, अलग-अलग प्रोफेशन के लोग अलग-अलग ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि जो लोग जुर्म से जुड़े हुए हैं कहीं हमारे जेल उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं हो गये? उन्हीं के जैसे लोग-बाग़ हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। चित्तौड़ में सरकारी व्यवस्था के रूप में मुझे जेल में एक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। मैंने अंदर बैरक में जो देखा, उसको देखकर मैं दंग रह गया। वह घटना, वह दृश्य मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकला है। मैंने देखा कि जो लोग उस बैरक में थे, वह हृष्ट-पुष्ट लोग थे। सड़क पर खड़ा हो जाऊं तो आधे घंटे बाद उनके जैसा तंदुरुस्त आदमी मुझे सड़क पर दिखे। कहीं कोई चिंता नहीं। इस प्रकार की हालत जब मैंने देखी तो मेरा माथा ठनका कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने इसलिए इस कौशल विकास की बात को अलग रूप से प्रस्तुत किया है। उसको मैं गौरवान्वित करने की बात नहीं कर रहा हूं।

हमारे प्रदेश में 10 तारीख को बजट पेश किया गया। 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस था। एक शब्द नहीं है जनसंख्या को रोकने के बारे में।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): भय नहीं है लोगों में।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, जनसंख्या वाला विस्फोट भयंकर है। पब्लिक में भय नहीं है। भय पैदा करो।

श्री सभापति: आप पर लागू नहीं होती यह बात। मुक्त हो इस समस्या से।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, जब पहली बार विधायक चुनकर आया था, उस समय प्रदेश की जनसंख्या 3 करोड़ से कुछ अधिक थी। आज वह 7 करोड़ के करीब है। हमारे प्रधान मंत्री जी जब प्रथम बार प्रधान मंत्री बने, तो लाल किले से बहुत लंबे समय तक सवा सौ करोड़, सवा सौ करोड़ कहते थे। द्वितीय चरण में वह 130 करोड़ की बात करने लगे।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

आज जो हमने बजट में घोषणाएं की हैं, नौकरियां दी हैं, पैरा नंबर 134 में नौकरी का उल्लेख है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 75 हजार नौकरियों की उन्होंने घोषणा की। आज सारे युवा सरकार की ओर नौकरियों के लिए देख रहे हैं। 75 हजार की आपने घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत्बहुत धन्यवाद दूंगा। मगर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 75 हजार क्यों, जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं, उन सब पदों को भरने की आवश्यकता है। यह जो हम इनको नौकरियां देते हैं, यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नहीं देखा जाए, यह मेरा कहना है।

सभापति महोदय, आपको यह भी देखना है कि हम शिक्षा विभाग में 21600 लोगों को नौकरियां देंगे। 21 हजार की जगह, जितनी भी वेकेंसीज हैं, आप उसको भर दीजिए। मगर आपको यह भी प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हम सारी वेकेंसीज भर दें, 6 लाख से ऊपर हमारे शिक्षक भाई हैं, शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर क्या है? इसका भी विचार करना पड़ेगा।

कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मैं आपको वन का उदाहरण दूंगा, वहां 1474 लोगों को नौकरियां देंगे। मगर वन विभाग वह है, जिसमें 30 प्रतिशत पद खाली हैं। जब आप वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो यह अवैध बजरी, अवैध खनन, पहाड़ के पहाड़ गायब कर लिए, पेड़ों की क्या बात करेंगे? जब पहाड़ गायब होंगे और पेड़ गायब होंगे तो उनके साथ वर्षा भी गायब होगी। वन विभाग में जो भर्तियां हैं, उसकी पूरी भर्तियां करें। वनों की रक्षा करने वाले रेंजर ही नहीं हैं। अगर किसी थाने में थानेदार नहीं है तो वह थाना कैसे चलेगा? वन खण्ड के अंदर रेंजर नहीं है, तो कौन संभालेगा उसको? इस ओर भी आपका ध्यान दिलाता हूं।

सभापति महोदय, 146 और 147 के ऊपर इस बजट में रणथम्भौर का उल्लेख किया गया है। गोडावण के संरक्षण की बात है। गोडावण के संरक्षण की बात है तो जैसलमेर से हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं। गोडावण तो हमारा स्टेट बर्ड है इसलिए हम उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। इनके यहां से अंडे लाएंगे और मेरे यहां जो बगल में क्षेत्र है, उसमें अंडों से चूजे बनाएंगे। नेक सोच है। मगर 2 साल से यह बात चल रही है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर यह हो रहा है कि जब बजट की बात आती है तो गोडावण आ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गोडावण ही नहीं, एक समय

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

था कि हम सारस क्रेन की बात कर रहे थे। यहां पर साइबेरियन क्रेन की बात करते थे। साइबेरियन क्रेन तो आनी बंद हो गयी। वह तो बाहर से आती थी। हमारा सारस पक्षी था इस राजस्थान में। आज उस सारस का दिखना बंद हो गया। ऐसे सैकड़ों हैं।

सभापति महोदय, रणथम्भौर की बात की। रणथम्भौर के गीत हम कब तक गाएंगे? आज राजस्थान में क्षमता है कि हम 5 रणथम्भौर खड़े कर सकते हैं। जब मैं रणथम्भौर खड़े करने की बात कर रहा हूं तो केवल जानवर बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। उससे टूयरिज्म बढ़ेगा। उससे नौकरियां बढ़ेंगी।

सभापति महोदय, जब पर्यटन का उल्लेख आया तो जयपुर की चारदीवारी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हैरिटेज साइट पर लेनी की बात कही गयी। जयपुर की सुन्दरता के जो प्रयास किये गये हैं, यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। उसके लिए तो सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जैसे आज कोटा का परकोटा है, वह बहुत भव्य परकोटा है। अगर हम जयपुर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं तो और जो सुन्दर परकोटे हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, ऐतिहासिक विरासत के रूप में 22 करोड़ रुपये दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किलों के संरक्षण की बात कही है, उसके लिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है।

सभापति महोदय, हम उद्योगों के विकास के लिए चाहते हैं कि उद्योग राजस्थान में विकसित हों, नए उद्योग आएं। मगर जो हमारे उद्योग लगे हुए हैं, उनके अनुकूल माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। पहले राजस्थान में जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। पिछली सरकार ने 2015 में जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, कोयले से जो कैप्टिव बिजली पैदा करते हैं, 40 पैसे इन पर टैक्स लगाया। इस बजट में उसको ढाई गुना बढ़ाकर 1 रुपया किया है। इससे इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं जब कैप्टिव प्लांट की बात कर रहा हूं तो वह इसलिए कर रहा हूं आप देखते होंगे प्रदेश के अंदर कि बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े-बड़े ट्रकों में भूसा भरकर ले जाते हैं। पहले सरसों का भूसा कोई खरीदता नहीं

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

था। उसको जलाना पड़ता था। यह खेती से जोड़कर मैं कैप्टिव पावर प्लांट की बात कर रहा हूं। आज वह किसानों का सारा भूसा बिकता है। वह भूसा ट्रांसपोर्ट होकर इन कैप्टिव पावर प्लांट में जाता है।

मैं तो चाहूंगा कि सरकार इस पर टैक्स लगाने की बजाय इनको और सुविधा दे कि सरसों का भूसा तो यह उपयोग कर रहे हैं, मगर जिन जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बड़ी मात्रा में जहां गेहूं पैदा होता है, उस गेहूं के भूसे का उपयोग नहीं हो पाता है।

किसानों के इस भूसे का उसी रूप में उपयोग कैप्टिव पावर प्लांट वाले करें, गेहूं का जो भूसा किसान आज जला रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, एक बात और रखूंगा। गोपालन विभाग हमने बनाया है, गौ की बात करते हैं। बजट में गोपालन और आवारा पशुओं का जिक्र किया गया है। मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने गाय के नाम पर टैक्स लगाया। गाय के बारे में हमारे यह है कि हमारे घरों में रोटी बनती थी तो एक रोटी गाय की निकालकर बच्चा गाय को देकर आता था। टैक्स लगाने की तकलीफ नहीं है। जब से यह टैक्स लगा है, 1 हजार करोड़ रुपया टैक्स के रूप में हम दे चुके हैं। शराब की बोतल पीने वाला भी टैक्स देता है गाय के नाम पर और जो रजिस्ट्री करवाता है वह भी टैक्स देता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण बात रखूंगा कि उस पैसे का उपयोग विवेकपूर्ण किया जाए जो गाय के नाम पर लिया हुआ है। मैं सदन में इसका रास्ता दिखाता हूं। कोटा में अभी दो साल से मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के 80 किलोमीटर एरिया को फैंसिंग किया गया है, शेरों को छोड़ने के लिए। उन्होंने उस 80 किलोमीटर की फैंसिंग करने में 30 करोड़ रुपये लगे, 80 किलोमीटर जंगल का क्षेत्र, केवल 30 करोड़ रुपये 80 किलोमीटर क्षेत्र की फैंसिंग की है। उसका मैंने अवलोकन किया, बहुत घास उग रही है। विचित्र बात तो यह है कि उसमें जानवर कम थे तो यहां जयपुर की सड़कों से आवारा सांड थे उनको भी पकड़कर वहां उस जंगल में छोड़ा गया। वह खूब चर रहे हैं। ऐसे जितने भी आवारा नर पशु हैं, 30 करोड़ में एक मुकन्दरा नेशनल पार्क जैसा ही अन्य पार्क खड़ा हो सकता है। आप कोटा के

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

अंदर ही 5 जंगल क्षेत्र को ऐसे फैंसिंग कर दीजिए। नगरपालिका के यहां तो 5 -6 गायें रोज मरती रहती हैं, उसमें जंगल बचेगा, उसमें आवारा जितने भी सांड हैं उनको छोड़िए, गायों को गौशाला में पालिए। ताकि दूध भी मिलेगा और आवारा पशु जंगल में जाएंगे तो वह बढ़ेंगे नहीं। यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि हम बजट बना करके और टैक्स लगाकर, कोरपोरेट जगत से सीएसआर का पैसा गाय के नाम पर ले लें, इस 1 हजार करोड़ रुपये का हिसाब तो दें, हम आपको योजना बता रहे हैं तो उसमें इसका उपयोग करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने समय काफी ले लिया, आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय सदन के नेता द्वारा 10 तारीख को रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट निश्चित रूप से किसी भी सरकार का आईना होता है, उसका विजन दिखता है कि सरकार किस दिशा में आगामी 5 वर्षों में काम करेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के पैरा नम्बर 4 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का उल्लेख किया, हम सब उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। उन्होंने यह कहते हुए आगे कहा कि राष्ट्रपिता बापू के सिद्धांतों पर अमल करते हुए उनके सपनों को साकार करना ही मेरी और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने बहुत थे। वह देश के किसान, गरीब वर्ग से जुड़े हुए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी चाहते थे कि इस देश में शराबबंदी हो और गरीब लोगों को इससे छुटकारा दिलाया जाए। चुनावी व्यस्तताओं के कारण हम कार्यक्रम नहीं कर पाए इसलिए इस शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम हम एक साल तक करना चाहते हैं, ऐसा भी उन्होंने उल्लेख किया, बजट पढ़ते समय उन्होंने कहा। गुरुशरण छाबड़ाजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो पूरे प्रदेश को शराब मुक्त कर दीजिए। उन्होंने शराबबंदी के लिए धरना दिया, भूख हड़ताल की, फिर उनकी मृत्यु हो गयी और आप यह बात सदन में कह रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छे उद्देश्य के कार्य किया था। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधीजी के सिद्धांतों पर हमारी सरकार चलना चाहती है और आप उनके नाम से सूरतगढ़

(श्रीमती अनिता भदेल)

में महाविद्यालय का नामकरण करना चाहते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परन्तु आप जिस बजट भाषण को महात्मा गांधीजी के नाम से शुरू कर रहे हैं, हां, 150वीं जयंती मना रहे हैं, जो चाहते थे गांधीजी कि शराबबंदी होनी चाहिए और आप उनके कार्यक्रमों को एक साल तक मनाना चाहते हैं तो मेरा सदन के नेता से निवेदन है कि आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो प्रायोगिक तौर पर ही सही कम से कम इस एक वर्ष में आप शराबबंदी करके देखिए कि इससे इस प्रदेश की स्थिति पर इसका क्या फर्क पड़ता है। तब यह माना जाएगा कि आप सच्चे अर्थों में महात्मा गांधीजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और आप सच्चे अर्थों में गुरुशरण छाबड़ाजी की जो मृत्यु हुई है जिस उद्देश्य को लेकर उनको भी आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आलरेडी इस महाविद्यालय का नाम उनके नाम से होना चाहिए, यह पहले से ही पाइप लाइन में था, आपने ठप्पा लगाकर बजट भाषण में इसका उल्लेख कर दिया। सिर्फ बातों से श्रद्धांजलि नहीं होती है, कर्मों से होती है। उनके द्वारा बताए गये मार्गों पर चलने से होती है। अच्छे-अच्छे भाषण तो कोई भी लिखकर दे देगा, आप पढ़ दीजिए, इससे इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपसे यह निवेदन कर रही हूं, सरकार से निवेदन कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मुझे पिछली बार अनुभव मिला था, महिला और बाल विकास विभाग में काम करने का, आपने इस बजट में बहुत ही चालाकी से, बहुत शार्पनेस के साथ, मैं आरोप लगा रही हूं, मैं तारीख के साथ में इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं। 12 सितम्बर, 2018, देश के माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो मानदेय कर्मी हैं, केवल राजस्थान के ही नहीं, पूरे देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो मानदेय कर्मी हैं, उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की है। बढ़ोतरी होने से जो राजस्थान प्रदेश की मानदेय कर्मियों की बढ़ोत्तरी हुई वह 6000 से 7500 रुपये हुई। यह बात 11 सितम्बर, 2018 की है। यह मानदेय, उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही कि 1 अक्टूबर से ही लागू होगा, कोई नये वित्तीय वर्ष से लागू करने की बात नहीं की। यह नहीं कहा कि हम घोषणा कर रहे हैं कि 5 साल में लागू करेंगे, 5 साल हैं हमारे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जिस दिन घोषणा की उसी दिन उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर, 2018 से लागू होगा लेकिन फाइनेंस की स्वीकृति नहीं निकली, आचार संहिता

(श्रीमती अनिता भदेल)

आ गयी और चुनाव हो गये। चुनाव के बाद में फाइनेंस की स्वीकृति निकली है 10 मार्च, 2019 को। अब 10 मार्च, 2019 को जिस बढ़े हुए मानदेय की फाइनेंशियल स्वीकृति निकल गयी हो, आप उसको बजट में कैसे रख सकते हैं? न केवल निकली, सरकार के अधिकारी ने उसको ट्वीट करके कहा कि हमने मानदेय बढ़ा दिया। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं उस तारीख को भी बता देती हूं, 10 तारीख का यह ट्वीट है। जब मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैंने कहा कि मैडम, यह आपके कार्यकाल का नहीं है। आपने तो 3 महीने इसको डिले कर दिया है, आप देंगी कब तक, आपने अभी तक तो फाइनेंशियली स्वीकृति ही निकाली है। तो उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन प्रदेश की 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मी, वह श्राप देंगी सरकार को, सही बता रही हूं। उनके श्राप से कोई बचने वाला नहीं है। बजट भाषण में यह बात लिखनी है इसलिए यह 10 महीने तक उनके मानदेय को रोककर रखना, बढ़े हुए मानदेय को रोककर रखना, यह कहां का न्याय है, कौनसा न्याय है? सदन के नेता क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? समझ नहीं आता मुझे तो। दस महीने में से सात महीने तो आपके थे। आज जुलाई है न। इसे बजट भाषण में रखा क्यों?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखकर बात करें आप। माननीय अनिता जी भदेल, इधर देखकर बात करें। संवाद न करें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अगर बजट भाषण में रखा तो उल्लेख करते कि देश के प्रधान मंत्री जी की घोषणा के अनुसार मैं उल्लेख कर रहा हूं। स्पष्ट करते न, तब तो मंशा जाहिर होती कि आपकी मंशा साफ है, लेकिन आपकी मंशा साफ नहीं है, इसलिए आपने इसका उल्लेख नहीं किया और दस महीने तक उनके मानदेय को रोके रखा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जो दस महीने का मानदेय आपने रोककर रखा है, क्या आप उस पर ब्याज देंगे? जिन कर्मचारियों को बहुत कम मानदेय मिलता है, उनका भी मानदेय आप रोककर बैठ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे? अभी कुन्दनपुर से आने वाले माननीय सदस्य 75 हजार नौकरियों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौकरियां लगनी चाहिए, होनी चाहिए, अच्छी बात है, परन्तु ये

(श्रीमती अनिता भदेल)

नौकरियां उन्हीं नौकरियों के आंकड़े के साथ फिट क्यों हो रही हैं पिछली सरकार ने जिनके विज्ञापन जारी कर दिये।

आप नौकरियां देना चाहते हैं तो फिर जो बात उन्होंने कही है, मैं भी उसका समर्थन करती हूं। तो जितने पद खाली हैं, उन सभी पदों पर विज्ञापन निकालिए न। 2008 से 2013 के बीच आपकी सरकार के कार्यकाल को मैंने बहुत अच्छे से देखा है और आरपीएससी में क्या-क्या घपले-घोटाले हुए, जिनके लिए एक साल तक हमारी सरकार को भी संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद में हम आरपीएससी को पटरी पर लेकर आए, तब जाकर यह सम्भव हुआ, नहीं तो यह सम्भव नहीं था। अपनी कार्य प्रणाली को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से आउटपुट दे पाएंगे और इस प्रदेश को आगे लेकर जा सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सदस्यों द्वारा मैंने सुना, बहुत एप्रिशिएट किया सत्ता पक्ष के लोगों ने कि 21 हजार रुपये की सहायता हम देंगे 'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना' में। अच्छी बात है। बीपीएल परिवारों की विधवाओं को यह देनी भी चाहिए, पर आपने क्या किया? यह कोई नयी योजना नहीं है, यह पुरानी योजना है। बीपीएल योजना में बीपीएल परिवारों की विधवाओं की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में पैसा दिया जाता है, यह पुरानी व्यवस्था है, पुरानी योजना है। आपने तो उलटा उसे घटा दिया। कैसे घटाया है, मैं बताती हूं।

यह प्रक्रिया में था कि अभी बीपीएल परिवार की विधवा की दसवीं पास बच्ची है तो उसे 10 हजार रुपये मिलेंगे, बारहवीं पास बच्ची है तो उसे 20-21 हजार रुपये मिलेंगे और यदि वह ग्रेजुएट है तो उसको 35 हजार रुपये मिलेंगे। आपने तो ये तीनों स्लैब खतम करके सिर्फ 21 हजार रुपये पर लाकर टिका दिया और अपने नाम से घोषणा कर दी। शर्म की बात है यह। बीपीएल में एससी, एसटी भी आते हैं, जनरल भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, सब आते हैं। सिर्फ बीपीएल लिखने से भी काम चल सकता था, परन्तु स्पेशली दर्शाया गया कि हम इन सब वर्गों के लिए करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आपने तो उलटा उनके स्लैब को घटाकर सबको 21 हजार की एक कैटेगरी में ला दिया।

इसका मतलब बीपीएल परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाएं या न पढ़ाएं, कोई इंसेंटिव उन्हें मिलने वाला नहीं है। इससे तो बेटियां पढ़ने के लिए

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्रोत्साहित हो रही थीं कि चलो ज्यादा पढ़ाएंगे तो इसके कन्यादान के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और अपना नाम लिख दिया 'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना'। यह सदन के रिकार्ड में है कि यह योजना चल रही है, इसलिए आप इसे बरगलाने की कोशिश न करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे दो-तीन निवेदन और करना चाहती हूं। एक निवेदन है चिकित्सा के बारे में। आपने जनता क्लीनिक खोलने की बात कही है। केजरीवाल जी के दिल्ली की तर्ज पर जनता क्लीनिक खोलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रदेश में जितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, शहरी क्षेत्रों में जितनी डिस्पेंसरीज हैं, जितने हास्पिटल हैं, सैटेलाइट हास्पिटल हैं, वे सब हास्पिटल पदों की रिक्ति के कारण से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। हर सरकार मेडिकल डिपार्टमेंट में भर्ती करती है, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। कभी कोर्ट का स्टे हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आये दिन विधान सभा में सदस्य कहते रहते हैं, मेरी फलां पीएचसी खाली पड़ी है, मेरी फलां सीएचसी पूरी खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में मुझे बताएं कि जो पहले से प्रदेश में संचालित अस्पताल हैं, उनमें तो आप स्टाफ पूरा लगा नहीं पा रहे हैं तो ये जो जनता क्लीनिक हैं, मोहल्ला क्लीनिक हैं, उनके लिए आप स्टाफ लाएंगे कहां से?

क्या आप जनता का इलाज झोलाछाप डाक्टरों से कराना चाहते हैं? मुझे अपने इस प्रश्न का जवाब माननीय सदन के नेता से चाहिए, जब वे रिप्लाई दें, तब। दूसरी बात, इस प्रदेश में पहले से भामाशाह योजना चल रही थी, चिकित्सा मंत्री जी तब तक चिकित्सा मंत्री जी नहीं बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इस भामाशाह कार्ड को फाड़कर फेंक दूंगा। अभी भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही इलाज चल रहा है। वे अपने वादे से मुकर गये। उन्हें पता है कि यह बहुत अच्छी योजना है।

देखिए, गांवों में हम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमने सीएचसी खोले, पीएचसी खोले, लेकिन स्टाफ उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हम किसी तरह से येन-केन प्रकारेण स्टाफ लगाते भी हैं तो वे अपनी एप्रोच लगाकर शहरों में आकर बैठ जाते हैं। यह भामाशाह योजना उन निजी चिकित्सालयों में भी संचालित थी और इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि वे निजी चिकित्सक जो गांवों में अपनी सेवाएं देना चाहते थे, उन्होंने अपने

(श्रीमती अनिता भदेल)

अस्पताल गांवों में भी खोलना शुरू कर दिये और ग्रामीण लोगों को भी इन चिकित्सालयों का लाभ मिलने लगा, चिकित्सा सेवाएं मिलने लगीं।

उन्हें चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए, चाहे निजी तौर पर मिले, चाहे सरकारी तौर पर मिले, उन्हें डाक्टर मिलने चाहिए और भामाशाह योजना में उसका लाभ भी मिल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे भामाशाह योजना को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी के आयुष्मान भारत का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जब केन्द्र सरकार हमें लाभ दे रही है, आपने अपनी बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया, जो-जो आप करना चाहते हैं और उनका घुमा-फिराकर के अपना कुछ उल्लेख किया, पर आयुष्मान भारत का उल्लेख नहीं किया, जबकि आपने सदन के बाहर यह कहा है कि हम इस योजना को लागू करेंगे।

सदन के नेता सदन में यह बताते कि कैसे लागू करेंगे, कब लागू करेंगे, कितने लोग इसमें लाभान्वित होंगे, पर यह बात गोल कर गये। क्या प्रदेश के मरीज आपके नागरिक नहीं हैं? इस योजना का लाभ उन्हें क्यों नहीं दिलाना चाहते हैं?

श्री सभापति: दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रथम वक्ता हूं और मुझे आप समय दीजिए। उन्होंने बीस मिनट बोला है।

श्री सभापति: प्रथम वक्ता हैं, पर आप पंद्रह मिनट बोल रही हैं, दो मिनट और बोलने के बाद आपके पंद्रह मिनट हो जाएंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं कोई गलत बात तो बोल नहीं रही हूं। मैं कोई गलत तथ्य रख नहीं रही हूं।

श्री सभापति: आप विराजें एक बार। जो समय आबंटन हुआ है, उसके हिसाब से 6 घंटे और 13 मिनट कल तक आप बोल चुके हैं और आज जो आपको समय आबंटित हुआ था, उसमें समय निल है। इसके बावजूद भी अगर आप दो मिनट और बोलेंगीं तो पंद्रह मिनट बोलेंगी, मेहरबानी करके आप अपनी बात अब समाप्त करें दो मिनट बाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, प्रथम वक्ता हैं।

श्री सभापति: पंद्रह मिनट बुलवा रहा हूं। बाकी सब कोई पंद्रह मिनट नहीं बोलेंगे। समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी किसानों की बात पर, मैं निवेदन कर रही थी चिकित्सा की बात पर। चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एसएमएस अस्पताल में संसाधन आने चाहिए, यूनिट्स आनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हो कि हम एसएमएस अस्पताल को ही पूरे प्रदेश का अस्पताल मान लें, क्योंकि जो भी नयी चीजें आती हैं, वे एसएमएस अस्पताल में आती हैं, लेकिन प्रदेश के बाकी मेडिकल कालेजों में सुविधाओं का, मशीनरी का अभाव है। नये-नये चिकित्सकों का, विशेषज्ञों का अभाव है। यदि हम एसएमएस अस्पताल के बर्डन को कम करना चाहते हैं तो बाकी के जो मेडिकल कालेज हैं, उनमें भी आप सुविधाओं का विस्तार करें, तभी हम इस प्रदेश में अच्छे से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, कौशल विकास और रोजगार की बात सरकार ने कही है और कहा है कि हम युवाओं को रोजगार के लिए एक लाख रुपये तक का ऋण देंगे। अब आप देखिए, आपने बेरोजगारी भत्ते की बात कही कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ते में भी आपने महिला और पुरुष में लिंग भेद कर दिया। एक तरफ तो यह चल रहा है कि महिलाओं और पुरुषों में लिंग भेद नहीं होना चाहिए, बच्चों में लिंग भेद नहीं होना चाहिए, हम बेटियों को बढ़ाना चाहते हैं। क्या बेरोजगार लड़की बराबर की हिस्सेदार नहीं है बेरोजगारी भत्ते के लिए? बताइये मुझे।

आप क्या संदेश देना चाहते हैं, महिलाओं को कम क्यों आंकना चाहते हैं आप? आप दोनों का भत्ता बराबर करिए और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के युवाओं को लगेगा कि हां, कांग्रेस ने जो वादा किया, उसे पूरा किया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रही हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इन्होंने बात कही है कि हम जीरो ब्याज पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराएंगे।

(15.00 बजे)

अब जीरो ब्याज पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुझे बताइयेगा कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कितना ऋण किसानों को उपलब्ध कराया है और यह आप बताएंगे तो पूरे प्रदेश को पता पड़ेगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अंत में, मैं अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचार और इस प्रदेश में बढ़ने वाले जितने भी अपराध हैं उनके बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जो अवैध खनन बजरी का हो रहा है, रोज अख़बार में आप पढ़ते होंगे कि बजरी का अवैध खनन करके ट्रक इतनी तेजी से दौड़ाते हुए लेकर जाते हैं कि रास्ते में कोई भी मरे उनको उससे कोई लेना-देना नहीं है। इस खनन से जुड़े हुए चारों विभागों के कर्मचारी इतने संलिप्त हैं कि आज एक गरीब व्यक्ति को घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो बजरी कभी 700-800 रुपये में आती है वह आज 3-4 हजार रुपये में आ रही है, उसका बजट बिगड़ चुका है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो मुझे बतायें कि जिस बात के लिए आप सदन के बाहर बहुत बड़ेबड़े वक्तव्य देते थे, मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य मैं कल टी.वी. पर देख रही थी, जो उस समय उन्होंने बजरी के लिए दिया था कि हम आएंगे तो चुटकियों में इसकी समस्या का हल करेंगे। दस महीने बाद भी उनकी चुटकी गयी कहां? कहां गयी उनकी चुटकी? अभी तक उन्होंने समाधान क्यों नहीं किया इस बजरी का?

श्री सभापति: श्री खुशवीर सिंह।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं वे इतने खतरनाक हैं कि जो स्थिति पहले थी वही स्थिति में आप प्रदेश को लाना चाहते हो क्या सुरक्षा की दृष्टि से?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री खुशवीर सिंह।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए। प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए आप। विराजिए, सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। थोड़ा बहुत अनुशासन तो रखें। जब आपको कह दिया है कि अंकित नहीं हो रहा है तो समाप्त करना चाहिए। श्री खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। मुझे बोलने के लिए आपने अनुमति दी उसके लिए धन्यवाद दूं, उससे पहले मेरे मारवाड़ की उस जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी बदौलत मैं आज इस विधान सभा के प्रांगण में उपस्थित हूं।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन हर दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सभापति महोदय, मैंने चुनाव से पूर्व एक संकल्प लिया था कि राजस्थान की विधान सभा में अगर मैं पहुंचा तो इस जनता के लिए मेरे दायित्व का निर्वहन करूंगा और विशेषकर जल के लिए। सभापति महोदय, मैंने 30 सितम्बर, 2018 को हर पांच वर्ष की भांति उस दिन को भी एक जल मेले का आयोजन किया था। वह इतना विशाल जल मेला हुआ था। जब शुरू-शुरू में मैंने जल मेले का आयोजन किया तो लोग पूछने लगे कि हमने पहली बार सुना है, जल मेला होता क्या है। दूसरे मेले, धार्मिक मेले बहुत होते हैं लेकिन जल मेला 35 हजार लोगों की साक्षी में हुआ। सभापति महोदय, मैंने कलश पूजन किया था और पांच नदियों का पानी मंगाया था। ब्रह्मपुत्र से भी मैंने पानी मंगवाया था और पांच नदियों के जल को एकत्र कर 35 हजार लोगों के सामने हमने संकल्प लिया था कि हम पांनी को बचाएंगे। आज हमें जरूरत है इस देश में नदियों को जोड़ने की। एक मैंने संदेश दिया था और उन 35 हजार लोगों ने संकल्प के साथ में, जब उनके दिल में यह बात आई कि इससे पवित्र काम कोई इस धरती मां के लिए हो नहीं सकता है और उनकी बदौलत मैं आज इस विधान सभा में हूं।

सभापति महोदय, चुनाव के दौरान कई गांवों ने मुझे गोद लिया। मुझे कहने लगे कि आप हमें गोद ले लो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी गांवों को गोद ले रही है। मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है। राम भी गांवों को गोद नहीं ले पाये तो मैं कैसे लूंगा इसलिए आप मुझे गोद ले लो। सभापति महोदय, 57 गांवों ने मुझे गोद लिया है। वहां 57 गांवों ने मुझे गोद लिया और रिजल्ट अगर आप देखें तो एकतरफा रिजल्ट रहा जिन्होंने मुझे गोद लिया है। हमारी हैसियत नहीं है कि सांसद की तरह भगवान राम से भी बढ़कर, राम भी अयोध्या को गोद नहीं ले पाये, सभापति महोदय। उन्होंने गोद

(श्री खुशवीरसिंह)

लिया उन गांवों की क्या हालत है? मेरे पाली जिले की अगर बात कर दूं तो सांसद महोदय ने बूसी गांव को गोद लिया और वहां जाकर देखिये किस तरह के हालात हैं, बद से बदतर हालात उस गांव के हैं। सभापति महोदय, नाम और घोषणाएं होने से कुछ नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, हाल ही में जून माह में 11 जून को चित्तौड़ जिले के पास में बादल फटने से एक ऐसी घटना हो गयी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के हजारों पशु वहां थे, पशुपालक अपने मवेशियों को लेकर मध्यप्रदेश से वापस पलायन करते हुए आ रहे थे तब 800 भेड़ों की डूबने से मौत हो गयी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर मुख्य मंत्री महोदय को कि 48 घण्टे के अन्दर उन्होंने उन पशुपालकों को एक-एक भेड़ के 6-6 हजार रुपये इतिहास में पहली बार मुख्य मंत्री जी ने दिये। 800 पशुओं के 48 लाख रुपये 48 घण्टे में दिये। मैं जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, चित्तौड़ को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तत्परता के साथ रात-दिन एक करके काम किया और मुख्य मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सभी ने चर्चा की कि मुख्य मंत्री जी के विचारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, वे गांधीवादी विचारों से जाने जाते हैं, मुख्य मंत्री जी मारवाड़ के गांधी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने गांधी से ओत-प्रोत विचारों से बजट रखा है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बजट में कमी निकालकर प्रस्तुत करना, यह विपक्ष का काम है। लेकिन, मैं कहना चाहूंगा गांधीजी ने दांडी मार्च के वक्त 1930 में पहली बार स्वराज और रामराज्य का एक लेख लिखा था और उसी को मुख्य मंत्री जी ने ध्यान में रखते रामराज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी उस कल्पना को साकार करने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने करके दिखाया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा राम जी वनवास जा रहे थे और जब भगवान राम और भरत, दोनों भाइयों के बीच में वार्तालाप हुआ कि शासन व्यवस्था कैसी होगी, किस तरह आप टैक्स लेंगे, भरत आप कैसे चलाएंगे इस राज्य को, मैं तो वनवास में हूं। तो भरत जी ने यह कहा और उस बात को तुलसी जी ने अपने शब्दों में कहा है वह मैं कहना चाहूंगा -

'बरसत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोई,

(श्री खुशवीरसिंह)

तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु स होई।'

भूप कैसा होना चाहिए, इसे मुख्य मंत्री ने करके दिया सभापति महोदय।

सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्री महोदय ने किस तरह से टैक्स लिया जाता है उसकी भगवान राम ने कल्पना की थी जिस तरह सूर्य समुद्र से पानी लेता है वह पता ही नहीं चलता है और वह पानी कहां बरसाता है। आज तो अकाल की स्थिति है, जरूरतमन्द लोगों को दिया जाता है। जिस तरह मुख्य मंत्री जी ने गरीब के लिए नि:शुल्क जांच, आज किसान के लिए जो बजट दिया है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सड़क, ऊर्जा, पानी, युवाओं के लिए रोजगार और गरीब के लिए नि:शुल्क तीर्थयात्रा कराने का काम किया है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। मुख्य मंत्री जी ने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, कभी धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगे। हर बुजुर्ग की एक अंतिम इच्छा होती है कि मेरा सपूत बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करा दे और पशुपतिनाथ तक करा दे, इस देश से उस देश तक करा दे।

विदेश में किसी ने कल्पना नहीं की थी और वह सपूत बेटा, माननीय अशोक गहलोत है। जिन्होंने करके दिखाया वह काम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, भगवान राम से ओत-प्रोत बजट है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बात चली टैक्स लेने की और रामराज में किस तरह टैक्स लिया जाता था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा-

मणि, माणिक महंगे किये,

सहजे तृण, जल, नाज!

तुलसी सोई जानिये, राम 'गरीबनवाज़'!!

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो किया है। मणि, माणिक महंगे किये, सहजे तृण, जल, नाज। सभापति महोदय, आज पानी पर पैसा माफ किया मुख्य मंत्री जी ने। आज गायों के लिए, जिनके नाम पर कभी राजनीति नहीं की, कभी उनके नाम पर वोट नहीं मांगा, उनके लिए नंदीशाला की बात कही है। आज नि:शुल्क खाद्य सुरक्षा के तहत नि:शुल्क अनाज की व्यवस्था की है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मणि-माणिक महंगे, मैं इसके ऊपर कहना चाहूंगा

(श्री खुशवीरसिंह)

कि केन्द्र सरकार ने पैट्रोल-गैस-डीजल तो महंगे कर दिये और जो गरीब के जरूरत की चीज थी और जो महंगे करने थे, मणि-माणिक महंगे करने थे, उन मणि-माणिक मालिकों के लिए एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये माफ कर दिये और कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक लाख रुपये किसानों के माफ किये थे, उस वक्त में।

सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा आपसे आज जब हम गौ माता की बात करते हैं, कभी मैंने यह नहीं सुना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से गाय के नाम पर राजनीति की हो। पार्टी से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे, किसी पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं दलगत राजनति से ऊपर उठकर बात करूंगा गाय पर। सभापति महोदय, हम सभी गाय का नाम लेते हैं। आज गाय की ऐसी स्थिति क्यों हुई है? इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, गाय को गौ माता हम कहते हैं। उसके पीछे हमारा कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा हुआ था। आज से 100 वर्ष पीछे अगर हम चले जाएं, तो उस वक्त गाय की उपयोगिता थी। आवागमन, परिवहन, हमारी खेती, हर चीज, हम डिपेंड गाय पर थे। घर में बेटा होता, उससे खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा बछड़ा होता, उस वक्त खुशी होती थी। क्योंकि, मालूम है बेटा तो बड़ा होकर सपूत होगा या नहीं होगा, लेकिन जब नकेल डाल दी जाएगी उस बैल के तो वह निश्चित रूप से सपूत बेटे की तरह हमें कमाकर देगा। इसलिए हमें बहु-उपयोगिता थी गाय की, लेकिन शनैः शनैः जब मशीन का आविष्कार हो गया, तब से गाय की उपयोगिता समाप्त हो गयी। 60 के दशक में हमने कल्पना की थी उन्नत कृषि और उन्नत कृषि के चक्कर में हम लेकर आ गये नागौर नस्ल के बैल, वे कड़ाई में और जुताई में बहुत मजबूत थे।

सभापति महोदय, लेकिन वह दुधारू नस्ल नहीं थी। हमारी थारपारकर नस्ल थी, राजस्थान की सहिवाल जो थी, उस तरफ की पंजाब की, आज उसकी उपयोगिता खतम होने से हमारी जो गायों की ब्रीड है, वह डी-ग्रेड हो गयी है। नस्ल परिवर्तन होने से जो दुधारू नस्ल की गायें थीं, वे आज आधा किलो और पाव दूध देती हैं।

हम राजनीति तो सब कर लेंगे गाय पर, लेकिन जब वह घाटे का

(श्री खुशवीरसिंह)

सौदा है, उसको हम रखेंगे नहीं। आज हमारी गायों की किस तरह से हालत हो रही है। एक-एक गाय जब मरती है। मैंने जाकर देखा है, मेरे पास वीडियो है, फोटोग्राफी है एक-एक गाय के पेट में 40-40 किलो तक पॉलीथिन निकलती है। गांवों के अंदर जब हम गौ माता की बात करते हैं, राजनीति तो सभी कर लेंगे गाय पर, लेकिन गाय हमारे गांव के अंदर गंदगी खाती है, घूमती है, उस वक्त हम कोई नहीं देखेंगे।

इसलिए सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नन्दीशाला अलग करने की बात कही है। आगे बढ़कर हमें काम करना होगा और उसके लिए एक ही समाधान है, नस्ल परिवर्तन। गिर नस्ल गाय आज अमेरिका में जाकर, साउथ अमेरिका, ब्राजील में जाकर 40 लीटर दूध दे सकती है तो उस गिर नस्ल को हम क्यों नहीं हमारे यहां एडोप्ट करें। मेरे गांव जोजावर में अमित विक्रम है एक लड़का, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रामवासियों ने मिलकर कहा गौशाला खोलने की जरूरत नहीं, कितनी गौशालाएं खोलेंगे? किस हद तक हम गौशाला खोलकर गाय को बेचारी कहेंगे। आज गाय हमारे ऊपर क्यों आश्रित है, गाय को वाइबल यूनिट बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम नस्ल परिवर्तन करके, गिर नस्ल को बढ़ावा देंगे और उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने इसमें भी एक प्रोग्राम रखा है। मैं कहना चाहूंगा..

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, शुरू ही हुआ है। बड़ी मुश्किल से जीतकर आए हैं। जीवन का अंतिम कहकर आया और यहां पर भी काट देंगे, वहां तो कट गये, लेकिन यहां भी काट देंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमें।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गोपालन विभाग बनाया है, उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा। एक नई कोख परिवर्तन की जो टैक्नोलॉजी है, वह हम एडोप्ट करना चाह रहे हैं। हमारे जोजावर गांव से उसकी शुरूआत करना चाह रहे हैं और वह है एम्ब्रियो ट्रांसफर टैक्नोलोजी, कोख परिवर्तन। यह आज का नहीं है सभापति महोदय, 25 सौ वर्ष पुराना महावीर स्वामी से कोख परिवर्तन हुआ, उस वक्त से आज हम लेकर आये हैं। यह हमारा 25 सौ वर्ष पुराना है और उसके तहत सेरोगेट मदर किसी भी जाति की, किसी भी ब्रीड

(श्री खुशवीरसिंह)

की, जो गाय होगी उसको सेरोगेट मदर बनाकर शत प्रतिशत उसका लाभ मिलेगा और जब हो जाएगा उसके अंदर नई टैक्नोलोजी है, 98 परसेन्ट तक बछड़ियां होती हैं।

आज हमे जरूरत है मात्र और मात्र दुधारू नस्ल की गाय की। सभापति महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको और बढ़ावा दिया जाए। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय जल के बदौलत मैं यहां सदन में आया हूं। उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा आज रीयूज आफ वाटर, मिसयूज आफ वाटर इन दो चीज पर हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि हम पानी का सदुपयोग किस तरह कर सकें। री-यूज पानी का कैसे करें और पानी का दुरुपयोग हम कैसे रोक सकते हैं? अकाल की स्थिति है और 7 दिन का तो हमें मौसम विभाग ने आंकड़ा दे दिया कि सात दिन तक तो बारिश के आसार नजर नहीं है। हमारी जो टैक्नोलोजी थी हजारों वर्ष पुरानी, नेफोलोजी जो कहते हैं, वे लोग छह महीने पहले सटीक विश्लेषण दे देते थे। विज्ञान और ज्ञान पर आधारित पर हमारा जो ज्ञान था। वह विलुप्त हो गया है।

सभापति महोदय, मैं कल अख़बार पढ़ रहा था, जयपुर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है 55 करोड़ लीटर रोज का और 25 करोड़ लीटर सिंचाई के लिए सप्लाई हो रहा है। सभापति महोदय, 30 करोड़ लीटर पानी सीवरेज का जा रहा है बहकर, मेरा आपसे अनुरोध है 30 करोड़ लीटर पानी और 25 करोड़ जो सिंचाई के लिए हो रहा है बाग़-बगीचों के लिए, वह पानी अगर वहां भेज दिया जाए तो रोज के 25 करोड़ लीटर पानी को आप कल से जयपुर में रोक सकते हो। प्रदेश में इस तरह से अगर आप देखो तो इस अकाल की स्थिति में सब चीजें भूलकर, मात्र इस पर हमें विचार करना होगा। माननीय सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे। सभापति महोदय...

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें, माननीय सदस्य। नहीं, सहयोग करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने पेंशन योजना लागू की है। सभापति महोदय, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, 2

(श्री खुशवीरसिंह)

मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। वह बात किसी ने नहीं कही है। सभापति महोदय, किसान के लिए मुख्य मंत्रीजी ने वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, ये चर्चा मेरे खयाल से मैंने नहीं सुनी है। उन्होंने 56 वर्ष के आयु के किसान को साढ़े सात सौ रुपये पेंशन की घोषणा की है और केन्द्र सरकार ने 6 हजार रुपये दिये एक किसान के लिए साल के, अरबों रुपये उसके एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो गये। जितनी राशि अलाट हुई है, एडवर्टाइजमेंट में उससे ज्यादा पैसे खर्च हो गये और 800 रुपये प्रति माह प्रत्येक किसान को, मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ लाख रुपये के जो ऋण....

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री जे.पी. चंदेलिया। समाप्त करें माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग मैं रखूं। प्लीज अंतिम मांग, सभापति महोदय मेरे उपखण्ड कार्यालय रानी है, मैं चाहूंगा कि वहां..

श्री सभापति: लिखकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दें, अपना। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मुंसिफ कोर्ट खोला जाए। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, एक मिनट, राज्य राजमार्ग 61 और 62 जो स्वीकृत हो चुके थे गहलोत सरकार में, पिछली सरकार ने रिव्यू के नाम पर बंद कर दिये, उन्हें भी पुन: स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने 2019-20 के परिवर्तित बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अधिकारी दीर्घा में लगभग 38 साल बैठने के बाद इस मुख्य सदन में आकर बोलने का मौका दिया तो बहुत-बहुत धन्यवाद पिलानी विधान सभा क्षेत्र की जनता को और वोटर्स को। जो बजट 10 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में प्रस्तुत किया वह बजट आमजन का बजट है। राज्य के हर व्यक्ति का बजट है। महिला का बजट है। पुरुष का बजट है। गरीब का बजट है। एससी का बजट है। एसटी का बजट है। ओबीसी का बजट है। सामान्यजन का बजट है। वह मीडिया जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की खबर छापने की जहमत नहीं उठाता था उसने 11 तारीख के हर अख़बार में

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी का विजन और हौंसला जो उन्होंने बजट प्रस्तुत करने से पहले जुटाया है, क्योंकि जो परिस्थिति मिली है राज्य की कांग्रेस को बजट प्रस्तुत करने से पहले विरासत में वह बड़ी विकट स्थिति थी। आर्थिक दृष्टि से जो राज्य की स्थिति मिली है कांग्रेस को शासन के समय, माननीय मुख्यमंत्री जी का हौसला यह बजट प्रस्तुत करते हुए बिलकुल दृष्टिगत होता है। गांधीयन फिलोसफी के साथ यह बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। एक विहंगम दृष्टि अगर हम प्री -कंडीशन को देखें तो कैसे हमें विरासत मिली वर्तमान सरकार को तो, माननीय सभापति महोदय, किसी भी अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए हमें तीन-चार इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं कि स्थिर मूल्यों पर वार्षिक औसत आर्थिक दर क्या है। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, राज्य में कुल ऋण भार और दायित्व कितना है, यह सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ताकि उसकी जो इकोनोमिक हैल्थ है उसका आकलन हो सके। अगर आप स्थिर मूल्य पर देखें, स्थिर मूल्य मैं 1965 से ले रहा हूं, ताकि किसी के प्रति बायस्ड नहीं बिलकुल न्यूट्रल असैसमेंट है। 1965 के अगर स्थिर मूल्यों को लें तो वार्षिक औसत आर्थिक दर 2008-09 से 2013-14 में जो कांग्रेस ने छोड़ी थी वह 8.16 थी और 2013-14 के बाद 2017-18 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित सरकार ने छोड़ी है वह थी 7.19 गिरावट, सिग्निफिकेंट गिरावट। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को अगर अपन देखें तो 2013-14 में जो आय कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी थी वह 14.95 परसेंट और जो हमें मिली इस शासन में आते वक्त वह थी 9.66 परसेंट, उसमें भारी गिरावट। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को अगर अपन देखें तो जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा था तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर थी 8.94 परसेंट और जब लिया इस बार तो वह थी 3.95 ओनली। यानी खेती पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है आंकड़े बोलते हैं किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं। किसी प्रकार की कृषि को कोई प्रायोरिटी नहीं। किसी प्रकार की खेतीहर मजदूर और कृषक को कोई प्रायोरिटी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, ऋण भार और दायित्व का बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है। जब हमने सरकार छोड़ी 2013-14 में तो 1 लाख 29

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

हजार 910 करोड़ का ऋण भार और दायित्व था और जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो 3 लाख 8 हजार 34 करोड़, थ्री टाइम्स। आर्थिक स्थिति जो राज्य की थी वह बहुत कमजोर थी। उस स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह शासन संभाला है। उनकी टीम ने यह शासन संभाला है। इसलिए पहले पेज पर जो मेरे सामने विराजमान मेरे साथीगण हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्ष के, उन्होंने जो टिप्पणी की थी पहले शेर पर,

'यकीन से आगे भी बढ़ना है,
बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है,
वे हवाओं की ओट में दीप जलाते हैं,
हम तो तूफानों से टकरा कर कारवां चलाते हैं।'

बिलकुल सत्य बात है संकल्प झलकता है माननीय मुख्य मंत्री महोदय का कि हमें इस राज्य को बहुत आगे ले जाना है और यह भी झलकता है कि परिस्थिति उनके सामने इतनी विकट नहीं थी। क्योंकि एक बहुत अच्छी विरासत कांग्रेस से उनको जब ये राज में आये थे तब मिली थी। इसलिए पांच साल का इनका काम भी चल गया। लेकिन 3 लाख 8 हजार 34 करोड़ का ऋण और दायित्व भार छोड़कर गये हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इतना शानदार बजट दिया तो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं आधा मिनट के अन्दर बताता हूं क्या स्थिति थी जब आपने यह शासन संभाला है। पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। बीएसएनएल के 54 हजार व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनका रोजगार खतरे में है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के पास आज सैलेरी देने को पैसे नहीं हैं। भारत सरकार का उपक्रम है। डाक विभाग का घाटा 15 हजार करोड़ रुपये का है, पोस्टल डिपार्टमेंट का घाटा। यह भारत सरकार की स्थिति को प्रकट करता है। ओएनजीसी का अब तक का जो प्रदर्शन रहा है वह सबसे ज्यादा घाटा इस बार रहा है। 36 बड़े-बड़े कर्जदार करोड़पति सेठ, अरबपति सेठ, खरबपति सेठ देश से गायब हो गये। कर्ज ले गये, देश से गायब हो गये और बैंक्स फेल हो गयीं। बड़े-बड़े कारपोरेट्स को 3 लाख 50 हजार करोड़ की माफी भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दी। 1 लाख 31 हजार 100 मिलियन डालर देश पर आज की तारीख में कर्जा है। तो ऐसी

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

स्थिति में अगर राज्य का बजट इतना शानदार आता है जिसकी प्रशंसा मीडिया भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, अमीर भी कर रहा है, मध्यम वर्ग का आदमी भी कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्री की और हमारे इस बजट की हमें भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए। मैं बहुत पुरजोर शब्दों में इस बजट का समर्थन करता हूं।

राजकीय कार्य योजना की परम्परा कांग्रेस की रही है जो हम मैनिफेस्टो देते हैं, मैनिफेस्टो जो जनता के सामने दे दिया उसको एक पब्लिक डाक्यूमेंट बनाने का राज्य के मुख्य सचिव को सौंपने का और उसको इस संकल्प के साथ सौंपने का कि यह हमारा डाक्यूमेंट है जिसकी अनुपालना आपको करनी है और राजकीय कार्य योजना मानी जाएगी। यह एक बहुत स्वस्थ परम्परा है। यह डाक्यूमेंट भी जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया और हमारा मैनिफेस्टो भी जो दिया है वह बहुत जल्दी धरती पर क्रियान्वित होगा, फलीभूत होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि किसान, कृषि, मजदूर और गरीब, यह जो हमारी पहले वाली सरकार थी इसके कहीं किसी प्रकार से प्रायोरिटी में नहीं थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो ईज आफ डूइंग फार्मिंग को दिया है, एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष जो इस बजट के माध्यम से बनाया है उससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से किसान के प्रति, खेती के प्रति, खेतीहर मजदूर के प्रति हमारे इस बजट का दृष्टिकोण, हमारे मुख्य मंत्री का दृष्टिकोण, मुख्य मंत्री की टीम का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा सकारात्मक है। फोकस पर खेतीबाड़ी रहेगी, फोकस पर किसान रहेगा, फोकस पर मजदूर रहेगा और सेठ-साहूकार जो पैसे लेकर भाग जाते हैं वे कहीं भी कोई कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी में नहीं आएंगे। अगर आप किसान की बात करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि उत्पादन का जो मूल्य आज का है उसको अगर अपन देश भर से आकलन करें तो 1965 में पैट्रोल और सोना, देखिये पैट्रोलियम प्रोडक्ट और गोल्ड, इन दो का आकलन करने से अर्थव्यवस्था का सारा पता लग जाता है। 1965 में 35 पैसे लीटर डीजल था आज मेरे विचार से 71-72 रुपये है। कितने टाइम उसकी प्राइस बढ़ गयी। सोना 1965 में 150 रुपये प्रति दस ग्राम था आज 35 हजार रुपये है और खेतीबाड़ी किसान जो करता है उसके उत्पादन का मूल्य 30-35 गुना ही बढ़ा है जबकि ये सारे प्रोडक्ट सैकड़ों टाइम्स बढ़ गये हैं। इससे स्थिति स्पष्ट है कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

किसान का जो प्रोडक्ट है वह तो मार्केट में बहुत सस्ता है और अन्य चीजें जो वह खरीदता है उसकी बहुत भारी कीमत उसको चुकानी पड़ती है।

इसलिए उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो खुद की आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज्यादा गड़बड़ा गयी है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को रियलाइज किया है, इस बात को समझा है कि किसान पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, खेती पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है।

खनिज नीति पर बात करता हूं, 2015 की जो खनिज नीति है उसको रिव्यू करने का फोकस माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट में किया गया है। पिछली सरकार में माइंस के नाम पर क्या-क्या घोटाले हुए हैं यह किसी से छिपा नहीं है। जो घोटाले करने वाले थे उनके साथ पिछली सरकार में किस तरह की सहूलियतें और किस तरह का सद्व्यवहार किया गया है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि यह जो खनिज नीति है इसको हम रिव्यू करेंगे। यह बहुत बड़ा कदम माननीय मुख्य मंत्री के बजट में उठाया गया है और बहुत जल्दी ही खनिज नीति में परिवर्तन होगा। रोजगार की स्थिति में परिवर्तन होगा, राज्य के मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका सही उपयोग होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग होगा।

रिफाइनरी की बात कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट कुछ भी दें, राजनीति में आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। कई बार आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के लिए दिया जाता है। रिफाइनरी का जो आउटपुट मिलेगा, उसका जो फायदा कांग्रेस सरकार में राज्य को मिलेगा, निश्चित रूप से इस राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, इस राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है, इस राज्य को आगे बढ़ाने का जो मिशन इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ना है। यह जो संकल्प लिया है उसका सहारा रिफाइनरी साबित होगी। आज के कुछ वर्षों पहले, दो वर्ष पहले, चार वर्ष पहले जो दुर्गति उस प्रोजेक्ट की हुई थी, जो उसको मिस हैंडलिंग किया गया था, वह सबके सामने है। हाउस का प्रत्येक विद्वान व्यक्ति इस बात को जानता है।

माननीय सभापति महोदय, अगर रोजगार की स्थिति देखें तो 75 हजार रोजगार कम नहीं होते हैं। कांग्रेस सरकार ने अगर रोजगार के लिए कहा है तो ईमानदारी से वह रोजगार देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, बीजेपी के राज में रोजगार की स्थिति यह थी, पहले बच्चा परीक्षा दे, परीक्षा के बाद हाई कोर्ट के चक्कर काटे और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे। बीजेपी के राज में यह सिस्टम था। लेकिन कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं है। अभी 75 हजार वैकेंसीज की घोषणा हुई और उनको भरने का काम चालू कर दिया गया है, यह बहुत बड़ी बात है।

आप टाइम कम दे रहे हैं तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं उससे पहले एक बात जनरल कर रहा हूं, नरेगा में जो कुंड बनाने का काम है वह पहले पूरे राज्य में लिया गया था। 10 परसेंट पैसा जमा कराकर कुंड का काम गांवों में दे दिया गया था, अच्छी बात थी। हमारा वाटर लेवल जिस तरह से डाउन जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सुझाव देता हूं कि जल कुंड प्रत्येक उस कुएं पर जो खेत में आदमी अपना कुआं बनाता है, उसको नरेगा से जोड़कर यह प्रोजेक्ट लाना चाहिये। क्योंकि किसान के कुओं का पानी, यहां अधिकतर खेती और किसान से जुड़े हुए लोग बैठे हैं हर व्यक्ति इस बात को समझता है। कुएं का पानी नीचे जा रहा है, उनको कुंड बनाने के लिए नरेगा से जोड़कर प्रोजेक्ट लाना चाहिये। ताकि जो ऐसी स्थिति में पानी चला गया तो वह कुंड के माध्यम से कम से कम अपने पेयजल की व्यवस्था तो वह करेगा।

सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन और है, कल झुंझुनूं में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। वहां पैराटीचर्स का संगठन हमसे मिला है। उनकी बड़ी तकलीफ है और मैं उसको एप्रिशिएट करता हूं कि जिस प्रकार से दूसरे संगठन आंगनबाड़ी वर्कर्स हों या अन्य कोई इस तरह के कार्मिक हों, पैराटीचर्स का पारिश्रमिक भी बढ़ाना चाहिये। उनकी मांग है कि उनको रैगुलर भी किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): पिलानी विधान सभा क्षेत्र में कालेज की स्थापना की जाए। गौरव पथ के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र में जितने गौरव पथ बने हैं। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच की मैं इस सदन में मांग कर रहा हूं। क्योंकि बहुत घटिया

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

क्वालिटी पिछले सालों में गौरव पथ में लगायी गयी है। जो चिड़ावा की सीएचसी है, उसको अपग्रेड करने की मांग करता हूं। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का पानी पिलानी विधान सभा क्षेत्र को मिले, इसकी मैं मांग कर रहा हूं। पिलानी में सीवरेज लाइन की भी मैं मांग कर रहा हूं। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, यह जो राजस्थान का बजट आया है यह मुख्य मंत्री जी का तीसरी बार की सरकार का पहला बजट है। पहले बजट पर ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करते हुए मैं कहना चाहूंगा जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह बजट एक दिन का काम नहीं है। It's not the statement of income and expenditure, it's a long term road map of the development. It's a vision document. सभापति महोदय, मैं मानता हूं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि राजकोषीय घाटे पर काफी बात हुई यह राजकोषीय घाटा एक दिन में तो नहीं आया। यह राजकोषीय घाटा राजस्थान में आया कहां से? हम प्रिंसली स्टेट थे, हमको यह इकोनोमी विरासत में मिली है। सभापति महोदय, यह राजकोषीय घाटा आया 1947 से लेकर 1977 तक, तीस साल तक तो आपकी कांग्रेस की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट थी। सभापति महोदय, मैं रिकार्डेड कह रहा हूं कि तीस साल तक हमारी अर्थव्यवस्था ओवरड्राफ्ट की थी, बैडडैट्स की थी, इस तरह की अर्थव्यवस्था थी और तीस साल तक हमारी विकास दर 3 प्रतिशत से कम रही। हम अन्य राज्यों से पिछड़े, हमारा आर्थिक विकास रुका और तो और यह रेवेन्यू डेफिसिट कैसा रहा, इसकी क्वालिटी भी बहुत पूअर थी। इसमें नोन प्लान का हिस्सा ज्यादा था। यह लोग कर्ज लेते रहे और घी पीते रहे। माननीय सभापति महोदय, पहली बार 1990 से 1998 में, बीच में दो ढाई साल के लिए बदली। लेकिन 1990 से 1998 में जब माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब की सरकार रही, तब यहां राजस्थान में सरप्लस की इकोनोमी शुरू हुई। सरप्लस की राजनीति शुरू हुई सरप्लस का बजट शुरू हुआ। इसी बजट में आपने लिखा है 2010-11 और 2012-13, दो साल में आपने लिखा है कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस था। सभापति महोदय, यह कौनसा न्याय है, अगर तुलना करनी है तो 2003 से 2008 की, 2008 से

(श्री अशोक लाहोटी)

2013 की और 2013 से 2018 की, यह पांच-पांच सालों की सरकार की करते। फिर भी आपने मान भी लिया कि दो साल आपका रेवेन्यू सरप्लस आया तो हमें भी लगा कि बड़ा अच्छा है। जब उसकी गहन जांच पड़ताल की तो सामने आया कि आप बहुत लक्की रहे, उस समय 13वां वित्त आयोग आया था। 13वें वित्त आयोग में आपको दो साल में 10 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला और वह अतिरिक्त क्यों मिला, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर आपने एकाउंटिंग एडजस्टमेंट किये, मुद्रा स्फीति उस समय रही, महंगाई की दर के कारण इन्फलेशन रेट बढ़ी, आपका रेशो बढ़ा, इंडेक्स प्राइज बढ़ा, होलसेल इंडेक्स प्राइज बढ़ा। यदि 24 परसेंट मार्केट में बढ़ा और आपने 18 परसेंट बढ़ाया तो उससे क्या फर्क पड़ा। आपको 10 हजार करोड़ रुपये केन्द्र से मिलने के बाद भी, इकोनोमिक ग्रांट मिलने के बाद जो सरप्लस रहा है केवल .31 परसेंट और .70 परसेंट रही आपकी इकोनोमी।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं यदि पांच साल की सरकारों की तुलना करूं तो मैं रेवेन्यू की बात नहीं करता, रेवेन्यू तो सैलेरी का पार्ट है। जो आपने ब्याज दिया उस पर आपको लोन पर इंट्रेस्ट देना है। हमको तो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेना-देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना रहा और आपने जनता के लिए क्या किया, यही किसी सरकार का डाक्यूमेंट है। सभापति महोदय, 2004 से 2009 जब हमारी सरकार रही तो हमने 170542 करोड़ रुपये की इकोनोमी दी और उसमें हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 23.69 परसेंट। उसके बाद आपकी सरकार आई, आपकी सरकार आते ही आपने 2009-14 में 343190 करोड़ की इकोनोमी दी और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा 19.10 प्रतिशत। यानी आपने राजस्थान की जनता के विकास के काम की गति धीमी कर दी। आपकी बढ़ोतरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं रही, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रही। सैलेरी का पार्ट ज्यादा रहा। (व्यवधान) माननीय जो मैं डाक्यूमेंट दे रहा हूं वह मैं देखकर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपने जो आर्थिक समीक्षा की किताब दी है। मैंने यह उसी से उठाया है। 2014 से 2019 में आपने बहुत आरोप लगाये। इस बजट में आरोप ही ज्यादा थे। लेकिन इस बजट में भी 840732 करोड़ रुपये की कुल इकोनोमी पांच साल में दी। उसमें 23.2 प्रतिशत कैपिटल

(श्री अशोक लाहोटी)

एक्सपेंडिचर था। यह जनता का बजट था, यह जनता के विकास के लिए बजट था। इसके बाद भी आपने एक जगह लिखा कि 2 लाख 33 हजार करोड़ का हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया है। इस साल के आपके बजट में पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 41 हजार 924 करोड़ रुपये लिया है। केवल 41924 करोड़ रुपये और यदि मैं पिछले साल से तुलना करूं तो कैपिटल एक्सपैंडिचर इस साल भी, इस बजट में भी।

सभापति महोदय, बजट हर साल बढ़ता है। आजादी के बाद से आज तक का एक बार का भी कोई बजट बता दें कि कम बजट पेश हुआ है। बजट तो बढ़ा लेकिन जनता के लिए क्या बढ़ा? जनता के लिए आपने इस साल भी मानइस साढ़े सात परसेंट कम कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाये हैं। पांच साल का आकलन करूं तो उसमें 5 प्रतिशत कम, इस साल का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 18 परसेंट है। यानी आपकी पिछली गवर्नमेंट से भी कम है। सभापति महोदय, पूत के पग तो पालने में ही दिख जाते हैं। आप इस पूरे बजट में केन्द्र सरकार को कोसते रहे। आपने कहा केन्द्र सरकार यह दे, यह दे। आप केन्द्र सरकार से मांगना तो चाहते हो, पर केन्द्र सरकार को कहीं धन्यवाद भी देते कि आपके इस बजट में 71138 करोड़ रुपये यानी 43.41 परसेंट शेयर केन्द्र का है। आपको वह शेयर मिल रहा है तब वरना, सभापति महोदय, यह जो बजट है। आज तो आपने केवल बजट ही पेश किया है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में कह रहा हूं कि आप इस बजट को लिख लें। आज अभी तक तो आपका बी.ई. है, फिर आप आर.ई. लाओगे, एक्चुअल आप दो साल लाओगे। आज तो आपके अधिकारियों ने बैंक लोन और बैलेंसशीट की कलाकारियां की हैं। दो साल बाद इसी सदन में इन्हीं तारीखों पर हम बैठकर, जब इस बजट का एक्चुअल आएगा तब आप देख लेना कि आपने यह जो बजट दिया है, ये यहीं पर रूकेगा या फिर आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, यह हम दो साल बाद बात करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपने कहा है कि हमारा राजकोषीय घाटा 32678.34 करोड़ रुपये है। जीएसटी भी 3.9 परसेंट जाएगा। सभापति महोदय, मेरा नाम लिख लो, पता लिख लो और आज की तारीख नोट कर लो। यह जीएसटी भी इससे ज्यादा जाएगी और घाटा भी इससे ज्यादा जाएगा। जब दो साल बाद एक्चुअल आए, उस दिन

(श्री अशोक लाहोटी)

मैं इस सदन में डिबेट करने के लिए तैयार हूं। क्यों आएगा, वह भी कह रहा हूं।

अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि 1 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी के लिए कल्याण कोष की स्थापना की। इसके लिए बजट में प्रोविजन कहां है? आपने कहा 9 हजार करोड़ का किसानों का लोन माफ करेंगे, आपने 3 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन किया। या तो आप असत्य बोल रहे हैं। आप नौकरियां नहीं देंगे। आप 75 हजार नौकरियों की वाहवाही लूट रहे हो। या तो आप असत्य बोल रहे हैं या फिर आप नौकरी नहीं देंगे। देंगे तो आपने इसमें प्रोविजन क्यों नहीं किया है? सभापति महोदय, कौनसी बात सही है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं तो आपको यह कह रहा हूं। यह तो धन्यवाद दो राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को और जीएसटी काउंसिल में हमारे यहां से मैम्बर राजपाल सिंह जी थे, उनको, कि उन्होंने जिस तरह से जीएसटी काउंसिल में हमारी पैरवी की। एक मजबूत पैरवी की। सभापति महोदय, उस मजबूत पैरवी का यह परिणाम रहा कि हमको ग्रोथ का 14 परसेंट, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल के बाद ग्रोथ का 14 परसेंट का उसमें इनबिल्ट प्रोविजन किया गया, On the basis of year 2015-16. अदरवाइज आपके पास सैलरी देने के लाले पड़ जाते। ये कहते हैं कि हमारे पास सैलेरी देने के लिए है। मैं चाहूंगा सदन के नेता जब रिप्लाई करें, तब यह बताएं कि आपके कैश लिक्विडिटी क्या है? आपके पास कैश-इन-हैंड क्या है? आपके पास कितना पैसा है? यदि पैसा है तो फिर आपने सारे सरकारी बिलों को क्यों रोक रखा है? आपने 3 हजार करोड़ रुपये तो पीडब्ल्यूडी में रोक रखे हैं, आपने ट्रैजरी बंद कर रखी है। लिक्विडिटी कितनी है, यह जवाब दे दें। यदि लिक्विडिटी है तो सदन में जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं पैरा नंबर 11 और 13 में जो राजकोषीय घाटे की बात कही है। सदन के नेता ने बार-बार यहां पर कहा 62 हजार करोड़ रुपये बिजली कंपनियों का सरकार ने ले लिया। यस, हमने ले लिया। बिल्कुल सही है । agreed. आपने कहा कि 9 प्रतिशत से अधिक हमारा राजकोषीय घाटा रहा। यस, बिल्कुल रहा है और यह चिंता की बात भी है। सभापति महोदय, यह घाटा किसका था? यह लोन किसने लिया। इतना ही

(श्री अशोक लाहोटी)

नहीं, केवल 62 हजार करोड़ रुपये ही नहीं, हमने उसके बाद 8 हजार करोड़ रुपये और लिए हैं, जो शायद सदन के नेता भूल गये होंगे। वह भी आप इसमें जोड़ लें। लेकिन यह घाटा किसका था? सदन के नेता शायद यह भूल गये कि जब आप मुख्य मंत्री थे तो ये कंपनियां बैंकरप्ट हो गयी थीं, इनको लोन देने से मना कर दिया था और आपकी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उनका कर्जा चुका दे। राजस्थान के किसान संकट में आ गये थे, राजस्थान के किसान पलायन करते। राजस्थान में बिजली गुल हो जाती और जिस एयर कंडीशन में बैठकर आप बजट बनाकर पढ़ रहे थे, ये बत्तियां नहीं जलतीं। यह घाटा आपकी सरकार ने लिया। यह घाटा आपने लिया। हमने पाप कर दिया कि आपके लिए हुए कर्ज को हमारी सरकार ने अपने माथे लिया। यदि हम अपने माथे नहीं लेते तो सदन के मुखिया जवाब देते कि उसका हम क्या करते? हमको रास्ता बताते कि आपने गलती की। हमने मान लिया कि हमने गलती की, लेकिन किसके लिए की? सदन के नेता अभी भी जवाब में बता दें कि यह गलती की और इसका यह परिणाम था और आपको इसकी जगह पर यह करना चाहिए था। सभापति महोदय, मैं तो आपको यह कह रहा हूं सदन में जो लीडर होते हैं, वे लीड करते हैं। लेकिन राजस्थान में तो सदन के नेता ने मिसलीड किया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मिसलीड इसलिए किया है आपने पैरा नंबर 227 में कहा है कि हमने 301 करोड़ रुपये की राहत दी है और एक भी पैसा हमने यहां कर्ज में, बजट में नहीं बढ़ाया।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, 12वीं क्लास के पहली बार पढ़कर आया हूं। दो-तीन मिनट और बोल लूं।

श्री सभापति: आप काफी अच्छा बोल रहे हैं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में शायद पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस सदन को धोखा दिया है। यह आपको बजट में लाना था, आपने 4 प्रतिशत वैट बढ़ाया और वह भी तब जब सदन चल रहा हो। जब आपके बजट के लिए सदन चल रहा हो। यहां से छिपाकर आपने 10 हजार करोड़ रुपये का भार राजस्थान की जनता पर डाला और आप कह रहे हो कि हमने 301 करोड़ रुपये की राहत दी है। आपने

(श्री अशोक लाहोटी)

ट्रांसपोर्ट पर टैक्स बढ़ाया। आपने ऋण पत्रों, जो लोग ऋण लेते हैं, उसमें आपने 0.15 परसेंट से 0.30 परसेंट करके ढाई सौ करोड़ रुपये का भार बढ़ाया।

सभापति महोदय, बजट तो क्या देंगे? मैं तो इनसे यह कह रहा हूं कि आप जो प्रेस नोट भेज रहे हो, उसको तो देख लो। बजट बनाने की बात तो बहुत बाद में कर लेना, काउंटिंग तो बाद में कर लेना, जो प्रेस नोट दिया है, उस प्रेस नोट में आपने कोआपरेटिव लिखा है और जो इंग्लिश का प्रेस नोट है उसमें आपने लिखा है Target of 16000 crores short-term agriculture loan waver through Kendriya Sahakari Bank. यानी आपने तो 16 करोड़ रुपये माफ कर दिये। उसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रोविजन किया। इसके बाद आपने लिखा है कि Nandi shala in each Grampanchayat. आप बजट में ग्राम पंचायत समिति पढ़ रहे हो और इस पर लिख रहे हो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर। सभापति महोदय, किसको सही मानें? हिन्दी का प्रेस नोट अलग है, इंग्लिश का अलग है, बजट की स्पीच अलग है। सभापति महोदय, यही नहीं, मैं तो आपको कहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उससे यह लग रहा है कि राजस्थान पोलिटिकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैस में आ गया है। क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सीएमओ के चीफ सैक्रेटरी और फाइनेंस सैक्रेटरी की आपस में नहीं बन रही। इस तरह का लड़खड़ाया हुआ बजट आपने दिया। इधर मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री की नहीं बन रही।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आप केवल इतना देख लें कि पंचायती राज विभाग किनके पास है, यह मुझे नहीं पता। उसमें भी बड़ी जबर्दस्त कलाकारी की। दिखाने को तो 14 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है, लेकिन 14 हजार करोड़ रुपये में कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 460 करोड़ रुपये है। राजस्थान के 200 सदस्य हैं। आपकी 10 हजार से ज्यादा पंचायतें और बढ़ने वाली हैं। उन 10 हजार पंचायतों में कितना काम होगा, किसका होगा, क्या होगा, यह देख लें।

सभापति महोदय, उद्योगों की बात करें। इस 21वीं सदी में आपने जो उद्योगों में दिया है। आप उद्योगों से ले तो रहे हो, उद्योगों का जीडीपी में

(श्री अशोक लाहोटी)

जो योगदान है वह 30 परसेंट है और आपने उद्योग में केवल 1.6 परसेंट दिया है। सभापति महोदय, मैं केवल यही कहूंगा एक लाइन में यह बजट जादूगर की चौथी फिल्म है। पहली, किसान कर्जा माफी थी। दूसरी, बेरोजगारी भत्ता थी। तीसरी, संविदाकर्मियों को नौकरी देना था और चौथी फिल्म है जो आपने 75 हजार नौकरियां दी हैं, यह जादूगर की चौथी फिल्म है। सभापति महोदय, इससे ज्यादा इस बजट में और कुछ नहीं है। मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी आपस में लड़ाई बंद करके दिल्ली के चक्कर लगाना बंद करें। राजस्थान की जनता पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का फायदा होगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान के नौजवानों को, राजस्थान के किसानों को ठगना बंद कर दें। जनता चिल्ला रही है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: श्री दानिश अबरार।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको आभार दूंगा कि मुझे इस सदन में मेरे जीवन के प्रथम बजट सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। आपने मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार। साथ ही मेरे सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता का भी आभार जिसने मुझे इस लायक बनाया।

श्री सभापति: समय खराब मत कीजिए। कुछ बोलिए।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, यह जो बजट आया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जैसा कि बजट में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है कि बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब देखती है। बहुत सही कहा है। लेकिन मैं तीन दिन से बजट पर यहां बहस सुन रहा हूं। इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस आईने के अंदर बजट का

(श्री दानिश अबरार)

अक्स नहीं दिख रहा है, यह मैंने सुना। हमारे सामने बैठे हुए चूरू से विधायक और मैं समझता हूं, विधान सभा की कार्यशैली देखता हूं, आप अपने आपमें एक इंस्टीट्यूशन है माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब। इन्होंने कहा कि इसमें अक्स नहीं दिखता है। मैं एक शेर से अपनी बात कहूंगा और इस अक्स को दिखाना चाहूंगा:-

मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के
जिसे बुरा लगे वह सामने से हट जाए।

सभापति महोदय, चार-पांच बिंदुओं पर बोलूंगा। सर्वप्रथम यह बात सच है कि जब हमारा पिछला कार्यकाल था तब 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ की लायबिलिटी छोड़ी थी जो एफआरबीएम एक्ट, 2005 के मुताबिक 25 परसेंट में आती थी। लेकिन इस बार जब हमारी सरकार आई, इस सरकार में हम आए हैं 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ का कर्ज लेकर, उसके बावजूद आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐसा बजट दिया है, इस बजट को मैं सलाम करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं गोपालन विभाग पर बोलना चाहूंगा। गोपालन विभाग राजस्थान के अंदर 12 मार्च, 2014 को बना। 22 जुलाई, 2014 को इस गोपालन विभाग का कार्य शुरू हो गया। गोपालन विभाग बना, गोपालन मंत्री बना, गोपालन डायरेक्ट्रेट बना। लेकिन सच्चाई क्या थी पिछली सरकार की, मेरे खुद के सवाईमाधोपुर जिले के अंदर कोचर के अंदर 30 से 40 गाय रोज मर रही थीं। वहां हमने आंदोलन किया। हमारे उप मुख्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिव पायलट साहब खुद कोचर गांव में आए और जब वह दर्दनाक मंजर देखा, उसके बाद यह सरकार जागी। जागने के बाद भी झूठी घोषणा एक करोड़ रुपये की की। झूठी घोषणा को लेकर फिर से 25 दिन तक आंदोलन चला तब एक करोड़ की झूठी घोषणा की और पैसा पहुंचते-पहुंचते मात्र 20 लाख रुपया रह गया था। यह बात मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, गोपालन विभाग की अब बात करते हैं, पिछली सरकार में पिछले बजट के अंदर 2017-18 के अंदर गोपालन विभाग को दिया गया 182 करोड़, 2018-19 के अंदर पैसा दिया गया 291 करोड़ और हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि आज सीधे ही 291 करोड़ से हमारी सरकार ने दिया है 714 करोड़।

(श्री दानिश अबरार)

माननीय सभापति महोदय, यह बात यहीं पूरी नहीं होती। इसी प्रकार जब पिछला कार्यकाल भाजपा सरकार का था तो पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने पिछले बजट के भाषण में पेज नंबर 19 के बिंदु नंबर 64 की लाइन नंबर 4 पर कहा था कि प्रत्येक जिले में, जैसा अभी लाहोटी साहब बोल रहे थे, प्रत्येक जिले में एक नंदी गोशाला के संरक्षण और संवर्द्धन नीति से 50 लाख तक का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूं, यह बात कही थी। यह बात हवाई साबित हुई। यह इसी सदन के अंदर घोषणा की गयी थी और इसके विपरीत आज हमारी सरकार ने इस बजट में घोषणा की है पेज नंबर 9 के बिंदु नंबर 31 की प्रथम पंक्ति में कि प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी शालाएं स्थापित की जाएंगी।

सभापति महोदय, मैं अल्पसंख्यक विभाग पर भी बोलना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी को आजकल अल्पसंख्यकों की बहुत चिंता हो रही है। बहुत अच्छी बात है। खास तौर पर अल्पसंख्यकों की कुछ विशेष चिंता हो रही है। तीन तलाक के मुद्दे पर चिंता हो रही है, अल्पसंख्यक मामलात पर चिंता हो रही है। बहुत अच्छी बात है। नारा दिया गया है 'सबका साथ, सबका विकास' और अब यह नारा परिवर्तित हो गया है 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।' बहुत अच्छी बात है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं होता क्योंकि चिंता तो की जा रही है, अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है लेकिन जो पिछली भाजपा सरकार राजस्थान के अंदर थी और आखिरी बजट 12 फरवरी, 2018 को इसी सदन में दिया था जिसमें 78 पेज हैं और 269 बिंदु है। अल्पसंख्यक की चिंता की बात करते हैं और कथनी व करनी का अंतर है कि पिछले बजट में 268 बिंदु 78 पेज के अंदर अल्पसंख्यक शब्द को जगह नहीं मिली। यह लेकर आया हूं मैं आपके सामने। यह आपका पिछला बजट है। इस पूरे बजट के अंदर अल्पसंख्यक शब्द नहीं है। इसके विपरीत हमारा बजट आया है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने 164 करोड़ रुपये की घोषणा की। पेज नंबर 28 के बिंदु नंबर 114 में मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अल्पसंख्यक को भी साथ लेने का वादा किया और 21 हजार रुपये हर बालिका को देने का वादा किया। हमारी सरकार ने अलवर के अंदर अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय खोलने की बात की। आज

(श्री दानिश अबरार)

अल्पसंख्यकों की बात पर एक शेर कहना चाहूंगा क्योंकि आपके पूरे बजट में जो कि पिछली सरकार का था, अल्पसंख्यक शब्द को जगह नहीं मिली-

लगा के देख लो जो भी हिसाब आता हो,
मुझे घटा के वह गिनती में नहीं रह सकता।

सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों को लेकर मदरसा पैराटीचर्स का एक बड़ा विवाद चल रहा है। मदरसा पैराटीचर्स एक शिक्षित समुदाय है। राजस्थान के अंदर तकरीबन 3500 मदरसे चलते हैं। तकरीबन साढ़े छह हजार पैराटीचर हैं। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन पैराटीचर्स के साथ कल भी जुल्म हुआ और आज भी जुल्म हो रहा है। आज यह शिक्षित वर्ग है। कोई भी समाज में अपराधी नहीं होता। कोई भी समाज में गलत काम नहीं करता। लेकिन जब किसी के साथ न्याय नहीं होता तो उसके हालात उसे गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज अगर इन पैरा टीचर्स के साथ न्याय नहीं हुआ तो इस सदन में बैठे हुए चाहे इधर के हों या उधर के हों, हम सब जिम्मेदार होंगे। अगर इन पैराटीचर्स को, एक शिक्षित वर्ग को गलत रास्ते पर जाने को मजबूर किया तो उसके जिम्मेदार आप और हम होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब पिछली भाजपा सरकार थी तो पूरे पांच साल मीठी गोली दी। मैं खुद डेढ़ लाख फूल लेकर मंत्री महोदय के घर पर बैठा था। आज हमारी सरकार आई है, बी.डी. कल्ला जी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, मैं हाथ जोड़कर यह मांग करता हूं कि एक पढ़ेलिखे समुदाय को गलत रास्ते पर डालने का प्रयास किया जाएगा तो सदन में बैठे नेताओं के द्वारा किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं सदन में बैठे चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के लोग हों, हम सबको मिलकर एक मांग करनी चाहिए कि मदरसा पैराटीचर्स नियमित होने चाहिए और उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। इसके लिए भी एक शेर बोलना चाहूंगा-

तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे,
हम तो वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे,
हमको महसूस किया जाए खूशबू की तरह,
हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, फख्र है कि मुझे इस सदन में आकर बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि मुझे सवाईमाधोपुर की

(श्री दानिश अबरार)

जनता ने भेजा है। हमारा सवाईमाधोपुर छोटा-सा विधान सभा क्षेत्र न सिर्फ प्रदेश में, न देश में, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय नक्शे में अंकित है रणथम्भौर अभयारण्य की वजह से।

सभापति महोदय, वन व पर्यावरण के संबंध में पिछली सरकार का बजट था। पिछली सरकार ने 12 फरवरी, 2018 को इसी सदन में बजट रखा, मुझे लगता है कि शायद बजट का अर्थ भूल गये थे। जब बजट की किताब पढ़ते हैं तो इसमें आंकड़ों की बात होती है। 12 फरवरी, 2018 को सदन में बजट पेश हुआ तो रणथम्भौर का जिक्र तो हुआ लेकिन क्या कहा गया वह मैं पढ़कर सुनाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी बजट पेश किया उसमें पेज 48 बिन्दु नम्बर 188 पर कहा गया कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में नवाचार कर उसे देश का महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ टूरिज्म केन्द्र बनाया गया। I agree, जिससे 23 करोड़ की आय होना अपने आप में कीर्तिमान है। यह सूचना है या बजट है, मेरी समझ से परे है। जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी प्रचारित है, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी के बजट के पेज 51 बिन्दु नम्बर 199 पर कहा गया, मैं आगामी वर्ष में 500 फोरेस्टर, 2000 फोरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों की भर्ती करने की घोषणा करती हूं। कौनसा पद, कौनसा फोरेस्ट और कौनसा गार्ड, एक भर्ती नहीं हुई है, यह मैं सदन में जिम्मेदारीपूर्वक कहता हूं। एक भर्ती नहीं हुई और झूठी घोषणा की गयी।

सभापति महोदय, हमारा बजट आया, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई और पेज नम्बर 35, बिन्दु संख्या 146 पर कहा रणथम्भौर नेशनल पार्क देश-विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान मिली है। टाइगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, आज की तारीख में रणथम्भौर अभयारण्य से 36 करोड़ 60 लाख की आय हो रही है। इसलिए मेरा हमारी सरकार से, मुख्य मंत्री महोदय से, वन मंत्री महोदय से एक निवेदन है कि आज वन विभाग के 937 करोड़ के बजट में 36 करोड़ रुपये की आय रणथम्भौर से आ रही है, तो क्यों नहीं आप 36 करोड़ रुपये में से 20 परसेंट सात-सवा सात करोड़

(श्री दानिश अबरार)

रणथम्भौर के विकास के लिए हमें दें। ताकि रणथम्भौर में बाहर का अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक आए, हम वहां एक अच्छा गेट बना सकें, रणथम्भौर का विकास कर सकें।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय सचिन पायलट जी ने विकास पथ की मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा करवाई। मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गौरव पथ जरूर बनाए। मैं सुन रहा था, जब बातें हो रही थीं तो गौरव पथ की बहुत तारीफ हो रही थी। लेकिन हम यहां बैठे हैं, हम सब विधायक हैं, हम सब गांव, ढाणियों में जाते हैं। इस गौरव पथ के नाम पर जब गांव ढाणियों में जाते हैं तो पंचायत हैडक्वार्टर पर इन गौरव पथ पर सिवाय कीचड़ के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि गौरव पथ तो बना दिए शायद नालियां बनाना भूल गये। हमारी सरकार ने विकास पथ की घोषणा की। इसमें खास तौर पर कहा गया है कि विकास पथ बनेंगे और विकास पथ नाली समेत बनेंगे, यह एक चर्चा का बिन्दु है।

सभापति महोदय, मैं सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा पेयजल विभाग के बारे में। मैं सामने बैठे साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको भी तारीफ करना चाहिए कि हमारी सरकार द्वेषतापूर्ण काम नहीं करती। हमारी सरकार के लिए अगर सर्वोत्तम कोई प्रिय है तो जनता जनार्दन और जनता की मांग है। जब भारतीय जनता पार्टी का आखिरी बजट आया था उसमें पेज नम्बर 10, बिन्दु संख्या 29 पर ईसरदा बांध परियोजना का जिक्र किया था। अब हमारा बजट आया है तो हमने जनता की बात को सर्वोपरि माना, हमने द्वेषतापूर्ण भावना नहीं रखी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी ने 3 हजार 159 करोड़ की ईसरदा बांध की घोषणा की। सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दे दीजिए। हमारी सरकार ने कृषक कल्याण योजना की घोषणा की, जो एक बहुत अच्छी पहल है। जिसमें कहा गया है किसान भाइयों के लिए Ease of doing Business की तर्ज पर Ease of doing farming की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए एक हजार करोड़ के गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जाएगा, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज सवाईमाधोपुर में खेत-खलिहान कम हो गये हैं और

(श्री दानिश अबरार)

अमरूदों के बगीचे ज्यादा हो गये हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब अमरूदों का मौसम आए, सदन के सभी साथियों को अमरूदों की पेटी भी पहुंचाई जाए ताकि आप और हम मिलकर सवाईमाधोपुर में इस योजना के तहत गुआवा रिसर्च एंड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट का निर्माण करें।

सभापति महोदय, गृह विभाग में बहुत अच्छी बात आई जिसमें कहा गया है कि हर थाने में CCTV मोनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): लास्ट वन मिनट। इसके बाद दो बिन्दु और हैं। गृह विभाग में अच्छी पहल है कि हम CCTV कैमरा लगा रहे हैं। उसमें मेरा एक निवेदन रहेगा कि CCTV हर थाने में लगेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उन CCTV कैमरे की मोनिटरिंग थानों में न होकर जिला हैडक्वार्टर पर हो। अगर वही कैमरा होगा, वहीं मोनिटरिंग होगी तो मैं समझता हूं कि इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा।

सभापति महोदय, आपने मना कर दिया इसलिए पत्रकारों का आखिरी बिन्दु बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब हमारा पिछला कार्यकाल था तो पत्रकारों को मकान आबंटित करने की लाटरी निकल चुकी थी। पत्रकारों को मकान देने की बात कही भी गयी थी और शुरूआत भी कर दी गयी थी, लाटरी भी निकाल दी गयी थी लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इस सारे काम को समाप्त कर दिया। समाप्त करके पिछले बजट में भारतीय जनता पार्टी ने पेज नम्बर 52 बिन्दु संख्या 204 पर कहा ऐसे पत्रकार जिनके पास पूर्व में अपने अथवा अपने परिवार के नाम पर सरकारी योजना में भूखण्ड अथवा आवास आबंटित नहीं है, उन्हें राज्य में मकान बनाने के लिए अधिकतम 25 लाख के आवासीय ऋण लेने पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): हमारा प्रयास कुछ और था। आपने खतम कर दिया और यह बात कह दी। आज हमारी सरकार ने इसके विपरीत जाकर बजट में फिर से घोषणा की है कि राज्य भर में....

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): राज्य भर में पत्रकारों,

(श्री दानिश अबरार)

साहित्यकारों, लेखकों को स्थानीय निकायों के माध्यम से रिहायशी कालोनी में भूखंड आबंटन किया जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, मैं एक शेर से अपनी बात समाप्त करता हूं। केवल एक शेर पढ़ने दीजिए। (व्यवधान). साहब, एक शेर तो बोलने दीजिए। चिकित्सा रह गया, शिक्षा रह गयी, मान लेता हूं, चिकित्सा व शिक्षा बाद में बोल लूंगा। एक शेर से अपनी बात को पूरी करता हूं ...(व्यवधान) मेरी तो एक ही शादी हुई है।

श्री सभापति: डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर):

यह तो किया कि सब पर भरोसा नहीं किया, यह तो किया कि सब पर भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं किया।

यह तो किया कि सब पर भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं किया, घर से बुलाकर लाई हैं घर की ज़रूरतें। मैंने खुशी से पार यह दरिया नहीं किया।

बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसी धरती से आता हूं जो धरती पूरे एशिया में सुगंध फैलाती है पूरे देश को चमकाती है, ऐसी धरती, कोटा स्टोन की धरती, रामगंज मण्डी से आता हूं।

सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपिता बापू के सिद्धांतों पर अमल करते हुए उनके सपनों को साकार करना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत अच्छी बात है महात्मा गांधी जी को याद किया है। महात्मा गांधी जी की दो इच्छा थी, वह चाहते थे कि देश में जब भी स्वराज आए तो सबसे पहले शराबबंदी हो और गौ हत्या पर पाबंदी हो, यह उनकी इच्छा थी।

सच्ची श्रद्धांजलि यही होती, यदि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सदन में घोषणा करते कि मैं आज शराबबंदी करता हूं। शराबबंदी नहीं की।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपने क्यों नहीं की?

एक माननीय सदस्य: आपको किसने रोका था?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): शराबबंदी नहीं की।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, शांत रहें। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौ-हत्या पर पाबंदी की बात गांधीजी ने कही थी। सभापति महोदय, उसके बदले में गौ-हत्यारों को संरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, कुछ लोग कह रहे थे कि शराब बंद कर दी जाएगी तो रेवेन्यू का लोस हो जाएगा, राजस्थान चलना मुश्किल हो जाएगा। (व्यवधान) पता नहीं किसने यह गणना की है, कहां से की है। मुझे जानकारी नहीं है। मैं अर्थशास्त्री भी नहीं हूं। परन्तु इतना जानता हूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कि जब तक शराब रहेगी तब तक इस देश के राजस्व का नुकसान होता रहेगा। इसलिये होता रहेगा क्योंकि शराब पी करके वाहन चलाने से हजारों लोग मर जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। बैठे-बैठे बोलने की आदत छोड़िये आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हजारों लोग विकलांग हो जाते हैं। हजारों शराबी शराब पी करके अपने मां-बाप को मार देते हैं, अपनी पत्नी को मार देते हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं। शराब पीने के बाद में जो झगड़े होते हैं, वे लाखों की संख्या में अदालतों में जाते हैं। इन सबका यदि अनुमान लगाते हैं कि कितना अस्पताल में जाने के बाद में चिकित्सा पर खर्च होता है, कितना पुलिस पर खर्चा होता है, कितना अदालतों का समय जाया होता है और खर्चा होता है, कितना मानव दिवसों का ह्रास होता है और कितने हजार लोगों को हम हमारे बीच में से खो देते हैं। यदि सबका आज आकलन किया जाएगा तो जितनी रेवेन्यू हमको प्राप्त होती है उससे ज्यादा रेवेन्यू जाती है। यानी कुल मिला करके हमारा रेवेन्यू माइनस में होता है। इसलिये यह कथन गलत है। जिसका भी आकलन है कि इससे राजस्व मिलता है, वह बिलकुल गलत है। मैं चाहता हूं कि इस देश में और इस प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह शराब ही है। जो हमारा मजदूर थोड़ा-बहुत पैसा कमाकर लाता है, उस कमाई का अधिकांश पैसा वह इसमें खर्च कर देता है।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, अभी बातें हो रही थीं कि श्री गौ-माताजी के लिए हमने यह किया, श्री गौ-माताजी के लिए हमने यह किया। नंदीशालाएं खोलने की बात भी हुई है। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं।

पर, माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में मैंने एक प्रश्न लगाया था। उस सवाल के जवाब में कहा कि हमारा ऐसा कोई भी विचार नहीं है। मैंने सवाल में कहा था कि क्या सरकार पुरानी परम्परा को जिंदा रखना चाहती है, श्री गौ-माताजी को चराने के लिए जो पुरानी व्यवस्था थी, गांव वाले मिल करके एक ग्वाल नियुक्त करते थे। सारी गायों को ले करके, गौ-माताजी को ले करके चराने जाते थे और शाम को उन गौ-माताजी को उनके पालकों के घर छोड़ते थे। शाम को उनको चारा मिलता था। उनके घर में, जहां वे बांधी जाती थीं वहो मूत्र मिलता था, वहीं वह अपना गोबर करती थीं। गौ-माता जहां बांधी जाती हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, सबको जानकारी होगी, मेरी जानकारी में एक ही प्राणी ऐसा है जो 24 घण्टा आक्सीजन देता है। इसके अलावा कोई प्राणी मैंने सुना नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है कि 24 घण्टे ही आक्सीजन देता हो। एक ही प्राणी है जो आक्सीजन देता है। वह पर्यावरण को शुद्ध रखती है। हमारे जीने के लिए आक्सीजन देती है और इसके अलावा सब जानते हैं कि जो सर्वोत्तम दूध है वह गौ-माताजी का है। वह भी कौनसी गौ-माताजी, ऊंचें कंधे वाली, देशी, वह चपटे वाली नहीं। यह वर्ण-संकर है। यह तो कैंसर पैदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। जो देशी गाय है, उसी का दूध सर्वोत्तम रहता है। उनके लिए यदि हम यह व्यवस्था कर दें कि पूर्व की भांति ही यह पुरानी परम्परा चालू होगी तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ राजस्थान की जनता को होगा, पर्यावरण को होगा। परन्तु सरकार ने मना कर दिया है।

एक हजार करोड़ रुपये गौ-माताजी के नाम पर ये सैस ले रहे हैं। जनता से ले रहे हैं तो उस पैसे को लगाने में इनका जाता क्या है। न नंदी गौशालाएं खोलनी पड़ेंगी, न दूसरी गौशालाएं खोलनी पड़ेंगी। न किसानों का नुकसान करेंगी और स्वतंत्र रूप से लोगों के बीच में गौ-माताजी रहेंगी। यह करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इन्होंने मना कर दिया है, और ये कह रहे हैं कि हम गौ-माताजी के बारे में सोच रहे हैं। ये गौ-माताजी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये तो बूचड़खाने खोल करके उनको कत्ल करने की सोचते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार से निवेदन करना

(श्री मदन दिलावर)

चाहता हूं कि यदि गौ-पालन के बारे में सोचना है, गौ-माताजी के बारे में सोचना है तो उनको पूर्व की भांति, जो हमारी चराने की परम्परा थी उसको जिंदा करना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, यहां जोर-शोर से कहा गया, इस बजट में पढ़ा गया कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है। लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट पर 40 पैसे से 150 पैसे कर दिया है, और ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगाया है। यह सबसे बड़ा असत्य है। इस बजट का यह सबसे बड़ा असत्य है। ऐसे दो-तीन टैक्स और लगाये हैं जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दिये हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के बारे में बहुत सोचने वाली सरकार है, ऐसा ये कह रहे हैं। यह सरकार किसानों के बारे में बहुत चिंता करती है, ऐसा ये कह रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में एक ताकली नाम से निर्माणाधीन बांध खड़ा है। उसके डूबत में जो सात गांव आ रहे हैं, उनको मुआवजा देना है। यह सरकार उनको मुआवजा नहीं देना चाहती है, उनके मकान नहीं बनाना चाहती है, जमीन के बदले जमीन नहीं देना चाहती है। उनको वहां से हटाना चाहती है। डूबत में गांव आये हैं, उनको हटाना पड़ेगा। दूसरी जगह बसाना भी पड़ेगा। लेकिन उनको बसाने के लिए पैसा दो। उनको पूरा मुआवजा दो। इस सरकार से मेरी मांग है कि ताकली बांध के डूबत में जो गांव आ रहे हैं, उनको तुरन्त, अविलम्ब मुआवजा दें और उस बांध का काम प्रारम्भ करें। क्योंकि वहां के किसान आंदोलित हैं। वह बांध का काम प्रारम्भ नहीं करने दे रहे हैं, जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता है। उस बांध से 31 गांवों के खेतों को सीधा पानी मिलेगा। उस बांध से लगभग 60 गांवों की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसमें, पीने के पानी के लिए हम बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। उस बांध से जब खेतों में पानी जाएगा, उससे जो आमदनी होगी, हमको टैक्स मिलेगा। चाहे मण्डी के माध्यम से मिले, चाहे किसी भी माध्यम से लो। वह बड़ी राशि होगी और जब किसान के जेब में पैसा आएगा तो बाजार में जाएगा। बाजार में जाएगा तो बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलने वाला है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अविलम्ब ताकली बांध को प्रारम्भ करने के लिए उनका मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा कितना है? माननीय सभापति महोदय, किसान केवल 21 करोड़ रुपये मांग रहे हैं,

(श्री मदन दिलावर)

ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। सारे कागज फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पड़े हुए हैं कैबिनेट में जाने की बात है। कैबिनेट में जाने के बाद उनको विचार करना है। मैं समझता हूं कि विचार करेंगे यदि सारी गणना करेंगे कि इससे लाभ और हानि कितनी है तो निश्चित रूप से उनको स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इसको स्वीकृति दें।

सभापति महोदय, इस बजट में कहा गया कि हम गरीबों के बारे में सोचते हैं। उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा है जो चार लाख बच्चे हैं इस राजस्थान में, जो पालनहार योजना के अंतर्गत पल रहे हैं, जिनके मां-बाप नहीं हैं, जिनकी मां विधवा है, जिनके मां-बाप विकलांग हैं, जिनके मां-बाप जेलों में हैं, ऐसे चार लाख बच्चे हैं। पालनहार योजना का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में जब मैं समाज कल्याण मंत्री था तो यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह पालनहार योजना मैंने प्रारम्भ की थी। हमने आधार यह रखा था कि जितना छात्रावास में एक बच्चे के ऊपर जितना पैसा खर्च होता है, उतना पैसा इनको घर बैठे देंगे, ताकि इनका लालन-पालन ठीक प्रकार से हो सकेगा। आज एक बच्चे के ऊपर छात्रावास में दो हजार रुपये खर्च होते हैं। लेकिन इनको एक हजार रुपया दिया जाता है। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। ये सबसे गरीब बच्चे हैं। जब गरीब के बारे में सोचने की बात करते हैं तो पालनहार योजना में जो पल रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं।

ये गरीब की बात करते हैं। जो महिलाएं मिड-डे मील में खाना बना रही हैं, तीन-चार साल हो गये उनको, हम लोग क्या देते हैं। पहले एक हजार रुपये देते थे अब 1320 रुपये हो गये हैं। वे सुबह आती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना परसोती हैं, स्कूल में यदि कोई चपरासी नहीं हो तो पानी पिलाती हैं, स्कूल में झाड़ू निकालती हैं। सब कुछ करने के बाद उनको महीने में 1320 रुपये मिलते हैं। 1320 रुपये से क्या होता है। लेकिन हम इतने निर्दयी हो गये हैं, हमको उनके बारे में कोई विचार भी नहीं आता है, ध्यान भी नहीं आता है।

हजारों की संख्या में जो हमारी बहनें हैं जो बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं, उनके लिए हम पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या कारण है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं देख रहा था कि मेरे से पहले के लोग 22-22, 24-24 मिनट बोले हैं और मेरे से ही कोई दुश्मनी हो तो मैं तो बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, दो मिनट और बोल लें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 20-20 मिनट बोले हैं।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, कोटा स्टोन रामगंज मण्डी में निकलता है तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार सभी कार्यालयों में सरकारी काम में फर्श के काम आने वाला यह स्टोन, कोटा स्टोन को अनुमोदित कर दे ताकि यही कोटा स्टोन लगाया जाए। यह कोटा स्टोन बहुत अच्छा स्टोन है। यह इसलिए अच्छा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बढ़िया है। इस पर चलने पर स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता है जबकि और पत्थरों से नुकसान होता है। यह मजबूत है, यह जितना पुराना होता है, उतना चमकता है, ऐसा पत्थर दूसरा नहीं होगा और इसकी उम्र भी और पत्थरों की अपेक्षा तीस गुणी है। तीस गुणी, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस कोटा स्टोन को सरकारी काम में जहां-जहां उपयोग होता है, वहां फर्श के रूप में कोटा स्टोन का ही उपयोग करें।

मेरी यह भी मांग है कि अन्य प्रदेशों को भी लिखें और निवेदन भी करें कि वह भी इस पत्थर का उपयोग करें क्योंकि यह चलने-फिरने के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मेरी यह मांग है कि भारत सरकार को भी यह लिखें कि भारत सरकार भी इस कोटा स्टोन का उपयोग करे तो कोटा स्टोन का उद्योग फलेगा-फूलेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया कि भिक्षावृत्ति नहीं होने देंगे। हां, यह बहुत अच्छी बात है कि भिक्षावृत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन उनके पुनर्वास की योजना हमारे पास है क्या? क्यों नहीं हम पुनर्वास की योजना बना रहे हैं? उनकी पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए ताकि भिक्षावृत्ति रुके और राजस्थान भीख मांगने वालों से मुक्त हो, यह सब चाहते हैं परन्तु इस बारे में हम सोचते नहीं हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, हम खेती के बारे में विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम खेती के बारे में विचार कर रहे हैं। हम जो भी खेती कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसके कारण से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। हम डी.ए.पी. का उपयोग कर रहे हैं, हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, हम पेस्टीसाइड का उपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमको किसान का हित चाहिए, देश का हित चाहिए तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें। सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें। प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी। माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज सहयोग करें। सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए। अभी चुनाव थोड़े ही हैं जो आप गौ-माता पर जोर-जोर से बोल रहे हो? माननीय सदस्य, आप थोड़ा आसन का निर्देश भी मानें। विराजिए। अब आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी। माननीय सदस्य, विराजिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप भी विराज जाइए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप तो बहुत अनुशासित सदस्य हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): एक मिनट, यह तो जरूरी बात है। इन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो यहां पर ठीक नहीं है, मैं यह बताना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने एक बहुत बड़ा चार्ज लगाया। माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार गौ-माता की सेवा नहीं कर रही है, बूचड़खाने और कत्लखाने खोल रही है, आप यह इसमें से हटवाइए।

श्री सभापति: जो भी असंसदीय होगा, सब हटा देंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इसलिए हटवाइए क्योंकि यह सरकार नन्दी-शालाएं खोल रही है, गौ-शालाएं खोल रही है और गौ-सेवा को अपना धर्म समझती है। बूचड़खाने और कत्लखाने इन्होंने खोले होंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग विराजिए-विराजिए। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। प्लीज आप विराजिए। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें। किसी का अंकित नहीं होगा। सिवाय श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज, मंत्री महोदय, आप सहयोग करें। सहयोग करें। मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें। यह सबका व्यक्तिगत मामला है। सबको गाय पालनी चाहिए और सबको यह करना चाहिए। प्लीज सहयोग करें। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब। माननीय राठौड़ साहब। किसी का अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें। श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारा राजस्थान विषमताओं से भरा हुआ राज्य है। कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर बंजर जिले हैं, तो कहीं पर हरे-भरे उपजाऊ जिले हैं, इन सबका समावेश करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है, वह पूरे राजस्थान के आमजन के हित के लिए है। बंजर जिलों के लिए भी राशि आबंटित की तो उपजाऊ जिलों के लिए, रेगिस्तानी जिलों के लिए, सबके लिए अलग-अलग नीति बनाकर सबका समावेश इस बजट में किया है जो राजस्थान के इतिहास में सबसे अच्छा बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है।

गांधी दर्शन की हमारी, गांधीजी के सिद्धांतों पर, गांधीजी की 150वीं जयंती पर मुख्य मंत्रीजी ने गांधी दर्शन के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर सरकार को इसका ट्रस्टी माना और एक आम आदमी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर इस बजट में पेश की हैं।

पूर्ववर्ती सरकार में राजकोषीय घाटा 9 प्रतिशत था जो वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार का था। हमारे पूर्व कार्यकाल में कर्ज का प्रतिशत 23.58 था जो अभी पूर्व सरकार के जाते-जाते 33.47 प्रतिशत हो गया जिससे राज्य पर ब्याज का भार अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया।

हमारी पिछली योजनाएं- सीनियर सिटीजन की, तीर्थयात्रा की योजनाएं, नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, खाद्य सुरक्षा की योजना, सामाजिक सुरक्षा की योजना, पेंशन की योजना, तरह-तरह की योजनाएं पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी थीं। उन सब योजनाओं की जब हम चुनावों में गये तो लोगों ने बड़ी तारीफ की और इन योजनाओं को पूर्व की सरकार ने बंद करने का काम किया, इनको धीमी गति से करने का काम किया, लोगों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिला। इसलिए माननीय गहलोत साहब की योजनाओं का ज़ोर शोर से गांवों में चुनावों के समय प्रचार-प्रसार हुआ और इसका लाभ हम लोगों को मिला।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

2012-13 तक राजस्व सरप्लस की स्थिति को गत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में अब तक 29 हजार करोड़ राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंचाया गया और वित्तीय कुप्रबंधन की मिसाल पेश की। गत सरकार का उदय योजना का बिजली कम्पनियों का जो पैसा था, 62 हजार करोड़ रुपये कर्ज भार, वह भी सरकार के ऊपर आया और सरकार ने जाते-जाते ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन किया कि नौ हजार करोड़ के सभी विभागों में बिना बजट प्रावधान के कार्य स्वीकृत कर दिये।

अभी यह कह रहे थे कि इस पर रोक लगा रखी है, उस पर रोक लगा रखी है। आपने बेरोकटोक स्वीकृतियां जारी कीं, जिसका कोई अंदाजा नहीं, जिसका कोई बजट में प्रावधान नहीं, तो उन सब वित्तीय स्थिति को ठीक करने में सरकार को समय लगेगा। सरकार विचार करके उसको व्यवस्थित कर रही है। वर्तमान में इस प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने शुरूआत की है।

वर्तमान में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.19 प्रतिशत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी वर्षों में मुख्य मंत्रीजी की नीतियों के तहत 3 प्रतिशत से भी नीचे के स्तर पर हमारी सरकार ले आएगी।

साथ ही, कुल ऋण एवं अन्य दायित्व, जोकि वर्तमान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.13 प्रतिशत था, मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी अपने कुशल प्रबन्धन से इसको भी 25 प्रतिशत के आस-पास लाने का प्रयास कर रहे है, जो अभी इस बजट से और उनकी नीतियों से महसूस हो रहा है।

सहकारिता के क्षेत्र में 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया 9 हजार 513 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये। 20 लाख 46 हजार किसानों को राहत दी गयी। एक लाख 10 हजार किसानों की जमाबंदी में, जो ऋण के दाखिले थे, उनको हटाने का काम माननीय गहलोत साहब ने किया और उन किसानों को बहुत बड़ी राहत हुई।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में फसली ऋण, अल्पकालीन ऋण 16 हजार करोड़ रुपये के मुख्य मंत्रीजी ने सहकारिता मंत्रीजी ने आनलाइन प्रारम्भ कर दिये। जो किसानों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे और बारबार विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि फसली ऋण कब मिलेगा, इसकी शुरूआत मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने की है।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

कृषक कल्याण कोष बनाया। इससे पूर्व भी सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता की सोच गांधीजी की थी और हमारे मुख्य मंत्रीजी की भी है। पिछली सरकार में मुख्य मंत्रीजी ने को-आपरेटिव सैक्टर में एक उनके मन में यह था कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत सहकारी समिति से जुड़े। उन्होंने अपने बजट में भी कहा था। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र को एक प्रयोग के तौर पर सभी ग्राम सहकारी समितियां, ग्राम पंचायतों में खोलकर सभी काश्तकारों को लाभ देने का राजस्थान में उदाहरण उन्होंने पेश किया।

पूर्व सहकारिता मंत्री भी अभी यहां विराजमान हैं परसादीलाल जी, और आज मुझे खुशी है कि राजस्थान में सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है, जिसमें हर ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति है। जिससे काश्तकारों को उसका लाभ मिल रहा है और सबसे ज्यादा जिले में, चाहे ऋण माफी हो, चाहे और कोई योजना किसानों की आती है, तो उससे लाभ मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस बात को भी मुख्य मंत्रीजी आगे बढ़ाएं।

वैसे भी मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व सरकार में भी भवनों की व्यवस्था की, गोदामों की व्यवस्था की और इस पर चिंता की। सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में भी 100 जी.एस.एस. के गोदाम बनाने के और 20 के.वी.एस.एस. के बड़े गोदाम बनाने के, जिसमें आपका डी.ए.पी., यूरिया और किसानों के खाद-बीज सुरक्षित रह सकेंगे और उनको समय पर मिल सकेंगे। यह मारामारी नहीं होगी कि जो पूर्व सरकार के अंदर थानों में किसान लाइनें लगाकर डी.ए.पी. और यूरिया ले रहे थे और लट्ठ पड़ रहे थे, तो यह व्यवस्थाएं करने का जो काम किया है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी बहुत ही बधाई के पात्र हैं।

पशुपालन की बड़ी बात हो रही थी और अभी माननीय सदस्य बड़ी चिंता कर रहे थे। बीफ बेचने में हिन्दुस्तान नंबर वन, माननीय प्रधान मंत्री के बनने के बाद नंबर वन पर है। कहां से यह व्यवस्था हुई, यह तो पता नहीं, लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी पर जो आरोप लगा रहे थे, उनकी सोच को आपको सराहना चाहिए कि अशोक गहलोत जी ने अपने पिछले कार्यकाल में सभी गौशालाओं को अनुदान देने का फैसला किया और 9 महीने का अनुदान दिया है। आपकी सरकार ने गायों के प्रति इतनी चिंता व्यक्त की कि माननीय

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

वसुन्धरा राजे जी ने उन गौशालाओं का अनुदान बंद करने का काम किया और आपकी चिंता बड़ी दयनीय चिंता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): साहब, अभी तो बोले ही नहीं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बोलेंगे कब? आप देखें कि गौशालाओं के लिए मुख्य मंत्रीजी ने हर पंचायत समिति के ऊपर एक-एक गौशाला खोलने की बात कही, नन्दी गौशाला, मैं मुख्य मंत्रीजी के इस कदम का स्वागत करता हूं। साथ ही, मैं यह निवेदन करता हूं कि हर पंचायत के अंदर भी किसी न किसी योजना से जोड़कर इसको लागू किया जाए।

इसके साथ ही, आवारा पशुओं के मामले में, जो निराश्रित पशु हैं, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी ने चिंता की। राजस्थान के इतिहास में पहले मुख्य मंत्री हैं अशोक जी गहलोत, जिसने इस बात की चिंता की कि आवारा पशु, उधर से एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 40-40 किलो प्लास्टिक की थैलियां गायों के पेट से निकल रही हैं, गायें मर रही हैं। मुख्य मंत्रीजी की भावना, चुनाव जीतते ही मुख्य मंत्रीजी ने यह चर्चा की मेरी समझ में यह आया। सभापति महोदय, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका बोर्ड को बुलाया और एक बैठक की कि नगरपालिका की एक गौशाला बने और जितने भी आवारा जानवर हैं, गौवंश है, उन सबको उस गौशाला में प्रवेश कराएं। मुझे खुशी है कि गंगापुर नगरपालिका ने पहली ऐसी गौशाला बनायी और माननीय गौ-पालन मंत्री, प्रमोद भाया जी, माननीय सदस्य पानाचन्द जी और मैं स्वयं उस गौशाला का उद्घाटन करने गये। 211 गायें, जो गंगापुर नगरपालिका में ऐसे ही घूमती थीं, उन सारी गायों को हमने उस गौशाला में प्रवेश कराया और गुड की लापसी खिलाकर स्वागत किया। वहां पर चारे के गोदाम, खाखले के गोदाम, छाया की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं कीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): साहब, अभी इस पर बोलें तो हैं ही नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप बोलने ही नहीं देना चाहते हो।

श्री सभापति: सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सौर ऊर्जा की बात की। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा, हर तरह का पहलू छुआ है कि बंजर भूमि क्या काम आ सकती है। मुख्य मंत्रीजी की सोच को सबको सराहना चाहिए कि बंजर भूमि का भी उपयोग हो। सौर ऊर्जा के पम्प सैट किसान लगाते थे। मुख्य मंत्रीजी ने 2010-11 में 2011-12 में पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी। सौर ऊर्जा नीति में किसान अपने खेत में सौर ऊर्जा से कनेक्शन लेता, उसको 86 प्रतिशत अनुदान राजस्थान की सरकार देती थी, 14 प्रतिशत पैसे में वह लगाता। आज इनकी सरकार में..(व्यवधान)

श्री सभापति: सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें। श्री मंजीत धर्मपाल।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 60 प्रतिशत अनुदान रह गया है। वह अनुदान कम किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें। श्री मंजीत धर्मपालजी।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि बजट प्रस्ताव 2019-20 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जिसको इस सदन में सदन के नेता ने 10 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में सदस्य के रूप में पहली बार निर्वाचित होकर आया हूं। हालांकि मेरे पिता स्व. चौधरी धर्मपाल जी, इस सदन के तीन बार सदस्य रहे और उन्होंने अपने तीनों कार्यकाल में मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं एम.बी.ए. तक शिक्षित हूं और एक शिक्षित नौजवान के रूप में मैंने इस 55 पृष्ठीय बजट को पढ़ने और समझने का प्रयास किया। लेकिन जितनी अधिक बार मैंने इसको पढ़ा और समझने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा मुझे निराशा हाथ लगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे पिता के परम मित्र और इस सदन के उप-नेता के द्वारा बजट के ऊपर दिये गये उनके विचारों को सुनकर मैंने यह जानने का प्रयास किया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की खुशहाली के लिए जो एक लाख 16 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, वह पैसा कहां से आएगा।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, मेरी ही तरह इस सदन के अधिकतर मेरे साथी सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं। मोटे तौर पर गांव का आम व्यक्ति यह कहता है कि कर के तौर पर जो पैसा सरकार हम सबसे लेती है, उसी को हम सबके और राज्य के विकास पर खर्च करती है।

आदरणीय सभापति महोदय, बजट के पश्चात् आपके द्वारा दी गई पुस्तकों में से एक एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2019-20 शायद मैं खोलता भी नहीं, उस दिन उप नेता के बजट पर भाषण सुनने के बाद मेरी जिज्ञासा हुई और जब मैंने इसे पढ़ना चालू किया तो एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2019-20 के पृष्ठ नम्बर नौ पर सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर वेतन के रूप में 55 हजार 785 करोड़ रुपये, ब्याज के रूप में 23 हजार 137 करोड़ रुपये, पेन्शन के रूप में 22 हजार 589 करोड़ रुपये, यानी कुल 1 लाख 11 हजार 486 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जैसा मैंने कहा गांव का आदमी सोचता है कि सरकार जो कर से पैसा लेती है उसी को आगे हमारे विकास पर लगाती है। तो कर के रूप में आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के पास जो पैसा आएगा, वह है 73 हजार 742 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, मैं यह देखकर अचम्भित रह गया कि कुल कर संग्रहण का 151 प्रतिशत सरकार पेंशन, ब्याज और वेतन के रूप में दे देगी। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो प्रदेश की जनता को सरकार ने सब्जबाग दिखाया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इसको कैसे पूरा करेगी?

आदरणीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने इस बजट को बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बजट बताया है। हालांकि मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं लेकिन मुझे याद है फरवरी 2019 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी-बड़ी घोषणाओं का अम्बार लगाया था। उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात कही थी, लाखों बेरोजगार युवाओं को साढ़े तीन हजार रुपये मासिक भत्ता देने की बात कही थी और खुशहाल राजस्थान का सपना दिखाकर, घोषणाओं का अम्बार लगाकर बजट प्रस्तुत किया था। माननीय सभापति महोदय, अगर इन घोषणाओं का असर प्रदेश की जनता पर होता तो जो हश्र सत्तारूढ़ दल का गत लोक सभा चुनाव में हुआ है वह हश्र उनका कभी नहीं होता। मेरा मानना है कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में सत्तारूढ़ दल के साथ ऐसा

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

पहली बार हुआ है कि पच्चीस की पच्चीस लोक सभा सीटों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी।

आदरणीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के मेरे साथी कहते हैं कि लोक सभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को घमंड हो गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने घमंड देखा था जब आप 2018 में चुनने के बाद इस सत्ता में आये थे। आपने कैसी-कैसी घोषणाओं का अम्बार लगाया, कैसे-कैसे किसानों को सपने दिखाये, रोजगार के माध्यम से, साढ़े तीन हजार रुपये भत्ते के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाये, उनका असर हुआ। अगर आज अपन लोक सभा चुनाव को मानें तो कांग्रेस के मात्र 15 विधायक इस सदन में होते और भारतीय जनता पार्टी 185 विधायकों के साथ सदन के अन्दर सत्ता में बैठी होती।

माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम आप रुक-रुककर कर रहे हैं वह काम इस बजट के माध्यम से आपने एक बार दुबारा किया है और कृपया ऐसा न करें। आप किसानों और बेरोजगार युवाओं के घावों को कुरेद-कुरेदकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसान को ऋण राहत प्रमाण पत्र तो मिल गये, उनको लेकर वह गली-गली घूम रहा है, बैंक के दरवाजों तक घूम रहा है। न रबी का लोन मिला, न खरीफ का। बजट की घोषणा अनुसार सरकार कहती है 16 हजार करोड़ का सहकारी ऋण और बांटेंगे, यह भी पता नहीं कब तक होगा। बेरोजगार युवा रोज सुबह उठकर बैंक जाता है और अपने अकाउंट को चैक करता है कि कहीं रात को सरकार ने साढ़े तीन हजार रुपये, जो भत्ता उनको देना था जिसकी घोषणा उन्होंने की थी, कहीं आ गया हो तो उसके भी अच्छे दिन आ जाएं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं स्वागत करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे फेमस औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा उसी के अन्दर है, शाहजहांपुर उसमें आता है, घिलोठ उसमें आता है। मैं स्वागत करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी का, उन्होंने

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

कहा कि हम नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, अगर वह इसके साथ जोड़ते कि जिस किसान की जमीन इन औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए जाती है तो उस किसान के बेटे को उसी कम्पनी के अन्दर रोजगार मिलेगा, तो मैं इसका बहुत जोर से स्वागत करता और आगे चलकर उनको धन्यवाद देता। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहीं भी इसकी बात नहीं की। जो शिक्षित युवा है वह कम्पनी के दरवाजे पर अपनी सी.वी. लेकर जाता है तो कम्पनी का गार्ड सी.वी. देखकर उसको कहता है, आप कौनसे क्षेत्र से आये हो। वह कहता है, साहब, मैं मुण्डावर से हूं, तो कहता है कि आपको यहां पर इस कम्पनी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हो। तो क्या, सभापति महोदय, जिस किसान की खूड़, दो खूड़ जमीन है, बीघा-दो बीघा जमीन है, आज जब उसका बेटा उस फैक्ट्री में नौकरी मांगने जाता है तो क्या वह यह सुनने के लिए है कि आप इसके लायक नहीं, आप इसके अन्दर काम नहीं करेंगे? पानी हमारा जाता है, प्रदूषण हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाती है तो वे शिक्षित नौजवान कहां पर जाए, जाकर नौकरी किससे मांगे? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जब वे बजट पर अपनी रिप्लाई दें तो एक पालिसी के तहत, जिस तरीके से गुजरात के अन्दर, मध्य प्रदेश के अन्दर 70 से 80 प्रतिशत लोकल लोगों को रोजगार दिया जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है उसी तरीके से एक पालिसी बनाकर यहां के लोगों को रोजगार दिया जा सके जिससे हमारे यहां के युवाओं को, जो शिक्षित युवा है उसको दर-दर ठोकर नहीं खानी पड़े।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना है डी.एम.आई.सी., देहली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर। मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन ली जानी है। सभापति महोदय, करीब 540 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति में है जिसका कुल मुआवजा 470 करोड़ रुपये के करीब बनता है, सरकार ने आज तक सिर्फ 9 करोड़ रुपये उसमें बांटे हैं वह भी सिर्फ दो गांवों के अन्दर।

आदरणीय सभापति महोदय, अब जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, सरकार ने केवल 128.64 करोड़ की पेमेंट के लिए और आगे कराया है, मैं जानना चाहूंगा पीछे जो 331 करोड़ रुपये बकाया रह जाते हैं, गरीब किसान

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

वहां पर रोजी-रोटी के लिए मजबूर है, वहां पर बुवाई नहीं कर पा रहा है, आवश्यकता अनुसार अपनी बेटियों की शादियों के लिए और कोई अन्य काम के लिए उस जमीन को बेच नहीं पा रहा है। सरकार से मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय बजट की रिप्लाईं करें तो कम से कम इसका जवाब दें, जो 331 करोड़ रुपया किसान का बकाया है, सरकार कब तक दे देगी? अपन बात करते हैं किसान की, उनकी आमदनी बढ़ाने की, पर उनकी जमीन लेने के बाद भी छह साल हो गये, सात साल हो गये सरकार को जमीन को लिए हुए, पर आज तक किसान बाट देख रहा है कि उसका मुआवजा उसको कब तक मिल जाएगा। (व्यवधान) भाई साहब, पहले सरकार आपकी थी, जमीन आपने एक्वायर की थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, आज सुबह ही मुझे 295 के तहत मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय का मुद्दा उठाने का मौका मिला था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। जैसा मैंने सुबह कहा कि आज वह राजकीय महाविद्यालय प्राइमरी स्कूल के अन्दर चल रहा है, जिसके भवन की हालत बहुत ही सोचनीय है, वहां पर लैक्चरर्स की बहुत भारी कमी है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जिस तरीके से सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने 18 कालेजों की बिल्डिंग बनाने की बात कही, मुझे भी बहुत खुशी होती क्योंकि बानसूर से लगता हुआ मुण्डावर क्षेत्र है और बानसूर से पहले मुण्डावर में कालेज खोलने की घोषणा हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बानसूर के लिए तो बिल्डिंग के फंड का पैसा दिया, पर मुण्डावर को भूल गये। तो मैं वापस कहना चाहूंगा, जब मैंने जल पर बोला था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वहां सरकार उसके साथ दुभांत करती है और जहां कांग्रेस का विधायक है उसको फंड देने का काम करती है। अपन बात करते हैं शिक्षा की, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी बजट का रिप्लाई करें तो कम से कम पुन: एक बार बानसूर के साथ मुण्डावर को जोड़कर उसकी जमीन आबंटन का और उसकी बिल्डिंग बनाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अवगत कराया कि नीमराणा, शाहजहांपुर और घिलोठ तीन बड़े औद्योगिक क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, पर एक भी बड़ा ट्रोमा सेन्टर, एक भी बड़ा हास्पिटल, सरकारी अस्पताल पूरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार इस बजट का रिप्लाई करे तो कम से कम उन परिस्थितियों को देखकर वहां पर एक ट्रोमा सेन्टर और एक बड़े हास्पिटल की घोषणा कर वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करे।

आदरणीय सभापति महोदय, अपन सब थानागाजी की घटना को जानते हैं। जब थानागाजी की घटना हुई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, प्रदेश के उप-मुख्य मंत्री जी और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता थानागाजी पहुंचे। उस दिन 16 मई को प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने अलवर में दो एस.पी. आफिस खोलने की घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, करीब दो महीने पूरे होने जा रहे हैं, वहां पर आज तक दूसरा एस.पी. नहीं बैठाया गया है। क्या ऐसी संवेदनशील सरकार है? वहां रोज, दिन-प्रति दिन अपराध बढ़ते जा रहे हं। जैसा कि अभी आज सुबह माननीय मंत्री जी रिप्लाई कर रहे थे कि हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के गुंडे हैं वे यहां पर आकर आश्रय लेते हैं। तो साहब, मेरा क्षेत्र तो पूरा हरियाणा के लोग नजदीक बसता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र बड़ा है और हरियाणा के नजदीक है। सरकार जो दूसरा एस.पी. आफिस खोलने का विचार कर रही है, उसको नीमराणा में स्थापित कर वहां की जनता को राहत पहुंचाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह। एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया गया।

श्री लाखन सिंह।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री लाखन सिंह (करौली): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं करौली विधान सभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनकर आया हूं। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने 10 जुलाई, 2019 को इस सदन में जो बजट पेश किया, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है, उसकी हम सराहना करते हैं कि ऐसा जोरदार और शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। यह बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्पित बजट है। इस बजट को पेश करने के बाद राजस्थान के हर वर्ग में इसकी तारीफ है। इस बजट में समाज के कमजोर वर्ग को, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को फायदा देने की कोशिश की गयी है। वह चाहे मजदूर हो, चाहे खेत में काम कर रहा किसान हो, उन सभी को समर्पित यह बजट है। यह बजट उस कमजोर आदमी को ताकत देने की दिशा में कदम रखता है।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, इन्होंने पहली बार, पहले बजट में 75 हजार नई नौकरियां देने की घोषणा की है। राजस्थान का बेरोजगार युवा एक आशा लगाए देख रहा था कि हमें सरकारी नौकरियां मिलें और आपने उनकी आशाओं को पूरा करने का काम किया। इसके लिए राजस्थान की जनता की ओर से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री लाखन सिंह)

सभापति महोदय, प्रदेश में डामर सड़क से वंचित 500 से अधिक आबादी वाले गांवों, ढाणियों को जोड़ने की बात कहीं गयी है। यह अपने आपमें अनूठी पहल है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डामर की सड़क पर चलने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। प्रदेश में पहली बार किसानों के लिए किसान सेवा पोर्टल केन्द्र शुरू किया जा रहा है। जिससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा।

सभापति महोदय, आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी, गौ शालाएं खोलने की घोषणा की है। इससे समस्त किसान वर्ग मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। जब फसल होती है तो किसान रात के वक्त भी खेत में जाकर पहरा देता है कि कहीं रात को जो आवारा गायें डोलती हैं, अगर खेत में आ गयीं तो एक रात में ही पूरे खेत को खतम कर देंगी। इन सारी बातों को देखकर मुख्य मंत्री जी ने यह नन्दी, गौ शाला का काम किया है, यह सराहनीय काम है। हर किसान इसके लिए इनको धन्यवाद देता है।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवारों में होने वाले विवाह के लिए अधिक संबल देने की दृष्टि से प्रदेश में मुख्य मंत्री कन्यादान योजना चलाने की घोषणा की है। इस योजना से गरीब, कमजोर तबकों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय, साथ ही हमारे मुख्य मंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्द को समझते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वृद्धजनों के लिए वृद्ध पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी की है। यह भी एक सराहनीय कदम है। इन सभी के लिए हमारी पार्टी मुख्य मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

लेकिन इस बजट में पूर्वी राजस्थान खास तौर पर करौली जिला जो डांग क्षेत्र में आता है, को चंबल का पानी देने के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि यहां पर पीने के पानी की बड़ी विकट समस्या है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा इस जिले को पीने के पानी के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। यह मेरी मुख्य मंत्री जी से विशेष मांग है।

(श्री लाखन सिंह)

करौली जिले की इंजीनियरिंग कालेज जो कि भरतपुर में संचालित है, एवं रोडवेज डिपो जो हिंडौन में संचालित है, इन दोनों को करौली जिले में संचालित किया जाए। यह भी मेरी एक मांग है।

करौली जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने वाली योजना के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। पहले जब कांग्रेस सरकार थी, तो रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया गया था। उस समय बहुत धन्यवाद दिया गया अशोक जी गहलोत को। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उस योजना को बंद कर दिया गया। मेरा पुन: मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना को दुबारा से चालू किया जाए। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

करौली चिकित्सालय को एक जगह शिफ्ट किया जाए क्योंकि करौली में करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक बड़ा हास्पिटल बनाया गया है, जहां पर जाने के लिए सुविधा नहीं है। जाने में बड़ी दिक्कत है, उसको एक जगह शिफ्ट किया जाए। पुराना जो हास्पिटल है, उसको सैटेलाइट हास्पिटल के रूप में संचालित किया जाए। जिससे कि शहर की जनता को नजदीक ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। हमारे यहां पर पीएचसी की बड़ी आवश्यकता है। पीएचसी के लिए 2 जगह मैंने मांग की है। ग्राम कटकड़ और कोटरी में 2 जगह पीएचसी स्थापित की जाए।

सभापति महोदय, करौली शहर में बाइपास का निर्माण किया जाए। करौली जिले की मासलपुर तहसील को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। मासलपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा जिला हैडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कालेज खोला जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में कटकड़, खींप का पुरा एवं मासलपुर में जीएसएस स्वीकृत किए जाएं। जिससे डांग क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ सकें। मासलपुर स्टोन पार्क के बारे में भी कुछ प्रबंध किए जाएं। जिससे करौली जिले को पिछड़ेपन से छुटकारा मिल सके। अत: मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए संशोधित बजट में शामिल किया जाए। करौली जिले में विकास कार्यों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनिया।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आज बजट पर चर्चा करते हुए बड़ा हर्ष है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

सभापति महोदय, मैं एक किसान परिवार से आती हूं। सम्माननीय मुख्य मंत्री जी का जब मैं बजट भाषण सुन रही थी तो सबसे पहले उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। किसानों के साथ ही समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, हरेक की भावना को देखते हुए, 1 हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की।

सभापति महोदय, मेरे लिए यह बड़ी खुशी है, हर्ष है और मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इसके तहत किसानों को उनकी कृषि का, उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। वह सही समय पर मंडी में पहुंचा सके, इस तरीके से हर उस समस्या से जब वह गुजरता है मंडी तक पहुंचने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है।

सभापति महोदय, पिछले दिनों पानी के ऊपर भी चर्चा रही थी। किसान बजट के अंदर, सम्माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच दर्शाती है कि उस गम्भीर विषय पर पूरे सदन में चर्चा रही थी।

(17.00 बजे)

आज उन्होंने बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने की जब बात कही तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। गिरते भूजल को बचाना, किसान को उन्नत खेती की तरफ लेकर जाना और कम लागत पर अच्छी उपज वह ले सके इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज काफी सदस्य गोपालन पर जरूर बोल रहे थे। मैंने पहले भी बोला कि मैं किसान परिवार से आती हूं। राजनीति में आए मुझे साढ़े पांच वर्ष हुए हैं। मैं जब गांवों में जाती हूं तो महसूस करती हूं, चाहे वह शहर के नजदीक लगते गांव हों, खेत हों। गांव के लगते जो खेत हैं उनमें किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। काफी गरम राजनीति गौ वंश पर होती है। वोट बटोरने के लिए की जाती है। आए दिन हादसों का कारण बनते हैं। जो लोग वोटों की राजनीति करते हैं, जब एक्सीडेंट होता है या गाय रोड पर मर जाती है तो उसे उठाने के लिए कोई नहीं आता है। गायें प्लास्टिक खाती हैं, कचरा खाती हैं तो उसके बारे में कोई गम्भीर विषय नहीं सोचा जाता है। आज मैं धन्यवाद देती हूं कि गोपालन विभाग को 145 प्रतिशत बजट की बढ़ोतरी हुई है, केवल वोटों की राजनीति करने का काम नहीं किया है। किसान को उसकी उजड़ती हुई फसल से बचाने के लिए और आए

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यह कार्य जो किया है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं और उनकी सराहना करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इससे जुड़ा हुआ एक वाकया जरूर बताना चाहूंगी, 2015-16 की बात है। मेरे क्षेत्र नवां गांव के किसानों ने क्योंकि मैंने देखा है कि किसान अपने गांव से गायें अपने क्षेत्र से उठाकर दूसरे गांव की तरफ छोड़ देता है, दूसरे वाले उठाते हैं, तीसरे की तरफ छोड़ देते हैं और यह एक लड़ाई का कारण बन जाता है। इस गम्भीर समस्या को लेकर, 2015-16 की बात जब मैं कर रही हूं, नवां गांव के किसान एसडीएम कोर्ट में गायें लेकर घुसे अपनी व्यथा बताने के लिए, जब एसडीएम साहब के पास पहुंचते हैं तो एक रात उन्हें हवालात में गुजारनी पड़ती है। वह कहां जाए अपनी व्यथा बताने के लिए? आज उस समस्या की जब बात की जा रही है तो यहां पर तरह-तरह के उदाहरण पेश किये जा रहे हैं या राय दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्ष में आप क्या कर रहे थे जब आपका राज था?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब उनका पिछला कार्यकाल था, उस दौरान बिजली की कीमतें हैं किसानों के लिए उनकी बढ़ोतरी नहीं की थी और इस बार भी उन्होंने इसी बात का, इसी सोच का उदाहरण देते हुए आने वाले इन पांच वर्षों के अंदर कृषि बिजली की बढ़ोत्तरी न करके किसानों को उसी मूल्य पर दी जाए ताकि किसानों को अतिरिक्त भार न झेलना पड़े इसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं महिला हूं और महिला का जब जिक्र आता है तो सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1000 करोड़ की प्रियदर्शिनी इंदिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा की है उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इसके तहत हमारी जो महिलाएं हैं, पीड़ित हैं, उनके पुनर्वास सम्बन्धी गतिविधियां सम्पादित करने के लिए, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिए, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता देने के लिए और वह अपना कोई छोटा-मोटा बिजनस कर सकें, इसके लिए सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह घोषणा की है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूं कि यह कितना बड़ा सहयोग हमारे लिए होगा।

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, प्रतिदिन होने वाली जो घटनाएं हैं बच्चियों के लिए, अपराध जो हो रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो बच्चियां हैं, राजकीय स्कूल में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करने की भी घोषणा सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। यहां पर सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगी कि यह अकेले सरकारी स्कूलों में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में भी इसे लागू किया जाए, इसके लिए भी मैं मांग करती हूं ताकि हमारी बच्चियां भविष्य में अपनी आत्मरक्षा कर सकें और उनमें एक आत्म विश्वास भी रहे कि वह असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़े होने के लिए सक्षम हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं खिलाड़ी हूं, खेल जगत से आती हूं और खेल का जिक्र न करूं तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं रहेगा। 2010 कामनवैल्थ गेम्स में जब मैं मैडल जीतकर आई थी, मुझे आज भी याद है, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस तक इतना जोरदार स्वागत किया गया था। पूरा जयपुर शहर स्वागत के लिए जगह-जगह खड़ा था इसका लाइव टेलीकास्ट किया था। एक सामान्य परिवार से आने वाले खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है जब राज्य का मुखिया उसके लिए रात्रि भोज देता है, प्रोत्साहन राशि देता है और डाइरेक्ट डीएसपी पद की घोषणा करता है। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी, राज्य के सभी, चाहे वे मंत्री हैं, नेता हैं, कोई भी हैं, वह वहां पर मौजूद थे। मैं स्टेज पर हूं, मेरे पति द्रोणाचार्य अवार्डी, वीरेन्द्र पूनियांजी हैं, सम्माननीय मुख्य मंत्री, श्री अशोक गहलोतजी हैं, राज्यपालजी हैं। हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है और पूरे प्रदेश में एक पहचान मिलती है, एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने के लिए ताकि हम देश के लिए मैडल जीतकर लाएं। 2014 के एशियन गेम्स, कामनवैल्थ गेम्स जब हुए और हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी मैडल जीतकर आए थे वे भी इसी प्रकार के प्रोग्राम का इन्तजार कर रहे थे कि उन्हें भी सम्मान मिले और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि उन्होंने भी देश का तिरंगा ऊपर उठाया है, राष्ट्र ध्वज का मान रखा है, राष्ट्र गान बजवाया है। बड़े अफसोस की बात है कि उन खिलाड़ियों को घर बैठे जाकर प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है। मैं कहती हूं कि अगर इस तरीके से खिलाड़ियों की अवहेलना की जाए तो हमारे खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रेरणा लेंगे? दूसरी तरफ 2012 ओलम्पिक में जब हमारे देश के खिलाड़ियों ने मैडल जीते थे ओलम्पिक गेम्स के अंदर, चाहे वह हरियाणा से

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

आते हों, सुशील कुमारजी हों, साइना नेहवालजी हों, विजय कुमारजी हों, चाहे गगन नारंगजी हो, सभी को बुलाकर प्रदेश के अंदर एक राज्य स्तर का आयोजन किया जाता है और उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे खेल के प्रति सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी का खेल के प्रति सोच प्रदर्शित होता है कि वह कितने गम्भीर हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पेंशन योजना और नवीन छात्रवृत्ति योजना लाने की बात की गयी है, यह खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ-साथ सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस घोषणा के माध्यम से एक बात और कही है कि एक उद्यमी एक खेल योजना, मैं खुद खिलाड़ी रही हूं तो महसूस करती थी कि जब तक हमें स्पोंसर्स नहीं मिलेंगे तब तक हम खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस नीति के तहत कोई भी घराना, किसी भी खेल को गोद लेता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है तो इसमें मैं कहती हूं कि एक नया आयाम स्थापित होगा। एशियन गेम्स और कामनवैल्थ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान के खेल गेम्स हों जिनमें सारे के सारे खिलाड़ी एक जगह पर इकट्ठे होकर खेलें। एक दूसरे से मिलने का मौका मिले, प्रोत्साहित होने का मौका मिले तो ऐसे में मैं उनकी सराहना करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं हरियाणा से आती हूं, अग्रोहा में मैंने जन्म लिया, संयोग से 2010 में कामनवैल्थ गेम्स में जब मैं पहली भारतीय महिला एथलीट बनी और मैंने गोल्ड मैडल जीता तो उसी समय हरियाणा में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सम्मानीय मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंहजी हुड्डा ने भी मुझे सम्मानित किया था। मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहती हूं कि जब मैडल जीता तो उस गांव के खिलाड़ी को उसकी मर्जी के हिसाब से एक प्राइज मनी सरकार की पालिसी के हिसाब से दी गयी थी कि वह अपने गांव में विकास कार्य अपनी मर्जी से करा सके और उस समय मुझे 72 लाख रुपये मिले थे जो गांव में विकास कार्य के लिए मेरी मर्जी से लग सकते थे। उसी तर्ज पर आने वाले खिलाड़ी अगर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और इतने मैडल हमारे आ नहीं रहे हैं तो हम उन्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस तरीके

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

से एक आग्रह यह भी करना चाहूंगी कि वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित तो करें ही साथ-साथ उसके गांव में भी उसका मान हो जाता है तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाता है और उस खिलाड़ी को लाइफ टाइम याद रखा जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि खेल ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि वह सक्षम हो जाए, वह सफल हो जाए। किसी भी समय किसी गम्भीर इंजरी से वह पीड़ित हो सकता है और उसका कैरियर बर्बाद हो सकता है।

मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगी कि जो बच्चे खेल में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में दो परसेंट कोटा जरूर मिलना चाहिए। जिस तरीके से सम्माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कामनवैल्थ गेम्स में मेरे मैडल जीतने पर मुझे डायरेक्ट डी.एस.पी. का पद राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया था, उसी तरीके से ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और कामनवैल्थ गेम्स में जो बच्चे मैडल जीतकर आते हैं, उन्हें फर्स्ट ग्रेड जाब मिलनी चाहिए, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं।

मैं सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। जिस क्षेत्र में आप देखते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खिलाड़ी वहीं से आते हैं। 2012 ओलंपिक में, 2008 और 2012 में खुद मैंने हिस्सा लिया। 2016 में सपना पूनियां ने हिस्सा लिया। सम्मानित वीरेन्द्र पूनियां जी खुद ओलंपियन रहे और मैं यहां कहना चाहूंगी कि देवेन्द्र झाझड़िया, वे भी मेरे क्षेत्र से आते हैं। इसी के साथ-साथ, एशियन गेम्स की अगर बात करूं तो शंकर स्वामी और मंजू बाला स्वामी भी वहीं से आते हैं। यूथ एशियन गेम्स की अगर बात करूं तो नितेश पूनियां, सोनू कुमार वहां से आते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो अभी हाल में चल रहे हैं, प्रदीप कुमार वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।

डैफ ओलंपिक गेम्स में रमेश कुमार ने वहां पर प्रदर्शन किया है। ठीक उसी तरह से चाहे खेल रत्न अवार्डी हों, चाहे अर्जुन अवार्डी हों, हमारे यहां पर हैं। उसके साथ-साथ राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्डी वीरेन्द्र पूनियां और अनूप सारण का भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी, जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मैडल तो जीते ही और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी वहां पर पैदा किये। इसी के साथ-साथ, राष्ट्रपति द्वारा जो अवार्ड शिक्षक को भी दिया जाता है, फिजीकल टीचर एथलेटिक्स में जसवंत पूनियां और फुटबाल में यासीन खान को भी मिला है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, लेकिन खेल को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए मैं एक मिनट का समय और लेना चाहूंगी। तकरीबन तीन सौ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीत चुके हैं। हजारों की संख्या में आज बच्चे वहां पर अभ्यासरत् हैं। चाहे देश के लिए मैडल जीतने के लिए, चाहे सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के लिए या पुलिस में नौकरी करने के लिए।

मैं यहां पर स्कूल में भी स्पोर्ट्स सब्जेक्ट को अनिवार्य करने की मांग करती हूं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 'पब-जी' नाम का एक गेम आया था, जिसके तहत बच्चों ने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त किया था। यह एक गम्भीर विषय है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल से खेलों के जरिये जोड़ देते हैं, इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वे मानसिक तौर पर मजबूत बनते हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते मैंने बहुत कुछ सीखा है, खिलाड़ी हार कर उसी पल जीतने के लिए तैयार हो जाता है कि अगली बार जब कंपीटिशन हो तो मैं तैयारी करूं और जीतकर आऊं।

खेल जिंदगी जीना सिखाते हैं, इसलिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगी, क्योंकि एक परसेंट-आधा परसेंट के लिए जो बच्चा सुसाइड कर ले, कितनी गम्भीर बात है। आज हमारे बच्चे किन परिस्थितियो से गुजर रहे होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी मजबूती देता है कि जो बच्चा ग्राउंड में हार जाता है, वह तुरन्त खड़ा होकर कहता है कि अगली बार मुझे जीतना है और अभ्यास करना शुरू कर देता है तो इस तरह जिंदगी जीना सीखता है।

सभापति महोदय, मैं खेल की गतिविधियों को देखते हुए और सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में टैलेंट को देखते हुए सम्माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मांग करती हूं कि एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दिया जाए ताकि सादुलपुर क्षेत्र से आने वाले खिलाड़ियों को तो लाभ मिले ही और होने वाले क्राइम को भी कम किया जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, आपने 2019-20

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

के इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 2019-20 का यह जो बजट है, मैं लगभग दो-तीन बार इसका अध्ययन कर चुका हूं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बजट का न तो इस प्रदेश के लिए आने वाले समय में कोई विजन है, न ही इससे हमारी युवा पीढ़ी को कोई रोजगार मिल सकता है और न ही हम इस प्रदेश के विकास को इससे आगे ले जा सकते हैं।

सभापति महोदय, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार पर हमारे सदन के नेता ने जो आरोप लगाये कि हमने वित्त प्रबंधन सही नहीं किया इसलिए राजस्थान पर इतना वित्तीय भार आया। मैं 1998-1999 की बात करना चाहता हूं। तब राजस्थान पर मात्र 19 हजार करोड़ का बोझ था। आपकी सरकार 1999 में आयी और 2003-04 में आपकी सरकार ने राजस्थान की जनता पर 55 हजार करोड़ रुपये का बोझ छोड़ा।

जो उस समय वार्षिक प्लान था, उसके तहत पूरे प्रदेश में ढाई हजार-तीन हजार करोड़ का सालाना बजट खर्च होता था। 2008 में फिर आप आये, उस समय वह कर्ज बढ़ते-बढ़ते 77 हजार करोड़ रुपये हो गया। 2013-14 में जब वापस भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो वह 77 हजार करोड़ रुपये का भार बढ़कर 1 लाख तीस हजार करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, उदय योजना के तहत 62 हजार करोड़ रुपये सरकार ने अपने खाते पर लिए जो आपकी देनदारियां थीं।

आपके कार्यकाल में डिस्कॉम पर 80 हजार करोड़ रुपये का जो घाटा आया, सरकार को मजबूरन अपने कंधों पर लेना पड़ा। आपका जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, वह 5 हजार करोड़ रुपये के घाटे में था, जिससे राजस्थान पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज आप छोड़कर गये। यही कारण रहा कि हमने अपने पांच साल के कार्यकाल में विकास भी किया और यह कर्ज बढ़कर 3 लाख 8 हजार करोड़ रुपये हुआ।

माननीय सभापति महोदय, यह कहना कि यह 3 लाख करोड़ रुपये का भार पिछले पांच साल के कार्यकाल में हुआ है, मैं समझता हूं कि 1998 से अगर आप इसकी स्टडी करें, जब-जब कांग्रेस सरकार आयी है, उसने दोगुना -तिगुना कर्जा लेकर राजस्थान का विकास किया है। जब-जब भी हम सरकार में आये, हमने कोशिश की कि इस घाटे को कैसे कम से कम किया जा सके

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और राजस्थान की फाइनेंशियल कंडीशन को सुदृढ़ किया जा सके। आपने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि हमने 9 हजार करोड़ रुपये एडिशनल बजट खर्च कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने 2013 में जो बजट रखा, जिस तरीके से आपने रेवड़ियां बांटी हैं, आपने हम पर 10 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ दिया, जो कि बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त था।

आपने रोड्स सैंक्शन कर दिये, मिसिंग लिंक सैंक्शन कर दिये, स्कूल सैंक्शन कर दिये, कालेज सैंक्शन कर दिये। आपके पास बजट में इनके लिए कोई वित्तीय प्रावधान ही नहीं था। यह कोई नयी बात नहीं है। इस बजट से यह साफ जाहिर होता है आने वाले समय में यहां रोजगार नहीं मिलने वाला। न यहां कोई उद्योग आने वाले हैं। किसानों के लिए आपने बहुत बड़ी बातें कीं। आपने सबसे पहले किसानों से ही शुरू किया है और मुझे लगा कि किसान के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं, पर मैंने जब इस बजट को पूरा पढ़ा तो पाया कि आपने गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया।

आपने किसान कल्याण कोष के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि किसानों को उत्पादन का सही मूल्य देंगे तो केन्द्र सरकार आज जो समर्थन मूल्य दे रही है, ऐसे कई जिंस हैं, जिनमें समर्थन मूल्य का पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा होता है, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कई जिंस, कई फसल हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन आदि जिन पर मार्केट प्राइस कम हो जाती है और जो केन्द्र सरकार के समर्थन मूल्य में सम्मिलित नहीं है, क्या वह हजार करोड़ रुपया आपने उसके लिए रखा है? क्योंकि समर्थन मूल्य में जो पैसा खर्च होता है, वह केन्द्र सरकार द्वारा खर्च होता है और एफसीआई के माध्यम से केन्द्र सरकार खरीदती है।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री ने एक बात कही थी कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी की जाएगी। इस तरफ वसुन्धरा जी ने और केन्द्र सरकार ने काम किया। सबसे पहले तो सोइल टैस्टिंग का काम स्टार्ट किया। प्रत्येक ब्लॉक में सोइल टैस्टिंग के लिए हमने मशींस लगायीं हैं। सॉइल में जो मिनरल्स की कमी है, उसे पहचानकर सोइल को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मिल सकें। ताकि किसान की ज्यादा उपज हो, उसके उसको अच्छे दाम मिले, इसकी तरफ भी हमने काम किया है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कृषि अनुदान, सरकारें आयीं, गयीं, कभी भी कोई फसल नष्ट होती है तो आज दिन तक किसी सरकार ने किसान को कृषि अनुदान नहीं दिया है। प्रधान मंत्री मोदी जी की एनडीए की पहली सरकार है जहां खरीफ की फसल में खराबी होती है तो 13700 रुपये खरीफ की फसल के पेटे उस किसान के खाते में जमा होने लग गये। रबी की फसल में 27600 रुपये आपके खाते में जमा होने लग गये। यह पहली सरकार है जिसमें किसानों को आज अनुदान के रूप में पैसा मिलना शुरू हुआ है।

हमारे कार्यकाल में दो बार विनियामक आयोग ने किसानों के बिल बढ़ाये, सरकार ने 2800 करोड़ रुपये का भार झेला, पर किसानों का हमने बिल बढ़ने नहीं दिया और 1998 में आपने जो रेट बढ़ाये थे उसी रेट पर आज 2019 में किसानों को बिजली मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान सम्मान निधि योजना, 6 हजार रुपये प्रत्येक किसान को देना, हर साल तीन किश्तों में देना ताकि किसान के हाथ मजबूत हों और वह खेती को आगे करता रहे। इसके अलावा समर्थन मूल्य लागू करना। प्रेक्टिकली किसान के लिए समर्थन मूल्य लागू हुआ है तो केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य लागू किया है। इसमें पूरा कैल्कुलेट किया है कि किसान जिस जिंस की खेती कर रहा है उसमें कितने उसके पैसे लग रहे हैं और उसका डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य किया है। जहां मूंग बाजार में 3 हजार रुपये के भाव में बिकता था उसका आज समर्थन मूल्य 7 हजार रुपये हुआ है और किसान मार्केटिंग सोसाइटी में 7 हजार रुपये में तुलवाता है। कपास है तो साढ़े पांच हजार रुपये में तुलवाता है। माननीय सभापति महोदय, आज अगर कपास का समर्थन मूल्य नहीं होता तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के किसान को मजबूरन 3 हजार रुपये में मूंग तौलने पड़ते क्योंकि मैं स्वयं भी खेती पर निर्भर हूं, मैं स्वयं किसान हूं, मैं जानता हूं कि किसानों की तकलीफ क्या है और उस समर्थन मूल्य को लागू किया है।

दूसरा, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां प्रत्येक किसान जो सोसाइटी के माध्यम से लोन लेता था, व्यक्तिगत लोन, उसका 50 हजार का इंश्योरेंस था उसको आज 181 रुपये में उसका 10 लाख का दुर्घटना बीमा सहकारी समिति से किया है। इसके अलावा राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो मण्डी द्वारा जो एक लाख रुपये आपके द्वारा मिलता था उसको हमारे मुख्य मंत्री जी ने

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बढ़ाकर दो लाख रुपये किया। इसके अलावा प्रत्येक कृषि कनेक्शन पर दस हजार का अनुदान दिया। दो लाख कृषि कनेक्शन दिये। इस बजट में ऊर्जा पर आप बोले कि हम एक लाख कृषि कनेक्शान देंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी से भी यह कहना चाहूंगा कि ये वे कनेक्शन हैं जो हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुए या इसको आप 2012 से 2013 तक ले जाना चाहते हो? इसको साफ जाहिर करें। इसकी भाषा में जो मुझे समझ में आया है उससे लगता है कि आपने अपने 8 महीने के कार्यकाल में जो 70 हजार कनेक्शन किये हैं उसको बढ़ाकर आप एक लाख कनेक्शन, इससे साफ मुझे लगता है कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हो। मैं यह चाहता हूं कि फरवरी, 2012 तक के जो हमने डिमांड नोटिस निकाले हैं वे हमने एक लाख कनेक्शन किये और आपने अभी 75 हजार कनेक्शन किये तो 25-30 हजार कनेक्शन पैण्डिंग हैं? क्या, मुख्य मंत्री जी, इस बजट में एक लाख कृषि कनेक्शन की जो घोषणा की है तो फरवरी, 2012 से लेकर 2013 तक की आपने घोषणा की है? इसका भी क्लीयर हो ताकि लोगों को पता लगे कि एक साल के कृषि कनेक्शन सरकार ने और हमको आबंटित किये हैं।

हमारे सहकारिता मंत्री जी कई बार इस हाउस में बोलते आये हैं कि हमने सहकारी बैंकों में लोन शुरू कर दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, मैं भी एक सोसाइटी का अध्यक्ष रह चुका हूं। आज आपकी साख सीमा तय नहीं हुई और जब साख सीमा तय नहीं हुई तो लोन देने की बात ही कहां हुई। मैं जिस जिले से आता हूं, आज एक भी किसान को लोन नहीं मिला है। जब तक आपके बैंकों में लोन का पैसा जमा नहीं होगा, जब तक सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में सरकार आपके पैसा जमा नहीं कराएगी तब तक किसान को लोन मिलना सम्भव नहीं है। अभी तो आपकी साख सीमा ही नहीं बनी है, आपने साख सीमा को आनलाइन करने का प्रोसेस में रखा है। अभी तो बरसात का टाइम चल रहा है और काश्तकार को एक महीने पहले लोन मिलना चाहिए था जब जाकर वह कर सकता था, डीएपी ला सकता था, यूरिया ला सकता था। बरसाता का आधा सीजन तो खतम हो गया है और आज दिन तक किसान को कुछ नहीं मिला है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, मुझे आप पांच मिनट बोलने का टाइम दो, मैं बहुत तर्क से बात कहना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान को लोन नहीं मिलेगा...

श्री सभापति: कनक्लूड करें। कनक्लूड करें माननीय सदस्य। प्लीज।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): तो आने वाले समय में उसका फसल बीमा कैसे होगा? सभापति महोदय, मैं तर्क से बात कर रहा हूं कि उसका बीमा कैसे होगा।

श्री सभापति: प्लीज हो गया। प्लीज, सहयोग करें। श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आने वाले समय में जिस तरीके से फसल नष्ट होगी तो उस किसान को आने वाले समय में फसल बीमा योजना का पैसा कैसे मिलेगा?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिये आप। एक मिनट विराजें आप। 28 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: एक मिनट, सुनिये तो सही। 28 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। 10-10 मिनट भी यदि आप बोलेंगे तो 280 मिनट चाहिए। मतलब 6 घंटे यदि आपको बैठना है तो मुझे एतराज नहीं है। मेरी कैपेसिटी है 6 घण्टे बैठने की। तय करिये। विराजें। शांत रहें। सदन के समय की जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने यह तय किया था कि 8 बजे हाउस एडजोर्न हो जाएगा। उस हिसाब से साढ़े पांच बजे हैं, 8 बजे यदि आपको समाप्त करना है तो दस मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा और दिये हैं उनमें से भी मुझे कुछ माननीय सदस्यों को सारी कहना पड़ेगा कि आप नहीं बोल पाएंगे। मेहरबानी करें, आप सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप योगी आदमी हो, सारी इन्द्रियों पर आपका नियंत्रण हैं तो चलने दो 11-12 बजे तक।

श्री सभापति: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब आपने यह कह दिया था, आपके नेता ने यह कह दिया था कि 8 बजे हमको हाउस एडजोर्न करना है तो फिर बार-बार तो ऐसा नहीं कर सकते हम। आपको सहयोग करना पड़ेगा, बिना सहयोग के तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज। बिधुरी राजेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: आप दस मिनट से ज्यादा बोल लिए। कनक्लूड करें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो मिनट में कनक्लूड कर लेंगे।

श्री सभापति: क्या फर्क पड़ जाएगा दो मिनट आप और बोल लेंगे तो? क्या फर्क पड़ जाएगा? बजट, बजट नहीं रहेगा? (व्यवधान) सहयोग करें, आप। दो मिनट आप बोलेंगे, दो मिनट वे बोलेंगे, फिर हर आदमी मेरे से यह कहेगा। माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। सहयोग करें आप। सहयोग करें माननीय सदस्य। आप बिलकुल सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य सुन लीजिये। 8 मिनट के बाद में मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि दो मिनट बाद आप विराज जाएं। आप को-आपरेट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, आज पिछले 8 महीने से सरकार कांग्रेस की है और पूरे पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल है। 8 महीने से यह सरकार जो अपने आपको संवेदनशील कहती है, आज पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी कमी है, वहां चारे की बहुत कमी है, पशु मर रहे हैं और आज दिन तक वहां बरसात भी नहीं है। आज भी आपने अख़बार में पढ़ा होगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में आंधी चल रहे हैं, धोरों ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। आज मनरेगा का पेमेंट है तो चार-चार महीने तक आपका पेमेंट होता नहीं है, वहां का जो आपका मिस्त्री है, मेट है उसको आठ-आठ महीने तक पेमेंट नहीं हो रहा है, लगभग 12 महीने से मैटेरियल का पेमेंट नहीं हो रहा है। बरसात से पहले आपने कंटींजेंसी रखी ही नहीं, आज पीने के पानी के लिए लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं पश्चिमी क्षेत्र से आता हूं और वहां गांवों की हालत यह है कि गांव का जो सार्वजनिक कुआ है वहां पांच मिनट पीने का पानी नहीं है और आपने पूरी गर्मी में कंटींजेंसी प्लान नहीं बनाया। इलेक्शन से पहले मार्च में आपका कोड आफ कण्डक्ट लागू

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हुआ। मैं भी 1999 में प्रधान था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मैं उस सरकार को सेंस कर सकता था, मैं उस सरकार को फील कर सकता था कि उस समय सरकार नाम की कोई चीज थी। मैं प्रधान था, अकाल राहत में 25-25 हजार लेबर चलती थी, 10 किलो गेहूं मिलते थे पर विदिन 10 दिन में उसको गेहूं मिलता था, उसको पेमेंट मिलता था।

श्री सभापति: अब कनक्लूड करिये नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं दिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अब तो हालत यह हो गयी कि रेवेन्यू में आपके ग्राम सेवक नहीं हैं, आज आपके पास वहां पटवारी नहीं हैं। जाति प्रमाण पत्र लोगों को मिल नहीं रहा है, मूल निवास प्रमाण पत्र लोगों को मिल नहीं रहा है और आम आदमी परेशान है। दूसरा, आपने अभी इसमें यह घोषणा की आरएए की कोर्ट बन्द कर दी। आपने यह कहा कि 3 लाख 50 हजार केस पैण्डिंग हैं, इनका तीव्र गति से, जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए तो क्या आम आदमी, गरीब आदमी गांव से उठकर डिवीजनल कमिश्नर के पास जाएगा?

श्री सभापति: श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह। अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये माननीय सदस्य। बिल्कुल विराजिये अब आप। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: आप वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिए, को-आपरेट कीजिए। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: विराजिए, आसन पैरों पर। बिधुरी राजेन्द्र सिंह।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में कर मुक्त शानदार बजट पेश किया गया है और 301 करोड़ की जो राहत दी गयी है, मैं उसका तहे दिल से अनुमोदन और समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों,

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

किसानों और नौजवानों को ध्यान में रखकर आगामी बजट दिया है। राजस्थान को बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा। पिछली सरकार 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़कर गयी थी। क्या किया पिछली सरकार ने, 3 लाख करोड़ का घाटा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए एक हजार करोड़ का कोष बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। राजस्थान के नौजवानों के लिए कौशल, रोजगार के लिए एक हजार करोड़ रुपये और 75 हजार नौकरियों का सृजन किया है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी माननीय श्री अशोक गहलोतजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने सैल्फ फाइनेंसिंग कालेज को गवर्नमेंट कालेज नहीं किया था। मेरे बेगूं विधान सभा क्षेत्र के दो सरकारी सैल्फ फाइनेंसिंग कालेज को सरकारी कालेज करने पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बेगूं विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहता हूं। मेरे उपखण्ड तहसील गंगरार में एक सरकारी महाविद्यालय खोलने का आदेश प्रदान कराएं।

सभापति महोदय, रावतभाटा तहसील, रावतभाटा परमाणु केन्द्र है। वहां आठ इकाइयां परमाणु की हैं। पूरे देश के नक्शे पर, पूरी दुनिया के नक्शे पर रावतभाटा का क्षेत्र है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां एक 100 बैड का हास्पिटल और ट्रोमा सेन्टर की स्थापना की जाए। मैं अपने क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और पीने के पानी की चम्बल नदी मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है। चम्बल का पानी पूरे राजस्थान के कई जिलों में जा रहा है लेकिन बेगूं क्षेत्र के गांवों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है।

मैं आपके माध्यम से रावतभाटा, बेगूं और गंगरार तीनों तहसीलों की डीपीआर बनवाकर चम्बल नदी का पानी पीने और सिंचाई की व्यवस्था के लिए करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर, बस्सी से भीलवाड़ा तक 50 किलोमीटर की सड़क को स्टेट हाइवे में सम्मिलित कराने की कृपा करें।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये गलत बात है। जब पहले हमारा देश आजाद हुआ, तीन करोड़ लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आए शरणार्थी, भारत के पहले प्रधान मंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया, वे इस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोच तीन करोड़ लोगों को विस्थापित करना, उनके लिए खाना देना, पानी देना, मकान देना, इतनी बड़ी चीज करने के बाद, यहां तो आप दस हजार लोगों का भी प्रबन्ध करने में, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास मकान नहीं थे रहने के लिए, हमारे पास जगह नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में विस्थापित आए, किसी को पंजाब बसाया गया, अम्बाला बसाया गया, हरियाणा बसाया गया, जयपुर बसाया गया।

हमारे पास उद्योग नहीं थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू हमें उद्योगों की तरफ ले गये। हमारे पास डैम नहीं थे, भाखड़ा नांगल जैसा डैम बसाया, नाथपा झाकड़ी जैसा डैम बनाया, राणातुंगा डैम बनाया, राणा प्रताप सागर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर डैम बनाया, गांधी सागर डैम बनाया, आज इन डैमों के सहारे भारत की तीस करोड़ आबादी के किसानों को फायदा हुआ। ये तीस करोड़ लोग आज इन डैमों से इर्रिगेशन के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे देश की इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवोल्यूशन लाकर, हम भारत के लोग आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाकर खाते थे। हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाकर भारत को खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया। वे ही इंदिरा गांधी थीं, जिसने पाकिस्तान के दो टुकडे किये। वे ही हमारे शास्त्री जी थे, जिन्होंने 'जय जवान-जय किसान' का नारा दिया और उनकी एक आवाज पर गांव के लोगों ने भी छतों पर गेहूं बो दिये थे।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य भाई सांगानेर से आने वाले ने बोला 1947 से 1977 तक कांग्रेस की वजह से घाटा रहा। ट्रेन हमने चलाई, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाई, पाकिस्तान के दो टुकड़े किये, सिक्किम को उस वक्त 22वां राज्य जोड़ा, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया? जो कल चन्द्रयान छोड़ा जा रहा था यह यूपीए-2 की तैयारी में था, वह भी 15 साल पहले तैयारी की थी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जिसको आप कल छोड़ने जा रहे थे।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

जहां सुई तक नहीं बनती थी, वहां पर हमने तेजस और नेट विमान बनाए, ये दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जैसी नेता दी, राजीव गांधी जैसा नेता दिया, जिसने कम्प्यूटर दिया, मोबाइल दिया, संचार क्रांति लाए। आपने कहा कि स्मार्ट सिटी बसाएंगे, चंढ़ीगढ़ शहर को जाकर देखो, प्रताप सिंह कैरो ने स्मार्ट सिटी बसाया। आपने एक गांव को भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया। एक गांव बता दो जो स्मार्ट सिटी बना हो। जो शहर घोषित किये कोई काम नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चली, बम्बई से।

जो भी राष्ट्र का विदेशी आता है, वह गुजरात में जाता है, कहां पर जाता है अहमदाबाद चला जाता है। चीन का राष्ट्रपति आएगा तो अहमदाबाद, जापान का राष्ट्रपति आएगा तो अहमदाबाद, भाई राजस्थान के जयपुर में भी ले आओ, विश्व नगरी है। राजस्थान के जयपुर में चीन का प्रधान मंत्री लेकर आ जाओ, जापान का लेकर आ जाओ...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। कम से कम हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानी दी है आपकी पार्टी के लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी। मैं आपके ऊपर एक शेर सुनाता हूं:-

उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दीया,
जिनके खूं से जलते हैं चिरागे वतन,
जगमगा रहे मकबरे उनके,
जो बेचा करते थे, शहीदों के कफन।

श्री सभापति: श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति जी, आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति जी, यह बजट आम जनता का बजट है। इस ऐतिहासिक व विकासोन्मुखी बजट पेश करने पर मैं राजस्थान की जनता की और मेरी तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। यह बजट किसान और गरीबों को समर्पित बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, व्यापारी, नौकरीपेशा, गरीब, गांव, शहर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए यह आदर्श बजट प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र

(श्री रामकेश)

में किसानों के लिए मुख्य मंत्री जी ने विशेष ध्यान रख करके किसानों के हित में एक नयी पहल करके इस बजट के माध्यम से क्रांतिकारी कदम उठाने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे देश में मनायी जा रही है। महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने की आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कोशिश की है। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत गांवों में निवास करता है और जब तक इस देश में किसानों का उद्धार नहीं होगा, किसान आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे यह कहते हुए आज बहुत खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में ईज आफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज आफ डूइंग फार्मिंग का एक नया कंसेप्ट जो इस देश में हम पहली बार देख रहे हैं, लाकर इस अवधारणा को स्थापित करने का काम किया है। मैं तहेदिल से राजस्थान की जनता की तरफ से, राजस्थान के किसानों की तरफ से मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति जी, हर माननीय सदस्य किसान के बारे में अपनी बात अपने तरीके से कह रहा है। पहली बार हमें यह देखने को मिला कि ईज आफ डूइंग फार्मिंग कंसेप्ट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों की चिंताओं को समझा, किसानों की कठिनाइयों को समझा, किसानों का जो बहुआयामी संघर्ष जिससे किसान आये दिन रूबरू होता है, खेती में बीज से लेकर दवाई, कृषि में विपणन से लेकर भण्डारण तक की जो समस्याएं किसानों की हैं उन समस्याओं को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी के लिए उन्होंने कृषक कल्याण कोष में एक हजार करोड़ रुपये का आबंटन किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे किसानों की दशा सुधरेगी उनकी उपज का ठीक मूल्य उनको मिल सकेगा। इसी के साथ-साथ आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जीरो बजट फार्मिंग से बीस हजार किसानों को जोड़ने का प्रयास किया है जिस पर दस करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है। राज्य में किसानों के हित के लिए एक लाख मीट्रिक टन डीएपी और दो लाख मीट्रिग टन यूरिया के भण्डारण की अग्रिम व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया है।

(श्री रामकेश)

सभापति जी, देखा यह जाता है कि जब किसान को खाद बीज की जरूरत पड़ती है और अपनी खेती के लिए वह जब बाजार में खाद के लिए जाता है, किस तरीके से उसको कालाबाजारी से रूबरू होना पड़ता है चाहे डीएपी का कट्टा हो, चाहे यूरिया का कट्टा हो, लागत मूल्य से दुगने मूल्य पर जाकर उसको खाद और बीज मुश्किल से मिलता है। ऐसे में उसकी जो फसल है, वह चौपट होती है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उस पीड़ा को समझा और अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम के तहत किसान मेले, गोष्ठियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन की नीति को भी इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नयी एग्रो प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट पालिसी राजस्थान में किसानों को विश्व पटल पर स्थापित करेगी। पूर्व में भी इसी सरकार की एग्रो प्रोसेसिंग पालिसी काफी सफल रही जिसके तहत राजस्थान में काफी मात्रा में फूलों, हर्बल, आंवला आदि का उत्पादन और निर्यात काफी मात्रा में बढ़ा है। किसान सेवा पोर्टल से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हर पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शाला की स्थापना से किसानों को आवारा जानवरों से मुक्ति मिलेगी।

आदरणीय सभापति जी, कुशल वित्तीय प्रबंधन किसी भी राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य में वर्ष 2010-11 में रेवेन्यू सरप्लस रहा। 2011-12 में रेवेन्यू सरप्लस रहा। 2012-13 में रेवेन्यू सरप्लस रहा और गत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 29 हजार करोड़ पहुंच गया। पूर्ण कार्यकाल में फिस्कल डेफिसिट लगातार 3 परसेंट से अधिक रहा और वर्ष 2015-16 में तो फिस्कल डेफिसिट 9 परसेंट से भी अधिक रहा जो सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य लाहोटी जी कह रहे थे कि राजकोषीय घाटा और कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर घी पीने का काम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार अशोक गहलोत जी साहब ने छोड़ी मार्च, 2014 में तो कर्ज और अन्य लायबिलिटीज का कुल भार 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ था और वर्ष 2018-19 में पूरा भार 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ पर पहुंच गया जो राज्य की जीडीपी का 33.45 परसेंट था। तो यह कर्जा लेने का काम और घी पीने का काम पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान में पीने के पानी की और सिंचाई की बहुत गम्भीर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। 2004 में पांचना बांध बन करके तैयार हुआ और केवल और केवल एक साल सिंचाई होने के बाद 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी थीं, राजनीतिक लड़ाई के कारण, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी खींचतान के कारण पांचना बांध को 2006 में बंद कर दिया और 2006 से लेकर आज 2019 तक लगातार पांचना बांध बंद है जिससे हजारों किसानों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। जिस क्षेत्र को कमांड एरिया घोषित किया गया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): पांचना बांध जिसके लिए बना, कमांड एरिये का किसान उस बांध की तरफ देख रहा है। बांध में कम से 1000 एमसीएफटी पानी अभी भी भरा हुआ है। इतना पानी भरे हुए होने के बाद भी सरकार के द्वारा पानी नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे हमारे पूरे कमांड एरिये की भूमि पूरी बंजर हो चुकी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, श्री संजय शर्मा।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पांचना बांध को जल्दी से जल्दी खोला जाए, हमारे किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का नया प्रोजेक्ट जो अभी इस बजट में प्रस्तुत किया है, मैं आपके माध्यम से इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराते हुए इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिये जिससे हमारे

(श्री रामकेश)

पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 10 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया, उस पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से पेज नंबर 4 पर पाइंट नंबर 14 पर 2008 से 2013 तक की जो उनकी सरकार थी, उसकी योजनाओं का उल्लेख किया और उन योजनाओं का उल्लेख करने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए यह कहा कि उन योजनाओं की वजह से ही वह दुबारा सत्ता में आये हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा संभवतः वह 2013 का चुनाव भूल गये और उन्हीं योजनाओं का परिणाम था कि 2013 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने केवल मात्र 21 सीट देकर कांग्रेस को उनके साथ यहां सदन में बैठने को मजबूर कर दिया था। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान का किसान 2008 से लेकर 2013 तक का आदरणीय अशोक गहलोत जी का वह शासन नहीं भूला है जिस शासन में यूरिया को लेकर उसको लाइन में लगना पड़ता था। यूरिया उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता था। यूरिया पुलिस के पहरे में बिकता था। पुलिस लाठीचार्ज करती थी। किसान रात रात भर यूरिया के लिए बैठा रहता था लेकिन उसको यूरिया नहीं मिलता था। राजस्थान का किसान इस बात को भी नहीं भूला है जब वह नकली बीज के कारण ठगा जाता था, उसकी फसल खराब हो जाती थी, उसकी फसल उगती ही नहीं थी। राजस्थान का किसान उस बात को भी नहीं भूला है, 2008 से 2013 की आपकी ही सरकार थी, 2013 में जब आदरणीय वसुन्धरा राजे जी की सरकार बनी और 2014 में आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार देश में बनी नीम कोटेड यूरिया बनाकर ब्लैकमेलिंग करने से यूरिया को रोकने का काम किसी ने किया तो वह केन्द्र की नरेन्द्र भाई मोदी सरकार ने किया। केवल और केवल इसलिए किया कि भारत के किसान को, राजस्थान के किसान को यूरिया पूर्ण मात्रा में मिले और उसको जब यूरिया चाहिये, यूरिया उसको मिले।

इसके साथ-साथ, नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार और हमारी मुख्य मंत्री

(श्री संजय शर्मा)

वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने चाहे वह ओलावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, किसान को जो खराबे का मुआवजा मिलना चाहिये था वह समय पर मिले, उचित समय पर मिले, उसके लिए सभी 200 माननीय विधायकों से आग्रह किया गया था कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर उस फसल के खराबे का जायजा लें और सरकार को रिपोर्ट देकर समय पर किसान को फसल के खराबे का उचित मुआवजा मिले, इसकी चिंता अगर किसी ने की तो वह भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने की। आदरणीय सभापति महोदय, यदि मैं ऋण माफी की बात करूं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2 लाख तक के ऋण माफी की बात की थी। उसके साथ-साथ, बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रत्येक बेरोजगार युवक के खाते में साढ़े तीन हजार रुपये प्रति माह डालने की बात भी की थी। लेकिन 2 लाख रुपये का ऋण जैसी कि मुझे जानकारी है, किसी किसान का माफ हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। लेकिन आज भी किसान इस बात की बाट देख रहा है कि बैंक उसको 2 लाख तक के ऋण का माफी प्रमाण पत्र दे। साथ ही साथ, जो बेरोजगार युवक हैं, जो मुझे जानकारी है, 3500 रुपये प्रति माह का एक पैसा अभी तक बेरोजगार युवकों के खाते में राजस्थान की सरकार के द्वारा डाला नहीं गया है। उसके साथ-साथ रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा आदरणीय वसुन्धरा राजे जी की सरकार को जिन्होंने 50 हजार तक के किसान के ऋण को माफ करके उसको ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया और साथ ही साथ उसके खाते में 50 हजार का ऋण देकर उसको ताकत प्रदान करने का किसी ने काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।

आदरणीय सभापति महोदय, यदि मैं सड़कों की बात करूं क्योंकि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सड़कों की बहुत सारी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। गत सरकार में आदरणीय वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में पांच वर्षों में जिस प्रकार से गांव गांव, ढाणी को सड़क से जोड़ने का काम किया, चाहे वह एनसीआर की सड़कें हों, चाहे राजस्थान सरकार की अलग से योजनाओं की सड़कें हों, सम्पूर्ण राजस्थान में यदि सड़कों को गांव, ढाणी और शहरों में अच्छी सड़क बनाने का काम किया तो वह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। गत सात माह में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने जो स्वीकृत कार्य थे, उनको रोका है,

(श्री संजय शर्मा)

ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है, नई सड़कों के काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं, यह काम कांग्रेस सरकार करने जा रही है।

यदि मैं बिजली की बात करूं, हम सबको ध्यान है कि जब अशोक गहलोत जी 2008 से 2013 तक मुख्य मंत्री थे उस वक्त बिजली की जो हालत थी, किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, शहरों में बहुत भयंकर कटौती हुआ करती थी। शहरों में इनवर्टर और जनरेटरों की बिक्री बढ़ गयी थी। 2013 से 2018 आदरणीय वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने गांवों में सिंगल फेस की बिजली 17 से 18 घंटे तक दी और थ्री फेस की बिजली बिना ट्रिपिंग के 6 घंटे तक दी। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार बिजली कटौती हो रही है। शहरों में मेंटिनेंस के नाम पर 5 से 6 घंटे बिजली कट रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजली कब आती है और कब चली जाती है, इस प्रकार की चर्चा हो रही है। इस प्रकार की किंवदंती जो माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ जुड़ी रहती है कि कांग्रेस आई और बिजली गयी, इस प्रकार की चर्चा सम्पूर्ण राजस्थान में हो रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अभी तो बोलना ही शुरू किया है।

श्री सभापति: दो मिनट में ही समाप्त कीजिए, अब दो मिनट ही हैं आपके लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, यदि मैं पेयजल की बात करूं, सम्पूर्ण राजस्थान में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। हमारी माताएं-बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, सब सड़कों पर पानी के लिए खड़े रहते हैं और जब सड़कों पर पानी की मांग करने जाते हैं तो प्रशासन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करता है। अमृत जल योजना जो केन्द्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस लाइन को शुरू नहीं किया जा रहा है। टंकी बनी खड़ी है उनमें पानी नहीं भरा जा रहा है। लेकिन विशेष रूप से अलवर के लिए मैं एक धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहूंगा चंबल का पानी अलवर लाने के लिए। अलवर, धौलपुर और भरतपुर के लिए जो 4718 करोड़ का जो बजट का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अलवर चंबल परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है, इसको एक समय

(श्री संजय शर्मा)

सीमा में पूरी करें। कहीं ऐसा न हो कि बजट का प्रावधान तो कर दिया लेकिन काम शुरू होगा कि नहीं होगा,....

(18.00 बजे)

अलवर और भरतपुर की जनता पानी के लिए बाट देखती रहे। इसके साथ-साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। पैट्रोल और डीजल के दामों में 4 प्रतिशत वैट बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने वृद्धि की है। हमारी राजस्थान की जनता की बहुत पुरानी मांग है। विशेष रूप से जो हरियाणा और दिल्ली से लगते हुए जिले हैं। हरियाणा और दिल्ली के बराबर यदि आप राजस्थान में पैट्रोल-डीजल के भाव कर देंगे तो निश्चित रूप से पैट्रोल और डीजल की कालाबाजारी रुकेगी। हरियाणा से आकर हमारे वहां के लोग पैट्रोल-डीजल बेचते हैं। मेरा यह मानना है कि इससे निश्चित रूप से सरकार की आय भी बढ़ेगी। एक साल के लिए यदि आप प्रायोगिक तौर पर इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और आम जनता को राहत भी मिलेगी।

श्री सभापति: कनक्लूड करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): इसके साथ-साथ एक बात और कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरासत की सम्पत्तियों को लेकर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है। डीएलसी की दरों में जिस प्रकार से 10 परसेंट से लेकर 49 परसेंट की जो वृद्धि की है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। सहयोग कीजिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं आसन का बहुत आभारी हूं कि इस पवित्र और परिवर्तित बजट वर्ष 2019-20 पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इस बजट में राजस्थान के तमाम हर समाज, हर नौजवान को एक अलग से मैसेज देने की आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने एक अपील के माध्यम से इस बजट को प्रस्तुत किया। माननीय सभापति महोदय, देश आज मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें हम

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। सभापति महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। चूंकि गत वर्ष पूरे एक साल चुनावी माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अच्छे मना पाये, इसलिए इसमें एक वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हम जिस राह में खड़े हैं हमारे प्रदेश को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रदेश के गांधीवादी सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह किसान व युवाओं और महिलाओं के साथ ही प्रदेश की आम जनता, आम आवाम के लिए कल्याणकारी बजट है। इस बजट की जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है। इस बजट की सभी वर्गों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सभापति महोदय, अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि जब तक हम वित्तीय व्यवस्था को संतुलित नहीं कर सकते और उसमें रेवेन्यू का जो घाटा है, उसे अगर हम पूंजीगत बचत से पूरा करते हैं तो वह एक अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं मानी जाती है।

महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी थी। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण रेवेन्यू सरप्लस में छोड़ी थी, जबकि पूर्ववर्ती सरकार की अविवेकपूर्ण नीति ने वर्ष 2018-19 में रेवेन्यू घाटा लगभग 29 हजार करोड़ के करीब छोड़ा है। मुख्य मंत्री ने किसानों को अग्रिम पायदान पर रखते हुए एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याणकारी कोष का गठन कर किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। ease of doing business की तर्ज पर ease of doing farming के साथ खेती को सशक्त, किसान की सोच के साथ खेती की लागत को कम करने के लिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रारम्भ करते हुए 10 करोड़ रुपये की लागत से 36 ग्राम पंचायतों के 20 हजार किसानों को शामिल करने के साथ ही उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। साथ ही राज्य में कृषि के लिए एक बहुत उपयोगी फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी दिशा देने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

चिकित्सा उप केन्द्र खोलने, जोधपुर में नवीन पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मानव के साथ-साथ पशुओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। महोदय, सम्माननीय मुख्य मंत्री

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

जी ने 2019-20 में ऊर्जा विभाग के लिए 30170 करोड़ के बजट का जो प्रावधान किया है, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11.41 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही, हमारी सरकार ने 1 लाख नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का जो निर्णय लिया था, उसमें अभी तक 75 हजार से अधिक कनेक्शन जारी कर दिये गये, जिसके लिए में माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह समय की मांग है, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी का सपना भी है। इसके लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसे जन आंदोलन बनाने के लिए नेतृत्व करें, जिससे प्रदेश के सभी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगें और हम अपने आने वाले कल की ऊर्जा की जरूरतों को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा कर सकें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सोलर पैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाए, जिससे हर व्यक्ति अपनी छत पर सोलर पैनल लगा सके। मैं चाहता हूं कि जयपुर की बिजली जयपुर पैदा हो, इसके लिए द्रव्यवती नदी के पाट पर एवं खाली जमीन पर ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा की जा सके।

महोदय, उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए प्रदेश में नया कानून बन गया है। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही देश में हमारा पहला राज्य बन गया है जो उद्यमियों को बिना किसी परेशानी के तीन वर्ष तक विभिन्न स्वीकृतियों और निरीक्षणों से मुक्त रखकर ease of doing business को साकार रूप दे पा रहा है। उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए मैं मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का भी स्वागत करता हूं।

जैसा कि आपको ध्यान है। अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान सरकार के द्वारा एक वर्ल्ड हैरिटेज कमेटी बनायी गयी। सभापति महोदय, सौभाग्य से मैं उस कमेटी का सदस्य हूं। पिछले दिनों आपने देखा कि वर्ल्ड हैरिटेज साइट पर जयपुर को डाला गया है। मुझे इस सारी भूमिका में सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी के जो दिशा-निर्देश थे, उसी के तहत आज हमारा यह सौभाग्य है कि जयपुर वर्ल्ड हैरिटेज सिटी में शामिल किया गया है।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

सरकार और उनके प्रयास के लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जयपुर एक वर्ल्ड हैरिटेज सिटी बनने में कामयाब हो सका।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की कि मैट्रो प्रथम चरण-बी का कार्य शीघ्र पूर्ण होकर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वाल सिटी में मैट्रो प्रारम्भ कर दी जाएगी। मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने मैट्रो नैटवर्क के विस्तार हेतु 13 करोड़ रुपये की लागत से द्वितीय चरण की संशोधित डीपीआर बनाने का जो कार्य प्रारम्भ किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत उनका आभारी हूं।

(18.08 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

चूंकि चरण-बी का कार्य अतिशीघ्र चालू होने वाला है, उसमें 80 परसेंट एरिया किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में आता है। राजस्थान के बाड़मेर में तेल का उत्पादन होने के बाद देश में बाम्बे हाई के बाद दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है। बाड़मेर क्षेत्र में 70 मिलियन टन से अधिक खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन होता है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी के अथक प्रयास के कारण केन्द्र सरकार ने राज्य को 10 ब्लाक आबंटित किये, जिससे तेल उत्पादन होने पर राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। मैं इस सारे अथक प्रयास के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कोटि-कोटि नमन और धन्यवाद देना चाहता हूं।

जयपुर शहर के डेलावास स्थित एसटीपी संयत्रों का अपग्रेडेशन और 70 एमएलडी क्षमता के नये संयत्र रुपये 150 करोड़ की लागत से प्रारम्भ किये जाएंगे जिससे इस शहर में पानी की कमी को सुव्यवस्थित करने में फायदा होगा, उसके लिए मुख्य मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे शहर जयपुर में इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर दिल्ली की तर्ज पर 2013 में एक सेन्टर बनाने की योजना बनाई। परन्तु वह सेन्टर पूर्ववर्ती सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। अब इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए जो 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

गरीब, निर्धन और निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने निःशुल्क दवा और जांच प्रारम्भ की। मुझे यह बात

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

तकलीफ के साथ कहनी पड़ रही है कि यह योजनाएं पिछली सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं थीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस योजना में अभी 608 दवाइयों के साथ 104 दवाइयों को और जोड़ा गया है। कुल मिलाकर 712 नि:शुल्क दवाइयां आ गयी हैं। गरीब, निर्धनों को जो नि:शुल्क दवाइयां मिलेंगी, उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज वाइंडअप।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरे देश में अहिंसा दिवस के रूप में....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पढ़ेंगे तो अंत नहीं होगा। वर्बली बोले। पढ़ना चाहेंगे तो आधा घंटा बोल लेंगे आप। प्लीज वाइंडअप।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): आदरणीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में पेज नंबर 35 पर बिंदु 145 के अंदर जो घोषणा की गयी है जिसमें 3 हजार 500 से बढ़ाकर 10 हजार कैमरे किये गये हैं, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। इससे जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में आमजन को सुरक्षा मिलेगी। विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैं राजस्थान जन आधार योजना का लाभ दिए जाने की जो बात है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह के जनहित के कार्य करेंगे। पुरानी विधान सभा में एक विश्वस्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो मेरे किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय धन्यवाद। गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं राजस्थान के हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कालेज के नव

(श्री गिरधारीलाल)

निर्मित भवन की स्वीकृति जारी की। साथ ही बजट में बिजली के बारे में बहुत सारी बातें कहीं गयी हैं। पहले की सरकार ने 2016 के अंदर बिजली की दरें बढ़ाई और जन दबाव में कुछ श्रेणियों की बिजली की दरें वापस ली। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बूंद-बूंद श्रेणी के जो कृषि कनेक्शन थे, उस समय पूर्ववर्ती सरकार ने जो दरें बढ़ायी वह वापस नहीं लीं। वर्तमान सरकार से भी कई बार निवेदन किया। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि बूंदबूंद श्रेणी के कनेक्शन कौनसी श्रेणी में आते हैं? एनडीएस में आते हैं या कृषि में आते हैं? माननीय, ऐसे कई किसान हैं, बढ़ी हुई दरें जो पहले की सरकार ने 2016 में बढ़ाई थीं, आज भी उनको वह वहन करनी पड़ती हैं। विशेषकर बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा बूंद-बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी जो वर्तमान श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में सबसे डबल पैसे कृषि कनेक्शनों पर किसानों के लगते हैं। जब डिमांड नोटिस जारी होता है, उस सूरत में दो लाख से कम किसान का डिमांड नोटिस नहीं होता, चाहे ढाई लाख के हो या तीन लाख के हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल के बाद उनका सामान्य श्रेणी में कनेक्शन होता है। मैं बजट के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस बजट में यह प्रावधान लें और जो बढ़ी हुई दरें हैं 2016 की। वह सामान्य श्रेणी के बराबर या फ्लैट रेट के बराबर की जाएं।

अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 5 पैराग्राफ 17 पर जो कृषक कल्याण कोष बनाया गया है। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि किसान को तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक सरकार द्वारा कोई कानून बनाकर इसको अमली-जामा नहीं पहनाया जाता। कल्याण कोष द्वारा जो लाभ हम चाहते हैं, वह किसान को नहीं मिलेगा। पूरे राजस्थान की सदन में लगातार चर्चा देखते आ रहा हूं, बहुत सीनियर साथी हैं जो लंबी राजनीति का जीवन जी रहे हैं। पहले बिजली, फिर पानी, अब आने वाले समय में मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है आवारा पशुओं के जो हालात पूरे राजस्थान के अंदर हैं, उस सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर सरकार ने बजट में पंचायती स्तर पर नंदी गौशाला खोलने की बात की है। निश्चित रूप से गांव-गांव में गौशालाएं किसानों द्वारा खोली गयी हैं। मगर

(श्री गिरधारीलाल)

आज यह हालात गांव में देखें जा रहे हैं कि आवारा पशु हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे। मेरी राय है कि इस बजट के अंदर जब तक आवारा पशुओं के लिए अलग से विभाग नहीं बना दिया जाता तब तक यह व्यवस्था सुधर नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंडअप करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा .....

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी का समय हो चुका है। प्लीज, वाइंड अप।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सर, एक मिनट बोलूंगा। नरेगा वैसे केन्द्र की योजना है। नरेगा को अगर खेती से जोड़कर बारानी क्षेत्र में किसान जो खेती करते हैं, उसको तारबंदी में समूह के रूप में ले लिया जाता है तो यह बजट में शामिल करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, मेरे को बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं 10 तारीख को जो बजट पेश हुआ है, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इससे आम जनता ठगा-सा महसूस कर रही है। यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। हमने भी पूरा पढ़ा है। हमारी सरकार के समय में बजट पेश हुआ करता था तो आम जनता खुशी के माहौल में रहती थी। लेकिन यह बजट जनता को गुमराह करने वाला, पूरे प्रदेश को गुमराह करने वाला है। इसमें ऐसे शब्द आए हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रिपीट किया गया है। जैसे शिवगंज जवाई पानी का डीपीआर हमारी सरकार में बना था, इसमें भी हवाला दिया गया है। महिलाओं का 7500 तक की जो वृद्धि का है, वह भी हवाला फिर से दिया गया है। यह हमारी सरकार में, हमारे बजट भाषण में था। एक्स एमएलएज का जो है, उसमें भी 2003 से 2008 में हमारी ठहरने की व्यवस्था थी। अगर जिला प्रमुख, प्रधानों का किया होता तो नया प्रावधान माना जाता कि कम से कम सरकार ने यह व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बत्तीसा नाला पानी के बारे में हमारे विद्वान साथी जो सिरोही शिवगंज से आते हैं, इन्होंने हवाला दिया कि हमारी सरकार ने डीपीआर बनाई।

2003-04 में जब मैं एमएलए था उस समय भी मैंने कहा था कि हमारा गुजरात पानी जाता है उसको रोका जाए। हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री

(श्री समाराम गरासिया)

ने घोषणा की और करोड़ों रुपये के बजट से वह काम चालू हुआ। पलायन करने वाले लोगों को मुआवजा भी हमारी सरकार में दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार में सड़कों का जाल बिछाया गया। 7.50 करोड़ का रतलाम वाला रोड, सागवाड़ा पुल का 2 करोड़ 76 लाख का, बावरी का पुल 2 करोड़ 57 लाख का, यह हमारी सरकार में हुआ। राठौड़ साहब हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने भी पहले 5 करोड़ का रजवाडी ब्रिज आबू रोड पर बनाया, 10 करोड़ का चैक पोस्ट वाला ब्रिज बनाया। 2013 में आपकी सरकार थी। राठौड साहब ने घोषणा की वह पांच पुल हमने बनाए। उसके बाद आपने पांच साल तक कुछ नहीं किया। फिर हमारी सरकार आई और बत्तीसा नाल में वह पुल फिर से बनाए गये। ऐसा काम और ऐसा बजट हमारी सरकार में हुआ था उसके लिए मैं पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। अगर आप वाहवाही लेना चाहते हैं, आपकी एक घोषणा थी, लीलूडी बडली शहीद स्मारक का आपने भूमि पूजन किया था वह भी नहीं बना सके। जहां शिलालेख खड़ा है वहां की घोषणा करते तो भी मैं मानता। सालगांव बांध की हमारी सरकार में 250 करोड़ की डीपीआर बनी। एकमात्र स्वीकृत करने का अगर आदेश करते और इस बजट में घोषणा होती तो आबू पर्वत के लोग भी कहते सालगांव बांध की घोषणा हुई है। सिरोही ज़िले के लिए एक भी बड़ा काम नहीं किया गया।

मैं आपको शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगा। शिक्षा विभाग में हमारी सरकार ने हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल किया। स्कूल बंद करने का आपने कहा लेकिन हमारी सरकार ने स्कूल बंद नहीं किये हैं, समानीकरण किया गया था ताकि स्कूल व्यवस्था सुदृढ़ रहे। शिक्षा का स्तर हमारी सरकार के समय बढ़ा था। शिक्षा का नामांकन भी हमारी सरकार में रहा, मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं। काउंसिल के आधार पर ट्रांसफर, भ्रष्टाचार को कम करना हमारी सरकार के समय हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर यह सरकार चाहती तो किसानों का मुआवजा, हमारी सरकार के समय दुर्घटना, सिलिकोसिस बीमारी होने पर दो लाख रुपये दिए जाते थे और अगर इस बीमारी से मौत हो जाए तो चार लाख दिए जाते थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने कोई चिंता नहीं की। न तो थानों की संख्या बढ़ाई गयी, एकाध थाना और

(श्री समाराम गरासिया)

बढ़ता क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, घटनाएं होती हैं। हमारी सरकार ने एक सीईओ कार्यालय भीलवाड़ा उपखण्ड में खोला था, अगर सीईओ भी लगा देते तो हम मानते कि वास्तव में सरकार ने कुछ व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बजट भाषण में बातें लिखी गयी हैं यह सच साबित नहीं हो पाती। आपने नंदी गोशाला की घोषणा की है। अगर सब जगह व्यवस्था हो जाए तो यह बहुत बड़ा काम है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार कर पाएगी क्योंकि यह सिर्फ घोषणा करते हैं उसकी क्रियान्विती नहीं होती। यह पांच साल भी निकल जाएंगे। जो सरकार की वाहवाही करते हैं, बड़ाई करते हैं, यह तो खाली अपना नम्बर बढ़ाने के लिए करते हैं, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जोर-जोर से बोलते हैं, आवाज़ें करते हैं लेकिन समय वही है, हम 2003 से 2008 तक रहे तो हमारी संख्या 120 थी, फिर हम नहीं आए तो भी हमारी संख्या ज्यादा थी, विपक्ष मजबूत था। हमारी सरकार 2013 से 2018 तक रही, मैं उसमें भी रहा। मुझे विपक्ष में तो पहली बार बैठने का मौका मिला, मैं दो बार सत्ता में रहा हूं। पूर्व सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो बजट पेश किया था वास्तव में बजट उसको कहते हैं। यह बजट तो जनता को गुमराह करने वाला बजट है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं नेहरू जी का एक कथन पढ़ना चाहूंगा "we are little men serving great causes, but because the cause is great something of that greatness falls upon us also."

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): उपरोक्त कथन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का है। इस कथन में नेहरू जी ने जो कहा वह इस परिवर्तित बजट 2019-20 को प्रस्तुत करते हुए हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत पर सार्थक सिद्ध होता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विधूड़ी जी ने यहां चर्चा की थी, मैं आपके समक्ष बंटवारे के वक्त की एक चर्चा करना चाहूंगा। मैं सदन के समक्ष यह बात इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि सदन में लगातार यह बात रही कि

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

कांग्रेस ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। खासकर उस किसान के लिए कुछ नहीं किया जो पिछड़ा है, गरीब है, कमजोर किसान रहा, जिसके पास भूमि कम रही। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो किसान भारत आए वह वहां पर 2.7 मिलियन हैक्टेयर जमीन छोड़कर आए थे और जो किसान यहां से पाकिस्तान गये वह 1.9 मिलियन हैक्टेयर जमीन छोड़कर गये थे, इतना भारी फर्क रहा जमीन में। आने वाली आबादी तो ज्यादा थी लेकिन जाने वाले लोग कम थे। यहां से गये वह कम जमीन छोड़कर गए और वहां से आए वह ज्यादा छोड़कर आए। भारत में उस समय सरकार थी, उस समय सरदार त्रिलोकसिंह जी नाम के अधिकारी थे, उनको वहां नियुक्त किया। उनको इसलिए नियुक्त किया कि वहां जाकर जमीन देनी है, पाकिस्तान से हमारे किसान आए हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि जो बड़े किसान है उनको कम जमीन मिले और छोटा किसान पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आ रहा है उसको ज्यादा जमीन मिले।

अध्यक्ष महोदय, इसी के तहत मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक महिला जिसका नाम विद्यावती था, पाकिस्तान के गुजरांवाला और सियालकोट क्षेत्र में उसकी बड़ी मिल्कियत थी। उस क्षेत्र में उसकी जमीन 11 हजार 500 एकड़ थी। वह उसे छोड़कर हिन्दुस्तान आई और यहां आकर बोली कि मुझे इस जमीन के बदले जमीन दी जाए। आप यकीन मानिए उसको जमीन दी गयी उसका माप 835 एकड़ था। 11 हजार 500 एकड़ जमीन जो छोड़कर आई उसको यहां 835 एकड़ जमीन दी गयी, यह सोच कांग्रेस की थी। यह सोच उस वक्त की सरकार की थी कि जो पिछड़ा किसान है, गरीब किसान है, जिसके पास कम जमीन है, उसको पूरी जमीन दी जाए और जो अगड़े और आगे आए किसान है उन को उस अनुपात में कम जमीन दी जाए। यह बात रखने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि मैं यह चीज सिद्ध कर सकूं कांग्रेस ही है जिसने यह परिपाटी रखी, यह सोच रखी। उसी सोच, उसी परिपाटी को निरन्तर रखते हुए यह बजट पेश किया गया है, इसमें किसान को सबसे पहले और सबसे आगे रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर सबसे बड़ी बात कही गयी, भारत में सबसे पहले देखने को मिलती है वह Ease of doing Farming है। इससे पहले सिर्फ धंधे की, बिजनस की बात की गयी, Ease of doing Business चलता था। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही Ease of doing

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

Farming, कृषि एक ऐसा व्यवसाय होता जा रहा है जिससे हमारी युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है। इसके पीछे यह कारण है कि यह घाटे का धंधा होता जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि इसके बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं शहरों की तरफ लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है। अगर पलायन को रोकना है, युवाओं का वापस खेती की तरफ ध्यान आकर्षित करना है तो हमें फार्मिंग, की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

इसी के तहत मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में ऐसी बातें कही हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया, यह एक ऐतिहासिक कदम है, सराहनीय कदम है। मेरा यह मानना है कि इससे भ्रष्टाचार में कुछ कमी आएगी। जो लोग किसानों को लोन बांटते थे, उसमें मनमानी थी, उसमें कमी आएगी। इसके अंदर एक सुधार की भी जरूरत है जो मैंने इतने दिनों में देखा। मैं मेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष भी हूं, वहां यह देखने को मिलता है जो फिंगर प्रिंट स्कैन करते हैं, बार-बार रगड़ते रहते हैं, हमारे वृद्ध किसान हैं उनके फिंगर प्रिंट नहीं मिलते, तो जब तक यह सिस्टम सुदृढ़ नहीं हो जाए, ठीक नहीं हो जाए तब तक मैं यह मानता हूं कि ओटीपी की व्यवस्था है उसको चालू रखा जाए। ताकि मोबाइल पर मैसेज आ जाए। किसान को पोर्टल पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वह उसका पूरा लाभ ले सके।

दूसरी चीज, 2012-13 में जब गहलोत साहब की सरकार थी और जो ब्याज मुक्त ऋण था उसको लागू करने के लिए, अभी की गहलोत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें 16 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरण का जो लक्ष्य रखा है, वह भी एक सराहनीय कदम है। इससे एक लाख 10 हजार बीघा जमीन ऋण मुक्त हो जाएगी। लेकिन मेरा सरकार से आग्रह है कि जो किसान ऋण माफी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाये। क्योंकि गांवों में बड़ी पीड़ा रही है कि कुछ लोगों को तो ऋण माफी का लाभ मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला।

इसके अलावा, सरकार से मेरा एक निवेदन और रहेगा कि भूमि विकास बैंक के लिए जो पांच प्रतिशत मुख्य मंत्री ब्याज अनुदान योजना थी, उसको फिर से लागू किया जाए। इस योजना से, जो किसान टाइम पर अपना ऋण चुकाते थे, उनको पांच प्रतिशत का अनुदान मिलता था। उसको फिर से लागू रखा जाए। इससे किसानों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उन

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो समय पर अपने ऋण को चुकता करते हैं।

प्रदेश की सरकार ने कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाकर किसानों की फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए राजस्थान की कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की उप विधियों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। लेकिन सब कुछ आनलाइन होने के बावजूद भी हमें जगह-जगह यह देखने को मिलता है कि अभी भी कृषि मण्डी में बिचौलियों का बोल-बाला है। कहीं न कहीं मिडिएटर काम करते हैं। तो, मेरा सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि व्यवस्था के अन्दर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सुधार किये जाएं जिससे कि किसान को सीधा फायदा मिल सके और जिन बिचौलियों की हम बात करते हैं, जिनकी वजह से किसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनसे उनको छुटकारा मिले।

गौ-वंश संरक्षण के खातिर प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी-शालाएं बनाने की घोषणा भी सरकार का सराहनीय कदम है। लेकिन जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, सिर्फ गौशालाएं बनाने से या नंदी-शालाएं बनाने से आवारा पशुओं से निजात मिल जाए, मुझे दूर-दूर तक कहीं ऐसा कोई चित्र नजर नहीं आता कि इससे हमें आराम मिल जाए, किसानों को निजात मिल जाएगी। जो आवारा या बेसहारा पशु हैं, इनके प्रजनन पर रोक लगाने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि इनकी संख्या में कमी आए। अगर इनकी संख्या में कमी नहीं आएगी तो यह तय है कि एक दिन हमारी आबादी से भी ज्यादा आपको आवारा पशु घूमते नजर आएंगे। मेरे डीडवाना में बहुत सारे खेत ऐसे हैं बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिये खेती करनी छोड़ दी कि ये आवारा पशु कहीं न कहीं उनकी पूरी फसल को एक ही रात में चौपट करके चले जाते हैं। उनका सीधा सा कहना है, बाऊजी, इससे बढ़िया अपने बच्चे को बाहर भेज देंगे, वह कमाकर ले आएगा, खेती पार नहीं पड़ती है।

प्रदेश में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव भी पशुपालन हेतु कारगर साबित होगा। पशुपालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है और आने वाले वक्त में अभी भी किसानों के लिए आय का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। लेकिन मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक छोटे गांव में

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

एक पशु कम्पाउण्डर और प्रत्येक बड़े गांव में पशु कम्पाउण्डर प्लस एक पशु चिकित्सक, दोनों की व्यवस्था हो। इससे हमें आने वाले वक्त में यह फायदा मिलने वाला कि हमारा जो पशुपालन का व्यवसाय रहा है, इसमें किसानों को बढ़ोतरी मिलेगी।

साथ ही साथ पशुपालन में मेरा एक सुझाव यह भी रहेगा कि हमारे साथ जो हमारे परम्परागत पशु रहे हैं, या ऐसे पशु जो हमारी क्लाइमेट के साथ, हमारी आबो-हवा के साथ सूट करते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ऊंट और साण्ड।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): वह आपको पता है, पुराने आदमी हैं।

प्रदेश में मौहल्ला एवं जनता क्लीनिक खोले जाने की घोषणा भी एक सराहनीय कदम है, जिससे कि गरीब व्यक्ति को अच्छी चिकित्सा सुविधा पड़ौस में मिल सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि मात्र चिकित्सालय खोलने से या क्लीनिक खोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक वहां पर कम्पाउण्डर, नर्स, डाक्टर नहीं बैठें। मात्र भवन तो मैंने खण्डहर होते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत देखे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जो भी चिकित्सालय खोलें, जो भी क्लनिक खोलें, वहां बराबर कहीं न कहीं ड्यूटी पर कर्मचारी बैठे रहें। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मेरी छोटी खाटू में पचास बैड का एक अस्पताल है। चार डाक्टर हैं, चारों के चारों प्रतिनियुक्ति पर लगे हैं और एक भी हाजिर नहीं है। अख़बार में खबर आती है उसके बाद भी हालत बद से बदतर वही की वही है। सी.एम.एच.ओ. साहब के यह बोला जाता है कि आप इनको नोटिस दो, क्या पता हाजिरी लगा दें। अगर यही हालात रहे तो मेरा यह मानना है कि हमें नये खोलने के बजाय, जो पुराने हैं उन्हीं को दुरुस्त करके चलना पड़ेगा। मेरे डीडवाना में एक बड़ा अस्पताल है, और एक नेशनल हाई-वे और छह स्टेट हाई-वे वहां से गुजरते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज वाइंड-अप, वाइंड अप करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): साहब, एक मिनट का वक्त लूंगा, एक मिनट।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने युवाओं की सुध लेते हुए 75 हजार नई भर्तियों की घोषणा की। लेकिन साथ ही साथ मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जब भी कोई भर्ती निकालें तो यह समुचित व्यवस्था की जाए कि वह भर्ती बिना किसी रोक-टोक के सम्पूर्ण हो जाए। उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जो अभ्यर्थी हों, उनको कोर्ट में न जाना पड़े। वर्ना मैं निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार ने पिछले बजट में डेढ़ लाख की घोषणा की थी। ग्यारह भर्तियां निकाली थीं, जिनमें से मात्र तीन भर्तियां ही पूर्ण हो पाईं। अभी बड़े जोर-जोर से कुछ साथी बोल रहे थे, आठ भर्तियां अपूर्ण या अधूरी पड़ी हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे जो युवा साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनको लगे कि जो सिस्टम है वह पूरा का पूरा सही और सम्पूर्ण है। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं हो गया एक मिनट, प्लीज, वाइंड-अप।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): मैं एक चीज इसमें और बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में भी केन्द्र की तर्ज पर एक भर्ती का कलेंडर फिक्स हो जाए कि इस साल इतनी भर्ती इस विभाग से निकलेगी ही निकलेगी। ताकि बच्चों में कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि यह देखने को मिलता है कि जो बच्चा क्लर्क की तैयारी कर रहा है, वह बच्चा पुलिस की तैयारी भी कर रहा है। उनको यह पता रहे कि कब कौनसी भर्ती निकलेगी। दूसरी चीज, जो संविदा-कर्मी, जिनसे कि हमारे जन घोषणा पत्र में भी वादा किया गया था, एक कमेटी गठित की गयी है, उस कमेटी की जल्दी रिपोर्ट लें और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी सुनवाई करके जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही करने की सरकार मेहरबानी करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, हो गया, प्लीज।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट, 2019-20 में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

एक कवि का एक संस्मरण सुनाते हुए अपनी बात को प्रारम्भ करूंगा। एक कवि ने एक संस्मरण सुनाया। अमेरिका में एक विद्यार्थी आठवीं कक्षा का पेपर दे रहा था। प्रश्न-पत्र हिन्दी का, और उसमें एक सवाल आया, वीरता के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिये। उस छात्र ने लिखा शूरता, पराक्रम, फिर कुछ देर रुका और फिर उसने लिख दिया राजस्थान। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वीर भूमि पर पैदा हुए हैं। मैं ऐसी वीर भूमि पर इस पवित्र सदन को प्रणाम करता हूं और सदन में उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं।

बजट की इस 55 पेज की किताब में चित्तौड़ का नाम सिर्फ तीन जगह पर आया। उसमें दो जगह तो वहां, जहां कालेज थे, रावतभाटा और बेगूं, उनको फिर से प्रारम्भ करने का था। एक, 21 सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए 517 करोड़ रुपये, यानी कि चित्तौड़ को मिले 24.33 करोड़ रुपया, जो बहुत कम है।

चित्तौड़ वैसे वीरों की भूमि पर है, पर बजट बहुत कम है। वैसे यूं देखा जाए तो पूरे मेवाड़ को इस बजट में बहुत नीचे रखा गया है। मेवाड़ की कहीं पर भी कोई उपलब्धि इस पूरे बजट में नहीं दी गयी है।

यह सरकार किसानों के विकास की बात करती है, किसानों को उचित मूल्य ज्यादा दिलाने की बात करती है। अभी लगभग सात महीने से यह सरकार कार्यरत है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर, किसी भी तौल केन्द्र पर बहुत कम गेहूं तुला। इसका मुख्य कारण भाव में कमी थी। सरकार को उस समय, अगर किसानों का हित ध्यान में रखना था तो उस समय बोनस, समर्थन मूल्य के साथ में कुछ बोनस की राशि काश्तकारों को देनी थी। अगर वह देते तो काश्तकारों का भला होता और गेहूं भी वहां पर तुलता। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पड़ौसी राज्यों की तरह राजस्थान में भी भाव-अंतर योजना, उसमें समर्थन मूल्य के साथ-साथ में सरकार, किसान कहीं पर भी माल बेचे उनको भाव के अंतर की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाए।

कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में पेज नम्बर तीन के बिन्दु संख्या दो पर लिखा है, किसानों को कृषि कार्य करने हेतु सहज तथा आसान दर पर ऋण देना। जबकि पूरे राजस्थान में बुआई हो चुकी है और एक भी काश्तकार को ऋण नहीं मिला।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

पेज नम्बर-3 के बिंदु संख्या-7 पर लिखा है कि वृद्ध किसानों को पेंशन, अभी तक तो पूरे राजस्थान में एक भी किसान को पेंशन नहीं मिली है।

पेज नम्बर-4, बिंदु संख्या-25, जानवरों और रोजड़ों से किसानों की फसल के नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी कार्य-योजना, जबकि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राजस्थान में जब से यह सरकार बदली है, तब से फव्वारा सैट और पाइप पर छूट के आवेदन आन-लाइन जमा हो रहे हैं और फिर काश्तकार को वहां आफिस में बुलाकर उनकी फाइल वापस लौटाई जा रही है, किसी एक भी काश्तकार को फव्वारा सैट और पाइप लाइन पर छूट नहीं मिली है।

नि:शुल्क दवा योजना, दवा पहले 608 थीं, 104 और बढ़ा दीं, आप चाहे तो दवा 1000 और भी बढ़ा देते लेकिन दवा लिखने वाले डाक्टर्स, नर्स और ए.एन.एम. और जे.एन.एम. के पूरे राजस्थान में पद खाली पड़े हैं। मेरे क्षेत्र में तो लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, पहले उन पदों की नियुक्ति की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंगलवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटना में कई मौतें भी होती हैं और कई जीवन भर के लिए अपंग भी हो जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक ट्रोमा-सेंटर खोला जाए।

इस बजट में पेज नम्बर-30, बिंदु संख्या-127, इस वित्तीय वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। पूरे राजस्थान में केवल 50, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय वसुन्धराजी की सरकार ने जो 22 हजार विद्यालय मर्ज किये थे, इसका मतलब उन्होंने उचित किया था। प्राथमिक विद्यालय खोलने की संभावनाएं राजस्थान में नहीं हैं, तब ही इस बजट में नहीं लिया गया।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विधायक मद की राशि सवा दो करोड़ है, सिर्फ सवा दो करोड़ है जबकि कई गांव बढ़ गये हैं, कई बस्तियां बढ़ गयी हैं तो इस राशि को भी बढ़ाने की मेहरबानी करें।

गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में जनता का लाखों रुपया जमा है। अभी तक स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं। इस बजट में उक्त योजना के लिए एक रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है। अकेले चित्तौड़

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

जिले में 75 काम के लिए 736.31 लाख के कार्य पैंडिंग पड़े हैं, जिसकी जन सहयोग की राशि जनता ने जमा करवा रखी है। सरकारी योजना के अनुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र के डूंगला सब-डिवीजन मुख्यालय में सरकारी कॉलेज खोलने की कृपा करें।

जाखम बांध का पानी बड़ी सादड़ी तहसील के पारसोली तालाब से तराऊ बांध में लाने की मांग हमारे जन-प्रतिनिधियों एवं संघर्ष समिति ने समय-समय पर की है। मेरा अनुरोध है कि जाखम बांध से बड़ी सादड़ी की कई पंचायतों को पेयजल सुलभ कराते हुए पानी तलाऊ बांध में पहुंचाने की कृपा करें, इससे जनता को पेयजल सुविधा भी मिलेगी तथा किसानों को पिलाई के लिए भी पानी मिलेगा।

इस बजट में एक घोषणा की है कि नाथद्वारा और पुष्कर में जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत करेंगे। मेरा निवेदन है हमारे पास में सांवलियाजी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहां पर भी इन बिजली की लाइनों को भूमिगत करने की कृपा करें।

अंत में इस एक गीत की दो लाइनें बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूं-

वह जीवन भी क्या जीवन है, जो देश के काम आ न सका,
वह चंदन भी क्या चंदन है, जो वन अपना महका न सका।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सर्वप्रथम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मेरे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की निम्न समस्याओं की तरफ आकर्षित करती हूं:-

मैं सर्वप्रथम खनिज मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजीविका चलाने का एक मात्र साधन पत्थर की खानें हैं, जिनकी

(श्रीमती मीना कंवर)

लाइसैंस अवधि नियम-26 में 90 वर्ष थी किन्तु विगत भाजपा सरकार ने नियमावली 2017 में क्वारी लाइसैंस की अवधि 30 वर्ष कर दी थी। उक्त क्वारी लाइसैंस की अवधि नियम-10 में पुन: 99 वर्ष की जाए।

दो, इसके बाद में मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा क्षेत्र नोन-इर्रिगेटेड क्षेत्र हैं, जिसमें अधिकांश जगह जमीन में पानी नहीं है। कुछ जगह पर पानी है तो खारा है जो पीने योग्य नहीं है अत: मेरा निवेदन है कि वृहत् हिमालय पेयजल योजना आर.डी. 134 व आर.डी. 159 के तीसरे चरण के पाइप लाइन कार्य हेतु बजट की स्वीकृति कराएं।

तीसरा, वृहत् हिमालय पेयजल योजना आर.डी. 159 के फिल्टर प्लांट गंगाणी, जीयाबेरी में रख-रखाव के संवेदक द्वारा पुराने पम्प बदलकर नई क्षमता वाले पम्प लगाए जाएं जिससे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी हद तक पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से हो सके। वर्ष 1994 में जनता जल योजना प्रारम्भ की गयी थी जिसके अंतर्गत आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र की बालेसर पंचायत समिति में 141 तथा सेखाला पंचायत समिति में 207, शेरगढ़ पंचायत समिति में 153 ट्यूबवैल खोदे गये थे, जिनका अप्रैल, 2011 तक रख-रखाव पी.एच.ई.डी. के पास था। इसके बाद इसका रख-रखाव पंचायत समिति को सौंप दिया गया। पंचायत के सरपंच के पास ऐसा कोई बजट नहीं था, जिससे इनका रख-रखाव कर सके। समय पर रख-रखाव के अभाव में आधे से ज्यादा नलकूप खराब हैं, अत: आपसे मेरा अनुरोध है कि उक्त योजना में बजट का प्रावधान किया जाए जिससे इनका रख-रखाव समय पर हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का शुभ-अवसर दिया। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत। (अनुपस्थित) श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने 10 तारीख को राजस्थान का पहला बजट पेश किया। मैंने इस बजट को तीन-चार बार पढ़ा लेकिन इसमें न कोई दिशा है, न कोई दशा है और न ही इसमें राजस्थान के विकास का कोई विजन दिख रहा है।

हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत सारी योजनाओं का नाम बदल-बदलकर दिया गया है। जैसे कि- ग्रामीण गौरव पथ था, अब उसको

(श्री अशोक डोगरा)

विकास पथ कर दिया। भामाशाह कार्ड को राजस्थान जन आधार कार्ड कर दिया। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना को अब राजीव गांधी जल संचय योजना कर दिया। किसान राहत आयोग को अब कृषक कल्याण कोष के नाम से किया। मेरा मतलब यह है कि इनकी जब पहले सरकार थी तो बूथ-वाइज योजना हमने उसी नाम से उसको चालू रखी, यह भी चाहते तो कर सकते थे लेकिन इन्होंने नाम बदलकर योजनाएं वही रखीं।

इन्होंने चुनाव के टाइम पर जन घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बहुत सारी बातें थीं लेकिन दो ऐसी मेन बातें थीं जिसकी वजह से वोटर इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। एक तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपये महीना और दूसरा किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं, वैसे गिनती करके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस, दसवें दिन किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ। कहीं दो लाख की बात भी नहीं थी और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसमें कहीं यह नहीं था कि को-आपरेटिव का ही लोन माफ करेंगे। को-आपरेटिव का तो लोन इतना होता ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50-50 हजार तक तो पहले ही माफ कर दिया था। एक लाख से ज्यादा लोन किसी का होता नहीं और अपन सहकारिता के क्षेत्र में देखें, वहां तो मात्र पिछले साल 22 लाख 29 हजार 515 किसान ही थे।

लेकिन, 31 लाख से ज्यादा किसानों की के.सी.सी. थी, उस टाइम किसानों से कर्ज माफी वाली बात कही, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गिनती गा-गाकर बोल रहे थे, तो लोग इनके बहकावे में आ गये। उन्होंने सोचा कि हमारे सारे कृषि लोन माफ होंगे। मेरी एक वोटर से बात हुई तो उसने कहा कि मेरी तो तीन के.सी.सी. हैं 17 लाख की और दो ट्रैक्टर फाइनेंस कराये हैं, वह भी कृषि लोन में आते हैं, मेरा तो सब कुछ ही फ्री हो जाएगा। किसानों ने ऐसी उम्मीद कर ली, लेकिन इन्होंने उसके बाद सिर्फ को-आपरेटिव सैक्टर में, सिर्फ एक कागज ही पकड़ाया है उनको। सरकार बनने के तीन दिन बाद एक आर्डर जारी किया इनके चीफ सैक्रेटरी ने, जिसमें कामर्शियल बैंकों के लिए इन्होंने यह लिख दिया कि जो दो लाख तक के डिफाल्टर होंगे, उनके कर्जे माफ होंगे। तब पहली बार किसानों को पता लगा कि यह तो हमारे कर्जे माफ नहीं करेंगे। किसानों ने ब्याज भी जमा नहीं कराया, किश्त जमा नहीं करायी, उन पर ब्याज और पैनल्टी और लग गयी। उसका यह नतीजा हुआ कि विधान सभा

(श्री अशोक डोगरा)

चुनाव के जब तीन-चार महीने बाद लोक सभा का चुनाव आया तो किसानों ने भी इन पर पूरी नाराजगी निकालकर 200 में से 185 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को हराकर और इनका राज होते हुए भी 25 में से एक भी सीट इनकी नहीं आने दी। किसानों ने इनको ऐसा सबक सिखाया। किसान अभी भी तैयार हैं, आने वाले जनवरी-फरवरी में जब पंचायती राज का चुनाव आएगा तो बाकी बचा हुआ बदला किसान इनसे लेने के लिए तैयार है।

बेरोजगारी भत्ते के लिए इस बजट में एक शब्द भी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ भी नहीं कहा। इनका राज आने के बाद पूरे राजस्थान में विकास के काम बिल्कुल ठप्प हो गये। जितनी सड़कें बन रही थीं, जब ठेकेदारों को पेमेंट बंद हो गयी, पैसा आना बंद हो गया, तो सारा काम ठप्प हो गया। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में 70 करोड़ से ज्यादा पी.डब्ल्यू.डी. के काम बंद हैं। कुछ काम तो इतने इम्पोर्टेंट थे कि मेरा एक बूंदी-नैनवां रोड बाई पास था, उसमें कम से कम सात-आठ लाख रुपये का काम हो चुका था, वह बंद हो गया। वह पूरा हो जाता तो मेरा शहर एक्सीडेंट मुक्त हो जाता। मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन सब अधिकारी यही कहते हैं कि साहब, पैसा ही नहीं आ रहा है।

मेरे यहां की एक पेयजल योजना, जो 1 करोड़ 82 लाख 86 हजार की थी, जिससे 116 गांव और 91 ढाणियों को पानी जाना था 207 जगह पर, जिसका पैसा आ चुका था, टेण्डर हो गये, उसकी टैक्निकल बिड खुल गयी। खाली फाइनेंशियल बिड खोलकर वर्क-आर्डर देना था। जिसको इन्होंने रिव्यू कमेटी में डालकर रोक दिया, उसको सात महीने हो गये, जबकि यह पानी उठना था, यह गरड़दा बांध एक निर्माणाधीन बांध है। अभी उसमें पानी नहीं है, निर्माणाधीन है, वहां अभी यह काम होगा। तब तो जो इंटेक वैल वगैरह बनेगा, वह आसानी से बन जाएगा। अगली बरसात में उसका पानी रूक जाएगा, उसमें भर जाएगा तो वह भी बनने में दिक्कत आएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि इस योजना को, क्योंकि इसमें 207 गांवों में शुद्ध पेयजल जाना है। यह तो बजट घोषणा थी पिछले साल की, कोई आखिरी छह महीने के काम के रिव्यू हो, वहां तक तो ठीक है, यह बजट घोषणा तो चुनाव से साल भर पहले की थी। इसका पैसा भी आ गया, टेण्डर भी हो गये, फिर भी इसको रोक

(श्री अशोक डोगरा)

दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं और पी.डब्ल्यू.डी. के भी जो काम हैं, वह भी जल्दी से जल्दी शुरू हों, ताकि जनता को राहत मिले।

महिला और बाल विकास के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय बढ़ाने की, यह भी सरासर असत्य है। क्योंकि यह तो हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पैसा दिया था। 11 सितम्बर, 2018 को इसका पैसा केन्द्र ने दे दिया था। उसके बावजूद आपने दस महीने तक पैसा भी रोककर रखा और अब वाहवाही लेने के लिए इसको बजट में दिखाया गया है।

75 हजार नौकरियों की बात की है। यह भी पूरी तरह फर्जी बात है, क्योंकि यह तो हमारे समय में ही वेकेंसी निकल गयी थी। इनके एग्जाम हो चुके हैं और इंटरव्यू चल रहे हैं। आर.पी.एस.सी. में जा चुकी हैं और अब यह इसमें दिखा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। बजट में असत्य बोला गया है।

बिजली की जहां तक बात है, बिजली की ऐसी स्थिति है कि राज बदलने के अगले दिन से ही, मैं तो जिला हैडक्वार्टर पर रहता हूं, कम से कम 25 बार लाइट जाती है, गांव में तो कोई पता ही नहीं। आज लाइट गयी तो पता नहीं कितने दिन में आएगी। ट्रांसफार्मर की ऐसी स्थिति है कि हमारे समय में तो ट्रांसफार्मर हाथों-हाथ किसान को मिलता था। ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे की बात थी। आज ट्रांसफार्मर एक-एक महीने से पैंडिंग है। मेरे यहां रोज फोन आते हैं। मैं अधिकारियों से बात करता हूं 10 के, 16 के, 25 के, 40 के ट्रांसफार्मर किसानों को नहीं मिल रहे, किसान उसके लिए परेशान हो रहे हैं।

हमारे यहां 10-15 दिन पहले बारिश हुई थी। हमारे यहां चावल की खेती होती है, वह बिना पानी के चल नहीं पाता है। अब बिजली मिल नहीं रही। जो थ्री फेस बिजली इनको छह घंटे देनी है, वह दो से तीन घंटे से ज्यादा बिजली दे नहीं पा रहे हैं। किसान इतना परेशान है कि उसकी फसल सूख रही है। उसके बाद बारिश भी नहीं आयी। वह डीजल पम्प से, इतना महंगा डीजल लेकर अपनी फसल को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन बिजली के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अशोक डोगरा)

इन्होंने जनता क्लीनिक की बात की। जनता क्लीनिक, जितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, हास्पिटल हैं, शहर का मेरे यहां तो 300 बैड का अस्पताल है, सभी जिला पोस्टें खाली पड़ी हैं। गांवों में डिस्पेंसरियों में ताले लगे हुए हैं तो जनता क्लीनिक कहां से चलाएंगे? इसके लिए स्टाफ कहां से आएगा? 'आयुष्मान भारत योजना' की इनको बजट में ही घोषणा करनी चाहिए थी। केन्द्र सरकार की इतनी अच्छी योजना, जिससे कितने ही लोगों को फायदा होता, उसका इस बजट में कहीं भी जिक्र ही नहीं किया इन लोगों ने।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। पुलिस की बात करें तो सारे थानेदार बजरी से पैसे कलेक्शन में लगे हुए हैं इसके अलावा उनके पास काम ही नहीं है। आज किसी आदमी को बजरी चाहिए तो सबसे बढिया थाने में जाकर बात कर लो, आपके यहां बजरी पहुंच जाएगी।

श्रमिक कल्याण की योजना, बच्ची 18 साल की होती थी तो 55 हजार मिलते थे। और बहुत सारी योजनाएं थीं। मजदूर को मकान मिलता था। मेरे बूंदी जिले में चार महीने से इस योजना में एक भी पैसा नहीं मिला किसी को। किसी भी पात्र व्यक्ति को फायदा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्लीज माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): ठीक है साहब, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पृथ्वीराज। एक सैकण्ड, विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: एक घंटा, सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का समय

(श्री अध्यक्ष)

कल ही खतम हो गया, जो आपका टाइम अलाटमेंट था। अब आप कष्ट करके पांच मिनट में अपनी बात कहें, सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय पृथ्वीराज। (व्यवधान) आपका जो अलाटमेंट टाइम है मान्यवर। (व्यवधान) आपका बिल्कुल नहीं होगा, चिंता मत करो। मालूम है, आपका नहीं होगा। (व्यवधान) आप बैठो आराम से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ऊपर वाला समय सबको देता है।

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं होगा, बैठो, आप आराम से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप उदारमना हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रार्थना करते रहो, आपका खतम नहीं होगा। माननीय पृथ्वीराज जी।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरा परिचय- श्रीमन्, मैं पृथ्वीराज मीणा, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम, जिला करौली से चुनकर आता हूं।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उनके बजट भाषण पर धन्यवाद देता हूं और उन्होंने यह 'नन्दी गौशाला' की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, अगर यह दोनों ही किसान हित में हो जाते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं, बशर्ते कि इसकी क्रियान्विति ढंग से हो जाए।

बजट, जो भी सरकार आती है, उसकी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी घोषणाएं की जाएं। पर, बजट उस राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर करता है और दुकान में, घर में कोई सामान हो तो ही चलता है।

राजस्थान में कृषि और खनिज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं कृषि 60 से 40 प्रतिशत पर आ गयी है, क्योंकि पानी की कमी हो गयी है और कुछ घाटे का सौदा है, इसलिए 40 प्रतिशत तक आ गयी।

दूसरा, राजस्थान में खनिज, खनिज के मामले में जितना मैं जानता

(श्री पृथ्वीराज)

हूं, मेरी जानकारी के अनुसार सन् 1995 से लेकर 2018 तक, दोनों ही सरकारों ने, सरकार चाहे किसी की भी हो, इस तरह लुटाया है। यह जनता का धन है, लेकिन बहुत गलत तरीके से लुटाया। पिछले शासन में 60 हजार करोड़ का खान घोटाला हुआ। चार सीमेंट के ब्लाक आबंटन हुए। अख़बार आप सभी पढ़ते हैं। इस वंडर सीमेंट को तो इनकी कैबिनेट ने आबंटन किया है, जिसको सामूहिक चोरी कहते हैं। मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के टाइम में भी हुए हैं। सच बोलने में कोई गुनाह नहीं है।

(19.00 बजे)

2007 में +++ वण्डर सीमेंट को आउट आफ वे, who is the Wonder cement?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिना तथ्यों के बात नहीं करें, अपनी बात करें।

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): साहब, मेरे पास तथ्य हैं।

श्री अध्यक्ष: लिखकर देना पड़ता है सिस्टम है। पहले लिखकर देना पड़ता है।

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): सोरी, सोरी, चलो। साहब, अब सीखने तो दो न।

श्री अध्यक्ष: सीखने के लिए ही तो बोल रहा हूं, बाकी थोड़े ही बोलता मैं।

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): हां चलो धन्यवाद, साहब।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी, आर.के. मार्बल के पीछे सारी, दोनों ही सरकारें पड़ गयीं। जो आये जो आर.के. मार्बल, वण्डर सीमेंट, श्री सीमेंट। 60 हजार करोड़ से पूरे राजस्थान की रोडें बन सकती हैं। हम दस-दस लाख के लिए मंत्रियों के पीछे भीख लगा रहे हैं, भाई साहब, इसको हैण्डपम्प अलाट कर दो न, मंत्री जी सुन ही नहीं रहे।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके मार्फत यह कहना है, इसमें लिखा है कि हम खनिज नीति, 2015 ला रहे हैं। तो हम यह अपेक्षा करते हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो चाहे बी.जे.पी., दोनों की सरकारों में खान आबंटन आम आदमी के बजाय बड़े घरानों एवं रसूखदार लोगों को मिलना ही सम्भव है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अत: सरकार अब जो नीति बनाने जा रही है, हम चाहते हैं कि वह नीति ऐसी हो जो वीकर सैक्शन से लेकर सभी को बराबर हिस्से में आबंटन हो।

(श्री पृथ्वीराज)

दूसरा, हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में भी सरकार ने आर.के. मार्बल, ईवन द आंधी, 2003 पहले सैशन में, दूसरे सैशन 2008 में आर.के. मार्बल, बांसवाड़ा जो कि ट्राइबल एरिया है, नोटिफाइड ट्राइबल एरिया, वहां सिवाय आदिवासी के अलावा दे नहीं सकते हैं, लेकिन पता नहीं बिना कोई विज्ञप्ति के वहां पर 300 बीघा जमीन अलाट की गयी, जो गलत है। फिर 2010, वण्डर सीमेंट, यह गलत बात है।

(19.02 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से, सभी से ऐसी अपेक्षा है कि सबसे ज्यादा धन देने वाला काम है खनिज। इसका आबंटन, निस्तारण ढंग से होना चाहिए तो राजस्थान की गरीबी गारंटी से मिट जाएगी। यह आप जो मांग रहे हो, सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो, पैसा होगा तो ही बजट प्रस्तुत होगा, कहीं से लाकर नहीं देंगे कोई मुख्य मंत्री जी। हमने अच्छा दिया, इन्होंने अच्छा दिया, मैं कहता हूं बी.जे.पी. के टाइम में तो अशोक सिंघवी जी जब से भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए उसके बाद ढाई साल में कोई काम ही नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति को अभी भी अगर आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक करना है तो यह खनिज की जो नीति है, निर्धारण है, आबंटन है, यह सही ढंग से हो।

एक मेरा पांचना के लिए निवेदन है, 15 साल से बंद है। नहर में पानी नहीं दे रहे, पानी भरा हुआ है। आपके मार्फत मेरी मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा है कि वह चालू हो। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के बारे में क्या कहूं, कुछ शब्द हैं जो बजट अपने आप में समाहित करता है, घोषणाओं का पिटारा, किसानों व बेरोजगारों के साथ धोखा, पैट्रोल, डीजल तथा गैस पर वैट बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका और केन्द्र की बजट घोषणाओं को अपने नये नामों और कलेवर में प्रस्तुत करने के अलावा और कुछ नहीं है। ख्वाबों की यह मृग मरीचिका, हमारे वहां पर जब 52 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है जो हरिण को इस प्रकार का आभास होता है कि आगे पानी है और वह पानी की तरफ भागता है, भागता-भागता जाता है, परन्तु पानी नहीं

(श्री पब्बाराम)

मिलता और इस तरह वह अपना जीवन त्याग देता है। इसी तरह से कांग्रेस के बताये गये ख्वाबों, इन घोषणाओं के पीछे किसान और युवा भाग रहे हैं और आखिर में जाकर उनको आत्महत्या तक करनी पड़ती है। इस प्रकार का यह बजट है।

शिक्षक से पहले मैं फौज में था तो फौज में एक शब्द प्रचलित था कि गांव या उसके जिले का, क्षेत्र का होता था न उसको बोलते थे गामोली। तो चूंकि मुख्य मंत्री जी भी मेरे गामोली हैं न इसलिए कुछ बातें जो उन्होंने की हैं उन गामोली के लिए भी प्रशंसा के दो शब्द कहना उचित समझता हूं। पहली बात आपने फलौदी किले कि लिए बजट दिया। कुछ मिलाकर 10 करोड़ का बजट पूरे राजस्थान में दिया। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर फलौदी किले को पांच करोड़ तक का बजट नहीं मिलेगा तो उस किले की सूरत नहीं सुधर सकती, पूरा का पूरा ढह चुका है इसलिए पांच करोड़ तक का बजट अवश्य दिया जाए और इस बजट आबंटन में घोषणा के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

दूसरा, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने एक पत्र लिखा, आप ही के समय में 2013 में प्रशासनिक स्वीकृति मिली और 150 बैड की फलौदी के चिकित्सालय की घोषणा की। उसके अन्दर प्रशासनिक स्वीकृति निकली थी और पुन: जब पत्र लिखा तो उसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मंत्री जी ने 150 बैड का तो नहीं किया, आधा-अधूरा आदेश निकाला है। एक तो चिकित्सा अधिकारी का नाम वरिष्ठ विशेषज्ञ किया है एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ का नाम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, यानी कि सी.एम.एच.ओ. से निकाल करके आप चिकित्सा मंत्रालय के अधीन ले आये हैं। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। परन्तु इसके लिए बजट एलोकेशन भी किया जाए और साथ ही 150 बैड की घोषणा भी की जाय।

तीसरी बात, जोधपुर में पावटा से लेकर आखलिया तक बहुत व्यस्त सड़क है और वहां पर दिन भर जाम लगा रहता है। मुख्य मंत्री ने जो एलिवेटेड रोड की घोषणा की है इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, पर जिस प्रकार का कांग्रेस का ट्रैक रिकार्ड रहा है, जब एलिवेटेड रोड बनती है तो वहां पर पूरा का पूरा निर्माण सामग्री भर करके यातायात में बाधा के अलावा कुछ नहीं होता। मैं समझता हूं इसको तुरन्त पूरा बजट देकर दो साल के अन्दर

(श्री पब्बाराम)

पूरा करें तो आम जनता को राहत मिलेगी और हम आपका आभार व्यक्त करेंगे।

चौथी बात, जब कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रचार के दौरान यहां पर आये थे तो ऐसा लगता था कि राजस्थान की जनता एक से दस तक की गिनती भी नहीं जानती थी। हमारे वहां पर पुराने समय में जब कोई चीज, पशु बेचते थे कि कितने बीसी रुपये के हुए 40 रुपये के दो बीसी, 60 रुपये तो तीन बीसी रुपये, इस प्रकार से उनको लगता था शायद राजस्थान की जनता दस तक की गिनती भी नहीं जानती है और दस तक की गिनती कह करके उन्होंने लोन माफ करने की जिस प्रकार की घोषणा की, उसका दंश राजस्थान का किसान आज भी भुगत रहा है। बैंकों में पैसा जमा नहीं करवाये, नया ऋण नहीं मिल रहा है और अब आपने जो आनलाइन करने की बात कही है। तो आनलाइन में पहले कृषक सारे डाकूमेंट्स लेकर अपनी सोसायटी में जाता है। सोसाइटी में जाने के बाद में उसको जांच करने के बाद में आनलाइन करता है। उसके बाद में बैंक में जाता है और बैंक उस डाकूमेंट को जांच करती है, हो सकता है बीच में रिजैक्ट भी कर दे, और फिर उसको हैडक्वार्टर में जाना पड़ता है। उसके बाद में वहां से स्वीकृति आती है और उसके बाद में यह सारा होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, अब जिस प्रकार की स्थिति पश्चिमी राजस्थान में बन रही है, आंधियों की झकझोर है और आम चौपाल पर सभी लोगों में, आम लोगों में यह बात चल रही है कि कांग्रेस और किसका जोड़ा है। कांग्रेस और काल का जोड़ा है, यह काल तो आना ही था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): और काल जब पड़ जाएगा तो, माननीय सभापति जी, आपके जो कृषि बीमा है, प्रधान मंत्री जी दे रहे हैं उस कृषि बीमा की 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर 31 जुलाई तक कृषि बीमा नहीं होगा तो किसानों को लाभ भी नहीं मिलेगा और आप जो लोन भी दे रहे हैं वह लोन के.सी.सी. वालों को नहीं दे रहे हैं। एक बात।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): दूसरा, नोशनल चेहरे पर पहले मिलता था, एक बाप के चार बेटे थे, चारों के नाम जमीन नहीं होती थी तो चारों के नाम भी मिलता था और डिफाल्टर को भी नहीं दिया जाता है।

श्री सभापति: श्री सुरेश टांक।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इस प्रकार से चौथाई लोगों को भी लोन नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री ने हर व्यक्ति को...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। पब्बाराम जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। पब्बाराम जी, विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: आसन का आप निर्देश तो मानें। आप आसन की तरफ ध्यान तो दें। श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आसन का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे परिवर्तित बजट वर्ष 2019-20 पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। साथ ही मैं मेरी किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता का आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पवित्र और गरिमामय सदन में उन सभी की आवाज बनकर बोलने का मौका दिया।

प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है वह किसान, युवा, महिला, श्रमिक, खिलाड़ी, बेरोजगार के साथ ही प्रदेश की आम अवाम को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए प्रबन्धन करते हुए किया जो कि सराहनीय है। मैं भी अपनी ओर से ऐसे सर्वांगीण विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस बजट पर कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं व

(श्री सुरेश टाक)

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे इन सुझावों को शामिल कर, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता को भी लाभान्वित करें।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों को अग्रणी पायदान पर रखते हुए एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष के गठन की जो घोषणा की है, यह किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य है। साथ ही 'खेती में जान तो सशक्त किसान' की सोच के साथ खेती की लागत को कम करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रारम्भ करते हुए जो दस करोड़ का बजट 3 जिलों के लिए आबंटित किया है, मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

साथ ही राज्य के 700 से अधिक GSS और KVSS में भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण की घोषणा, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। किसान की फसल को रखने की जगह नहीं होती है। GSS और KVSS में भण्डारण की कमी की वजह से कई बार किसानों को अपनी फसल को तुलवाने के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। मैं इसी में यह कहना चाहूंगा कि किशनगढ़ व अराईं दोनों जगह किसानों की फसल की तुलाई होती है और दोनों जगह भण्डारण के लिए गोदामों का अभाव है। मैं चाहूंगा कि इन 700 गोदामों के निर्माण की जब स्वीकृति हो तो मेरे किशनगढ़ और अराईं के लिए भी गोदामों का प्राथमिकता के साथ निर्माण हो।

पशुपालन के क्षेत्र में, आगामी पांच सालों में 400 ग्राम पंचायत में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की घोषणा इस बजट में की है। सबसे पहले मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुतबहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में अत्यन्त धार्मिक महत्व के तीर्थ निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में एक प्रथम श्रेणी चिकित्सालय की घोषणा की है, जिसके लिए मैं पूरी जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो 400 उप केन्द्र खोले जाएंगे, उनके साथ-साथ पंचायत स्तर पर जो नन्दी शाला खोलने का प्रावधान किया है, वहां पर भी पशु चिकित्सालय आवश्यक रूप से खोला जाए। जिससे

(श्री सुरेश टाक)

उस गौ शाला में रहने वाली गायों के समुचित इलाज का प्रबंध हो सके और उस पंचायत के सभी किसानों की गायों का इलाज वहां पर सुलभ हो सके।

सभापति महोदय, रोजगार में जिस तरह से 75 हजार नई भर्तियों का प्रावधान माननीय गहलोत साहब ने किया है, यह बेरोजगारों के जख्मों पर मलहम लगाने का बहुत बड़ा काम है। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कुछ भर्तियां जिसमें स्टेनोग्राफर की भर्ती भी शामिल हैं, इन भर्तियों को स्थगित कर दिया गया है और दुबारा फार्म भरे जाएंगे। मेरा निवेदन है कि इन भर्तियों को शीघ्र से शीघ्र दुबारा शुरू किया जाए ताकि बेरोजगारों में जो सरकार के प्रति संदेह प्रकट किया जा रहा है वह दूर हो और यह भर्तियां पुन: पटरी पर आ जाएं।

माननीय सभापति महोदय, गौ पालन एक बहुत बड़ा विषय है। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हर किसी सदस्य ने इस विषय पर बोला है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शाला खोलने की घोषणा की है, इसका मैं स्वागत करता हूं। शहर में व ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसकी वजह से इसका समाधान निकलेगा। आवारा पशुओं से जान-माल का बड़ा नुकसान हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, नन्दी शाला के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि नन्दी शाला खोलने के साथ-साथ एक बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि नन्दी शाला का जो उपयोग है, वह अच्छी तरीके से हो जाए। जिससे उसमें रहने वाले पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था हो सके। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि 2009 में नगरपालिका अधिनियम की धारा 87 में एक प्रावधान था, जिसकी धारा में नगरपालिकाओं को अधिकार थे कि वे गौ शालाओं को अनुदान दे सकें।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट और दे दें। वहां की नगरपालिका, नगर परिषदें, नगर निगम अगर थोड़ा-थोड़ा अनुदान

(श्री सुरेश टाक)

देना शुरू कर देंगे तो गौ शालाओं को अनुदान मिलेगा और गायों का कहीं न कहीं संवर्धन होगा। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर एक बार फिर समीक्षा करें और यह एक्ट वापस लागू किया जाए।

सभापति महोदय, सड़क तंत्र में मुख्य मंत्री जी की घोषणा, 1000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। सड़कों का जाल बिछेगा तो प्रदेश के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): साथ ही समस्त ग्राम पंचायतों को एक नए विकास पथ के साथ जोड़ना, वाल टू वाल सड़क बनाना, यह एक बहुत बड़ा आयाम है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए चाहूंगा कि किशनगढ़ एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है। विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। लेकिन वहां की सड़क इतनी जीर्ण-शीर्ण है कि वाहन चलाना तो बहुत दूर की बात है, वहां पैदल भी नहीं चल सकते। इस बजट के माध्यम से मैं चाहूंगा कि किशनगढ़ को प्राथमिकता दें।

श्री सभापति: श्रीमती निर्मला सहरिया।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, 2 मिनट दें। बोलने का बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है।

श्री सभापति: नहीं, प्लीज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जनता ने यहां भेजा है, बात करने के लिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आप अगर हमें 5 मिनट भी नहीं देंगे तो हम हमारी बात कैसे कहेंगे।

श्री सभापति: कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। सभी को बुलवाना पड़ेगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभी से अलग भेजा है। किसी भी पार्टी से नहीं आए हैं। निर्दलीय हैं। आप अगर हमें मौका नहीं देंगे तो हम कैसे बात रखेंगे।

श्री सभापति: बोल लिया न।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): फिर इस सदन में आने का अर्थ ही खतम हो जाएगा।

श्री सभापति: 10 मिनट बोल लिए आप।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): नहीं बोला हूं। मैंने टाइम नोट किया है। मैंने 7.10 पर शुरू किया है। मैं 6 मिनट बोला हूं।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें आप।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैंने टाइम नोट किया है। सौर ऊर्जा में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा में सरकार सब्सिडी का प्रावधान वापस लागू करे ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा घरों में लगाया जा सके और मुख्य मंत्री जी की योजना साकार हो सके।

सभापति महोदय, बिजली में मेरा छोटा-सा सुझाव है। मुझे बिजली के दिन भी नहीं बोलने दिया गया था। मेरा नंबर नहीं आया। मैं आज ही इस पर विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए बिजली के बिलों में जो छूट की राशि है, वह बिलों में कम की जाए, न कि खातों में दी जाए। साथ ही शहरी क्षेत्र में जो ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या है, इसके लिए ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कराया जाए, ताकि सरकार पर यह दोष नहीं लगे कि बिजली नहीं आ रही है। अधिकारियों की कमी की वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर ट्रांसफार्मर अपग्रेड हो गये तो निश्चित रूप से बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा।

मेरा शहर औद्योगिक क्षेत्र है। बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है। मैं उद्योग मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि रीको का छठा चरण वहां कट गया। विश्व की प्रसिद्ध मार्बल मंडी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए अब आप।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, एक छोटी-सी बात। वहां पर रीको की दरें 4000 से सीधी 5500 कर दी गयीं।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। विराजिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): इस पर विचार करें। छठा चरण वहां कटा। औद्योगिक निवेश बंद हो जाएगा। एक बार पुन: समीक्षा करें।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। अब विराजिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को खतम करूंगा।

श्री सभापति: क्या फर्क पड़ने वाला है एक मिनट से?

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): बहुत कुछ बोलना था। आप बारबार मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा सदन को।

श्री सभापति: खतम करें आप इसको।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट। एक मेरी गुजारिश है,

सत्ता के गलियारों में फिर नई बहार आएगी
मानव के जीने की उमंग वादों की याद दिलाएगी
आशा के पंछी खेतों में बीज नए फिर बोएंगे
मीठे पानी की आस लिए धरती का गर्भ टटोलेंगे
बच्चों के सपनों की खातिर खेतों को रक्त से सींचेंगे
वादों के जमीदारों से अब मेरी यही गुंजारिश है
न दिल टूटे न मन बदले हो सपने पूरे हर इंसां के
कोशिश करने वाला ही प्यार सभी का पाता है
वादों पर मर मिटने वाला इतिहास बनाकर जाता है
आओ अब सब बैर भुलाकर कदम मिलाकर चलते हैं
कर्मभाव से मंजिल पाकर ठंडी छांव में सोते हैं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती निर्मला सहरिया।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, 2019-20 का बजट आम नागरिक का बजट है। प्रत्येक वर्ग की राय लेकर बजट प्रस्तुत किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है। वर्षा से लेकर फसल बेचने तक किसान संघर्ष करता है। किसान के इस बहुमूल्य संघर्ष पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

पशुओं पर सभी बोल रहे थे कि आवारा पशुओं के लिए नंदी-गोशालाएं स्थापित की जाएंगी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आवारा पशुओं पर कहना चाहती हूं कि आए दिन हाई वे पर या रोड पर गाड़ियों या मोटरसाइकल

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

से एक्सीडेंट होने से लोगों की मृत्यु होती है। जो नंदी-गोशालाएं खोली जा रही हैं उसके लिए तो मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ ही कहना चाहती हूं कि घर में जो पशु रखते हैं उनके लिए भी विशेष नियम बनाए जाएं तो शायद आवारा पशु कम हो जाएंगे। क्योंकि घर में पशु रखते हैं, उनका दूध दुहने के बाद उन पशुओं को रोड पर आवारा छोड़ देते हैं। रात्रि में सब निकलते हैं तो उनके कारण वाहनों का एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा आपको सुझाव है कि इसको आप क्रियान्वित करें।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में डामर सड़क से वंचित गांवों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का व्यय करने के लिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही यह कहना चाहती हूं कि मैं किशनगंज विधान सभा क्षेत्र से आती हूं मेरा पूरा एरिया जंगलात का है, वहां पर सड़कों का डामरीकरण बहुत कम होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में कई जगह पिछले टाइम पर उद्घाटन तो कर दिया गया था, पर काम शुरू अभी तक नहीं किया गया है। मेरे यहां अधिक से अधिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, कई सड़कें बिगड़ी हुई हैं उनके कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनका भी सुदृढ़ीकरण होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन एवं सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहती हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करना चाहती हूं कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास को ध्यान रखते हुए 21 जिलों में जिनमें मेरा बारां जिला भी आता है, बूंदी, कोटा, राजसमन्द, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, सिरोही आदि जो लघु सिंचाई में आते हैं, मैं मांग करना चाहती हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वहां पानी का अभाव है। जनवरी में ही पानी कम हो जाता है, वहां के लोग पलायन कर जाते हैं, मेरे यहां बांध बनाने की मांग करती हूं। वहां पर पहाड़ी बांध और नरेली बांध को इस बजट में लिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि गरीबों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा और जांच योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना में अभी 608 दवाइयां नि:शुल्क दी जा रही हैं।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

हार्ट एवं कैंसर जैसे गम्भीर रोगों की दवाओं सहित इसमें कुल 104 प्रकार की दवाइयां शामिल की गयी हैं, यह प्रयास सराहनीय है। मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि मैं जिस किशनगंज विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह बारां से बहुत दूर पड़ता है मेरा अनुरोध है कि आपने दवाइयां तो उपलब्ध करवाई है उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन वहां पर दवा देने के लिए डाक्टर्स की भी बहुत कमी है। अभी बरसात का मौसम है, इस मौसम में बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, इसलिए वहां डाक्टर्स की शीघ्र व उचित व्यवस्था की जाए। आपने नि:शुल्क दवा योजना में हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की है लेकिन हमारे यहां से कोटा मेडिकल कालेज बहुत दूर पड़ता है। मेरी आपसे मांग है कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं वहां सहरिया परिवार बहुत ज्यादा हैं, इन बीमारियों से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं, वह कोटा तक नहीं आ सकते इसलिए बारां में मेडिकल कालेज खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के बहुआयामी विकास के लिए प्रियदर्शिनी इंदिरा शक्ति निधि योजना बनाने के लिए सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र से बहुत बच्चे कोटा कोचिंग के लिए आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते क्योंकि गरीब सहरिया इलाका है, गरीब परिवारों से बच्चे हैं, कोटा आकर पढ़ाई करने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते। इसलिए बारां क्षेत्र में कोचिंग खोली जाए ताकि आदिवासी सहरिया बच्चे बारां में ही कोचिंग कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र शाहबाद में किला सुदृढ़ीकरण के लिए पैसा दिया। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने के लिए समय दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2019-20 पर आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए सदन में मौका दिया उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं।

(श्री आलोक बेनीवाल)

माननीय मुख्य मंत्री, आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब ने राज्य के कल्याण, जन उपयोगी एवं सुशासन को समर्पित जनता का बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी थी जिसको पटरी पर लाने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रखा है।

कृषि के क्षेत्र में सरकार ने आते ही कर्जा माफी की घोषणा की। इस बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की जो घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, निश्चित तौर पर आज की हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें किसान को अपनी फसल के उचित मूल्य के लिए अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब जब पिछली बार मुख्य मंत्री बने थे।

उस समय भी संवेदनशील सरकार उनकी थी। उस सरकार ने भी कृषि के क्षेत्र में नये-नये जो नवाचार किये हैं, निश्चित तौर से आने वाले समय में किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और उसका लाभ किसान को मिल सके, यह सुनिश्चित करने का काम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

किसान रबी और खरीफ की फसल ही नहीं, फल और सब्जी भी पैदा करता है। अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी वह सब्जी पैदा करता है, जब सब्जी के दाम अच्छे होते हैं, तब तो उसे अच्छा प्रोफिट मिल जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि टमाटर सड़क पर फेंके जाते हैं। प्याज भी फेंके जाते हैं, जो दुर्दशा किसान की होती है, हमें उस क्षेत्र में भी हमें काम करने की आवश्यकता है कि किसान जो फल और सब्जी पैदा करता है, उसका दाम भी उसे पूर्ण रूप से मिल सके।

देखा गया है कि प्याज के कारण तो कई बार सरकार ही चली गयी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम किसान को जो हर उपज वह

(श्री आलोक बेनीवाल)

पैदा करता है, उसका उसे सम्पूर्ण लाभ मिले। वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर युवाओं का गांवों से पलायन रुक पाएगा। उन्हें नयी दिशा में डाइवर्ट करने की भी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग अगर कृषि के माध्यम से लगा सकें और वहां रोजगार के अवसर पैदा कर सकें, तब जाकर ग्रामीण क्षेत्र से नौजवानों का पलायन हम रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नौकरियां इतनी नहीं हैं कि हम नौकरियां दे पाएं।

हर नौजवान इस क्वालिफिकेशन का नहीं है कि उसे हर जगह नौकरी मिल जाए। हर तरह का नौजवान है, ज्यादा पढ़ा-लिखा नौजवान भी है और कम पढ़ा-लिखा नौजवान भी है, हमें हर तरह के नौजवान की तरफ देखने की आवश्यकता है कि वह कहां पर अपना जीवन यापन करने की क्षमता रखता है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने निश्चित तौर पर, चाहे हमारे ग्रामीण परिवेश में हो या शहरी क्षेत्र में हो, आज हमारी गौमाता है, चाहे आवारा पशु हैं, इनके संधारण के लिए जो नंदीशाला की व्यवस्था की है हरेक पंचायत समिति में, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि नंदीशाला के साथ में डाक्टर्स और कंपाउंडर्स की व्यवस्था भी जरूर करें, क्योंकि उनकी भारी जरूरत नंदीशाला में पड़ती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया है।

आने वाले समय में आवश्यकतानुसार पंचायत स्तर पर भी अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे पता है माननीय मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं और वे इसकी व्यवस्था भी करेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, सड़कों के विस्तार के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में अच्छा प्रावधान किया है। अभी विपक्ष के साथी बजट पर कह रहे थे कि सड़कों का काम नहीं हो रहा है। मेरे यहां भी कई सड़कें सैंक्शन हुई थीं चुनाव से पहले, लेकिन उनका बजटीय प्रावधान नहीं होने से वे आज भी अधूरी पड़ी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय जो काम शुरू किया था, उसे अब पूरा करें जिससे यह महसूस हो कि हमने सैंक्शन करायी है। कम से कम उसमें बजट का प्रावधान तो करते। वह काम तो शुरू होता, उसका डामरीकरण तो होता, लेकिन सिर्फ अपना नाम लिखाने के लिए उन सड़कों का उद्घाटन किया गया। आज छह या सात महीने में जाकर उसमें कहीं न कहीं डामरीकरण का काम हुआ है। मैं

(श्री आलोक बेनीवाल)

आपसे कहना चाहता हूं, लाखों-करोड़ों रुपये ठेकेदारों के बाकी हो गये हैं। ये कोई सात महीने में नहीं हुए, ये पिछली सरकार के कारण ही बाकी हुए हैं, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है।

विगत सरकार की जो नीतियां हैं, उनके कारण भी आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज उन सड़कों का निर्माण नहीं होगा। बरसात का समय है, वहां पर पैदल चलने वाला भी उस सड़क पर नहीं चल सकता। आज भी सड़कों की हालत ऐसी है जिन पर गाड़ी, मोटरसाइकल या साइकल चलना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। लेकिन अधिकारियों, माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने कोशिश की और उन पर डामरीकरण का काम लगभग-लगभग पूरा हो गया है। बीच में कहीं-कहीं बाकी है और कुछ समय बाद वह काम भी पूरा हो जाएगा।

सभापति महोदय, साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और भी करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ओवरब्रिज है जो वैसे तो नेशनल हाई-वे का मामला है, लेकिन राज्य और केन्द्र में पांच-पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रह गयीं, पर आज तक उस ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। भगवान जाने कब होगा। उसके कारण आज भी मेरे क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। जनहानि हुई है उसके कारण। केन्द्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने कई बार घोषणा की कि दिल्ली-जयपुर हाई-वे को जल्दी पूर्ण किया जाएगा, लेकिन आज तक उस ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

गांव की जनता बंटी हुई है आधी इस साइड में और आधी उस साइड में, उसे आने-जाने में भी बहुत परेशानी है। उसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। जनहानि हुई है मेरे यहां पर। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, पिछली सरकार इतनी संवेदनशील थी और मेरे यहां की इस समस्या का समाधान अगर करती तो निश्चित तौर पर आम जनता को राहत मिलती। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा व्यवसाय है जहां 25 से 30 हजार ट्रक आपरेटर काम करते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक मांग करता हूं कि बहुत समय पहले आदरणीय कमला जी वहां से मंत्री थीं, उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की योजना बनायी थी। आज आवश्यकता है कि उस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी हमें कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की सौगात अवश्य दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा। पेयजल की स्थिति हमारे यहां बड़ी खराब है। पानी बहुत नीचे चला गया है। सिंचाई के लिए कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की भी बहुत खराब हालत है। जो हमारा पड़ौसी क्षेत्र है, वहां से पानी लेने की हमें जरूरत पड़ती है और वहां लगातार हमें संघर्ष करना पड़ता है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री राजकुमार रोत।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से एक अच्छा चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता है। पिछले समय में सौ बैड का हुआ था, अब दो सौ बैड का करने की कृपा करें। साथ ही आपसे कहना चाहूंगा रोजगार के क्षेत्र में, पिछली सरकार के टाइम में जो नौकरियां निकाली गयीं, वे लगातार न्यायिक प्रक्रिया में उलझकर रह गयीं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो 75 हजार नौकरियां उन्होंने घोषित की हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की गलतियों को इसमें नहीं दोहराया जाएगा और निश्चित रूप से जो हमारे युवा साथी हैं, उन्हें समय पर नौकरी मिल पाएगी।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): 000

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): 000

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। बैठिए माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज 2019-20 के राज्य के इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपकी नजरें इनायत इधर भी रखिएगा।

श्री सभापति: पूरी हैं नजरें इनायत इधर। बिना समय के आपको बुला रहे हैं। यह आसन का अधिकार है किसको बुलाना है। आसन को निर्देश न दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, नजरें इनायत के लिए तो कह ही सकते हैं न। नजरें इनायत रहे, यह तो कह ही सकते हैं। बाकी थोड़ी कुछ कहा है हमने।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद सभापति महोदय, हम नये-नये सदस्य आये हैं, पक्ष और विपक्ष हमें डरायें नहीं, हमें बोलने का मौका दें। सर आज 2019-20 के बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए सभापति महोदय को हार्दिक जोहार करते हैं। राजस्थान के सर्वांगीण विकास, सभी समुदायों व भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी जो 10 तारीख को बजट लाये, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। सभी सदस्यों ने इस बजट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं, अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और अपने-अपने सुझाव दिये। मेरे भी सुझाव हैं, मेरी भावना है कि सदन में इस बजट में विशेषकर किसानों के मुद्दों पर, किसानों की योजनाओं पर तो चर्चा हुई है क्योंकि इस राज्य के किसान इतने पीड़ित हैं, सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं फिर भी आज किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने पूरी कोशिश की है कि राज्य के किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए। अभी हाल ही में जो ऋण माफी वाला मामला था कि सरकार ने ऋण माफी नहीं की, यह नहीं किया, वह नहीं किया तो हम सरकार से भी कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो ऋण माफी का घोटाला हुआ, उस घोटाले को निकाले, पाई-पाई का हिसाब ले। क्योंकि ये जो दबाव बना रहे हैं कि ऋण माफी नहीं कर रहे हैं, यह नहीं कर रहे हैं तो मैं सरकार को कहना चाह रहा हूं वे चैलेंज कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा घोटाला किया है, आप उस घोटाले का खुलासा करो तो सरकार इसका खुलासा करे, जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करे।

जो किसानों को बीज दिया जाता है, खाद दिया जाता है तो मैं भी किसान परिवार से हूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र से हूं। मैंने देखा है किसान कुछ बो देता है उसके 2 महीने, 3 महीने बाद उसको खाद मिलता है, बीज मिलता

(श्री राजकुमार रोत)

है तो वह क्या करता है? गेहूं मिलता है या मक्का मिलता है तो रोटी बनाकर खा लेता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि समय पर किसान को खाद, बीज, उर्वरक दिया जाए।

जो कृषक कल्याण बनाया गया है इसका उद्देश्य यह है कि जो किसानों की स्थिति है, जो परिवार पीड़ित है, कोई मृत्यु हो जाती है तो उनमें सुधार लाया जाए। पर फिर भी पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं किसान अपने कर्जे के कारण, खेती के कारण आत्महत्या करता है तो सरकार से अपील है कि आने वाले समय में किसान के लिए ऐसा मौका नहीं आने दें।

मुख्य मंत्री महोदय ने जीरो बजट, प्राकृतिक कृषि पर फोकस किया है। मैंने भी पढ़ा, मैंने भी समझा कि जीरो बजट क्या है, तो मतलब बिना बजट के, बिना किसी खर्चे के किसानों को फायदा पहुंचाना। किसान ऐसी खेती की उपज करे कि उसमें कोई बजट नहीं लगे। मैंने भी इसके बारे में जानकारी ली कि जैविक खेती की जाए। पिछली सरकार ने तो हमारे डूंगरपुर जिले को जैविक जिला घोषित कर दिया था। जैविक जिला भी घोषित कर दिया और चाय की थड़ी पर बात करने वाले नेताओं को आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगहों का किसानों के नाम से भ्रमण करा दिया। करोड़ों रुपये का खर्चा किया गया, पर आज मेरे जिले में कहीं जैविक खेती नहीं देखी जा रही है। मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूं, उसमें सुझाव देना चाह रहा हूं कि एक किसान जो प्राकृतिक खेती करेगा, जैविक खेती करेगा, वह जब बीज लाता है, बोता है, दुकान से जो बीज दिया जा रहा है, मेरा अनुभव है कि जो बीज सरकार दे रही है उसमें अगर यूरिया खाद नहीं डालेंगे तो वह उसकी उपज ही सही नहीं दे रहा है।

जब एक किसान यूरिया खाद डालेगा उसमें 46 परसेंट नाइट्रोजन होगा और एक किसान जो देशी खाद डालेगा उसमें 0.5 परसेंट नाइट्रोजन होगा। अब जो जैविक खेती करेगा उसको 40 से 50 दिन तक गोबर उठाना पड़ेगा, गोबर उठाकर वहां मेहनत करेगा फिर खाद डालेगा और दुकान से जाकर या सरकार से मिलने वाला यूरिया लाकर एक दिन में डाल देगा तो मजदूरी भी बहुत पड़ती है। अब आगे का देखा जाए और जब उसकी कीमत तय होती है तो जो यूरिया से पैदा होता है वह 40 रुपये में बिकता है और जो जैविक खेती करता है उसकी कीमत रहती है 16 से 18 रुपये। इसलिए किसान जब खेती करता है

(श्री राजकुमार रोत)

तब भी मारा जाता है और उसकी खेती की उपज होती है तब भी मारा जाता है क्योंकि मार्केट में कोई भी ग्राहक है, कोई भी उपभोक्ता है वह देखता है कि दाना कौनसा बढ़िया है, मोटा कौनसा है तो वह उर्वरक वाला ही है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि जैविक खेती के लिए सरकार जो योजना बना रही है, उसमें जो प्राकृतिक उत्पादन हो रहा है, जो जैविक खेती के द्वारा उपज हो रही है उसका ऐसा कोई मार्केट तय करे कि यह जैविक खेती से उत्पादन है। हमारे एरिया में लोगों ने किया, एक साल किया और दूसरी साल अहमदाबाद भाग गये। क्योंकि जो अनाज पका था उसका कोई मूल्य ही नहीं मिला। तो मैं सरकार से अपील करना चाह रहा हूं कि इसमें थोड़ा और अध्ययन करे और इसमें कोई सुधार करे तथा इसका कोई प्रमाण दे या ऐसी कोई व्यवस्था बनाकर अलग से जैविक खेती का मार्केट बनाए तो किसानों को जैविक खेती में प्रोत्साहन मिलेगा और उनको फायदा मिलेगा।

हमारा डूंगरपुर जिला है, मैं पहले बोल चुका हूं कि जैविक खेती में आन्ध्रप्रदेश राज्य इस देश में प्रथम है और इस राज्य में डूंगरपुर जिला जैविक खेती में प्रथम है। मैंने यह चीज देखी है कि डूंगरपुर जिला हर चीज में पहले नम्बर पर रहता है। जैविक खेती में पहले, शौचालय मुक्त में पहले, स्वच्छता में पहले और दारू पीने और पिलाने में भी पहले। मतलब डूंगरपुर को बलि का बकरा बना रखा है और वह सिर्फ कागजों में पहले है, धरातल में कोई नहीं मिलेगा वहां। जैविक खेती के बारे में देख लो, शौचालय के बारे में देख लो, नरेगा के बारे में देख लो, हर चीज में कागजों में पहले, रिकार्ड पर पहले और धरातल पर कुछ नहीं। हम सरकार से चाहेंगे कि जो योजनाएं लागू हो रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उनका नियंत्रण सही हो, उनकी निगरानी सही हो। ऐसा विभाग बनाया जाए या जो विभाग है उसको ऐसे एक्टिव किया जाए कि व्यवस्थित निगरानी रखे और इस पर नियंत्रण रखे।

1974-75 में केन्द्र सरकार ने अलग से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए....

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): उप योजना का निर्माण किया था। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, एक मिनट, अभी समय हुआ नहीं है। मैंने नोट किया है 7.39 से 10 मिनट का समय मिला है मुझे।

श्री सभापति: बहुत मौका मिलेगा बोलने का, अब आप समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): दो मिनट। मैं कहना चाह रहा हूं कि 1974-75 से जो अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजना की थी, 2016-17 में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने बन्द कर दी तो वह एक तरह से कहीं न कहीं एससी, एसटी के साथ धोखा हुआ है। मैं वर्तमान सरकार से अपील करना चाहूंगा कि तेलंगाना सरकार की तरह, महाराष्ट्र सरकार की तरह अलग से एससी, एसटी के लिए विशेष विकास कोष का निर्माण किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सरकार ने हमारे एरिया में भीखाभाई नहर के लिए बजट दिया है। उसमें मैं यह सुझाव देना चाह रहा हूं कि सरकार पहले यह तय करे कि उस नहर को पूर्ण करने में टोटल कितना पैसा लगेगा क्योंकि यह नहर 30 साल से चल रही है और 30 साल से उसका निर्माण चल रहा है, पर आज तक पूर्ण नहीं हुई है। इसके अलावा जो पीछे बनी है खतम हो रही है और आगे बन रही है तो सरकार यह तय करे कि इस नहर को पूर्ण करने में टोटल कितना पैसा लगेगा उस आधार पर इस नहर के लिए पैसा दे।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): पेयजल के लिए सरकार ने, स्वच्छ पेयजल के लिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पूरा राजस्थान फ्लोराइड युक्त है, फ्लोराइड से पीड़ित है तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो सरकारी स्कूलें हैं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें डी-फ्लोराइड यूनिट लगाई जाए। उसमें सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से डी-फ्लोराइड यूनिट लगवाई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इधर से भी बुलायें साहब। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो चले जाएं।

श्री सभापति: सब क्रमबद्ध ही बुला रहा हूं, आप निश्चिंत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनके तीन हो गये साहब।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सरकार से यह निवेदन है कि राजस्थान में फ्लोराइडयुक्त जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं उनमें डी-फ्लोराइड की यूनिट लगवाई जाए। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ऐसा मत करो आप। मेरी प्रार्थना है आपसे प्रतिपक्ष हैं हम भी।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, क्रमबद्ध ही बुला रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उधर से चार बोल चुके हैं, यह चौथी बार है।

श्री सभापति: वह सब अलग-अलग पार्टियों के हैं, निर्दलीय हैं। आपके निर्देश की आवश्यकता नहीं है आसन को, विराजिये आप। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आम बजट पर चर्चा करते हुए मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस आम बजट में अपनी बात रख रही हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं जोधपुर की जनता को कि उन्होंने मुझे यहां अपनी बात रखने के लिए भेजा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार सभी के दिल को छूने वाला बजट और आम आदमी के लिए बजट पेश किया है। मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हर वर्ग और हर शहर का ध्यान रखा है। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में जनता के लिए जनता का बजट पेश किया है, इस हेतु राजस्थान और हमारी सरकार को बहुत-बहुत बधाई। यह बजट किसी न किसी रूप में सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी रहेगा।

चाहे शिक्षा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, कृषि एवं उद्योग, साथ ही बेरोजगार युवाओं की दृष्टि से भी यह बजट बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कानून व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जवाबदेह बजट पेश किया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूं मुख्य मंत्री जी को और बहुत भाग्यशाली भी अपने आपको समझती हूं कि मैं उस क्षेत्र से आती हूं जो मुख्य मंत्री जी का गृह जिला है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो बहुत भाग्यशाली हूं। लेकिन पूर्व में पांच साल वसुन्धा सरकार रही

(श्रीमती मनीषा पंवार)

थी, उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला जोधपुर है, उससे बहुत ही सौतेला व्यवहार रखा गया था और एक भी विकास के कार्य को अंजाम नहीं दिया गया था। जहां जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए था। लेकिन वसुन्धरा सरकार ने उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा न देते हुए, एक भी विकास कार्य के साथ नहीं जोड़ा। रिफाइनरी को पांच साल तक भटकाये रखा।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले बजट भाषण में जोधपुर में पुन: नये विकास के आयाम स्थापित करने की कोशिश की। बार-बार विपक्ष से यह बात रखी गयी कि बजट में केवल जोधपुर का नाम रखा गया है, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। क्योंकि, राजस्थान की दूसरी सिटी जोधपुर शहर है, जो शिक्षा का हब बन चुका है। जहां एम्स स्थापित हो चुका है, जहां बड़े-बड़े बिजनस स्थापित हो चुके हैं, तो वहां विकास करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है।

मैं धन्यवाद देती हूं गहलोत साहब को कि उन्होंने आते ही किसानों के ऋण माफी की घोषणा की और अपने बजट में किसानों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया। जोधपुर में भी पशुपालन को देखते हुए एक नवीन पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की। आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए क्योंकि हर शहर में आज हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आवारा पशु की समस्या खड़ी हो रही है। पंचायत समिति हो चाहे, नगर निगम हो, नगर निगम के माध्यम से नंदीशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसलिए, मैं गहलोत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ एक बार और जोधपुर की जनता की तरफ से गहलोत साहब को धन्यवाद देती हूं कि जोधपुर में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना करने का उन्होंने निर्णय लिया। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। जोधपुर सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जहां सूरज बहुत तेज तपता है तो वहां सौर ऊर्जा की बहुत ज्यादा उमंग रहती है।

अत: जोधपुर में हर छत, हर घर में, हम चाहते हैं मुख्य मंत्री जी की अनुशंसा पर सोलर पैनल लगे। युवाओं को एक नई सौगात दें और बिजली बचत करने में भी इसका उपयोग करें।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

जोधपुर में भी सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 765 केवी का ग्रिड सब-स्टेशन जोधपुर में स्थापित करने की घोषणा की, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूं। जैसे ही गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने जोधपुर में प्रथम बार आए और जनता को जब धन्यवाद दिया तो जनता की सबसे पहली मांग थी कि जोधपुर की जो यातायात की अव्यवस्था है, उसको सुधारा जाए। उन्होंने अपने भाषण में जोधपुर की जनता को सबसे पहले इस एलिवेटेड रोड का एक तोहफा दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूं उन्होंने अपने पहले बजट में ही मां मन्दिर से होते हुए पावटा और सोजती गेट से होते हुए आख्यलया चौराहे तक जो एलिवेटेड रोड का वादा जनता से किया, उन्होंने अपने पहले ही बजट में पूरा किया।

आदरणीय सभापति जी, हमेशा से ही मुख्य मंत्रीजी चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील और सजग रहे हैं। उन्होंने हमेशा नि:शुल्क दवा योजना की ओर देखा है। नि:शुल्क दवा योजना में उन्होंने बढ़ोतरी की है। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मौहल्ले और गलियों में भी एक जनता क्लीनिक खोलने का, बजट में प्रावधान किया है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

इसी क्रम में जोधपुर की जनता की तरफ से मैं उनको ढेरों धन्यवाद करती हूं कि कैंसर रोगियों के उपचार हेतु 31 करोड़ की लागत से लिनियर एक्सीलंलेटर मशीन की स्थापना कर जोधपुर की जनता को सौगात दी है। हमारे शहर का सबसे बड़ा हास्पिटल है मथुरादास माथुर हास्पिटल, उसमें भी एक आईसीयू वार्ड का चरणबद्ध निर्माण करने, मल्टी स्टोरी, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

इसके साथ प्रदेश के हर स्तर, हर वर्ग चाहे वह महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, उनके लिए जो उन्होंने योजनाएं बनायीं, अपने बजट में जो उन्होंने आयाम पेश किये, वह बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के उत्थान के लिए, बहुआयामी सशक्तीकरण के लिए प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की घोषणा की, जिससे महिलाओं में एक सशक्त निर्णय करने की अब क्षमता होगी, महिलाओं के उद्यम स्थापित हेतु उचित व्यवस्था की जाएगी। बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए, सरकारी स्कूलों में छठी क्लास से लेकर

(श्रीमती मनीषा पंवार)

12वीं क्लास तक, उन्होंने राजकीय स्कूलों में शारीरिक आत्म परीक्षण अनिवार्य किया है। उसके लिए छात्राओं की तरफ से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वृद्ध पेंशन बढ़ानी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना हो हर स्तर पर मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं।

श्री सभापति: श्री जगसीराम।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण में शुरूआत भी उन्होंने की और जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में दर्शको को...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): बैठने की सुविधा के लिए बजट का प्रावधान किया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, 10 जुलाई, 2019 माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर, अपना अर्थशास्त्र लगाए बिना, भाजपा सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर नकल करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, जिस तरह से हम लोग, अभी हमारे बोलने के क्रम में भी ऐसा महसूस हो रहा है, एक प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सभापति महोदय, इन्होंने बजट भाषण में दर्शाया है, जैसे कि भामाशाह योजना है, इसका नाम बदलकर जन आधार कार्ड, आधार योजना, यही नहीं ग्रामीण गौरव पथ के नाम से पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में, जो कि पूरे प्रदेश भर में हर ग्राम पंचायत पर ग्रामीण गौरव पथ के नाम से जाना पहचाना जाता था तो उसके नाम को बदलकर इन्होंने विकास पथ। इसी तरह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना है, इसका नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचय योजना। किसान राहत आयोग के स्थान पर कृषक कल्याण योजना।

माननीय सभापति महोदय, किसान क्षेत्र से मैं भी आ रहा हूं और पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किये थे, उन कामों की तुलना में, वर्तमान सरकार करके दिखाए तो प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान समझेगा कि कुछ किया है। यही नहीं सरकार ने अपने बजट में कर्ज माफी की बात तो कही है, लेकिन कर्ज माफी के लिए सरकार ने बैंकों को धनराशि देने का प्रावधान नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, बजट में घाटा पूर्ति के लिए, बजट कहां से जनरेट होगा, बताया नहीं गया है। घाटे के बजट में यह व्यवस्था अनिवार्य थी।

माननीय सभापति महोदय, डीजल, पैट्रोल एवं गैस पर वैट लगाकर आम आदमी पर बेहद भार डाल दिया है। यही नहीं जमीनों की डीएलसी रेट में 20 परसेंट से 47 परसेंट की बढ़ोतरी से प्रदेश की जनता निराशा महसूस कर रही है।

(20.00 बजे)

सरकारी नौकरियों में 75 हजार भर्तियों की गलत बयानबाजी की। बजट से पहले से इनमें से आधे से ज्यादा भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की

(श्री जगसी राम)

जा चुकी है। आधी से ज्यादा भर्तियां पहले से ही ओपन की जाकर अण्डर प्रोसेस हैं तो फिर बजट में इन्हें पुन: दर्शाना प्रदेश की जनता के साथ गुमराह करने का प्रयास है।

सभापति महोदय, इस बजट में प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं देकर उस क्षेत्र को मुंह ताकने को छोड़ दिया है। भाजपा काल में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में जो काम किये थे उनमें आबू रोड़ क्षेत्र में 43 सड़कें 45 करोड़ की लागत से प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र की ढाणियों में सड़क पहुंचाने का प्रयास किया था।

सभापति महोदय, प्रदेश में एक तरफ तो जहां डीजल, पैट्रोल पर वैट लगा दिया है, दूसरी तरफ दुपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहनों की कीमतों में वृद्धि करने से आम आदमी के आवागमन से लेकर व्यापार, व्यवसाय को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मंदी और महंगाई की ओर जाने को मजबूर कर दिया है।

सभापति महोदय, बेरोजगारी भत्ते का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। किसानों की कमप्लीट कर्ज माफी की गयी है। युवा, महिला, किसान, व्यापारी, गरीब आम जनता के लिए निराशाजनक है। कृषि यंत्र से जीएसटी हटाने की कांग्रेस घोषणा पत्र में घोषणा की गयी थी। घोषणा पत्र की पालना हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, पुलिस को अपराध से निपटने की खुली छूट तो दे दी है लेकिन आज भी प्रदेश के पुलिस थानों में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की मानिटरिंग की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गयी है। हत्या, गोलीबारी, चोरी, डकैती, चैन स्नेचिंग, बलात्कार, साइबर क्राइम बेतहाशा बढ़ता ही जा रहा है।

सभापति महोदय, महिला उद्यमियों के लिए बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। जयपुर को भिखारी मुक्त ...(व्यवधान) करना अच्छी बात है लेकिन इन भिखारियों को रोजगार देने का प्रयास करने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने जो बजट भाषण में बात कही है उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया है। जब भी सदन के माननीय नेता जवाब दें तो उसके लिए जरूर बताएं। राजधानी जयपुर

(श्री जगसी राम)

को विश्व विरासत का दर्जा मिलना बड़े ही फख्र की बात है। भाजपा सरकार भी इसके लिए श्रेय की पात्र है। अब सैलानियों का अवागमन बढ़ेगा, लेकिन जयपुर की बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था, पग-पग पर जयपुर शहर में जाम और शहर में घूमते हुए आवारा पशु कुत्ते, सूअर, नंदी आदि को सड़कों, बाजारों, आवासीय कालोनियों में खुले घूमने की इजाजत सरकार ने दे रखी है। विश्व धरोहर राजधानी जयपुर की इस मेजर समस्या के समाधान के लिए कोई व्यवस्था बजट में नहीं की है।

सभापति महोदय, प्रदेश की सड़कें लो फ्लोर बसों से लेकर, डम्परों और ट्रोलों आदि से लाल हो रही हैं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। आप विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये आप। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आसन पैरों पर है। सहयोग करिये आप। क्यों समय खराब कर रहे हैं आप। विराजिये आप। प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, भाजपा के राज में किसानों की व्याख्या इस प्रकार से होती थी कि 'क' का मतलब किसी को नहीं परवाह जिसकी। 'सा' का मतलब सांसे अटकी हुई थी जिसकी। 'न' का मतलब नतमस्तक साहूकारों के आगे। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी में किसानों की थी। आज मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसान नीति और किसान के लिए बजट आबंटित किया है। देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है। आजादी के साठ दशकों बाद भी खेती करना फायदे का सौदा नहीं माना जाता है फिर भी अन्नदाता अदम्य साहस से आज देशवासियों का भरण-पोषण बिना लाभ-हानि की चिन्ता किये कर रहा है।

(श्री रामलाल मीणा)

पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह किसानों का शोषण किया है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को देखते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय गहलोत साहब ने किसानों को खाद, बीज सहित दवाइयां भी फ्री में देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी-पूरी कोशिश की थी। परन्तु चुनाव बाद राज परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सभी किसानों को मिलने वाले खाद, बीज सहित सभी योजनाएं बंद कर दी गयीं। कृषि यंत्रों पर नब्बे परसेंट सब्सिडी कांग्रेस सरकार में थी उसको भी खतम कर न के बराबर कर दी। गत पांच वर्षों में किसानों की स्थिति को बिगाड़कर रख दिया। सभी योजनाएं बंद कर दीं और उसके बाद में फसल का उचित दाम भी नहीं मिलने लगा। किसान परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। इन सभी समस्याओं से जूझते अन्नदाता के लिए करुण हृदय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक हजार करोड़ रुपये की लागत से कृषक कल्याण कोष की स्थापना की उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि इस योजना की विभिन्न प्रदेशों में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है और आज किसान पुन: सुख की अनुभूति कर रहा है। पूर्व भाजपा सरकार में जहां खाद, डीएपी और यूरिया की कीमतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया था। सीजन में खाद, बीज के लिए किसानों को कई दिनों तक लगातार इंतजार करने के बाद में घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लाख मीट्रिक टन डीएपी व दो लाख मीट्रिक टन यूरिया अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की है। ये लोग जो आज जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं गला फाड़-फाड़कर उच्च ध्वनि से, ये लोग सत्ता में जब बैठे थे उस समय किसानों को खाद-बीज के लिए लाइनों में लगना पड़ता था और बर्बरता से लाठीचार्ज कर उन किसानों को पीटा जाता था। आज ये किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है जनता इस बात को समझ चुकी है। जब-जब कांग्रेस सत्ता में आयी है गरीब, मजदूर और किसानों की बात की है और भाजपा हमेशा किसानों का शोषण करते हुए बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम करती है। सहकारी बैंकों का मामला भी आप देख लीजिये जब कांग्रेस की सरकार थी किसानों को बिना ब्याज के लोन का प्रावधान था। आज किसानों के कर्जे को लेकर जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं मेरे साथी लोग भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने भी एक घोषणा

(श्री रामलाल मीणा)

की थी ऋण माफी की पचास हजार की, आठ हजार करोड़ के ऋण माफ करने की बात थी और इन्होंने लीपापोती करके 2 हजार करोड़ ही माफ किया 6 हजार करोड़ उसमें से बचाकर चले गये। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि भाजपा के शासन में किसान कर्जे में डूबा जा रहा था और सरकार में बैठे मंत्री अन्नदाता की जमीन कुर्की के लिए किसान के खेत पर पुलिस और एसडीओ को गाड़ी पर माइक लगाकर भेज देते थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी, अम्बानी को यह कहकर कि ये तो डिफाल्टर हैं ऐसा करके उनके हजारों करोड़ों रुपये माफ कर देते, लेकिन अन्नदाता किसान को चोर साबित करने की इन्होंने कोशिश की।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, थोड़ा समय और दीजिये मुझे। आज पुन: जब माननीय मुख्य मंत्री जी के श्रीमुख से बजट सुनने को मिला तो दिल गद-गद हो गया कि पुन: किसान को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ऊर्जा के क्षेत्र के बारे में आज जो हमारे बजट में बात कही गयी है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के समय में हर साल बिजली के दाम बढ़ा दिये जाते थे। कल परसों यहां इधर के लोग कह रहे थे कि दिन में लाइट दी जाए। मैं इन सदस्यों से पूछना चाहता हूं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी किसानों को एक दिन भी दिन में लाइट नहीं दी। लेकिन मैं ऊर्जा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आज दिन में लाइट देने की बात की और मेरे प्रतापगढ़ जिले में 27 ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगाकर आपने जिस प्रकार से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करे। श्री छगन सिंह राजपुरोहित। माननीय सदस्य, पांच मिनट में समाप्त करना है आपको।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): कम समय में दिन में लाइट देने का जो प्रावधान किया था। आज कुसुम योजना की बात की है 30 परसेंट पैसा राज्य सरकार का, 30 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का और 30 परसेंट पैसा नाबार्ड से देने की बात की है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): बाकी पैसा जनजाति क्षेत्र में जनजाति विभाग से देकर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को फ्री में कुसुम योजना का फायदा मिले, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए, सहयोग करे, विराजिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मुझे परिवर्तित बजट 2019-20 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है परिवर्तित बजट, सब नामों को चेंज करना ही नाम लिखा हुआ है परिवर्तित बजट। आपने नाम में ही दिखा दिया है कि इसमें नाम का परिवर्तन करना है। जब बजट की घोषणा हो रही थी सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार था तो वह पंचायत सहायकों को था। सबसे ज्यादा अगर इंतजार था तो वह संविदा कर्मियों को था। सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार था तो वह बेरोजगार युवाओं को था। उनको पता था कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो लिखा था कि बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये देंगे, 3500 रुपये की बजट में कहीं भी चर्चा नहीं हुई माननीय सभापति महोदय, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पंचायतकर्मी और संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की थी, वह भी इस बजट में कहीं भी प्रदर्शित नहीं हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग की तो बजट में घोषणा होती है लेकिन जिसको बड़ा इंतजार था, जो आपकी सरकार को लाये हैं, जो 50 हजार युवा संविदाकर्मी और पंचायत सहायक थे, सिर्फ डेढ़ लाख वोटों का जो डिफरेंस था, यह 50 हजार परिवार ही आपकी सरकार लाने के लिए सक्षम बने थे, जिनके द्वारा सरकार बनी उन पर आपका ध्यान नहीं गया। इस ओर ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि लोक सभा चुनाव के पहले आपने जालौर में तीन, चार बार दौरा किया। दौरा करने का कारण था कि लोक सभा चुनावों में आपके पुत्र का भविष्य देखना चाहते थे। लेकिन इस बजट में आप पूरे जालौर जिले को भूल ही गये, जालौर जिले के लिए आपने कुछ नहीं दिया। आपने सभी जिलों की बात की, जालौर जिले के लिए कोई बात नहीं की। रीको की बात करूं तो तीन-चार जिलों में तो

(श्री छगनसिंह)

आपने रीको दिया है लेकिन मेरा आहोर विधान सभा क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है, वहां अगर रीको की घोषणा करते तो मुझे खुशी होती।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करूं तो आपके बजट में घोषणा हुई है कि दो आरओबी बनेंगे। मैं जालौर जिले की बात करूं तो आरओबी के लिए जो उपयुक्त रेलवे क्रासिंग है, जहां पर आत्मानंद जी स्वामी का मंदिर बना हुआ है और सर्किट हाउस के बीच में रेलवे क्रासिंग है, वहां पर तीन लाख वाहनों का भार है, वहां पर आरओबी बन जाए तो वास्तव में आपका विजन क्लीयर होगा।

इसी प्रकार से मैं पुनर्भरण की बात करूं, आपने शिवगंज में पेयजल के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की। उससे पहले आप जवाई पुनर्भरण की बात करते तो मुझे समझ में आता कि आप शिवगंज को पानी देना चाहते हो। आप सिर्फ और सिर्फ डीपीआर बनाकर उसको छोड़ देना चाहते हो। अगर आप जवाई पुनर्भरण की बात करते तो मुझे समझ में आता कि आप वास्तव में शिवगंज की जनता को भी पानी पिलाना चाहते हो, पाली वालों को भी पानी पिलाना चाहते हो और आहोर की जनता को भी पानी पिलाना और सिंचाई के लिए देना चाहते हो। आपके इस विजन में भी कहीं न कहीं दिक्कत है।

मैं आपकी एक बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि पंचायत समिति पर आपने नंदी शाला खोलने की घोषणा की। लेकिन यह सिर्फ घोषणा ही नहीं रहे, तुरन्त क्रियान्विति हो, इसी महीने से इस पर काम हो तो लगेगा कि वास्तव में आप पंचायत समिति स्तर पर नंदी शाला खोलना चाहते हैं। इसी प्रकार से जनजाति क्षेत्र की बात करूं तो जनजाति क्षेत्रों में मेरा आहोर विधान सभा क्षेत्र भी बैकवर्ड है, वहां पर जनजाति रहते हैं। अगर उनके छात्रावास के लिए भादरा और आहोर में आवासीय छात्रावास खोल दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, अनुकम्पा होगी क्योंकि वह भी टाडा, माडा जैसे क्षेत्रों के हैं। उन्हें भी टाडा माडा से जोड़ें जिससे उनका भी विकास पूर्ण रूप से हो सके।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित की बात अगर किसी ने की है तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है जिन्होंने नीम कोटेड यूरिया दिया। नीम कोटेड यूरिया से कालाबाजारी में रोक लगी। आपने तो किसानों को

(श्री छगनसिंह)

सिर्फ ऋण माफी का एक झुनझुना पकड़ा दिया जिसमें पहले तो कहा कि सम्पूर्ण कर्जा माफ होगा। सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, फिर कहा 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, 2 लाख तक का भी कर्जा माफ करने के लिए आपने सहकारी समितियों को निर्देश दिया जबकि आपको सभी बैंकों का करना था, वह भी आपने नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करुंगा, मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में भूति रोडला के बीच नदी क्षेत्र है, वहां पर 8 से 10 गांव थोड़ी-सी बारिश में ही रुक जाते हैं। अगर भूति और रोडला के बीच में पुल बन जाए तो वास्तव में विकास का कार्य होगा। इसी प्रकार से हुरजी और उम्मेदपुर के बीच में जवाई नदी पर भी पुल बन जाए तो विकास का काम होगा। यह विकास ही आपको बताएगा कि वास्तव में सरकार आई है।

चिकित्सा विभाग की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र भवरानी और घाणा में पीपीपी मोड पर दो गांव थे जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने कैंसिल कर दिया था कि इनको पीपीपी मोड पर नहीं रखना है, अभी तक वह पीपीपी मोड पर ही हैं, कृपया करके तुरन्त राजकीय सेवाओं में लें, धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें, श्री प्रशान्त बैरवा।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट 2019-20 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत साहब और उप मुख्य मंत्री आदरणीय पायलट साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन दोनों की वजह से मैं यहां पर आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे, फिक्र वह करे जिनकी शक्लों में कुछ और दिलों में कुछ होता है। हमारी कांग्रेस सरकार की मंशा बिलकुल साफ है। राजस्थान में जो विकास हमें कराना है उसके लिए हम बहुत कटिबद्ध हैं। उसी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बजट यहां पर राजस्थान की जनता को दिया है जिसमें हर वर्ग को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने चुनाव लड़ा तो जनता से हमने कई सारे वादे किये थे। कांग्रेस ने वादे किये इसीलिए कांग्रेस

(श्री प्रशान्त बैरवा)

की आज यहां पर है और जो वादे किये थे कांग्रेस का बजट उसी के मन मुताबिक बना है। चाहे वह युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे एसटी की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, हमने सभी वर्गों को इसमें शामिल करके सबको लुभाने का, उनको मदद करने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए वह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।

आपको मालूम है कि भाजपा का जो वित्तीय कुशासन था, वह सबसे बड़ी जड़ था, जिससे हमें आज तकलीफें महसूस करनी पड़ रही हैं। आपको मालूम है, केन्द्र में भाजपा की सरकार थी और राजस्थान में सम्माननीय वसुन्धरा जी की सरकार थी। दोनों सरकारों में थोड़ा-सा फर्क था। केन्द्र से बजट नहीं आता था। इसलिए राजस्थान को थोड़ा नीचा देखना पड़ा। मगर इन्हीं भाजपा वालों की सोच होती तो, हमारे जो पिछली सरकार के प्रोजेक्ट थे, चाहे वे मैट्रो रेल का मामला हो, चाहे वह रिफाइनरी का मामला, चाहे मैमू कोच फैक्ट्री का मामला, चाहे रेलवे लाइन का मामला जिसमें बांसवाड़ा, टोंक और करौली का मामला है। हमारी सारी की सारी योजनाएं बंद करके रख दी। अगर आज हमारे यहां पर रिफाइनरी होती तो हमारी जो वित्त की प्रोब्लम है, मैं समझता हूं कि वह काफी हद तक दूर रहती। The seven sins of Mahatma Ghandhi are :

1. Wealth without work
2. Pleasure without conscience
3. Knowledge without character
4. Commerce without morality
5. Science without humanity
6. Religion without sacrifice
7. Politics without principle

ये जो सात sins हैं, महात्मा गांधी जी ने दिये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 50 करोड़ का प्रावधान गांधी जी के संग्रहालय के लिए रखा है। हमारी नयी पीढ़ी को उनके आदर्श से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री प्रशान्त बैरवा)

भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय की बात की। मगर आपको मालूम है कि पिछली साल कई बड़े-बड़े केस हुए, जहां पर भाजपा में सुनवाई नहीं हुई। चार साल तक एस.सी. चेयरमैनशिप की सीट खाली रही। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, गलियों में भागे, तब जाकर एक बुजुर्ग नेता को बनाया। अगर किसी यंग को बनाते तो कोई काम भी कर पाता। ऐसे बुजुर्ग को बनाया, जिसने कोई काम नहीं किया। सामाजिक न्याय को देखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमारी पेंशन थी, गरीब की पांच सौ रुपये थी, उसको साढ़े सात सौ रुपये कर दिया। जो साढ़े सात सौ थी, उसे एक हजार रुपये कर दिया गया। इसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

सहकारिता के मामले में हमारी सरकार बहुत ज्यादा फोकस थी। राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके प्रयासों से, कांग्रेस की एक मंशा थी, कर्ज माफी की। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया। मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में भी 9 हजार के आसपास फसली ऋण को माफ किया गया है। हमने रोजगार देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने सभी डिपार्टमेंटों में 75 हजार के करीब नयी जोब्स क्रिएट की हैं। मैं समझता हूं कि इससे युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। जो हमने वादे किये थे, वे पूरे होने वाले हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): सर, थोड़ा-सा ही है। मैं कुछ अपने एरिये की डिमांड भी बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय महाविद्यालय पीपलू के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे एरिये में महिलाओं के लिए एक कालेज खुले। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार एक कालेज खोले। चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र जयपुर के पास पड़ता है। जयपुर में जमीनें महंगी हैं। रीको निवाई में भी है। मगर अभी वहां गुंजाइश है कि वहां पर सस्ती रेट में इंडस्ट्रियल एरिया डवलप हो। मैं सरकार से चाहूंगा कि आप वहां नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर दें, जिससे कि नये रोजगार खुलने का मौका मिलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): मैं बताना चाहूंगा पिछली बार की जो

(श्री प्रशान्त बैरवा)

भाजपा सरकार थी, वह एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। उन्होंने जितने भी उद्घाटन किये हैं, वे जनता से दूर किये हैं। बालीवुड में जब पिक्चर की लांचिंग होती है, तो वहां पर रैड कारपेट बिछाये जाते हैं। उसी तरह से उन्होंने रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन किया है। जनता के बीच में नहीं गये हैं। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज यहां पर है।

मैं जाते-जाते अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा। अभी माननीय कटारिया साहब और आदरणीय धारीवाल जी दोपहर में भारी आवाज को लेकर बात कर रहे थे। जो मन की बात करने वाले हैं, उनके लिए चार पंक्तियां हैं।

झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखो,

बात मन की कहो या वतन की कहो,

झूठ बोले तो आवाज अपनी भारी रखो।

धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): झूठ को डिलीट करवाइए।

श्री सभापति: पता है, क्या करना है। आप विराजिये। श्री हमीर सिंह भायल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक निवेदन करूं गुरूजी। धोरा धरती से बाड़मेर, पाकिस्तान बोर्डर से आता हूं। आप थोड़ी देर ठंडी नजर रखना। दो मिनट बोलने देना।

श्री सभापति: आपके पास पांच मिनट है। जल्दी करिए, लेट मत करिए। सब माननीय सदस्य को बोलना हैं। आपके पांच माननीय सदस्य हैं। सबके बारे में आप बोल लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेता महोदय, आपकी तरफ से हमीर सिंह जी सहित पांच सदस्य हैं। सबको बोलना है तब तो निर्देश मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अकेले बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): राजस्थान सरकार का बजट आम जन के लिए निराशाजनक है। इसमें घोषणा कम हैं, डीपीआर पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें किसान, व्यापारी एवं युवाओं के लिए थोथी घोषणाएं की गयी हैं। धरातल पर इस बजट से कुछ नहीं होना है। बजट में बताया गया है कि बहुमूल्य सुझावों का इसमें समावेश किया गया है। मुझे तो इसमें एक प्रतिशत भी ऐसा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थीं, उनका नाम जरूर बदला गया है। मैं तो आपसे निवेदन करुंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, गांव और ढाणी तक अगर इसका विस्तार किया है, तो स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने एक साथ। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार में स्कूलें नहीं बनीं, पर जहां वे जरूरी समझते थे, अपने आदमी समझते थे, वहां। उन्होंने एकदम पंचायत हैडक्वार्टर पर पांचवीं से आठवीं करके राजस्थान में गांव और ढाणी तक सौगात दी। 2003 से 2008 में आदरणीय वसुन्धरा जी राजे ने पूरे राजस्थान में आठवीं से दसवीं करके गांव और ढाणी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो सौगात दी और 2013 से 2018 में एक साथ 5356 स्कूलें सीनियर करके हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल बनाने का जो कार्य किया है, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार 2008 से 2013 में जीरो बैलेंस में अच्छी कालेज खोलकर गयी थी। उसमें मेरे यहां से एक सिवाना की थी। न कालेज चालू हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी से मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा कि 100 करोड़ का बजट दिया, वहां कालेज भी बनीं, स्कूलें भी बनीं, क्रमोन्नत भी हुईं।

सड़कों के मामले में मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एन.एच. 325, 315 में 900 करोड़ में मेगा हाइवे साण्डेराव तक रोड बनी। जालौर से बाड़मेर वाली 376 करोड़ में बनी और सिवाना से समदड़ी कल्याणपुर 320 करोड़ की लागत से। भारतीय जनता पार्टी का जब भी शासन रहा है, गांव, गरीब और किसान के लिए।

(श्री हमीर सिंह भायल)

किसानों के लिए फर्माता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कृषि फसल बीमा योजना लागू करके किसानों के लिए, आज दिन तक किसानों को जितना भी नुकसान है, उसमें फसल बीमा का अनुदान मिला है। 1 से 10 तक की गिनती करके जो कर्जा माफ की बात की थी, आज दिन तक किसानों की जेब में सहकारी समिति से एक नया पैसा भी नहीं आया। माननीय मंत्री महोदय फर्मा रहे थे कि हमने किसानों को ऋण देने का कार्य शुरू कर दिया है, वह भी आज दिन तक नहीं हुआ है। आज ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से लौटा हूं। एक भी जीएसएस सहकारी समितियों में किसानों का लाभ नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सहकारी समितियों से जो किसान लोन धारी था, उसके लिए पचास हजार, खेती में काम करते हुए अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती थी, उसे बढ़ाकर 2014 में, 2015 में और 2016 में तीन लाख, पांच लाख, छह लाख और दस लाख तक की। जब-जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उसमें किसानों के लिए पूरा काम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की तारीख में, बाड़मेर और जैसलमेर में दस दिन से तेज आंधी चल रही है। पीने के पानी की दिक्कत है।

अभी जो पोकरण फलसूंड योजना हमारे बाड़मेर, सिवाना और बालोतरा के लिए हुई थी, उसमें सिर्फ 450 मीटर पाइप अभी तक नहीं लगे हैं। त्राहि-त्राहि मची हुई है, पेयजल के लिए। यह स्थिति बन गयी है कि पशुओं के लिए चारा, पीने का पानी और इंसान के लिए भी पानी टैंकर मुहैया नहीं हो पा रहा है। अगर पानी की व्यवस्था पर समय रहते जोर नहीं दिया गया तो आज की तारीख में पानी की यह स्थिति बन गयी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): दो मिनट दीजिए।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर। आप विराजिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट पर चर्चा हो रही है। इस बजट भाषण का मैं पिछले दो-तीन दिन से बार-बार एक पन्ना पलट रहा था। इसमें कहीं भी झालावाड़ का नाम नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इस बार राजस्थान में 33

(श्री नरेन्द्र नागर)

की जगह 32 जिले ही सरकार के पास हैं। वर्तमान में सरकार की योजना जो झालावाड़ जिले में चल रही है, उस योजना में भी झालावाड़ जिले को बजट के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है।

मैं चूंकि किसान हूं और किसानों की स्थिति जिस प्रकार से दिनोंदिन देखने को मिल रही है, किसान निश्चित रूप से चाहता है कि अच्छी पैदावार हो ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अच्छी पैदावार के लिए वह अत्यधिक रसायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग बार-बार करके प्रयास करता है कि अच्छी पैदावार हो। जितनी भी कीटनाशक दवाई बाजार में आ रही हैं। जितनी बार किसान उसका उपयोग कर रहा है, उससे ज्यादा प्रकार के कीट पैदा हो रहे हैं। खरीफ की फसल में एक बार खरपतवार के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। परन्तु खरपतवार भी अब दो-दो बार उगने लग गई। एक विशेष रूप का घास सोयाबीन जब आती है, उस समय आने लग गया तो दो-दो बार खरपतवार का उपयोग हो रहा है। इस फसल को खाद्यान्न के रूप में मनुष्य यूज में ले रहा है। सभापति महोदय, वर्तमान में उदाहरण सामने आ रहे हैं कि कैंसर का प्रकोप बढ़ रहा है। पहले कैंसर जिस प्रकार से होता था लगता था 60 साल, 65 साल किसी की उम्र हुई है। अब 20 साल, 25 साल या जन्म होते ही कैंसर, ये सारे जो हो रहे हैं, चूंकि किसान बच्चों का पालन-पोषण करता है। बच्चों की शादी करनी है, उनके बच्चों को पढ़ाना है इसलिए मजबूरी है उसका यह करना कि किस प्रकार से उसकी पैदावार निकले। जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए जिस प्रकार से पिछली सरकार ने हर जिले में विशेष रूप से पैकेज बनाकर शुरूआत करने की घोषणा की थी, उसी प्रकार से विशेष रूप से किसानों को सरकार की तरफ से सहायता देने का प्रयास करना चाहिए।

चूंकि कोई भी किसान जैविक खेती करेगा तो लगातार तीन साल तक वह बराबर की स्थिति में नहीं आता है। तीन साल तक उसका उत्पादन कम होता है। तीन साल के बाद उसका उत्पादन बराबर स्थिति में आता है। इसके लिए विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जैविक खेती ज्यादा से ज्यादा हो ताकि राजस्थान की जनता को अच्छी तरह खाद्यान्न मिले। जिस प्रकार पंजाब के लोग चावलों में कीटनाशक का प्रयोग करके गर्मी के समय में राजस्थान में अपना चावल बेचने के लिए आते हैं, वहां उनका चावल बिकता

(श्री नरेन्द्र नागर)

नहीं है क्योकि वहां उनका चावल कोई खरीदता नहीं है। वह पंजाब में चावल दूसरी जगह से मंगाते हैं। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान की हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जैविक खेती पर विशेष रूप से ध्यान दें।

साथ ही वर्तमान में जिस प्रकार से जंगली जानवरों का प्रकोप बढ़ा है और जिस प्रकार से नरेगा योजना सरकार की तरफ से चल रही है तो कहीं न कहीं जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए बाड़बंदी के लिए कुछ अनुदान निश्चित रूप से सरकार की तरफ से मिलना चाहिए ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके। किसान चौबीस घंटे दिन-रात रखवाली के नाम पर खेत पर बैठा रहता है और कभी-कभी एक घंटे के लिए भी निकल जाता है तो उसकी फसल चौपट हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से सरकार की इस प्रकार की कोई योजना हो ताकि किसान अपनी खेती को बचा सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र और कोटा संभाग में परवन सिंचाई वृहत योजना बहुत बड़ी योजना है जिसमें पूरा बारां जिला है, कोटा जिला है, झालावाड़ जिला है। पिछले बजट में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने एक हजार करोड़ रुपये का उसमें बजट दिया था। वर्तमान में नहर का काम अभी चल रहा है और कुछ गांवों को अभी मुआवजा बाकी है। कुछ लोग जो दस साल से, काश्तकार जो अपनी जमीन बेच नहीं सकता, किसानों की इस प्रकार की स्थिति है कहीं न कहीं किसानों की मजबूरी है कि किसान को जमीन बेचना जरूरी है तो वह उसको बेचनी पड़ती है। सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे किसान हैं जो हमें फोन करके कहते हैं कि एमएलए साहब हमें बजट दिलाओ, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। हमें फोन करते हैं, इसके अलावा वहां के जिला कलेक्टर से मिलते हैं। एक के खिलाफ तो हमने कहा कि इनको समझाओ। माननीय सभापति महोदय, हमने यहां तक कहा कि बजट है जुलाई में, बजट आने के बाद...

श्री सभापति: समाप्त करिए माननीय सदस्य। समाप्त करें। श्री अविनाश गहलोत।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): एक दो सुझाव और हैं। हम कभी-कभी तो बोलते हैं सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। पश्चिमी राजस्थान के जैतारण विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं जहां जैन संत लोकमान्य संत रूप मुनि महाराज की समाधि स्थल है। उस विधान सभा क्षेत्र में नाथ सम्प्रदाय का सबसे बड़ा आराध्य स्थल है और रामस्नेही सम्प्रदाय का सबसे बड़ा आराध्य स्थल है। उसी जैतारण विधान सभा क्षेत्र में उत्तर भारत के सबसे बड़े उद्योगों के प्लांट स्थित हैं। इतना होने के बावजूद इस परिवर्तित बजट 2019-20 में पाली जिले के जैतारण के लिए कुछ नहीं दिया गया।

मैं कहना चाहता हूं राजस्थान विधान सभा आम चुनाव 2018 से पहले कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मात्र दो वादे बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज माफी का जनता के सामने लेकर आयी। जनता ने उनको मेन्डेट दिया और उनकी सरकार बनी। किन्तु लोक सभा चुनाव 6 महीने के बाद होने वाले थे। उन लोक सभा चुनाव में एक बार कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए पुन: ऐसे वादे कर दिए जिससे कांग्रेस सरकार को लगा कि एक बार हम पुन: लोक सभा के चुनाव में जीतेंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 72 हजार रुपये देने का वादा किया और कहा कि हम राष्ट्रदोह की धारा को खत्म कर देंगे। लेकिन विधान सभा चुनाव के नतीजों के बाद में 6 महीने तक कांग्रेस की राज्य सरकार ने न किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। राजस्थान की जनता ने उन दोनों वादों पर मुहर लगाने के बाद में, 72 हजार रुपये को ठोकर मारी और केन्द्र की मोदी जी की सरकार की किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपये को गले लगाकर राजस्थान की 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में दीं।

इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता जब कांग्रेस के मित्र यह कहते हैं कि राष्ट्रद्रोह की धारा को खतम कर देंगे। अगर राष्ट्रद्रोह की धारा को खतम कर देंगे तो आने वाले समय में राजस्थान के प्रति, हिन्दुस्तान के प्रति कोई भी व्यक्ति अपने संविधान के खिलाफ बोलने से नहीं चूकेगा। चूंकि, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक सिपाही हूं इसलिए इस बजट घोषणा पत्र पर बोलने से मुझे आदरणीय नंदलाल बाबाजी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें मैं इस सदन में पेश करना चाहूंगा-

सुन्दर सपने नव आकर्षण, सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले,
वैभव-महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले,

(श्री अविनाश)

साधन की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है,

मन मस्त फकीरीधारी है,

अब एक ही धुन जय-जय भारत, जय-जय भारत।

उस परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधाराओं को पूरे हिन्दुस्तान के अंदर स्थापित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन को, अपनी जवानी को इस देश के प्रति समर्पित कर दिया था। मैं उस पार्टी से आता हूं। मैं बात करना चाहता हूं बजट पर, किसान कर्जमाफी और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा जी की सरकार थी उनकी योजनाओं को परिवर्तित कर, उनका नाम बदलकर इस सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने दोबारा कहा है।

भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की केन्द्र सरकार की योजनाओं को अगर देखें तो चाहे उज्ज्वल योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, चाहे बिजली विभाग की महत्वपूर्ण सौभाग्य योजना हो, यह बहुत सी जनहित कल्याणकारी योजनाएं थी जिससे सीधा फायदा हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को उसके खाते में मिलने वाला था। दुबारा 2019 के लोक सभा चुनाव के नतीजे मिले तो 282 सीटों से सीधे 303 पर आकर मिले। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को एकदलीय बहुमत मिला। केन्द्र की मोदी जी की सरकार का 2022 तक का सपना है कि प्रत्येक घर को पीने के लिए मीठा पानी मिले। गरीब व पिछड़ा वर्ग जिसके रहने के लिए मकान नहीं है, उसको छत देने का वादा भी हमने 2022 तक किया है।

आजादी के 70 साल बाद भी हमारे गांव व ढ़ाणी में बैठे हुए व्यक्ति को, जो आज तक लाइट नहीं देख पाता है, जिसके घर में बल्ब नहीं जलता है, 100 परसेंट विद्युतीकरण करने का वादा हमारी केन्द्र की मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आज इस सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार का पांच साल का कार्यकाल होगा तो प्रत्येक गरीब, पिछड़े वर्ग को, आम अवाम को रहने के लिए मकान मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में, 100 परसेंट मिलेगा। जिसके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है उसको

(श्री अविनाश)

लाइट का कनेक्शन मिलेगा। 2022 के बाद 2024 तक प्रत्येक घर में मीठा पानी दे देंगे।

भाजपा का एक संविधान है, हमने एक वादा किया था कि ''सब का साथ सबका विकास और सबका विश्वास'' यह भावना लेकर हम लोग चले थे। यह भारतीय जनता पार्टी की विचाराधारा है लेकिन कांग्रेस का सपना है सबका साथ नहीं सिर्फ अपना साथ, सबका विकास नहीं सिर्फ अपना विकास और सबका विश्वास नहीं सिर्फ अपना विश्वास लेकर वह चले हैं। बजट में यह दर्शाया गया है कि जिन कांग्रेसी मित्रों ने जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं उनके इलाके में बजट में बहुत कुछ दिया गया है लेकिन राजनीतिक भेदभाव करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो विधायक हैं वहां इन्होंने कुछ नहीं दिया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं कि बजट पर मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। चूंकि समय की नजाकत है, मैं इसे समझता हूं। मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात को खतम करूंगा। पैरा नम्बर 3 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं

तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से,

मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं

क्योंकि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने, जिसको जादूगर कहा जाता है

श्री सभापति: सुमित गोदारा।

श्री अविनाश (जैतारण): अगर उनमें जादू होता तो लोक सभा की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आतीं। मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि बढ़ते हुए अपराध, दुष्कर्म की घटनाएं पिछले 6 महीने में राजस्थान में जिस तरीके से बढ़ी हैं उसको देखते हुए..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): उसको देखते हुए कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश अपराध की घटना में दूसरे नम्बर पर है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 6 महीने...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द्र जय भारत।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापति महोदय जी का आभार, being a citizen of world's fastest-growing economy standing at $2.8 trillion today from 2014, $2 trillion and with Modi Ji vision of making it $5 trillion dollars. I'm feeling proud of that being a citizen of fastest growing economy before the third-largest in the world by 2022.

उसी राज्य, देश का राजस्थान राज्य जो भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था जिसको बीमारू प्रदेश के नाम से हम जानते थे, जब पढ़ते थे राजस्थान क्या है एक बीमारू प्रदेश। प्रदेश में वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनीं 2003 में, दस साल में विकास की जो गति मिली उसी से राजस्थान बीमारू प्रदेश से निकला और आज भारत में विकास की गति में, आप इसी से सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत में महाराष्ट्र व गुजरात के बाद तीसरा नम्बर हमारा राजस्थान है। बढ़ते कदम हमारे राजस्थान के, पर हम बजट देखते हैं, जब राजस्थान के मुख्य मंत्री बजट पर, कृषि पर बोलते हैं, पृष्ठ 5-पाइंट नम्बर 15 पर आजादी के सात दशकों बाद भी खेती करना फायदे का सौदा नहीं माना जाता है। तो 55 साल शासन आपने किया। 55 साल शासन करने के बाद भी आप कहते हो कि खेती फायदे का सौदा नहीं माना जाता, तो दोषी कौन? मुझे पंक्ति याद आती है कवि सुमित्रानंदन पंत की कि है हमारा हिन्दुस्तान कहां, हिन्दुस्तान बसा हमारे गांव में, जहां रहते हैं हमारे किसान।

आजाद भारत में यदि किसी ने किसान की सुध ली तो भारत के वीर सपूत किसान, यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में प्रधान मंत्री बने और किसान क्रेडिट कार्ड, के.सी.सी. योजना लाए, जिसने किसान को संबल दिया।

मैं रेगिस्तान के धोरे लूणकरणसर से आता हूं। 1998 से पहले जब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री नहीं थे तब हमने अपने गांव में देखा कि क्या था, किसानों के क्या हाल थे, अगर किसी को छोटा-सा काम भी होता था तो किसान को ब्याज पर जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। के.सी.सी. योजना आई जिसने किसान को संबल दिया। हम ऐसे राजनीतिक दल से तुलना करते हैं जिसका नारा था "गरीबी हटाओ, देश बचाओं"। 30 साल तक वह नारा देते

(श्री सुमित गोदारा)

रहे। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और देश गति की ओर जाने लगा तो उन्होंने नारा बदला "कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। देश में हल्ला हुआ तो उन्होंने रातों रात नारा बदला और गरीब के साथ हटाकर कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ"। यह नारों वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है जिसने किसानों को संबल दिया। आज किसान अपना सिर ऊंचा करके जाते हैं तो के.सी.सी. योजना, फसल बीमा योजना के तहत जाते है।

बीच में दस साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, पर उन्होंने किसानों की कोई सुध नहीं ली। उसका इतना-सा उदाहरण है कि जब वाजपेयी जी के.सी.सी. योजना लेकर आए तो उसमे रोलओवर का प्रोवीजन था। उसमें कुछ कठिनाइयां जरूर रहीं, पर दस साल मनमोहन सिंह जी ने कोई बदलाव नहीं किया। नरेन्द्र मोदी जी ने रोलओवर में, जिसमें किसान को पूरा का पूरा पैसा बैंक में जाकर जमा कराना पड़ता था, 2016 में सरकार ने नियम वापस लिया और किसान को सिर्फ ब्याज जमा कराना पड़ा, किसान के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी बजट में पीडब्ल्यूडी के बारे में बोले पेज नम्बर 10-पाइंट नम्बर 37 पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर। यह सड़क की योजना किसकी थी? गांवों में, धोरों में, जहां सड़कें नहीं होती थीं, विकास में धोरे पीछे, रेगिस्तान पीछे, पूरा राजस्थान पीछे। एक के.सी.सी. और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क ऐसी योजनाएं लायी गयी जिससे आज राजस्थान का बजट और देश आगे बढ़ने लगा है।

ऐसी योजनाएं जिसने गांवों में विकास के नये पंख लगाये। फास्ट मूविंग कंज्यूमर कम्पनियां गांव में जाने लगीं, सड़कें पहुंचीं तब ही देश में प्रगति आयी, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।

जब शिक्षा की बात आती है पृष्ठ 30 पाइंट नम्बर 127, यहां मुख्य मंत्री जी स्कूल खोलते हैं 60 प्राइमरी और 100 मिडल। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब भैरोंसिंह जी ने आठवीं की स्कूलें प्रत्येक पंचायत पर खोली, दसवीं की स्कूलें वसुन्धरा जी ने 2003 में खोलीं। 2014 में पहले ही साल में मुख्य मंत्री जी ने पांच हजार स्कूलें क्रमोन्नत कीं। हम रेगिस्तान के लोग जानते हैं कि कितना जीवनदान दिया। आपने 70 साल में 55 साल

(श्री सुमित गोदारा)

शैक्षणिक हत्या की बच्चों की। क्योंकि आपने गांव में पढ़ाई नहीं पहुंचाई। कितनी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी, कितने बच्चे जिनका भविष्य बन सकता था वह शिक्षा की वजह से गया, यह जीवनदान, राजस्थान को विकास की गति पर लेकर आए भैरोंसिंह जी व वसुन्धरा राजे जी।

मैं तीन दिन से बजट पर बहस सुन रहा था। कई लोग पंडित दीनदयाल योजना के नाम पर हंस रहे थे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कल्ला जी हमारे ऊर्जा मंत्री बीकानेर के हैं, इनसे जाकर पूछो। लूणकरणसर क्षेत्र में हमने 12 हजार पोल पिछली सरकार में लगाये, 4 हजार से ऊपर ढाणियों में लाइट के कनेक्शन किये। मुश्किल से 600 कनेक्शन वंचित हैं, उस रोड पर, हाई वे पर कोई जाता है तो चारों और लाइटें चमचमाती दिखती हैं, तो याद करता है पंडित दीनदयाल योजना, जो भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी लेकर आए। ऐसी सरकार है हमारी जिसने काम किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं पृष्ठ 23-पाइंट 95-जनता क्लीनिक के नाम पर, इसकी तुलना करो हमारी भामाशाह योजना से। आप आज देखो नारायण हृदयालय हास्पिटल, गरीब आदमी कोई आ सकता था, हास्पिटल में कोई घुसने देता था? आज 3-3 लाख, 4-4 लाख के आपरेशन, कितने ही व्यक्ति हैं जिनको हम लूणकरणसर गांव से भेजते हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ डाक्टर, सर्वश्रष्ठ हास्पिटल से वह इलाज करा रहे हैं, भामाशाह योजना की बदौलत यह काम हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भामाशाह योजना नहीं होती तो आपका सरकारी तंत्र फैल हो जाता, इतने पेशेंट का लोड आप सहन नहीं कर सकते थे। आज डाक्टर्स हमें बताते हैं कि इस भामाशाह योजना की वजह से सरकारी हास्पिटल में पेशेंट का लोड कम हुआ है। प्राइवेट की ओर जाने लगे हैं तो हमें काफी सहूलियत मिली है। पीबीएम आर्थोपेडिक्स बीकानेर का हास्पिटल है, दो-दो महीने में नंबर नहीं आता था, दो-दो दिन में नंबर आने लग गया, लोग प्राइवेट की तरफ जाने लगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बात समाप्त करते हुए अंत में इतना ही कहूंगा...

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): लास्ट का पाइंट है। रोजागार के

(श्री सुमित गोदारा)

ऊपर पाइंट लिखा है, पृष्ठ 32-पाइंट 134, मुख्य मंत्री के द्वारा कि हम 75 हजार नौकरियां देंगे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मुझे याद आता है 1998 से 2003 में जब मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत बने थे तो एक भी नौकरी नहीं मिली। मुझे वह समय याद है जब युवा कहते थे कि पढ़कर क्या करेंगे? कांग्रेस सरकार है, प्रदेश में नौकरियां नहीं हैं। बच्चों, युवाओं का मोह पढ़ाई से छूट गया था। कृपया करके ऐसा प्रदेश के साथ मत कर देना युवा अपने आपको कोसें कि एक भी नौकरी नहीं दी। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे 2019 के बजट पर बोलने का मौका दिया।

मैं आदरणीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए बजट पेश किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। किसान भाइयों के लिए Easy of Doing business की तर्ज पर Easy of Doing Farming की ओर पहला कदम उठाया। एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। इस कोष से राज्य भर के किसानों को फायदा मिल पायेगा। मैं कहना चाहूंगा पूरे राजस्थान की जनता को एक महत्वपूर्ण बजट मिला है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि 2013 में जो बजट पेश हुआ, उसमें राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जमवारामगढ़ बांध की 1068 करोड़ की जो स्कीम है उसको इसमें प्रस्तावित रखा था। पांच साल तक उस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मैं इस योजना को चाहूंगा कि 2019 के बजट में रखा जाए, ताकि चार जिलों को इससे फायदा होगा। जयपुर शहर को पेयजल का फायदा मिलेगा और सिंचाई के लिए जमवारामगढ़, दौसा, बूंदी और जयपुर जिले को पानी मिलेगा। सिंचाई में फायदा मिलेगा, जिससे किसानों को भी फायदा होगा।

मैं कहना चाहूंगा 2013 के बजट में अम्बेडकर विश्वविद्यालय खोला गया, उसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को

(श्री गोपाल लाल मीना)

कि इस बजट में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को दुबारा, इस सरकार के आते ही खोला इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में 90 करोड़ की रोड, 2013 के बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी। हमारे जमवारामगढ़ ही नहीं, जमवारामगढ़ बांध से वाया आंधी, किशोरी-बीकमपुरा तक, यह रोड था। इस रोड को पिछली सरकार ने निरस्त कर दिया। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि इस बजट में उस रोड को पुन: स्वीकृत करें ताकि हमारे क्षेत्र, जयपुर जिले और अलवर जिले के आने-जाने का मार्ग सुदृढ़ हो पाये क्योंकि स्टेट हाई-वे भी है।

समय की बहुत कमी है, मैं मेरे क्षेत्र में जो डिमाण्ड है, उनके बारे में पहले बोल देता हूं। जमवारामगढ़ जयपुर के नजदीक है लेकिन भौगोलिक स्थिति इतनी विचित्र है कि वहां पर पहाड़, जंगल, सब कुछ है और दूर-दूर से छात्रों का जयपुर में आना बड़ा मुश्किल है। इसलिये जमवारामगढ़ में एक सरकारी महाविद्यालय होना जरूरी है। उसके साथ में जो हमारा सामुदायिक केन्द्र है जमवारामगढ़ में, उसके अन्दर पूरे जमवारामगढ़ और अलवर तक के मरीज वहां पर आते हैं, वहां पर सैटेलाइट हास्पिटल होता है तो निश्चित रूप से उन लोगों को फायदा मिल पायेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उद्योग विभाग से जमवारामगढ़ क्षेत्र में दो हजार बीघा जमीन का प्रपोजल भी बनाया गया था, लेकिन इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि जयपुर में रीको खोला जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्योंकि रायसर में, जो बाई-पास पर है, 2000 बीघा जमीन है और उसमें अगर रीको खोला जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र और जयपुर जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन पाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र को फायदा हो पाएगा।

मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक महत्वपूर्ण 75 हजार युवाओं को नौकरी का जो वादा किया है, अभी सामने से माननीय

(श्री गोपाल लाल मीना)

सदस्य कह रहे थे कि सब असत्य है, अभी पांच साल हैं और निश्चित रूप से 75 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): उसके साथ में जो हमारे... (व्यवधान) एक मिनट दें। युवाओं को नौकरी मिलेगी। इससे हमारे राजस्थान के युवाओं को फायदा होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट ...(व्यवधान)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आपका टाइम नहीं हुआ अभी।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें जल्दी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): मुझे बजट भाषण पर आपने बोलने का ...(व्यवधान)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं इस बजट पर यही कहना चाहूंगा कि इस बजट में ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): चार मिनट बचे हैं मेरे लिए।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। चन्द्रकान्ताजी बोल रही हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट भाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। बजट प्रदेश की आर्थिक नीति और विकास का आईना होता है और उसी अनुसार इसमें जनता की उम्मीदें और हम कहें कि 2019-20 का परिवर्तित बजट सपनों का प्रतिबिम्ब है तो निश्चित तौर पर यह बजट जनता के लिए सपनों का एक प्रतिबिम्ब है।

मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात कही। उसी निमित्त मैं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को डाइरेक्ट यहां रखना चाहती हूं, किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती।

मैं कहना चाहूंगी कि पूरे बजट भाषण में मेरे विधान सभा क्षेत्र का कहीं नाम और निशान नहीं है। मुझे बड़ा दु:ख हुआ इस बात को लेकर। क्योंकि अनेकों ऐसी योजनाएं थीं, जिनका टेंडर हो चुका था। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिनके काम चालू होने में ही थे। लेकिन उन कामों को रोकने का, जैसा मैं तीन-चार महीने से देख रही हूं, तो मुझे लग रहा है कि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। ऐसा मेरा बोलना है।

मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में बजरी की जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है क्योंकि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं आप देखिये, चम्बल, जो हमारी नदी है, लगातार अवैध खनन होने की वजह से दो महीने पहले भी चार मौतें हो चुकी हैं। लगातार हमने देखा, माधोपुर के नजदीक भी हम लोगों ने देखा। आपने बजरी के लिए एक खनन नीति बनाने की बात कही है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूं कि प्रशासन के ऊपर हमारा दबाव होना चाहिये। आज पुलिस प्रशासन की वजह से चारों तरफ हम देखें तो चाहे मेज नदी हो, चाहे हमारी चम्बल नदी हो, चारों तरफ अवैध खनन हो रहा है, अगर इस पर रोक लगेगी तो मैं कहूंगी कि जनता के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि लगातार ट्रैक्टरों को दौड़ाते-दौड़ाते ले जाते हैं, इससे हादसे बढ़ रहे हैं। यह मैं आज के दिन कहना चाहूंगी।

पैरा नम्बर छह में सम्माननीय सी.एम. साहब ने जो बात कही है, उसके लिए भी कहूंगी कि निश्चित तौर पर डाक्टर भीमराव अम्बेडकरजी ने जो अधिकार दिया, उसी के निमित्त आज हम यहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर से महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है, मैं कहूंगी उसी की वजह से आज हम लोग चुनाव लड़कर यहां पर आ रहे हैं। यह बात सम्माननीय सी.एम. साहब ने भी कही है।

सात नम्बर पैरा है, उसमें बात कही है कि हम युवाओं की अपेक्षाओं को समझते हैं। इसलिये उन्हें अच्छी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, सरकार से पूछना चाहती हूं कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

केशोरायपाटन की जो शुगर मिल है, वह बरसों से बंद पड़ी है। इस वजह से जो स्थिति वहां की बनी हुई है, वह आप सबके सामने है। हमारे सम्मानणीय मंत्री महोदय, कोटा से यहां विराजमान हैं, बूंदी के विधायकजी भी अभी यहीं बैठे थे, मैं कहूंगी कि अगर यह चालू होती है तो वहां की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 16 जुलाई, मंगलवार, प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 21.00 बजे मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ में प्रवेश से वंचित बालक-बालिकाएं

133. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रतापगढ़ जिले में सत्र 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में बीए प्रथम वर्ष में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजकीय महाविद्यालय धरियावद, राजकीय महाविद्यालय छोटी सादडी, जे.आर. कन्या निजी महाविद्यालय प्रतापगढ़ में कितने बालक बालिकाओं ने प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन किया एवं कितने बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया गया? कितने बालक-बालिकाएं प्रवेश से वंचित रहे? प्रवेश से वंचित बालक-बालिकाओं के अध्ययन हेतु सरकार की क्या योजना हैं?

(2) क्या सरकार प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय एवं अरनोद उपखण्ड के दलोट क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रतापगढ़ जिले में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ, राजकीय महाविद्यालय, धरियावद, राजकीय महाविद्यालय, छोटी सादड़ी में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जन सहभागिता क्षेत्र में महिला शिक्षा का जे.आर. कन्या महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में सत्र 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में बी.ए. प्रथम वर्ष में प्राप्त आवेदन व प्रवेशित छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित राजकीय महाविद्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के 5 सहशिक्षा एवं 1 कन्या महाविद्यालय (कुल 6 महाविद्यालय) संचालित हैं। परिशिष्ट-3

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय एवं अरनोद उपखण्ड के दलोट क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थानी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा देने की कार्ययोजना

135. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने राजस्थानी को अपनी मातृभाषा बताया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थानी भाषा को राजस्थान राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 2011 की जनगणना में जनगणना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में भारत में राजस्थानी मातृभाषा बोलने वालों की कुल संख्या 2,58,06,344 तथा राजस्थान में कुल संख्या 2,52,79,304 दर्शाई गयी है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चरागाह एवं आबादी क्षेत्र में आपसी विनिमय की योजना

136. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार चरागाह एवं आबादी क्षेत्र में आपसी विनिमय का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? उक्त के संबंध में वर्तमान योजना व भावी क्रियान्विति संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में चरागाह एवं आबादी क्षेत्र को विनिमय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाला किला दुर्ग, अलवर का पर्यटन की दृष्टि में विकास

137. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संजय शर्मा)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में स्थित बाला किला दुर्ग को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाला किला दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वर्षवार वृद्धि हुई है किन्तु विभिन्न अव्यवस्थाओं के कारण पर्यटकों को असुविधा हो रही है। यदि हां, तो सरकार उक्त किले पर पर्यटकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए उक्त समस्याओं का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हैरिटेज सर्किट के अन्तर्गत बाला किला के विकास हेतु राशि रुपये 166.22 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बोरीबूज दोयतरा ग्राम (आबूरोड) के अग्नि पीड़ितों को मुआवजा

139. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बोरीबूज दोयतरा (पंचायत समिति, आबूरोड) में झोपड़ी में आग लगने से बच्चों की मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो कब? क्या सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि देने का विचार रखती है।

उत्तर

जी हां। तहसील आबूरोड के ग्राम बोरीबूज, ग्राम पंचायत दोयतरा (पंचायत समिति, आबूरोड) में दिनांक 03.01.2019 को झोंपड़ी में अचानक आग लगने से श्री जोवनाराम के पुत्र करण कुमार की जलकर मृत्यु हो जाने से एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये की सहायता राशि मृतक के पिता के खाते में जमा करा दी गयी है।

रिसर्जेंट राजस्थान के एम.ओ.यूज. की क्रियान्विति

140. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और नये उद्योग आमंत्रित करने के लिए रिसर्जेंट राजस्थान के तहत कुल कितने MOU हुए? MOU के तहत कितने नये उद्योग शुरू हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उद्योगों को बढ़ावा देने और नये उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए सरकार रिसर्जेंट राजस्थान जैसे आयोजन जारी रखेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के दौरान रुपये 3.38 लाख करोड़ के 470 एमओयूज (MoUs) विभिन्न विभागों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये थे।

इन 470 एमओयूज में से आदिनांक रुपये 11,577.46 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 72 निवेश प्रस्ताव क्रियान्विति हो चुके हैं, जिनकी सूची अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(2) नये उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी एक मेगा इवेन्ट का आयोजन वर्ष 2020 के माह जनवरी/फरवरी में किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन में विभिन्न निवेशकों के साथ-साथ राजस्थान के प्रबुद्ध उद्योगपति एवं अपने क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित कर निवेश के साथ-साथ राजस्थानियों को राज्य के प्रति लगाव बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पद

141. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त पदों पर कितने अध्यापक कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं क्या सरकार रिक्त पदों पर नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में नागौर जिले में संचालित राजकीय विद्यालयों में प्राध्यापक के 15 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 121 पद, अध्यापक लेवल-। के 156 तथा लेवल-।। के 147 पद स्वीकृत हैं।

(2) नागौर जिले में संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालयों में 5 प्राध्यापक, 48 वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल। के 129 अध्यापक एवं लेवल।। के 103 अध्यापक कार्यरत हैं।

उक्त संचालित विद्यालयों में प्राध्यापक के 10 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 73 पद, अध्यापक लेवल-। के 27 तथा अध्यापक लेवल-।। के 44 पद रिक्त हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापकों के विभिन्न विषयों के 134 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 690 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पद, प्राध्यापक के 152 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 177 पद, अध्यापक के 226 पद, शारीरिक शिक्षक ।।। ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष ।।। ग्रेड के 31 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रस्तावित है।

जनजाति कल्याण के कार्यों पर व्यय राशि

143. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति कल्याण हेतु प्रदेश में भिन्न-भिन्न कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वित्तीय वर्षों में जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यों हेतु आबंटित धनराशि उक्त जातियों के कल्याण हेतु शत-प्रतिशत व्यय हो गयी? यदि हां, तो मदवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति कल्याण हेतु प्रदेश में वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार और भारत सरकार से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की सूचना निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(राशि लाख रु.)

मद/वर्ष	**व्यय**
(अ) राज्य सरकार	
वर्ष 2017-18	26229.36
वर्ष 2018-19	29264.21
(ब) केन्द्र सरकार	
वर्ष 2017-18	23395.26
वर्ष 2018-19	24529.58

जनजाति कल्याण हेतु प्रदेश में स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) वितीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जनजाति कल्याण हेतु विभिन्न कार्यों हेतु व्यय राशि का प्रतिशत निम्नानुसार है-

(राशि लाख रु.)

वर्ष	**स्वीकृत राशि**	**व्यय**	**प्रतिशत**
2017-18	50281.72	49624.62	98.69
2018-19	55106.02	53793.79	97.62

मदवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भौतिक सत्यापन

144. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा विधवा/वृद्धावस्था इत्यादि पेंशन की राशि को बढाया गया है? यदि हां, तो कब से आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या यह भी सही है कि पेंशन को प्रत्येक वर्ष में भौतिक सत्यापन करवाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वर्तमान में ऐसे कितने पेंशनर हैं, जिनकी पेंशन भौतिक सत्यापन के कारण बन्द है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भौतिक सत्यापन के अभाव में बन्द पेंशन का भौतिक सत्यापन विभागीय स्तर पर करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब-तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा पेंशन राशि में की गयी थी बढ़ोतरी का विवरण निम्न प्रकार है:

दिनांक 01.01.2019 से वृद्धावस्था पेंशन की दरों में रुपये 250 प्रतिमाह की बढोतरी कर 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर की रुपये 500 के स्थान पर 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर की रुपये 750 के स्थान पर रुपये 1000 प्रतिमाह की गयी है।

विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2019 से 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 250 प्रतिमाह की दर से बढोतरी कर 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये प्रतिमाह की गयी है।

दिनांक 01.07.2019 से विशेष योग्यजन पेंशन की दरों में रुपये 250 प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये के स्थान पर रुपये 1000 प्रतिमाह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर की पेंशन दरों में 500 रुपये की बढोतरी करते हुए 750 रुपये के स्थान पर 1250 प्रतिमाह की गयी है। जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट 1 से 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा परित्यक्तता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के नियम 12 के तहत प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन किये जाने का प्रावधान है।

जालौर जिले के विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा में 63 पेंशनरों की वार्षिक

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सत्यापन के अभाव में माह मई, 2019 की पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जिन पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से ई-मित्र कियोस्क एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वार्षिक सत्यापन करवाया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल के देवस्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास

145. श्री बाबु लाल (झाड़ोल): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार देवस्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कमल नाथ मन्दिर, सांडोल माता, रामकुण्डा, पानरवा राणा पूंजा आदि स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर देवस्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाता है।

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के कमल नाथ मन्दिर, सांडोल माता, रामकुण्डा, पानखा राणा पूंजा आदि स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रस्ताव विभाग में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

मालपुरा में ओलावृष्टि का मुआवजा

147. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2018 में हुई ओलावृष्टि के कारण कृषकों को मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में ओलावृष्टि से रबी एवं खरीफ फसलों में कोई खराबा नहीं हुआ है।

नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को सुविधाएं

148. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रीको द्वारा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या उक्त औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां? क्या नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में पार्कों को विकसित किया गया है? यदि हां, तो उक्त पार्कों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा नीमराणा में औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों के लिए निम्न सुविधाएं मुहैया करवाई गयी हैं:-

1. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में 11 निर्मित कियोस्क आबंटित किये गये हैं ताकि मजदूरों को क्षेत्र में चाय आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके।
2. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में 232 व्यावसायिक दुकानें नियोजित कर आबंटित की गई हैं ताकि मजदूरों को दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता की खान-पान की उपलब्धता हो सके।
3. इस क्षेत्र में कुल 37 स्थानों पर 568000 वर्गमीटर भूमि पर पार्क/ग्रीन बैल्ट/वुड लैण्ड की स्थापना की गयी है।
4. इस क्षेत्र में रीको द्वारा आबंटित 1800 वर्गमीटर भूमि पर यू.आई.टी. भिवाड़ी (बीडा) द्वारा एक सामुदायिक केन्द्र की स्थापना भी की गयी है।
5. औद्योगिक क्षेत्र में 8 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आबंटित हैं जिसमें से 3 भूखण्ड राज्य सरकार की अफोरडेबल हाउसिंग योजना के तहत आबंटित हैं। अफोरडेबल हाउसिंग योजना के तहत 2500 एकल बैड रूम इकाइयों का निर्माण किया गया।

(उद्योग मंत्री)

6. नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में 3 भूखण्ड अस्पताल हेतु आबंटित हैं जिसमें से 2 भूखण्डों पर अस्पताल संचालित हैं।
7. औद्योगिक क्षेत्र में कुल 9 बैंक कार्यरत है।
8. औद्योगिक क्षेत्र में 2 भूखण्ड स्कूल हेतु आबंटित हैं जिसमें से एक भूखण्ड पर स्कूल संचालित है।
9. औद्योगिक क्षेत्र में 05 भूखण्ड शैक्षणिक संस्थानों हेतु जिसमें से 02 भूखण्डों पर इन्जीनियरिंग कालेज संचालित हैं।

2. औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत मजदूरों के लिए भूखण्ड आबंटियों द्वारा अपने स्तर पर इकाई परिसर में शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों जैसे व्यवसायिक केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्र में भी शौचालय की व्यवस्था है।

रीको द्वारा नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में 3 पार्क/रोटरी विकसित किये गये हैं। जिनमें फुटपाथ, पानी का फव्वारा, पेड़, घास एवं लाइटों की सुविधा उपलब्ध है।

नसीराबाद में संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पद

149. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के किस-किस संस्कृत विद्यालय में कितने-कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापकों के विभिन्न विषयों के 134 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 690 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पद, प्राध्यापक के 152 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 177 पद, अध्यापक के 226 पद, शारीरिक शिक्षक ।।। ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष ।।। ग्रेड के 31 पदों एवं कनिष्ठ सहायक के 131 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका, प्राध्यापक विभिन्न विषय एवं वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के संस्कृत विद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

150. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के तहसील मुख्यालय बुहाना व सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है।

(2) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के तहसील बुहाना में निजी क्षेत्र में 17 एवं तहसील सूरजगढ़ में निजी क्षेत्र में 11 महाविद्यालय संचालित हैं। (परिशिष्ट-1)

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय बुहाना व सूरजगढ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

राजकीय महाविद्यालय खोलना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में वनाधिकार के पट्टे

151. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की पंचायत समिति अनूपगढ़ व घडसाना में वनाधिकार योजना के तहत गत 10 वर्षों में कितने वनाधिकार पट्टे वितरित किये गये हैं। उक्त योजना की कितनी फाइले पंचायत समिति स्तर पर व कितनी पत्रावली श्रीगंगानगर जिला स्तर पर किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वनाधिकार पट्टे के वितरण में आ रही बाधाओं को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अंतिम वनाधिकार पट्टा कब जारी किया गया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की पंचायत समिति अनूपगढ़ और घड़साना में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत गत 10 वर्षों में वनाधिकार पत्र वितरित नहीं किये गये हैं एवं कोई फाइलें पंचायत समिति स्तर पर व जिला स्तर पर लम्बित नहीं हैं।

(2) राज्य में वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत दावे प्राप्त करना एक सतत् प्रक्रिया हैं। प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर दावों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाकर दावेदारों को वनाधिकार पत्र जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्शिता (Transparency) लाने एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेयता (Accountability) सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा FRA Online MIS Portal विकसित कर फरवरी, 2019 में प्रारम्भ किया जा चुका है।

(3) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई वनाधिकार पत्र वितरित किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

निरमेक्स सीमेन्ट लिमिटेड निम्बोल (जैतारण) में अवैध जलापूर्ति

140. श्री अविनाश (जैतारण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के निरमेक्स सीमेन्ट लिमिटेड, निम्बोल में पानी की जलापूर्ति का स्रोत क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सीमेन्ट प्लांट में जलापूर्ति के लिए बोरवैल, ओपनवेल, हैण्डपम्प जैसे पारम्परिक स्रोत उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या इनकी कानूनी स्वीकृति ली गयी है यदि नहीं, तो क्यों? यदि स्वीकृति नहीं ली गयी है तो क्या सरकार निरमेक्स सीमेन्ट प्लांट, निम्बोल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्व में उक्त सीमेन्ट प्लांट के विरुद्ध अवैध रूप से जलापूर्ति के संबंध में कोई शिकायत हुई है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैतारण में निरमेक्स लिमिटेड निम्बोल में पानी की जलापूर्ति का स्रोत बोरवैल है। वर्तमान में 3 बोरवैल से पानी की जलापूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। जलापूर्ति के लिए 3 बोरवेल उपलब्ध हैं, जिसकी स्वीकृति क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 21-4 (493) डब्ल्यू आर/सीजीडब्ल्यू ए/2011-4952 दिनांक 10.12.2012 से जारी की गयी है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निरमा लिमिटेड (निरमैक्स) के पत्र क्रमांक एनएल/आरजे/ईएनवी-132-बी/595/2018 दिनांक 09.05.2016 व दिनांक 02.11.2018 द्वारा क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय भू-जल वेस्टर्न रीजन, झालाना डूंगरी, जयपुर को 3 बोरवैल हेतु पूर्व में जारी स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने उनके पत्रांक संख्या टी-एस/21बी (451) सीजीडब्ल्यूए/डब्ल्यूआर/आर/2008/573 दिनांक 25.02.2019 द्वारा सदस्य सचिव केन्द्रीय भू-जल आर्थोरिटी 18/11 जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी हां। पूर्व में अध्यक्ष सिणला विकास समिति तहसील जैतारण द्वारा दिनांक 21.08.2018 को श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को उक्त उद्यम द्वारा अवैध रूप से भू-जल का अंधाधुंध दोहन की शिकायत की गयी थी। उक्त शिकायत की जांच प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक, भू-जल विभाग, पाली के पत्रांक एसपी-1-2 दिनांक 16.10.2018 से वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायक द्वितीय भू-जल विभाग, जोधपुर को भिजवायी गयी है। उक्त पर कार्यवाही के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली अधिकृत है।

कोटा में चम्बल फर्टिलाइजर में श्रमिकों की कार्य करते हुए मृत्यु पर सहायता

141. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स गढ़ेपान जिला कोटा में कुल कितने स्थाई अधिकारी व कर्मचारी कार्य करते हैं? कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो गढेपान व इससे लगती नजदीक के ग्राम पंचायत के निवासी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में दैनिक श्रमिकों की संख्या कुल कितनी है? इन श्रमिकों को वेतन का भुगतान क्या चम्बल फर्टिलाइजर द्वारा किया जाता है अथवा संवेदकों के माध्यम से होता है? यदि संवेदकों के द्वारा किया जाता है तो संवेदकों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किसी भी श्रमिक की दुर्घटना या मृत्यु होने पर चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स किस प्रकार से श्रमिक की मदद करता है? गत 10 वर्षों में कार्य पर रहते हुए कुल कितने श्रमिकों की मृत्यु हुयी नाम-पते व उनको प्रदान की गयी सहायता राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स गढेपान जिला कोटा में कुल 818 स्थाई अधिकारी व कर्मचारी कार्य करते हैं। 48 कर्मचारी ऐसे हैं जो गढ़ेपान व इससे लगती नजदीक के ग्राम पंचायत के निवासी हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स गढ़ेपान जिला कोटा में दैनिक श्रमिकों की संख्या कुल 2317 है। 817 श्रमिकों को चम्बल फर्टिलाइजर

(उद्योग मंत्री)

एण्ड कैमिकल्स द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है एवं 1500 श्रमिकों को ठेकेदारों के माध्यम से वेतन का भुगतान होता है। ठेकेदारों की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जब कोई श्रमिक ड्यूटी पर हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जब कोई श्रमिक ड्यूटी पर हो और उसकी दुर्घटना हो जाए तो संबंधित ठेकेदार द्वारा उसका इलाज कराया जाता है और जब तक वह कार्य से अनुपस्थित रहता है उसको नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

गत 10 वर्षों में कार्य पर रहते फैक्ट्री में एक हाउस कीपिंग श्रमिक की दिनांक 03.04.2018 को प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई। नाम-पते सहित सूची व उनको प्रदान की गयी सहायता राशि का विवरण निम्न है:-

नाम	**पता**	**सहायता राशि**
श्याम लाल पुत्र श्री बाबूलाल	गांव सीमलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा	रु. 7.00 लाख

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

142. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं, इनमें से कितनी इकाइयां वर्तमान में संचालित व बंद हैं? विधानसभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बंद इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बालेसर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में अक्टूबर, 2015 से पूर्व 23441 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनका विधानसभावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं। अक्टूबर, 2015 के बाद 25464 औद्योगिक इकाइयों द्वारा UAM Portal पर स्वैच्छिक मेमोरेण्डम प्राप्त किये गये हैं, जिनका विधानसभावार विवरण

(उद्योग मंत्री)

उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त में से कितनी इकाइयां वर्तमान में संचालित व बंद है, की सूचना राज्य सरकार द्वारा संधारित नहीं की जाती हैं।

(2) जी हां। राज्य में रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु औद्योगिक नीति विचाराधीन है।

(3) जी हां। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको लि. द्वारा जिला कलेक्टर से प्रस्ताव चाहे गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कालाडेरा (चौमूं) औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक पानी से प्रदूषण

143. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कालाडेरा तहसील चौमूं में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पानी के कारण आस-पास में प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे उद्योग हैं जिनका दूषित पानी फैक्ट्रियों से बाहर निकल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समस्या की पहले भी कई बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किसने शिकायतें दर्ज करवायीं और उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रीको औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा, चौमूं में स्थित उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल से आस-पास के क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता है। निरीक्षण के दौरान निम्न उद्योग प्रदूषित जल का नि:स्राव करते हुए पाये गये-

1) मैसर्स देय भूमि उद्योग, एफ-137, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया कालाडेरा, तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर
2) मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क डेयरी प्रा. लि., ई-42-ई, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया कालाडेरा, तहसील-चौमूं, जिला जयपुर
3) मैसर्स उमंग बोर्डस लिमिटेड, ए-27 रीको इण्ड्रस्ट्रियल एरिया कालाडेरा, तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल नि:स्त्राव संबंधी शिकायते राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) निरीक्षण के दौरान किसी उद्योग से प्रदूषित जल का नि:स्त्राव पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, संचालन सम्मति निरस्त करना एवं उद्योग को बंद कराने के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास के लाभार्थी

144. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत 5 वर्षों में उक्त योजनाओं में कितने व्यक्तियों को कहां-कहां लाभान्वित किया गया व उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से किस-किस व्यक्ति का आवेदन पत्र कब से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लम्बित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति जारी कर लाभांवित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत 5 वर्षों में लाभान्वित व्यक्ति एवं भुगतान की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में उक्त योजनाओ के अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(4) पात्र लम्बित आवेदन पत्र बजट उपलब्धता के अनुरूप स्वीकृत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में पंजीकृत होम्स में बच्चों की चिकित्सा जांच

145. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जे.जे. एक्ट हनुमानगढ जिले के तहत पंजीकृत होम्स में बच्चों की चिकित्सा जांच करने का क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में जिला स्तर पर संचालित उक्त गृहों में कब-कब बालक/बालिकाओं की चिकित्सकीय जांच की गयी? गृहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सकीय जांच के दौरान बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां पायी गयीं तथा उनके उपचार के लिए क्या व्यवस्था की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए क्या-क्या उपकरण उपलब्ध करवाये गये एवं कितनी राशि आबंटित की गयी तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत गृहों में आवासियों की चिकित्सा जांच करने हेतु जे जे एक्ट 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के नियम 34 में चिकित्सा देखभाल का प्रावधान है। छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में जिला स्तर पर संचालित गृहों में आवासित बालक/बालिकाओं की जांच का विवरण परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है।

(3) उक्त जांच के दौरान गृहो में आवासित बच्चो में मौसमी एवं सामान्य बीमारियां पायी गयीं। जिसके उपचार हेतु गृहो मे विजिट बेस पर चिकित्सक उपलब्ध हैं एवं आवश्यकतानुसार नजदीकी चिकित्सालय मे बच्चों का उपचार करवाया जाता है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत बाल देखरेख गृहों में पृथक से रोगों के इलाज हेतु कोई प्रावधान नहीं है। उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक बच्चों को भोजन वस्त्र एवं दवाइयों हेतु 2150 रुपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है एवं रोगों के इलाज हेंतु राजकीय चिकित्सालय के माध्यम से नि:शुल्क उपचार करवाया जाता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में चिकित्सालय में दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण बाजार से दवाइयां उपलब्ध करवायी जाती हैं। गृह में 71 रुपये की राशि व्यय की गयी है। विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में संचालित छात्रावास

146. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने छात्रावास संचालित हो रहे हैं? उक्त छात्रावासों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं? प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्र-छात्राओं के रहने की क्षमता है? वर्तमान में उक्त छात्रावासों में कितने छात्र/छात्रा रह रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधानसभा क्षेत्र रायसिंहनगर में संचालित 6 छात्रावासों एवं उनकी स्वीकृत क्षमता का विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध हे एवं विभाग द्वारा छात्रावास में आवासरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क आवास, बर्तन, बिस्तर आदि सुविधाओं के साथ 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से भोजन सामग्री व अन्य सामान इत्यादि मैस भत्ते के रूप में दी जा रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। वर्तमान में उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिक

147. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में अन्य विभागों के कितने कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? नामवार एवं विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रतिनियुक्त कार्मिकों को वेतन विभाग से दिया जा रहा है तथा वह किस मद से दिया जा रहा है? ये यहां कितने समय से कार्यरत हैं और किस कार्य को कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग में किन-किन जिलों में किस-किस कार्य के कार्मिकों की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा नये पदों का सृजन किया गया अथवा रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कोई प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग में संविदा के आधार पर कार्मिक कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस-किस कार्य हेतु किस-किस जिले में नियुक्त किया गया है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मे 01 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रतिनियुक्ति कार्मिक को विभाग से वेतन दिया जा रहा है। मद व कितने समय से कार्यरत है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिलों में कार्य की आवश्यकतानुसार कार्मिकों के पद पूर्व से ही सृजित हैं। सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) हां। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक विभाग द्वारा सृजित किये गये नये पदों की सूचना शून्य है।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारियों के रिक्त पदों पर दिनांक 08.07.2019 को 25 अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। नियुक्ति आदेश परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भामाशाह योजना में निजी चिकित्सालयों को पुनर्भुगतान

148. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भामाशाह योजना के तहत किन-किन निजी चिकित्सालयों को कितनी-कितनी राशि का पुनर्भुगतान जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर में स्थित निजी चिकित्सालय भामाशाह योजना से जुड़े हुए हैं। यदि हां, तो कौन-कौनसे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भामाशाह योजना के तहत किन-किन निजी चिकित्सालयों में जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक रोगी पंजीकृत किये गये? पंजीकृत रोगियों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भामाशाह योजना के तहत बीमा की राशि रखने के लिए कौन-कौनसे निजी चिकित्सालयों के विरुद्ध गलत आपरेशन किये जाने एवं गलत उपचार की शिकायत दर्ज हुई दर्ज प्रकरणों में किन नियमों के तहत कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध निजी अस्पतालों के द्वारा जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक रु. 14,35,63,90,925 राशि के क्लेम्स सबमिट किये गये तथा बीमा कंपनी के द्वारा राशि रु. 12,83,01,64,625 का निजी चिकित्सालयों को भुगतान किया जा चुका है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले के 261 निजी अस्पताल सम्बद्ध हैं। अस्पतालवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध निजी अस्पतालों के द्वारा जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक कुल 10,75,553 पात्र मरीजों को लाभान्वित किया गया है। अस्पतालवार मरीजों की संख्या की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सम्बद्ध चिकित्सालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/प्रकरणों में, योजना के दिशा-निर्देश वर्ष 2017 (बिन्दु संख्या 32-44) तथा Guidelines for de-empanelment and penalty against private hospitals, दिनांक 20.07.2018 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राज्य स्तर पर राज्य परिवेदना निस्तारण कमेटी अपीलीय प्राधिकरण में सम्बद्ध अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों व कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में चिकित्सालयों में रिक्त पद

149. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कितने चिकित्सालय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सक, नर्स एवं कम्पाण्डरों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गणेश घोघरा)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में उक्त वर्ग के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जिला चिकित्सालय 1, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण) 13, उप स्वास्थ्य केन्द्र 83 स्वीकृत हैं एवं एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में संचालित चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स संलग्न है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पातेला पर कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां। पदोन्नति/विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी/पीजी पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को स्थानान्तरण से यथासम्भव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियधीन है भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात रिक्त पदों को प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा। विभाग में पदोन्नति के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाली में चिकित्सालयों में स्वीकृत पद

150. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में कुल कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उप स्वास्थ्य केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? इनमें वर्तमान में कुल कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी एम्बुलेंस स्वीकृत हैं? कितनी एम्बुलेंस चालू हालत में हैं व कुल कितनी एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में हैं? क्या सरकार बन्द पड़ी एम्बुलेंस को बदलकर नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 91 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-ब पर एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

पदोन्नति/विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी/पीजी पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से यथासम्भव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक उपरान्त प्राथमिकता के साथ भरे जाने के प्रयास किये जाएंगें।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विधान सभा क्षेत्र बाली में संचालित चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता/ आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली में कुल 11 एम्बुलेंस स्वीकृत हैं जिसमें से 9 एम्बुलेंस चालू हालत में हैं तथा 2 एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त जर्जर एम्बुलेंस के एवज में नवीन एम्बुलेंस के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त नवीन निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से नवीन वाहनों का क्रय विभाग द्वारा न किया जाकर वाहन सेवा प्रदाता द्वारा ही वाहन उपलब्ध (On Turnkey Basis) करवाये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर के गीतांजली मेडिकल कालेज की मान्यता

151. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गीतान्जली मेडिकल कालेज, उदयपुर को किस वर्ष में मान्यता प्रदान की गयी? उक्त कालेज में ट्रेनिंग हेतु छात्रों को एडमिशन कब से दिया गया? तिथिवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थान के नियम विरुद्ध भर्ती के संबंध में पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी एवं उसके क्या परिणाम रहे? शिकायतवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शिकायतों पर किसी जांच समिति एवं जांच अधिकारी द्वारा उक्त संस्थान में भर्ती नियमों की अवहेलना की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त संस्थान के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है? क्या सरकार नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गीतान्जली मेडिकल कालेज उदयपुर को वर्ष 2008 में एम.बी.बी.एस. कोर्स हेतु मान्यता प्रदान की गयी, उक्त कालेज में छात्रों को एडमिशन कब से दिया गया, की वर्षवार एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2018 में एक शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित कर जांच करवायी गयी। जांच में गीतांजली मेडिकल कालेज, उदयपुर को 47 सीटों पर प्रवेश अनियमित तरीके से पाये

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जाने की रिपोर्ट पर एक बैठक की गयी उसका कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उसके पश्चात विशेषाधिकारी, उप शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं सहायक विधि परामर्शी निदेशालय मुख्यालय की एक संयुक्त जांच समिति पुन: गठित की गयी उक्त कमेटी की जांच प्रक्रियाधीन है। संयोजक, नीट यू.जी. काउन्सलिंग बोर्ड, 2018 (प्रधानाचार्य एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर) से कुल पांच प्राइवेट मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत छात्रों की सूची का परीक्षण करवाया गया जिसमें चार कालेज की सूची परीक्षण करने उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो उनके परीक्षण में सही पायी गयी बताया है। गीतांजली मेडिकल कालेज की सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसके लिए कालेज को पत्र लिखा जा चुका है।

(3) बिन्दु संख्या-2 के अनुरूप, परिशिष्ट-2 पर।

(4) परिशिष्ट-2 पर की गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी मेडिकल कालेजों की प्रवेश सूची की जांच करायी गयी जिसमें चार सही पायी गयीं एवं गीतांजलि से सूची प्राप्त नहीं हुई। साथ ही उप शासन सचिव के स्तर पर पुन: एक और कमेटी गठित की गयी जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है। जांच में दोषी पाये जाने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मसूदा में ब्लड बैंक की स्थापना

152. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मसूदा के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ब्लड बैंक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रो में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति मसूदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक तथा पंचायत समिति भिनाय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति मसूदा एवं भिनाय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में मसूदा, लूलवा, भिनाय एवं बान्धनवाडा में 30-30 शय्याओंयुक्त एवं विजयनगर में 75 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्ष 2018 में शय्याओं की उपयोगिता (बी.ओ.आर.) निम्न प्रकार है:-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	**(बी.ओ.आर.)**
मसूदा (30 बैडेड)	43.65 प्रतिशत
लूलवा (30 बैडेड)	00.00 प्रतिशत
भिनाय (30 बैडेड)	42.51 प्रतिशत
बान्धनवाडा (30 बैडेड)	13.30 प्रतिशत
विजयनगर (75 बैडेड)	59.41 प्रतिशत

विधान सभा क्षेत्र मसूदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शय्याओं की उपयोगिता (बी.ओ.आर.) 100 प्रतिशत से कम होने के कारण शय्याओं में वृद्धि/क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिनाय एवं विजयनगर पर ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित हैं, जिनकी वार्षिक खपत 2000 यूनिट से कम है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार ब्लड की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वार्षिक खपत 2000 यूनिट होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वर्तमान में नवीन ब्लड बैंक खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आर.टी.डी.सी. की होटल्स को पीपीपी माडल पर देने की योजना

153. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) के होटल्स, मिड-वे यात्री भवन आदि निगम को हो रहे लगातार आर्थिक घाटे के कारण बन्द किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां, कितने-कितने होटल, मिड-वे, यात्री भवन आदि बन्द किये गये? वर्ष 2003 से 2018 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पर्यटन निगम को हो रहे घाटे के कारण निगम के होटल्स, मिड-वे यात्री भवन आदि को पीपीपी माडल या निजी क्षेत्र को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003 से 2018 तक की अवधि में हानि में रहने के कारण आर.टी.डी.सी. की 27 होटल\मोटल\यात्रिका का संचालन बंद किया गया। जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सपत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने का सैद्धान्तिक अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 17.06.2015 के द्वारा किया गया। तदनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निगम के अध्यधीन इकाइयों को निस्तारित किये जाने के संबंध में राजस्थान पर्यटन विभाग/राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा भूमि, सम्पत्तियों का व्ययन नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्य राज्यों में स्थित देवस्थान सम्पत्तियों का निस्तारण

154. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभाग की अन्य राज्यों में भी सम्पत्तियां स्थित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? राज्यवार, स्थानवार सम्पत्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त सम्पत्तियों पर किस-किस का कब्जा है? सरकार द्वारा इनकी देखरेख के लिए किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी को नियुक्त कर रखा है? सम्पत्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। देवस्थान विभाग की राजस्थान राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित राजकीय मंदिर/संस्थान की सम्पत्ति (अचल) की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त सम्पत्तियां देवस्थान विभाग के प्रबंध एवं नियंत्रण में हैं। इनमें जिन सम्पत्तियों पर अतिक्रमण है, उनकी सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। राज्य के बाहर स्थित मंदिरों एवं परिसम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव तथा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली में स्थित मंदिरों एवं परिसम्पतियों की व्यवस्था हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन नियुक्त है तथा इनकी सहायता हेतु प्रबंधक/पुजारी/चौकीदार आदि कर्मचारी नियुक्त हैं तथा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों एवं निरीक्षक द्वारा सम्पत्तियों का निरीक्षण एवं देखरेख की जाती है। सम्पत्तिवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देवस्थान विभाग की संपदाओं के लिए राज्य सरकार की किराया नीति 2000 बनी हुई है, जिसके अन्तर्गत संपदाएं किराये पर दी जाती हैं। किराया नीति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत में मंदिर व मठों की भूमि पर अतिक्रमण

155. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में मंदिरों व मठों के नाम से कितनी भूमि वर्तमान में कहां-कहां पर स्थित है? वर्तमान में उक्त भूमि का कहां-कहां किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त मंदिरों, मठों के नाम से दर्ज भूमि पर अतिक्रमण अथवा इसके गलत उपयोग करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में तहसील सोजत एवं रायपुर का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है। तहसील सोजत के 88 राजस्व ग्रामों में मंदिरों एवं मठों के नाम से 1820.2483 हैक्टेयर भूमि स्थित है। तहसील रायपुर में मंदिर एवं मठों के नाम से 22 ग्रामों में 337.94 हैक्टेयर भूमि स्थित है वर्तमान में ग्रामवार भूमि एवं उसके उपयोग का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राजस्व ग्राम बगड़ी नगर तहसील सोजत के वादग्रस्त भूतनाथ डोली की भूमि खसरा सं. 2809 पटवार हलका बगड़ी चक 2 में शिकायत प्राप्त हुई। उक्त भूमि गै.मु. आबादी के रूप में दर्ज एवं उपयोग में आ रही है।

उक्त भूतनाथ डोली भूमि द्वितीय भू-प्रबंध के दौरान गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत बगड़ी के नाम दर्ज की गयी, तदुपरांत ग्राम पंचायत द्वारा एकल पट्टा जारी किया गया। जिस पर भवन निर्माण अपूर्ण है। वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में वादग्रस्त भूमि पर स्थगन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्द्रगढ़ (जमवारामगढ़) में भूमि के सीमा ज्ञान

156. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित ग्राम इन्द्रगढ़ के खसरा नम्बर 149 से 152 तक की सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा दिनांक 24-06-2015 के आदेश की पालना में फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट गिरदावर गठित टीम द्वारा दिनांक 02-07-2015 के आधार पर उप खण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ के आदेश क्रमांक 566 दिनांक 02-11-2015 के द्वारा पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार को आदेश दिया गया था? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि काश्तकार द्वारा उक्त खसरान के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने बाबत दिनांक 20-11-2016 को भू-राजस्व विभाग में 20 हजार रुपये भी जमा कराने के बावजूद सैटलमेंट टीम द्वारा उक्त खसरान के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी नहीं करायी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा तीन सर्वे शीट बंदोबस्त, एकीकरण एवं हाल में उक्त खसरान का नक्शा सही पाया गया है? यदि हां, तो विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उक्त खसरान की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी क्यों नहीं की गयी तथा क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भू-प्रबंधक विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर 149 से 152 की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करने हेतु एक टीम गठित कर मुस्तकिल पाइंटों को बिन्दु मानकर एवं गांवों की सीमाओं को आधार मानकर पुन: सीमाज्ञान एवं निशानदेही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेशानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही की गयी थी सीमांकन रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। राशि जमा कराने के बाद तहसीलदार, जमवारागढ़ द्वारा नियत की गयी दिनांक को सीमाज्ञान में तकनीकी सहयोग हेतु भू-प्रबन्ध टीम भेजी गयी। विवादित खसरा नम्बरान के समीप मुस्तकिल बिन्दु नहीं होने से सीमाज्ञान नहीं हो सका।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। सर्वेशीट, एकीकरण नक्शा व हाल नक्शा लगभग सही है। लेकिन मौके पर मुस्तकिल मुकामात नहीं मिलने से सीमांकन कार्यवाही नहीं की जा सकी। कार्मिकों द्वारा कार्य को अंजाम देने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं।

(4) भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके पर पुन: दूरस्थ स्थान से मुस्तकिल मुकामातों को तलाशा जाकर सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु टीम का गठन किया जाकर सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 157

(स्थगित)

पहाड़ी ग्राम (टोडाभीम) चरागाह भूमि का किस्म परिवर्तन

158. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पहाड़ी (नांगल) तहसील टोडाभीम (करौली) में बढ़ती आबादी के कारण ग्रामीण आवास निर्माण के लिए सरकारी एवं चरागाह भूमि सहित विभिन्न प्रकार की भूमि की किस्म को परिवर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में किसान परिवारों द्वारा आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरी से अन्य किस्म की भूमियों पर आवास तथा मवेशियों के लिए बाड़े आदि निर्मित किये हुए हैं? यदि हां, तो ऐसे आवासों के नियमन किये जाने तथा भूमि की किस्म को परिवर्तित किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कार्यवाही को पूर्ण कर भूमि के पट्टे कब तक जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पट्टे प्राप्त होने के पश्चात् ही ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पहाड़ी (नांगल) में सरकारी व चरागाह भूमि पर बने हुए आवासों का सर्वे करवाया जाकर किस्म परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। इन भूमियों पर पट्टे जारी किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के साथ संयुक्त रूप से परिपत्र दिनांक 30.11.2017 जारी किया हुआ है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। बिन्दु संख्या 1 की कार्यवाही पश्चात इस परिपत्र के तहत नियमन योग्य भूमि आबादी हेतु पंचायत को आबंटित की जाएगी।

ग्राम पंचायत को आबादी भूमि आबंटित होने के पश्चात राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के दिशा-निर्देशानुसार आरम्भ में बेघर परिवारों को, उनके बाद कमरों की संख्या शून्य, 1 या 2 कमरों के आधार पर परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिस क्रम में भूमिहीन पात्र परिवारों को प्राथमिकता से नि:शुल्क/रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन करने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं।

योजनान्तर्गत भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता से आवास स्वीकृत किये जाते हैं एवं भूमि उपलब्ध होने पर अनुदान राशि की किश्त जारी किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों का पदस्थापन

159. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व विभाग में सिरोही जिले से कितने पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के गत दस वर्ष में जिले से बाहर स्थानान्तरण किये गये? सूची मय तिथि सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विभाग में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले से नियुक्त होकर अन्य जिलों में गये

(श्री संयम लोढ़ा)

पटवारियों को पुन: सिरोही जिले में लगाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले से 26 पटवारी एवं 03 भू अभिलेख निरीक्षकों के गत दस वर्ष में सिरोही जिले से बाहर स्थानान्तरण किये गये। सूची मय तिथि के परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में राजस्व विभाग में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**नाम पद**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त**
1	भू.अ. निरीक्षक	65	51	14
2	पटवारी	189	89	100
3	प्रशासनिक अधिकारी	1	-	1
4	अति. प्रशा. अधिकारी	5	1	4
5	सहा. प्रशा. अधिकारी	19	11	8
6	वरिष्ठ सहायक	43	31	12
7	कनिष्ठ सहायक	57	31	26
8	वाहन चालक	15	7	8
9	शीघ्र लिपिक	6	-	6
10	जमादार	1	1	-
11	च.श्रे. कर्मचारी	135	53	82

(3) राज्य सरकार आवश्यकता एवं स्थानान्तरण नीति अनुसार विचार रखती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में माडा-बिखरी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

160. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माडा/बिखरी योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

विभाग द्वारा विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से अब तक भीलवाड़ा जिले में बिखरी/माडा योजना के तहत किन-किन निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि को प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां कब-कब जारी की गयी और पूर्ण कराये गये सभी निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं? यदि नहीं, तो किस किसके? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भीलवाड़ा जिले में माडा/बिखरी जाति के लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और जातियों की पहचान कर ली गयी है। नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि माडा/बिखरी क्षेत्र के अन्तर्गत भीलवाडा जिले के लिए निर्माण हेतु जनजाति विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिले में दिनांक 1 अप्रैल 2014 से अब तक बिखरी/माडा क्षेत्र के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु बिखरी क्षेत्र के तहत 50.14 लाख रु. तथा माडा क्षेत्र के तहत राशि 25.97 लाख रू. एवं इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत राशि 111.81 लाख रु. निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई। कुल राशि 187.92 लाख रु. स्वीकृत किये गये। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त आबंटित राशि की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयीं और पूर्ण कराये गये सभी निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जो प्राप्त हो गये हैं, उनकी सूचना परिशिष्ट "अ" में सम्मिलित है। माडा क्षेत्र में 2 सी.सी. रोड एवं बिखरी क्षेत्र में 2 सी.सी. रोड व 1 एनिकट। इसी प्रकार संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत 3 सामुदायिक भवन के उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त नहीं हुए हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) हां। भीलवाड़ा जिले में माडा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजौलिया, जहाजपुर एवं माण्डलगढ़ तहसील क्षेत्र के जनजाति बहुल सम्मिलित होने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है। माडा एवं बिखरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(S.T.) की जातियों की जनसंख्या को आधार माना गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र बिखरी क्षेत्र मे सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण के जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्य

161. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर जिले में करीब 70 प्रतिशत जनजाति परिवार रहते हैं? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 से जून, 2019 तक क्या-क्या विकास कार्य किये गये? विधान सभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्र में पानी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में पानी की कोई परियोजना बनाकर व डोडावाली बच्छार पंचायतों के लिए बनाकर टंकी से पानी की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर जिले में करीब 70 प्रतिशत जनजाति परिवार नहीं रहते हैं, अपितु 49.71 प्रतिशत जनजाति परिवार रहते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर जिले की विभिन्न विधान सभा क्षेत्रो में दिसम्बर 2018 से जून 2019 तक स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

विधान सभा क्षेत्र	कुल स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि लाखों में	विवरण
धरियावद	16	74.59	समस्त कार्य पेयजल संबंधित
खेरवाड़ा	12	107.05	5 कार्य राशि 24.30 लाख पेयजल संबंधी 7 कार्य राशि 82.75 लाख विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण संबंधित

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र	**कुल स्वीकृत कार्य**	**स्वीकृत राशि लाखों में**	**विवरण**
सलूम्बर	17	82.24	समस्त कार्य पेयजल संबंधित
उदयपुर ग्रामीण	17	51.60	15 कार्य राशि 41.60 लाख पेयजल संबंधी एवं 2 कार्य राशि 10.00 लाख सम्पर्क सड़क निर्माण निर्माण संबंधित
उदयपुर शहर	2	10.95	समस्त कार्य पेयजल संबंधित
गोगुन्दा	6	15.18	समस्त कार्य पेयजल संबंधित
झाडोल	1	134.09	सम्पर्क सड़क निर्माण निर्माण संबंधित

(2) हां। जनजाति एरिया के 35 ग्रामों 99 ढाणियों में पानी की समस्या आयी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा ग्रीष्मऋतु 2019 में जनजाति क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए 35 ग्रामों 99 ढाणियों में 96 टैंकरों द्वारा जल वितरण किया गया। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वर्तमान में स्थाई समाधान हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं हैं।

(3) ग्राम डोडावली की 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 1706 एवं बच्छार की जनसंख्या 1820 है। वर्तमान में दोनों ही ग्राम हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है। ग्राम डोडावली में कुल 42 हैण्डपम्प हैं, जिनमें से 25 हैण्डपम्प कार्यशील हैं, 17 सीजनल एवं 6 सिंगलफेज पनघट कार्यशील है, ग्राम बच्छार में कुल 45 हैण्डपम्प हैं, जिनमे से 20 हैण्डपम्प कार्यशील एवं 25 सीजनल हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मापदण्डों के अनुसार जनजाति क्षेत्र में 3000 जनसंख्या से अधिक की आबादी होने पर उस गांव को पाईप्ड योजना के तहत उच्च जलाशय बनाकर लाभान्वित किया जाता है। उक्त दोनों गांव की आबादी 3000 से कम है तथा दोनो गांवों की आबादी बिखरी एवं भूतल काफी उंचा नीचा होने से दोनों ही गांवों में टंकी बनाकर पेयजल वितरण किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली में माडा योजना में कार्य

162. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माडा योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र करौली में किस-किस ग्राम पंचायत से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतवार आबंटित की गयी तथा आबंटित राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते हैं एवं उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें उक्त योजना के तहत आती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में माडा योजना अन्तर्गत कार्य की आवश्यकता, उपादेयता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र करौली में निर्माण कार्य हेतु मानदण्डानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए एवं उक्त विधान सभा क्षेत्र करौली में निर्माण कार्य हेतु किसी भी ग्राम पंचायत को राशि आबंटित नहीं की गयी।

वर्ष 2018 में विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला मुख्यालय कालेज स्तर पर महिला आश्रम छात्रावास खोलने हेतु 350.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी।

(3) माडा योजना के तहत कराये जाने वाले कार्य की सूची एवं ग्राम पंचायत की सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम का संचालन

163. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में 10+2 उच्च माध्यमिक के बाद इन्टीग्रेडेड (एकीकृत) पाठ्यक्रम के तहत पी.टी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा के बाद बीए, बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं? प्रदेश में वर्तमान में किन-किन महाविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन्टीग्रेडेड बीए, बी.एड, बीएससी करने वालों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम तय कर रखा है? क्या सभी महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए महाविद्यालय प्रधानाध्यापक/सहायक प्रोफेसर उपलब्ध है, किन-किन महाविद्यालयों को इसकी मान्यता दे रखी है? कौन-कौन प्राध्यापक किन-किन महाविद्यालयों में लगे हुए हैं, किस महाविद्यालय में कितनी-कितनी सीटों का आबंटन बीए, बीएड व बीएससी, के लिए है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन्टीग्रेडेड बीए, बी.एड, बीएससी पाठ्यक्रम केवल सरकारी महाविद्यालयों में ही चल रहा है अथवा निजी महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं? सरकारी व निजी महाविद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सरकारी महाविद्यालयों में स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति व सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वर्तमान में यह पाठ्यक्रम की सुविधा जिन-जिन महाविद्यालयों में है उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इन्टीग्रेटेड बी.ए. बी.एड बीएससी बी.एड. करने वालों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम तय करना सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। महाविद्यालयों में नियुक्त प्रधानाचार्य/सहायक प्रोफेसर नियुक्ति का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। उक्त पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची मय सीटों की संख्या के साथ परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। इन्टीग्रेटेड बी.ए. बी.एड बीएससी बी.एड. पाठ्यक्रम सरकारी महाविद्यालयों में संचालित नहीं है। निजी महाविद्यालयों में संचालित है। निजी महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(4) जी हां। विभाग द्वारा वर्तमान में 1248 पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनमें आज दिनांक तक 1081 अभ्याथियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष को नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त आयोग को 830 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना दिनांक 06.04.18 को भिजवायी गयी। आयोग द्वारा इन अभ्यर्थनाओं में एम.बी.सी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण को सम्मिलित कर संशोधित अभ्यर्थना भिजवाने हेतु दिनांक 25.03.19 को लिखा गया है। संशोधन कर अभ्यर्थना पुनः भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश से पूर्व 25 प्रतिशत विद्यार्थियों की सीट बढ़ाई जा चुकी है। संलग्न परिशिष्ट-2

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नीमराना (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

164. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर तहसील नीमराणा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की तहसील नीमराणा से लगभग 23 किमी की दूरी पर सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर संचालित है। इसके अतिरिक्त नीमराणा तहसील क्षेत्र में 03 निजी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराणा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू में कन्या महाविद्यालय का भवन निर्माण

165. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में जिला स्तर पर संसाधन सुलभ कराने के लिए जिला संसाधन सहायता समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी समितियों का गठन अब तक किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति कब जारी की गयी तथा वर्तमान में कितनी छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए कितनी राशि कब स्वीकृत की गयी व उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की गयी तथा भवन निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू स्थित लोहिया महाविद्यालय व राजकीय कन्या महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कालेज शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की समितियों का गठन नहीं किया गया है।

(2) चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दिनांक 31.05.2017 को जारी की गयी। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू में सत्र 2019-20 में अध्ययनरत कुल 451 छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू के भवन निर्माण के लिए दिनांक 29.11.2017 को राशि रुपये 600.00 लाख स्वीकृत किये गये, स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। स्वीकृत राशि में सें जून, 2019 तक राशि रुपये 161.92 लाख व्यय हो चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यादेश अनुसार भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 29.07.2019 है, प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू में विभिन्न विषयों के सह/ सहायक आचार्य के पदों का विवरण परिशिष्ट-5 एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू में विभिन्न विषयों के सह/सहायक आचार्य के पदों का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू के रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/अनुकम्पात्मक नियुक्ति/स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

166. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उक्त संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार के सुराज संकल्प के बिन्दु संख्या 10.17 के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिए जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं है, वहां सरकारी कालेज की स्थापना की जाएगी। (परिशिष्ट-1)

उक्त घोषणा के क्रम में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति मुख्यालयों पर पुस्तकालयों का संचालन

167. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जिला संभाग एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर विभाग के नियंत्रण में कितने पुस्तकालय संचालित हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) प्रदेश की कितनी पंचायत समिति मुख्यालयों पर पुस्तकालय भवन निर्मित हैं एवं कितने मुख्यालयों पर भवन नहीं हैं? वहां कब तक भवन निर्माण करवाया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्ष 2014 से 2019 तक प्रतिवर्ष कितनी नई पुस्तकें क्रय की गयीं, कितनी पुरानी पुस्तकों को अपलिखित किया गया एवं नई पुस्तकें खरीदने पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में ई-पुस्तकालय सुविधा कितने स्थानों पर उपलब्ध है? ई-पुस्तकालय सुविधा विस्तार के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के नियंत्रण में 47 पुस्तकालय संचालित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य में 210 पंचायत समिति मुख्यालयों पर भवन निर्मित हैं एवं शेष 72 स्थानों पर भवन नहीं है। उक्त स्थानों पर भवन निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर करवाया जा सकेगा। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) राज्य में वर्ष 2014 से 2019 तक प्रतिवर्ष नई क्रय की गयी पुस्तकों की संख्या, अपलिखित की गयी पुरानी पुस्तकों की संख्या एवं नई पुस्तकें खरीदने पर हुए व्यय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) ई-पुस्तकालय सुविधा 02 पुस्तकालयों में उपलब्ध है। ई-पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों को कैटालाग, पुस्तक आदान-प्रदान एवं सदस्यता कार्य किया जा रहा है। ई-पुस्तकालय विस्तार के संबंध में सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय की स्थापना

168. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अनूपगढ़ में सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय को प्रारम्भ करने के लिए पुस्तकालय प्रभारी का पदस्थापन करने का विचार

(श्रीमती संतोष)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुस्तकालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सार्वजनिक पुस्तकालय की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पुस्तकालय में कितनी व किस-किस विषय की पुस्तकें कब तक उपलब्ध करवायी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनूपगढ़ व घड़साना में राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय में पुस्तकालय प्रभारी पदस्थापित है।

(2) उक्त पुस्तकालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 22,000/- का प्रावधान किया गया है।

(3) उक्त पुस्तकालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित है। इसलिए पुस्तकालय सुरक्षा भी विद्यालय सुरक्षा के अधीन है।

(4) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राज्य पुस्तकालय समिति की बैठक का आयोजन निकट भविष्य में प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित बैठक में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तक क्रय हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से राशि का निर्धारण किया जाएगा। तदोपरान्त पुस्तक चयन एवं क्रय समिति का आयोजन किया जाएगा। इस पुस्तकालय को कितनी व कौन-कौनसी पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाएगी, का निर्धारण केन्द्रीय पुस्तक चयन एवं क्रय समिति द्वारा इस बैठक में किया जाएगा।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्नीचर एवं वाहन का क्रय

169. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को आफिस के लिए एक वाहन एवं फर्नीचर पहले से उपलब्ध होने के उपरान्त भी नये कुलपति के आने के बाद फिर से नया फर्नीचर तथा वाहन

(श्री पुखराज)

कितनी-कितनी राशि का क्रय किया गया है? उक्त सामान/वाहन किस नियम के तहत क्रय किया गया? इसके लिए किस-किस सक्षम स्तर से स्वीकृतियां ली गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पूर्व तकनीकी विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर व वाहन उपलब्ध न होने के कारण बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा नया फर्नीचर राशि रुपये 1,67,441.00 (एक लाख सड़सठ हजार चार सौ इकतालीस रुपये) तथा एक वाहन नवीन कार मय रजिस्ट्रेशन एवं असेसरीज राशि रुपये 10,33,618.00 (दस लाख तैंतीस हजार छह सौ अठारह रुपये) का क्रय किया गया।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा कार का क्रय जैम GeM (Government e Marketplace) पोर्टल से उपापन नियम RTPP Act, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) के अन्तर्गत किया गया तथा फर्नीचर का क्रय क्रय समिति गठित कर उपापन नियम RTPP Act, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement **Act**, 2012) के अन्तर्गत किया गया।

इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा ली गई सक्षम स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोलीटैक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल संकाय की स्थापना

170. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बाड़मेर पोलीटैक्निक कालेज में पेट्रोकेमिकल विषय प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो इस विषय में अब तक कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कालेज में यह विषय प्रारम्भ ही नहीं किया गया यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब इस विषय को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में सत्र 2005-06 में पेट्रोकेमिकल शाखा स्वीकृत की गयी थी तथा सत्र 2006-07 से पेट्रोकेमिकल शाखा 40 छात्र की प्रवेश क्षमता के साथ प्रारम्भ की गयी।

राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में सत्र 2006-07 से 2008-09 तक प्रवेश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या**
2006-07	40
2007-08	40
2008-09	44
कुल	**124**

(2) जी नहीं।

राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में सत्र 2005-06 में पेट्रोकेमिकल शाखा स्वीकृत की गयी थी तथा सत्र 2006-07 में पेट्रोकेमिकल शाखा में 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

तत्पश्चात राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में विशेषज्ञ शिक्षकों आदि की अनुपलब्धता तथा उक्त शाखा को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा की जा रही मांग को देखते हुए, छात्र हित में संचालित पेट्रोकेमिकल शाखा को दिनांक 25.5.2009 को केमिकल शाखा में परिवर्तित किया गया।

वर्तमान में राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल शाखा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देवली उनियारा में पोलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना

171. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली उनियारा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजकीय पोलीटैक्निक कालेज कहां-कहां पर हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में पोलीटैक्निक

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 35 राजकीय सह शिक्षा पोलीटैक्निक महाविद्यालय एवं 08 राजकीय महिला पोलीटैक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में टोंक मुख्यालय पर पूर्व में ही राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय संचालित है जिसमें गत वर्ष (2018-19) स्वीकृत दो पाठ्यक्रमों में 120 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध कुल 16 छात्र हुए हैं।

उक्त के अतिरिक्त टोंक जिले में 04 निजी पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में 1140 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध कुल 275 छात्र ही प्रवेशित हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)